

प्राप्तिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 15]

म**र्ड बिल्ली, धानिवार, अप्रैल 13, 1985/खे**ळ 23, 1907

No. 15]

NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 13, 1985/CHAITRA 23, 1907

इत भाग में भिन्न पृष्ठ संस्था की जाती है जिस्से कि यह अलग संकलन के कप ने

रचाना सक

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग **म-कण्ड** 3-उप-क्षण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा भंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किए गये सांविधिक आवेश और अधिसूचनाएं Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)

विभि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्ययिभाग)

नई दिल्ली, 14 जनवरी, 1985

का. आ. 1471.—-केन्द्रीय सरकार सोटरा अधिनियम, 1952 (1952 का 53) की धारा 6 के उपबंधों के अमुसरण में, अपने द्वारा नियुक्त किए गए और वर्ष 1985 के प्रारम्भ में विधि व्यवसायरंग नोटरियों की भूची प्रकाशित करनी हैं.---

ऋ.सं.	नोटरियों का नाम	आवास और व्यवसाय का	पता अर्हेनाएं	बहु अब जिसमें वह बिधि- व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत है।	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6
१ श्री	चत्रवर्ती दोगस्वामी	मैं. किंग एड पेट्रीज कैंश् मेटर (सेकिड पलोर) 6, आर्थिनियन स्ट्रीट, मद्रास-1	प्रांलिक अधिवन्ता महास उच्च न्यायालय	मपूर्ण भारतः	
2. श्री	हस्तम अरदेमिर गगरेट	गगपेट एंड कं . अलीचेबर नगीनवास मास्टर रोड, मेडोज सेंट, फोर्ट, बंबई	अधिवक्षा बस्वर्ध	संपूर्ण भारत	
सर्वश्री					
3. भ ग	विनी प्रसाद खेनान	1- बी, ओल्ड पोस्ट आफिस स्ट्रीट, कल	कत्ता एटर्नी एट लॉ कलकता उच्च न्यायालय	संपूर्ण भारत	
4 रघी	द्र कुरुण देव	टे म्पल चेम्बर्स, 6 ऑल्ड पोस्ट आफिस स्ट्रीट, कलक	एटर्नीपट लॉ त्या कलकत्ता कु ठ च स्थायालय	संपूण भारत	
5. हिम	तेणुप्रकाण गोगुली	4, ६श्वर दस लेन, हावड़ा (प. घंगाल)	ग्रधिक्ता, कलकसा उच्च न्यायालय		

1 2	3	4	5	в
सर्वेषी		,		
6.सुधीर कुमार हे मलिक	मार्फन मार्टिमबर्न लि 12 मिशन रोग एक्स, कलकत्ता-।	एटर्नी एट लाँ कलकत्ता उ च् व न्याया ल य	संपूर्ण भारत	
7. रास मोहन भटर्जी	मार्फत मैं . और दिग्नाम एंड कं . मार्लिसिटर्म, 29 नेताजी सृभाष रोष, कसकता	मालिसिटरः कलकत्ता उच्च स्यायालयः	पष्टिचमी बंगाल, असम बिहार, उ.प्र. और पंजाब	
8. अभु वयाल हिम्मत सिंहका 9. पुण्यव्रत बोस	•	अटर्नी एट लॉ कलकत्ता उच्च त्यायालय अटर्नी एट लॉ कलकत्ता उच्च न्यायालय	संपूर्ण भारत सम्पूर्ण भारत	
1 0. विक्टर इलियस मौसेल	6 ओल्ड पोस्ट आफिस स्ट्रीट, कलकत्ता	ः अटर्नी एट लॉ कलकत्ता उच्च न्यायालय	संपूर्ण भारत	
11. मुलकली राज बधावन	अधिवक्ता जर्लधर सिटी,पंजाब	अधिवक्ता पंजाब उच्च म्यामालय	् पंका बिभी रिच प्र.	
- 12. मनोहर लाल कपूर	3/9 पटेल नगर (पू.) नई विल्ली	अधिवस्ता	दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र	
13. हरप्रसाद मेहरा	नं. 3060 चर्लोधालान, विल्ली	अधिवक्ता पंजाब उच्च स्यायालय	े मध राज्य क्षेस्न विल्ली	
14. चमन लाल अरोड़ा	1 0, स्यू कोर्ट रोज, असृतसर, पंजाब	अधिवक्ता	अमृतसर जिला पञाब	
15. दामोवर देवजी वामोद र		मालिसिटर	महारा ब्द्र	
16 देव प्रसाद घोष	मार्फंत फाउलर एंड कं . , सालिसिटर्स एंड एडबोकेट एंड नोटरीज, रीजेंट हा उस, 12, गवनैमेंट प्लेस, पूर्वी कलकत्ता-69	अटर्नी	संपूर्णे भारत	
17. नयमल हिमतसिंगका	6 आरुड पोस्ट आफिस अटर्नी स्ट्रीट कलकत्ता	अटर्नी	संपूर्ण भारत	_
18. राम किशन गर्गे	56 ओल्ड विजयसगर कालोनी, आगरा (उ. प्र.)	वकील, आगरा	जिला आगरा	
19. सी. एच, पार्कीवाला	मार्फत में . काफोर्डवेंसे एंडक . स्टेट बैक बिल्डिंग, बैक स्ट्रीट बम्बर्ड- 1	सालिसिटर	संपूर्णं भारत	
20. सर्वेश्री मचीन्द्र सी. सेम	अटर्नी एट लॉ,टैन्पल चैम्बर्स पहली मंजिन 6 ओल्बपोस्ट आफिस स्ट्रीट, कलकता	र अटर्नी	कलकत्त ा	
21 जी. ए. मेहता	अधिवक्ता, 43 वी हनुमान रोड, मई विल्ली	बार एट लॉ	विल्ली संघ राज्य क्षेत्र	
22. दुर्गा प्रसाद तुलस्यान	अधिवक्ता , झुनसुन् , राजस्थान	अधिवक्ता	मुनमुन् जिला राजस्थान	
23. एम . जी . दोसित	मै . एम . जी . सोसित एंड मं . सालिसिटर 35-एम्बेसी मार्केट, अहमदाबाद	अटर्नी	गुजरात और महाराष्ट्र	
24. तूर मृहम्मद	अधिवक्ता उवगपुर, राजस्थान	अधिवयता	उदयपु ^र र जिला (राजस्या म)	-
25. मुधीर कुमार गील	मार्फत मै . सैण्डरसंस एंड मोरगन्स, सालिसिटर्स रॉयल इंग्यूरेंस बिल्डिगस 5 और 7 नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता-	सालसिटर 1	संपूर्णभारत	
26. जितेन्द्र नाथ सान्याल	मार्फत मै. सैन्डरसंस रायल इन्स्यो- रेंग बिल्डिंग 5 एंड 7 नेताजी , सुभाष रोड, कलकत्ता-1	सानीमिटर	संपूर्ण भारत	
7. इंद्रसेन इसरानी	मधिवन्ता, जे-54, नवल हाउस, जयपुर (राजस्थान)	प्रधिवक्ता	जयपुर सिटी मी र जिला	
18. पी० सी० कृ रियन	14 , कोंडीचट्टी स्ट्रीट, Π , पलोर, मक्रस	अधियस्ता	मद्रास और केरल	
29. गुरवयाल सिंह सि ञ्	नं. 1, दोखा जंसंधर (पंजाब)	म धिव क्ता	जलंधर जिला	
30. सी भाई. वेंकट- सुबहुमण्यन	140, क्रांस कट रोड, कोयम्बतूर	म धियक्सा	कोयम्बतूर जिला	

1 2	3	4	5	6
31. पुष्कर लाल जनेजा	एफ-1, शंकर मार्केट, कनाट सर्कम, नई पिल्ली	प्रधिवक्ता	संपूर्ण भारत	
32. चुन्नी लाल भाटिया	सी-4/ए/68/सी, जनकपुरी, नर्ष विल्ली-58	म धिव क्ता	दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र	_
33. जगम नाथ	सिविल लाइन, मोगा, जिला फिरोजपुर (पंजाब)	प्रधिवक्ता	मोगा मुख्यालय स्थित फिरोजपुर जिला घौर साथ ही मोगा स्थित मुख्यालय सहित संपूरी- वकोट जिले में स्थवसाय करने के लिए प्राधिकृत	
34. रामजी बास सिंघल	गुरत्नारा स्ट्रीट मटिंडा (पंजाब)	ग्र धियक्ता	जिला भटिंदा	
35. बास कृष्ण	भ्रश्चिषकता हनुमान गढ़ टाउन जिला गंगा नगर (राजस्थान)	म्रधिव क् ता	हर्नुमानगढ़ स्थित मुख्यालय सहित जिला गंगानगर (राजस्थान)	
36 एस. घार. मेहता	<mark>घधिव≑ता खलोला, राजस्था</mark> न	श्रबित्य ग	बलोला स्थित मुख्यालय सहित बाड़ मेर मौर जालौर जिले (राजस्थान)	
37. जी. सी. वर्मा	भ्रधिषस्ता भीर शपथ [े] स्नायुक्त, ई/12, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली	ग्रधिवक्ता धौर शपथ भायु क् त	दिल्ली संघ राज्यक्षे त	
38. पी.एल. गांधी	श्रधिवक्ता, गांधी बाग के सामने सूरत	भा <u>धिवन्ताः</u>	जिला सूरत	
39. ए. भार. मलकानी	मधितक्ता, बी०बी०जेड, एन-७, गांधी धाम (कच्छ)	प्रधियकता	सपूर्ण गुजरात	
40. एन.सो. णाह्	नं. 1 बर्दवान रोड पहली मंजिल, अक्षीपुर कलकत्ता-27	प्रधिवक्ता, कलकत्ता	कलकत्ता भौर मई विल्ली	~ =
41. टी. दिलीप सिंह	मार्फत मैं किंग एंड पैट्रोज दूसरी मंजिल कैयोलिक सेंटर झार्मेनि- यन स्ट्रोट, बाक्स नं० 121, मद्रास-1	प्रधिव क्ता, म द्रा स	संपूर्ण भारत	_
42 जे. भार, गगराट	मार्फत में. गगराट एंड कंब्घला चैम्बर्स नगीनवास मास्टर रोड, फोर्ट वं बर्द ा	श्रधिवक्ता, बंबई ,	संपूर्ण भारत	
43. भार. सेतलूर	श्रोलिम्पस ग्रपीटमेंट फैलैट नं. 308 तोसरी मंजिल, एटामा- उण्ट रोड, बंबई-26	भटर्नी भ्रौर श्रधिवक्ता, बंबई	संपूर्ण भारत	
44. बुज मोहन मेहला-	13 ए/2 राजिन्बर मगर, नई दिल्लों	प्रधिवक्ता, नई दिल्ली	विल्ली संघ राज्य क्षे <mark>त्र</mark>	-
45. सुरजोत सिंह सूद	23 नेताजी पा के जलंधर सिर्ट। (पंजाब)	प्रधिवक्ता, जंलधर	जलंधर, पंजाब	
46. जगजीत सिंत बैस	376 एल माडल टाउन जलंधर सिटी, पंजाय	श्रधिवस्तः, जलंधर,	जलंधर पंजा य	
.17. सर्वेश्री के . जे ० ख मूबाटा	र जब म हल, 144 क्वीस रो ड, क्ष म्बई- 20	अधिवस्ता, बंब ई	संपूर्ण भारत	
48. अम्बे लाल बाबू माई लाल पटेल	वैद्य स्ट्रीट,पो. आ. नावासारी, जिला पुलसार,गुअरात.	अधिवस्ता	गु ज रात	
49. पूनम चन्द्र सीम चन्द्र णाह	गुजरात समाचार भवन, सैकिंग फ्लोर, खानपुर, अहमदाबाद !	अधिवस्ता	गुज रात	_

1 2	3	4	5	
50. बी. टी. मर्चेंट	मार्फत मै . ठाकुरदास और महगावकर, फीर्ट चैंबसें दीन लेन फीर्ट, बम्बई-1	अटर्नी और अधिवक्ता	संपूर्ण भार≀स	
51. एच. एस. भगत	मार्फन अम्भू भाई एड दीवानजी सालि सिटर्स एंड एडवोकेट्स इंडस्ट्रीज हाउस, आश्रम रोड, अहमदाबाद-9	- अधि य मता और सालिमिटर	गुंआरान	
52-एच. बी. छक्षपति	मार्फत मे. भाई शंकर कंगा गिरधारी लाल मानकजीवाडिया बिल्डिंग बेल लेन, फार्ट बम्बई-1 और मार्फन में साई गंकर लाल कंगा और गिरधारी लाल, गुकरात समाचार भवन खान- पुर, अहमदाबाद		संपूर्णे सुकारात	<u></u>
53. जी , एस , स्थास	35, लावण्य नगर जीवराज पार्क रोड इलियाम विज्ञ, अहमदाबाद-7	अधिवस्ता	अहम ाम ाय शहर	
54. अभर सिष्ठ	क्रमीयत सिंह रोड, मोगा जिला फरोद- कीट, पंजाब	अधिवक्ता	मानाजिताफरीदकौट पंजाब	
55. बी. एच. अनितिया	मार्फत मैं . मुल्ला ए ड मुल्ला एंड ग्रेग प्लंट एंड कैरोइस. स िलिसिटर्स एड नोटरीज, जहांगीर वाडिया बिल्डिंग- ^I 51, महास्मा ^{गो} धी रोड, बम्बई-1	अटर्नी और अधिवक्त(सपूर्ण भारन	
56. बी . पी . गुक् ला	रधुनाथ बि न् ^{हि} ग, टा उन ह।ल रा जकोट, गुजरान	अ घिषक्ता	^र ाजकोट और जूमाग जिला	
57.सर्वश्री बी.के. माह	म नसुख निवास नै री चाहिषवा ड वड़ौदा -6	श्रधिबक्ता	बहारा	
58. रमेश जे . मेहता	नादियाद जिला कैरा गुजरात राज्य	म् धितक ता	कैरापच(मान ग्जिल ा	
s9. वसंत लाल डी . मेहता	मार्फत मालवी रणछोड़ दास एक के. सालिसिटर्स एंड एडबोकेट्स यूसूफ बिल्डिंग्स महात्मा गांधी रोड, फोटें, बम्बई-1	स≀लिलिटर	महाराष्ट्र	
G0. म . एक . करमालावाला	वर्ष गेट चैम्बर्स, 5, स्यू मेरिन ले 1, कमरा सं . 611, छठी मंजिल बस्बई-20	मालिमिटर	काई -िया दुशालाः महित सर्गुणंसहार∘ष्ट्र राज्य	
61. वर्शन सिंह	ए-321 क्रिफेस कालोनी, नई दिल्ली	म्र धिव क्ता	दिल्ली सब राज्य क्षेत्र	
62. श्रीमती के. वी. देखाई	5 भारत कालोनी, नजदीक सरदार पटेल कालोनी, अहमदाबाद∽1 4	प्रधिवक्ताः	प्रहमशबाद 	
63. मोहिन्द्र सिंह	2 77 सैव न गेट, जलंधर	प्लीडर	जलधर	
64. रा जिन्द्र कु मार पट्ट	एस-401 ग्रेटर वॉलाश, नई दिल्ली-48	भ्र धिव क्रना	सघ राज्य क्षेत्र दिल्ली, उ.प्र. क्रौर हरियाणा	
3 5. भारायण प्रसाद गोयल	ई-165, नारायण बिहार, नई दिल्ली-48	प्रधिवक्ता	मंघ राज्य क्षेत्र विल्ली	
36. र्क . बी. पो मस	विराजपेट कुर्ग जिला कर्नाटक	प्रधित्रक्ता	कुर्गजिला	
37. एस . ह सन कोया	चलायपराम कालीकट, केरल	य िव क्ता	कालीकट भीर मालापुरम जिला	
38. सलिल क्रमार गोगुली	50 रामतन् बोस लेम, कलकत्ता-७	प्रटर्नी एट ना ए ड अधियक्ता	कलकत्ता	
39. पल्लव कुमार बनर्जी	मैं , टी . बनर्जी एंड क . सालिसिटर्म एंड एडवोनेट्स टेस्पल चैंस्वर्स. नं . 6 झाल्ड पोस्ट झाफिस, स्ट्रीट, कलकत्ता	मालिमिटर भ्रौर भ्राधित्रक्ता	क <i>ा</i> करने !	
70. सर्वेश्वी एम. वाई. एस. मेनन	मी. मजूमधार एड क., इस्माइल बिल्डिग, 381, जा. जी. एन. रोड, (फ्लोर फाऊनटेम) बम्बई	सालिमिटर ब्रीर घधिवक्ता	ग्रेटर बम्बई	

7 1. बूज भूषण गुप्ता	कलाल मजरी, प्रवाला सिटी	भ्र धिनम ्सा	श्रंबाला सिटी	
7.2. रचुकीर सिंह कुल्हा	घीरवा तहसील, राजस्थान	प्रधिवक्ता	विड्वा सहसीच	
73. सलेमानी गुरबोनी	202, फंबर नगर, रजामल का तालाब,	ग्र धियम् ता	जयपुर ज	
23. सम्माना मुख्यामा इ.स.च्या	जयपुर	VIII (1) (1)	जन <u>उ</u> र	
7 4. नस्द किशोर पारीख	321 नाहरगढ रोड, गोपाल हलवाई की गली, जयपुर	प्रधिय " ना	जयपुर	
7 5. ग्रन्तिलेश्यर दास बदगल	ग र्मा रेस्टोरेंट, जौहरी बाजार जयपुर-302003	ग्र धिय मना	जयपुर	
76. डी, भार. जैलवाला	में . डी. श्रार, जैलवाला एड कं. सारि सिटमें रेडीमनी मेंशन, 43 वीर नारीमन रोड फॉर्ट, बंबर्ड		ग्रेटर व म्ब र्ड	
7 7. ब्रंथोनी दा कोस्टा	मैं , वा कोस्टा एंड दा कोस्टा एडवो- केट्स एंड टैक्स कंसलटेंट्स, 2 I/12 महारमा गोबी रोड पहली मंजिल,, बंगलीर-1	प्रधिवक्ना	मपुर्णं भारत	
7 8. श्रीमती सुमति घर्रांदर पाटिल	23 6 जैन टैम्पल रोड, गोमेस नगर हिं दवाडी, बेलगाम, कर्नाटक	अधिव यता	जिला बेलगाम	
79. टी. एम. सेन	मैं . खेतान एड कें . सालिसिटर्स एड एडवॉकेट स हिमालय हाउस, मातबीं मंजिल, 23 कम्तूरबा गांधी मार्ग, न र्ह दिल्ली	भटनीं एण्ड लॉ	सरूर्गं भारत	~ ~
o. श्रीमती एन . श्रनुसूया बाई	4624/ 1 प्रियाजी रोड, एनं . थार. माहल्ला, मैसूर- ७	ग्र धिव क्ता	मैसूर सिटी	
3 1. पद्मनाथ गगाधर गोखले	ए-36 डिफेस कालोनी, नई दिल्ली	प्रधिव क् ता	संपूर्ण भारत	
 राम नरेल लाल गुप्त 	"बिहार धाम", सी-2श/70 नेलियाबाग, वाराणसी <i>कें</i> ट, उत्तर प्र वेण	भ <u>्रधिवक्ता</u>	वाराणसी, उप.	- -
33 समन ग्रसगर भ्रली पूर्नावाला	1 2-इस्माइल बिल्डिंग, 81, डा , बादाभाई नौरोणी रोड, फोर्ट, बम्बई	भ्रधिषयता	मद्दाराष्ट्र राज्य	
u 4. स र्वे श्री ग्रवधे श कुमार वर्मा	मार्फत श्री रवु राम वर्मा, प्रधिवक्ष्मा सिविल कोर्ट, वाराणसी, उ . प्र	भ्रधिवक्ता	जिला बाराणसी, इ.प्र.	
5. गुलाम ताहिए	डी-50/29 मोमाजीपुराकला, वाराणसी, उ.प्र.	मधिवक्ता	वाराणसी ,जिला उ . प्र .	
6. किमोरी लाल कपूर	5 1 6 वर्ष गेंट जै म्बर्स, पांचवीं मंजिल 5-स्यू भेरीन लेन, बम्बर्ध- 20	ग्रिधिवक्ता	महाराष्ट्र राज्य	- -
7. टी . के . थण्मु गगनन्दम्	8 8, हजूर रोड, कीयम्बत्रर-641018	अधिव क्ता	कोयम्बद्गर	
8. राजेंद्र क् मार	37, साउच कु मार पाड़ा लेन, कलकत्ता-42	म्म धियम ता	कलकत्ता भीर 24 परगंता	
9. र मुबीर सहाय हितकारी	सिविल कोर्टस, कानपुर	प्रधिवन ना	कानपुर श्रौर दिल्ली	
o. झोम प्रकाश जैन	ए-5-की 126-की जनकपुरी, नई दिल्ली-110058	ग्रधिवषतः।	दिल्ली	
1. बिमल जुमार बनर्जी	J, बंकणाल स्ट्रीट, कलकत्ता-700001	प्रधिवम् या	कथकत्तां भीर 24 परगना	
2. पदमसी बाजीखोना	45, टेमेरिण्ड स्ट्रीट, फोर्ट बम्बई-23	भ्र <u>धिवम्</u> ता,	ग्रेटर सम्बर्ध	
3. जी . ए . बनासवाला	मार्फत पायने ए इं क 0 . एसपला हे हाउन बाउडचे रोड, फोर्ट, बस्बई-40001	न प्रश्रिवस् ता	संपूर्णं भारत	-;
4. लीयो बेनेडिनट बेलहों	कोस्टा परेरा बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, मारगोधा सैलेक्ट गोधा	ग्रविवन्ता	संपूर्णं गोवा	

1 2	3	<u> </u>		
95. कृमा री जसव त कीर	एच-21, कैंसाम कालोनी, नई दिल्ली	भ्र <mark>धिवक्</mark> ता	विल्ली संग राज्य क्षेत्र	
96. सर्वश्री ६च जलागुर बलगारा	मै . पायने एंड र्क , इसप्लाडे हाउस बाउडवे रोड, फोर्ट, बम्बई- ।	भ्रधिय क् ता	संपूर्ण भारत	
9 7. बरलेम की सिल्वा शेनाई	92, ''सनमन'' क्रफे—-परेड, बम्बई- 400005	ग्रधिवक्ता	सपूर्ण महाराष्ट्र राज्य	
98. रामेश्वर द यास गुप्त	४৪, सी . गास्त्री नगर, जोधपुर	श्रधिवक्ता	जिला जोधपुर	
99 . খুন্দ খ ন্ব	मुक्तसर जिला फरीवकोट,पंजाब	प्रधि वम्त ा	चंडीगड़ संच राज्य क्षेत्र	
100. राम रतन लेख	र्ष्ट्स-553, मोहिला अवदुरा, कालंधर सिटी	: म्रधियक्ला	जालंधर सिटी	_
01. एम. श्राई० सेठना	फजलभाई बिल्डिंग, दूसरी मजिल, $45/57$, एम. जी. रोड फोर्ट, बम्बई-1	ग्र धिश् य क्ता	बम्सई सालकेश्वर भौर फोर्ट क्षेत्र	~-
102. दुर्गा शंकर वये	भ्रोसवालवारा राजस्थान जासवाङ्गा-३२७००।	ग्रधियक्ता	बासवाङ्गा जिला राजस्थान	-
03. मुरलोधर राव नायक	मकतानपुरा गुलबर्गं कर्नाटक	श्रधि वक्ता	गुलबर्गा जिला मीर शहर	
o 4. भगवती प्रसाद भट्ट	1 1-ज्ञान मार्ग गिं, उत्त्यपुर, राजस्थान	ग्र <mark>धिवस्ता</mark>	उदयपुर	
i 0 5. जनकलाल भग्नवाल	9 , बलेनबिल्ले रोड, दार्जि लिंग	प्रधियक्ता	वार्जिलिंग	<u> </u>
। 06 के, सी. सिधवा	गाखा सचित्रालय बर्बई, प्रायकर भवन एनैक्सी, न्यू मैरीन लाइंस	केंद्रीय सरकार प्रधिवक्ता ,	संपूर्ण भारत	
	ब म्ब ई-4 00020		भविवस्ता भौर सालिसिटर	
07. सूरज कुमार भास्कर	खेस सडी जिला क्षुनशुन्तू, राजस्थान	ग्रधिवक्ता	खोतङ्गि, राजस्थान	
08. देवी भारण चोपड़ा	बो-3, टूरोजेज, पाली रोड, बं बई	प्र धिवन्ता	बंबई गहर	
() 9. देवज्रत बसु	7, देवनारायण वास क्षेन, स्थाम बाजार, कलकत्ता	प्रधिव श् ता	समालदण स्थित मुख्यालय सहित 24 परगना	
10. कुमारी मजुला सेन	33, घीतम कुफे परेड, बम्बई	ग्रधिवक्सा भीर सालिसिट	र्सूपूर्ण भारत	
11. ए. सैयद प्रानी	⁻ 53, आर्मेनियन स्ट्रीट, मद्रास	प्रधिवम लो न	मद्रास राज्य	
12. जी, सी. वर्मा	सिविल कोर्टेस जगाधरो, जिला श्रंबाला हरियाणा	प्र धियम् सा	जगाधरी	-
13. गजेब्र नाथ चक्रवती	9, ग्रोल्ड पोस्ट माफिस स्ट्रॉट क लक त्ता	भ्र <u>धिवक्</u> ता	कलकसा∼ 1	
14. भदिती कुमार परामशीक	10, घोल्ड पोस्ट ग्राफिस स्ट्रीट कमरा सं. 110, कलकत्ता	भधिवस्ता	पश्चिमी बंगाल र।ज्य	
15. इंद्रा चंद्र चोह्	1 2, ओल्ड पोस्ट प्राफिस स्ट्रीट, कमरा स० । 10, कलकत्ता	भ्र धिवक्ता	कलकसा	
16. एल. भहालिगणा	98/II 3 इदिरा नगर, मै सूर कर्नाट क	गश्चिष≄ता	मैसूर सिटी	
17. के . गरुवाचर	''युदर्शन सोमेश्वरपुरम, तुमकुर कर्नाटक	अधिव स्ता	जिला और गहर तुमकुर, कर्नाटक	
18. ब्रिलोक चन्द्र मिघल	दाल बाजार, भ्वालियर	प्र <u>धिव</u> क्ता	ग्र्बालियर, म.प्र.	
19. त्रिभुषन भ्रग्रवाल	पो . भ्रा . हनुमानगेद, टाउन जिला श्रीभंगानगर राजस्थान	ग्रधिवक्ता	संपूर्ण हनुमानगढ़, टाउन, राजस्थान	
20. जगराम सिह्	र्षाली कोठी स्टेशन रोङ, झुनझुनू, राजस्थान	ग्रधिब स्ता	जिला झुनझुनूं	
21. वी. एस. चंद्रासेखर	2694 स्रकाहारा स्ट्रीट हमन पोस्ट आफिस कर्नाटक-573201	प्लीङर	कर्नाटक का हसन शहर	
3.2. एस॰ एन० एम० मा० वेरिया	जबेरिया निवास नोबीवाडा उद्यपुर, राजस्थान	अभिजन শা	उद्यपुर, श जस्थान	

1 2	3	4	5	6
123 एम, सी, जैन	र्श्ना पाश्येनाथ जैन कालोन्। सुभाष बाग, प्रजमेर, राजस्थान	श्र धिय क्ता'	ग्रजसेर,राज ल्था ड्ड	
124. राम बाबू श्रीवास्तव	अधिवक्ता जेल रोड, सीतापुर, उ.प्र	प्र धिवस् ता	सीतापुर जिला	
12.5. के. बालक्रुष्ण	नं. 4 यर्ड कास रोड, फोर्थ ब्लाक के. पी. डब्ल्यू, एक्स., बगलौर-20	ग्रक्षिवयना	क्षगली र	
126. बू ज मोहन मिश्रा	1 5 सवर बाजार, आ सी, उ.प्र.	प्रधियभ ता	सा र्स(च.प्र.	
27. श्रीमती प्रेम लता निगम	29 4 भार्गम बिल्डिंग लोबार साग सीतापुर	श्रधिवक्ता	सोनापुर, उ.प्र.	
28. सुरजीत सिंह मेहता	181 विश्वकर्मा नगर, यमुना नगर जिला श्रम्बाला, हरियाणा	'प्रधिथन्ता	जग धा री	
29. चन्द्र कुमार मेहता	212-की माडल टाउन, यमुना नगर हरियाणां	प्रधित्र क्ता	यम्ना नगर	
30 जगर्दाण चन्द्र घोष	19, शरत बोस रोड (हर्क'मपाडा) सिर्लागुड़ी-434421 जिला दार्जिलिग पश्चिमी बंगाल	प्रधिवक्ना	नियाभुई। स्थित मुख्यालय सहित जिला दार्जिलिंग	 -
31. अमरेग्द्र नाथ जान	टैम्पल चैम्बर पहली मंजिल) 6, श्रील्ड पोस्ट श्राफिस स्ट्रीट, कलकत्ताः	म्रधियक्ता 1	कलकना	
2. सर्वेश्री राजा राम बसुराय	9 घोल्ड गोस्ट आफिस स्ट्रीट, कलकत्ता-1	श्रधियकोा ग्रीर सालिसिटर	पश्चिमी बंगाल राज्य	
33. विनोद फांत यमी	फानस . 13ए - 1, मयूर विहार विल्लो - 110091	श्रविवक्ता	विरुर्ला	
34. नंद लाल चौधरी	जें-4/15 राजोरो गार्डेन, नई विल्लो- 110027	अधियक्ता	दिल्ला संघ राज्य क्षेत्र	- -
35. देर्वेद्र नाय मिश्रा	328 गुरु रा मवास नगर (लक्ष्मी नगर) दिल्ली-92	प्रधिवस्ता	नई बिल्ली)	
36. मन मोहम सिंह सेठी	डो-83 अशोक विहार, नई विल्ली- 110052	भधिवक्ता	दिर्ल्ला मध राज्य क्षेत्र	
37 जगदीम लाल यन्ना	57 2 झील कुरंजा, विल्ली-110031	ग्र िव न्ता	दिव्यर्न।	
38. राजवीर सिह	बो∼5.5/ 3 मेन रोड, नार्थ घोंडा, विल्ली-5.3		णाहदरा स्थित मुख्यालय महित दिल्ली	
39. घीरेन्द्र एच . माह	पलैट नं. 10, चौथा मंजिल, अधिवक्ता मर्र ना हाजस, सामने लिबर्टी सिनेमा 5, सर बिहल वास थाकासी मार्ग, बंबई-20 कार्यालय: 33 घार. एस. सपरे मार्ग, (पिकेट रोड) नजदीक लघुबाद गायाल कलाबादेवी, बंबई-400002 .		धौर्व। तालाग्र प्रिसेम स्ट्रीट जानेरी बाजार क्राफो र्ड मार्केट एंड मेरीन लेन, ग्रम्बई णहर	
40. बी. एस. नरसिंहमन	मार्फत किंग एंड पैट्रीज एडकोकेट 26/ 1, लवेली रोड, बंगलीर-865551	भटनीं एट सीला	कर्नाटक राज्य	
4 1. एस . के . घोट्रटी	1, प्रकाश पलैट, 8 पहली मंजिल, बसन्त स्ट्रोट शांताक्ज़ (पश्चिमो), बंबई-400005	श्रीध् <u>रयक्ता</u>	साताकृजा एंड फोर्ट एरिया, ग्रेटर बंबई	
4 2. मर्फेन्द सी . गांधी	मार्फंत मर्कन्य गोधी एंड कं. एडवोकेट्र एंड सालिसिटर्स दूसरी मंजिल, भाग्योदय 79, एम मेडोज स्ट्रीट गीन- दास मास्टर रोड, फोर्ट, बंबई-23	र श्रधिवय ता	ग्रेटर वयई	-

MINISTRY OF LAW & JUSTICE

(Department of Legal Affairs)

New Delhi, the 14th January, 1985

S.O. 1471.—In pursuance of the provisions of Section 6 of the Notaties Act 1952 (53 of 1952), the Central Government hereby publishes a list of Notaries appointed by them and in practice at beginning of the year 1985.

SI. No.	Name of Notary	Residential and professional Addresses	Qualifications	Area in which he is authorised to practice	Remarks
1		3			<u> </u>
	S/Shri				
1.	Chakravarthi Doraswamy	M/s King and Patridge Catholic Centre (2nd floor) 6, Armanian Street Madras-1.	Advecate Madras High Court	Whole of India	-
2	Rustam Ardeshir Gagret	Gagrat & Co. Alli Chamber Nagindas Master Road Medows St. Fort Bombay.	Advocate Bombay	Whole of India	-
3.	Bhagwati Prasad Khaitan	1-B Old Post Office St., Calcutta	Attorney at Law Calcutta High Court	Whole of India	
4.	Rabindra Krishna Deb	Temple Chambers 6 Old Post Office St., Calcutta	Attorney at Law Calcutta High Court	Whole of India	
5.	Humansu Prakash Ganguli	4 Issur Dutt Lane, Howish (W. Bengal)	Advocate Calcutta High Court	Whole of India	******
6.	Sudhir Kumaı Dey Mullick	C/o Mertin Burn Ltd. 12, Mission Row Extension Calcutta-1.	Attorney at Law, Calcutta High Court	Whole of India	_
7.	Rash Mohan Chatterjee	C/o M/s Orr. Dignam and Co. Solicitots, 29, Netaji Subhas Road, Calcutta.	Solicitor Calcutta High Court	West Bengal, Assam, Bihar, UP & Punjab	
8.	Prabhudayal Himatsingka	6, Old Post Office St., Calcutta	Attorney at Law, Calcutta High Coutt	Whole of India	~-
9.	Punyabarata Bose	60, Old Post Office St. Calcutta-1.	Attorney at Law, Calcutta High Court	Whole of India	_
10.	Victor Elias Moses	6, Old Post Office St., Calcutta	Attorney at Law Calcutta High Court	Whole of India	
11.	Mulkli Raj Wadhawan	Advocate Jullundar City Punjab	Advocate Punjab High Court	Punjab & UP	-
12.	Manoharial Kapur	3/9 Patel Nagar (East) N. Delhi	Advocate	Union Territory of Delhi	_
	Harpershad Mehra	No. 3060 Charkhewalan Delhi.	Advocate Punjab High Court.	Union Territory of Delhi	-
14.	Chamanlal Arora	10-New Court Road, Amritsa,, Punjab	Advocate	Amritsar District Punjab	
15.	Damodar Devji Damodar	C/o M/s Kangs & Co. Solicitors Ready-Money Mensions 43 Vecr Nariman Road, Bombay	Solicitor	Maharashtra	-
16.	Deba Prasad Ghosh	C/o Fowler & Co. Solicitors & Advocates & Notaries Regent House 12 Govt, Place East Calcutta-69.	Attorney	Whole of India	
17.	Nathamal Himatsingka	6 Old Post Office St., Calcutta	Attorney	Whole of India	
18.	Ra <u>mk</u> ishan Garg	56 Old Vijay Nagar Colony Agra (UP)	Vakil Agıa	Agra Diett.	
	C.H. Pardiwala	C/o M/s Crawford Bay by & Co. State Bank Bldgs. Bank St., Bombay-1.	Solictor	Whole of India	_
20.	Sachindra C. Sen	Attorney at Law, Temple Chambers 1st Floor, 6 Old Post Office St., Calcutta.	Attorney	Calcutta	-
21.	D.A. Mehta	Advocate 43B Hanuman Road Road New Delhi	Barat Law	Union Territory of Delhi	

<u>—</u>			4	5	6
	S/Shri				
	Durga Prasad Tulsyan M.G. Doshit	Advocate Jhunjhunu Rajasthan M/s N.G. Doshit & Co., Solicitor 35-Embassy Market Ahmedabad.	Advocate Attorney	Jhunjhunu Distt, Rajasthan Gujarat and Maharashtra	
24.	Noor Mohammad	Advocate Udaipur Rajasthan	Advocate	Udaipur District (Rajasthan)	1
25.	Sudhir Kumar Seal	C/o M/s. Sander Sons & Morgans, Solicitors Royal Insurance Bldgs 5&7 Netaji Subhash Road, Calcutta-1.	Solicitor	Whole of India	-
26.	Jitendra Nath Sanyal	C/o M/s Sendersons Royal Insurance Bidgs. 5&7 Netaji Subhas Road Calcutta-1.	Solicitor	Whole of India	_
27.	Indersen Israni	Advocate J-54 Nawalc House Jaipur (Raj)	Advocate	Jaipur City & District	
28.	P.C. Kurian	14 Kondichatty Street, II Floor II Floor Madras-1.	Advocate	Madras & Kerala	_
	Gurdayal Singh Sidhoo	No. 1, Dokha Jullundur (Pb)	Advocate	Jullundur District	-
30.	C.I. Vonkatasubramanian	140 Cross Cut Road, Coimba- tore	Advocate	Coimbatore District.	
31.	Pushkar Lal Juneja	F-1, Sankar Market Connaught Circus, New Delhi	Advocate	Whele of India	_
32.	Chunilal Bhatia	C-4/A/68C Janakpuri New Delhi-58.	Advocate	Union Territory of Delhi	_
33,	Jegan Nath	Civil Line, Moga District Ferozepur (Punjab)	Advocate	Ferozepur Distt. with Headquarter at Moga also authorised to practise in and throughout Faridkot Distt. with Headquarters at Moga	
34.	Ramji Das Singhal	Gurdwara Street Bhatinda (Punjab)	Advocate	Bhatinda District	
35.	Bal Krishan	Advocate Hanumangarh Town District Ganganagar (Rajasthan)	Advocate	District Ganganagar with Headquarters at Hanumangarh (Rajasthan)	_
36.	S.R. Mehta	Advocate Balotra (Rajasthan)	Advocate	District of Barmer and Jalore with Headquatters at Balotra (Rajasthan)	
3 7 .	G.C. Verma	Advocate cum Oath Commissioner E/12, Green Park, New Delhi	Advocate cum Oath Commissioner	Union Territory of Delhi	_
38.	P.L. Gandhi	Advocate Opp. Gandhi Bagh, Surat.	Advocate	Surat District	_
39.	A.R. Malkani	Advocate BBZ-N-6 Gandhi Dham (Kutch)	Advocate	Whole of Gujarat	
40.	N.C. Shah	No. 1 Burdwan Rd. 1st Floor Alipore Calcutta-27	Advocate Calcutta	Calcutta & New Delhi	
41.	T. Dilip Singh	C/o M/s Kings & Patridge 2nd Floor Catholic Centre Armenian St. Box No. 121 Madras-1.	Advocate Madias	Whole of India	_
42.	J.R. Gagrat	C/o M/s Gagrat & Co Alli Chambers Negindas Master Rd., Fort, Bombay-i	Advocate Bombay	Whole of India	
43.	R. Setlur	Olympus Apartment Flat No. 308 Mrd Floor Attamount Rd, Bombay-26.	Attorney & Advecate Bombay	Whole of India	
4 4 ,	Brij Mohan Mehta	13A/2 Rajinder Nagar, New Delhi	Advocate, New Delhi	Union Territory of Delhi	_

1	2	3		5	6
	S/Shri		-		
45.	Surjit Singh Sood	23 Netaji Park Jullundur City (Punjab)	Advocate Jullunder	Jullunder Punjab	-
46.	Jagjit Singh Bains	376 L. Model Town Jullundur city (Punjab)	Advocate Jullundur	Jullundur Punjab	
47.	K.J. Khambata	Rajab Mahal, 144 Queens Rd. Bombay-20	Advecate Bombay	Whole of India	-
48.	Ambelal Bayb ai Patel	Vaidya St. PO. Navasari Distt. Bulsar (Gujarat)	Advocate	Gujarat	_
49.	Punamachan Somehand Shah	Gujarat Samachar Bhavan, II Floor Khanpur Ahmedabad.	Advocate	Gujarat	_
50.	B.T. Merchant	C/o M/s Thakordas & Madgavakar Fort Chambers Deen Lanc Fort, Bombay-1.	Attorney & Advocate	Whole of India	-
51.	H.M. Bhagat	C/o Ambhubhal & Diwanji Solicitors & Advocates Industries House, Ashram Rd Ahmedabad-9.	Advocate & Solicitors	Gujarat	_
52.	H.V. Chatrapati	C/o M/s. Bhai Shankar Kanga Girdhari Lal Manakji Wadia Building Bell Lane, Fort, Bombay-1 and C/o M/s Bhaishankar Kanga & Girdhari Lal, Gujarat Samachar Bhavan Khanpur, Ahmedabad.	Advocate & Soliciters	Whole of Gujarat	_
53.	G.S. Vyas	35, Lavanyanagar Jivaraj Park Rd. Ellis Bridge Ahmedabad.	Advocate	City of Ahmeda bad	
54.	Amar Singh	Jamiat Singh Rd Moga, Distt. Faridkot (Punjab)	Advocate	Moga Distt. Faridkot Punjab	_
55 1	B.H. Anita	C/o M/s Mulla & Mulla and Griaghe Plunt & Caroes, Solicitors & Notaries, Jehangii Wadie Buildings, 51, Mahatma Gandhi Rd., Bombay-1.	Attorney & Advocate	Whole of India	
56. 1	3 P. Shukia	Rugnath Building Town Hall Rajkot (Gujarat)	Advocate	Rajkot & Junagadh Distt.	_
57. E	B.K. Shah	Mansukh Niwas Nairi Chahipwad Baroda-6.	Advocate	Baroda	_
58. F	Ramesh J. Mch	Nadiad District Kaira Gujarat State	Advocate	Kaira Panchamahal District	_
59. V	/asantlal D. Mehta	C/o Malvi Ranched Das & Co. Solicitors & Advocate Ysuf Buildings Mahatma Gandhi Rd., Fort., Bombay-1.	Solicitor	M⊕harashtra	_
60. N	Aoiz F. Karamalawala	Church gate Chambers 5 New Marine lanes Room No. 611 6th Floor Bombay-20.	Solicitors	Whole of the State of Maharastra with HQ at Bombay.	_
61. I	Darshan Singh	A-321 Defence Colony New Delhi.	Advocate	Union Territory of Delhi	_
52. N	īrs. K.V. Desai	5 Bharat Colony Near Sardar Patel Colony, Ahmedabad-14.	Advocate	Ahmeda bad	
<i>(</i> 2)	Iohinder Singh	277 Saidan Gate, Jullundur	Pleader	Jullunder	_

1			3	4	5	6
	S/Shri					·
61.	Rajendra Kun	ıar Bhatt	S-401 Greater Kailash, New Delhi-48	Advocate	Union Territory of Delhi UP & Haryana	
65.	Narain Prasad	Goyal	E-165 Naraina Vihat N. Delhi-	20 Advocate	Union Territory of Delhi	
66.	K.V. Thomas		Vnajpet Goorg Distt. Karnataka	Advocate	Goorg Distt.	-
67.	H. Hassan Koy	a.	Chalaypuram Calicut Kerala	Advocate	Calicutt & Malappurum Distt.	-
68.	Salil Kumar Ge	ınguli	50 Ramtanu Bose Lane Calcutta-6	Attorney at Law & Advocate	Calcutta	<u>-</u> ·
69.	Palav Kumar B	anerjee	M/s T. Bancrjee & Co. Solicitors & Advocates Temple Chamber' No. 6 Old Post Office St., Calcutta	Solicitor & Advocate	Calcutta	-
70.	M.Y.S. Menon		M/s Majumdar & Co. Ismail Building 381 Dr. D.N. Rd., (Flora Fountain) Bombay.	Solicitor & Advocate	Greater Bembay	mparing.
71.]	Brij Bhushan G	ıpta	Kalal Maju Ambala City	Advocate	Ambala City	_
	Raghubir Singh		Chirwa Tehsil Rajasthan	Advocate	Chirwa Tehsil	
	Salematri Gurbo		202 Kanwat Ngr. Rajamal-ka- Talab, Jaipur	Advocate	Jaipur	
	Nand Kishore I		321 Nahargarh Rd., Gopal Halwaiki Gali, Jaipur	Advocate	Jaipur	
75. 2	Akbileshwar Da	s Badgal	Sharma Restaurent Johari Bazar Jaipm-302003	Advocate	Jaipur	
7 6. 1	D.R. Zajiwalia		M/s D.R. Zailwalla & Co. Solicitors Reedymoney Mansion 43 Veer Nariman Road, Fort, Bombay	Solicitor & Advocate	Greater Bembay	
77. A	Anthony Da Co	sta	M/s Da Costa & Da Costa Advocates & Tax Consultants, 21/12 Mahatma Gandhi Road, 1st Floor Bangalorc-1.	Advocate	Whole of India	
	Mrs. Sumati Are Patil	wind	236 Jain Temple Road, Gomeshnagar Hindwadi, Belgaum Karnataka	Advocate	Belgaum Distt.	
7 9. 7	Γ.M. Sen		M/s Khaitan & Co. Solicitors & Advocates Himalaya House 7th floor, 23 Kasturba Gandhi Marg, New Delhi.	Attorney at Law	Whole of India	~-
80. 1	Mrs. N. Anasoo	ya Bai	4624/1 Shivaji Rd. N.R. Mohalla Mysore-7.	Advoçate	Mysore City	
81. P	admanath Gan Jokhale	gadhar	A-36 Defence Colony, New Delhi	Advocate	Whole of India	-
	am Naresh Lal	Gupta	'Bihari Dham' C-28/70 Teliya Bugh, Varanasi Cantt., UP.	Advocate	Varanasi U.P.	_
33. S P	amoon Asgaral oonawala	i	12-Ismail Bldg 381—Br. Dadabhoy Naroji Rd., Fort Bombay-1.	Advocate	State of Maharashtra	•
34. A	wadesh Kumar	Verma	C/o Sh. Raghoram Veima Advocate Civil Court Vaianasi UP.	Advocate	Varanasi Distt. of UP	
35. G	lulam Tahir		D-50/29 Qazipura Kalan Varanasi UP.	Advocate	Varanasi Distt. of UP.	•
36. K	Ishori Lal Kapo	oor	516 Church Gate Chambers 5th Floor 5-New Marine Lanes Bombay-20	Advocate	State of Maharashtra	

	1 2	3	4	5	6
	S/Shri				<u> </u>
87.	T.K. Shanmuganandum	8/8 Huzur Rd. Coimbatore- 641018.	Advecate	Coimbatore	•
88.	Rajendra Kumar Ray	37, South Kumar Para Lane Calcutta-42.	Advocate	Calcutta & 24 Parganas	_
89.	Raghubir Sahai Hitkari	Civil Courts, Kanpur	Advocate	Kanpur & Delhi	
90.	Om Prakash Jain	A-5-B/126-B Janakpuri New Delhi-110058	Advocate	Delhi	→
91.	Bimal Kumar Bancrjee	3 Bankshall St. Calcutta- 700001	Advocate	Calcutta 24 Parganas	-
92.	Padamsi Danji Khona	45, Tamarind St. Fort, Bombay-23.	Advocate	Greater Bombay	
93.	G.A. Banatwala	C/o Payne & Co. Esplanade House Woudeby Rd. Fort Bombay-400001.	Advocate	Whole of India	_
94.	Leo Benedict Velho	Costa Pereira Building al Floor Margoa Salecte, Goa	Advocate	Whole of Gca	_
95.	Miss Jeswant Kaur	H-21, Kailash Colony, New Delhi.	Advocate	Union Territory of Delhi	-
96.	Eruch Jalagur Balsara	M/s Payane & Co Esplanade House Woudey Rd. Fort, Bombay-1.	Advocate	Whole of India	_
97.	Bertram D Silva Shenoi	92, "Satman" Cuffe Parade Bombay-400005.	Advecate	Whole of State Maharashtra	_
	Rameshwar Dayal Gupta	88, C. Shastri Nagar Jodhpur	Advecate	Jodhur District	···-
	Dhul Chand	Muktsar District Faridkot Punjab	Advocate	Únion Territory of Chandigarh	
	Ram Rattan Lekh	ES-553, Mobila Awedoura Jullundur City	Advocate	Jullundur City	
101.	M.I. Sethna	Fazalbhoy Bidg. 2nd Floor 45/57, N.G. Road, Fort Bombay-1	Advocate	Walkeshwar and Fort arcas of Bombay	
102.	Durga Shankar Dave	Oswalwara Rajasthan Banswara-327001.	Advocate	Banswara District Rajasthan	_
103.	Murlidhar Rao Naik	Maktanpura Gulbarga Karnataka	Advocate	District and City of Gulbarga	-
	Bhagwati Prasad Bhatt	11-Gyan Marg Udaipur Rajasthan	Advocate	Udaipur	_
	Janklai Agarwal	9 Balenville Road Darjeeling, Darjeeling	Advocate	Darjeeling	-
106.	K.C. Sidhwa	Branch Secretariat, Bombay Aayakar Bhavan Annexe New Marine Lines Bombay- 400020.	Central Govt. Advecate Advecate Solicitor	Whele of India	_
	Suraj Kr. Bhaskar	Khetri Distt Jhujhunu Rajasthan	Advocate	Khetri Rajasthan	-
	Devi Saran Chopra	B-3, Two Roses Pali Road, Bombay	Advocate	City of Bombay	_
	Debabrata Basu	7 Devanarain Das lane, Shyam Bazar, Calcutta	Advocate	24 Parganas with Head Quarters at Scaldah	-
	Miss Manjula Sen	33, Venus Cuffe Parade Bombay.	Advocate & Solicitor	Whole of India	_
	A Syed Ali	53 Armenian St. Madras	Advocte	State of Madras	_
	G.C. Verma	Civil Courts Jagadhri Distt. Ambala Haryana.	Advocate	Jagadhri	
	Gajendra Nath Chakraborty	9 Old Post Office St. Calcutta, Bombay.	Advocate	Calcutta-1	-
	Aditikumar Pramarick	10 Old Post Office St R No 110 Calcutta	Advocate	State of West Bengal	
115	Indra Chand Sanecheh	12 Old Post Office St. R No 110 Calcutta	Advccate	Calcutta	

1 2	3	4		6
S/Sht i				
116. L. Mahalingappa	938/II Indira Nagar Mysore Karnataka	Advocate	Mysore City	_
117. K. Garudachar	'Sudershana' Someshwarapuram Tumkur Karnataka	Advocate	Distt. & City of Tumkur Karnataka	
118. Trilokchand Singhal	Dal Bazar Gwalior	Advocate	Gwalior (M.P.)	
119. Tribhuwan Agarwal	PO Hanumangarh Town Distt. Sriganganagar Rajasthan	Advocate	Throughout the Town of Hanuman garh Rajasthan	
120. Jagram Singh	Pili Kothi Station Rd. Jhunjhunu Rajasthan	Advocate	Distt Jhunjhunu	-
121. B.S. Chandra Sekhar	2694 Agrahara St. Hassan Post Office Karnataka 573201	Pleader	Hassan City of Karnataka	
122. SNSC Javeria	Javaria Niwas Mochiwara Udaipur Rajasthan	Advocate	Udaipur Rajasthan	-
123. M.C. Jain	Sh. Parshwanath Jain Colony Subhas Bhagh Ajmer (Rajasthan)	Advocate	Ajmer Rajasthan	~
124. Ram Babu Srivastava	Advocate Jail Road Sitapur UP	Advocate	Sitapur District	
125. K. Balakrishna	No. 4 3rd Cross Road 4th Block KPW Extn, Bangalore-20	Advocate	Bangalore	
126. Brij Mohan Misra	15 Sadar Bazar Jhansi (UP)	Advocate	Jhansi (UP)	
127. Smt. Prem Lata Nigam	294 Bhargava Bldg. Lobar Bagh Sitapur.	Advocate	Sitapur (UP)	-
128. Surjit Singh Mehta	181 Vishwakarma Nagar Yamunanagar Distt, Ambala (Haryana)	Advocate	Jagadhari	
129. Chander Kumar Mehta	212-D Model Town Yamunanagar (Haryana)	Advocate	Yamunanagar	
130. Jagdish Chandra Ghosh	19 Sarat Bose Rd. (Hakimpara) Siliguri-734401 Distt. Darjeeling West Bengal.	Advocate	Distt. Darjeeling with his Headquarters at Siliguri	-
131. Amarendra Nath Dawn	Temple Chamber (First Floor) 6 Old Post Office St. Calcutta-1.	Advocate	Calcutta	_
132. Raja Ram Basu Ray	9 Old Post Office St. Calcutta-1.	Advocate & Solicitor	State of West Bengal	_
133. Vinod Kant Verma	H. No. 13-A/I Mayur Vihar Delhi-110091.	Advocate	Delhi	
134. Nandlal Choudhury	J-4/15 Rajouri Garden N. Delhi,	Advocate	UT of Delhi	_
135. Devendra Nath Mishra	328 Guru Ramdas Nagar (Laxmi Nagar) Delhi-92	Advocate	New Delhi	_
136. Man Mohan Singh Sethi	D-83 Ashok Vihar I New Delhi-110052	Advocate	UT of Delhi	_
137. Jagdish Lal Batra	572 Jheel Kuranja Delhi-110031	Advocate	Delhi	
138. Rajvir Singh	D-55/3 Main Road North Ghonda Delhi-53.	Advocate	Delhi with HO at Shahdara	_
139. Dhìrendra H. Shah	Flat No. 16 4th Floor Marina House Opp. Liberty Cinema 5 Sir Vithaldas Thakersey Marg Bombay-20 Off: 33R.S. Sapre Marg (Picket Rd) Near Small Cause Court Kalbadevi Bombay-400002	Advocate	Dhobi Talao Princos St. Zaveer Bazar Crawford Market and Marino Lines of Bombay City	

1 2		4	5	6
S/Shri				
140 B.S. Narasimhan	C/o King & Patridge Advocate 26/1 Lavelle Rd. Bangalore-560001	Attorney at Law	State of Karnataka	-
141. S.K. Shetty	l Prakash Flat; 8 First Floor Besant St. Santacruz (West) Bombay-400054.	Advocate	Santacruz & Fort areas of Greater Bombay	
142. Markand C. Gandhi	C/o Markand Gandhi & Co. Advocates & Solicitors 2nd Flr. Bhaggadaya 79 Medows St. Nagindas Master Rd. Fort Bombay-23.	Advocate	Greater Bombay	
			[No. 5(3)/	8 5-J udl.]

S. GOOPTU, Competent Authority

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 28 मार्च, 1985

का, आ. 1472 :--केन्द्रीय सरकार, सरकारी स्थान (अप्राधि त अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम , 1971 (1971 का 49) की धारा 3 हारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग क्षरते हुए, श्री एम. सी. वर्मा सहायक निदेशक, आसूचना ब्यूरो, नई दिल्ली को जो सरकार के राजपितत अधिकारी है, श्री जी. डी. केवलानी के स्थान पर, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए संपदा अधिकारी नियुक्त करती है और निदेश देती है जि उन्त अधि ारी 1-2-1985 को और संनिदेशक, आसूचना ब्यूरो, नई दिल्ली के नियंत्रणा-धीन सभी सरकारी वास सुविधा के संबंध में, उक्त अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन संपदा अधिकारी को प्रदत्त मक्तियों का प्रयोग करेगा ऑर अधिरोपित धर्तव्यों का पालन करेगा।

> [सं. 1/सी-II/83-(बी)-1(3)/एफ. पी.-5] वो. के. जैन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS New Delhi, the 28th March, 1985

S.O. 1472.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby appoints Shri M. C. Verma, Assistant Director, Intelligence Bureau, New Delhi, a Gazetted Office of the Government to be the Estate Officer vice Shri G. D. Kewlani for the purposes of the said Act and directs that the said officer shall exercise the powers conferred, and perform the duties imposed on the Estate Officer by or under the said Act, in respect of all Government accommodation under the control of the Director, Intelligence Bureau at New Delhi on and from 1st February, 1985.

> [No. 1/CII/83(B)-1(3)|FP V.] V. K. JAIN, Jt. Secy.

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) नई दिल्ली, 23 भार्च, 1985 आदेश

का. आ. 1473 -- केन्द्रीय सरकार, विल्ली पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 (1946 का 25) की 6 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा णिक्सयों का प्रयोग करते हुए, उड़ीसा सरकार की सहमति से भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 380 और 457 के अधीन अपराधों के और उक्त अपराधों के संबंध में या उनसे संबंधित प्रयत्नों, दूष्प्रेरणों और षड्यंत्रों के तथा 24/25 सितम्बर, 1984 की रात में उड़ीसा के सम्बलपुर जिला में एक मंदिर से भगवान नरसिह नाथ की प्रस्तर मृति की चोरी की बाबत पुलिस थाना पंकमाल, जिला सम्बलपुर में रजिस्ट्रीकृत प्रथम इतिला रिपोर्ट सं. 37, तारीख 25 सितम्बर, 1984 के संबंध में वैसे ही संव्यवहार के अनुऋमण में किए गए किन्हीं अन्य अपराधों के अन्वेषण के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का विस्तारण सम्पूर्ण उड़ीसा राज्य पर करती है ।

[संख्या 228/1/85-ए. वी. ही. (II)]

MINISTRY OF PERSONNEL & TRAINING, ADMN. REFORMS & PUBLIC GRIEVANCES & PENSION

(Department of Personnel and Training) New Delhi, the 23rd March, 1985

ORDER

S.O. 1473.—In exercise of the powers conferred by subsection (1) of section 5 read with section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946) the Central Government with the consent of the Government of Orissa, hereby extends the powers and jurisdiction of members of Delhi Special Police Establishment to the whole

of the State of Orissa for, the investigation of offences under sections 380 and 457 of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860), and attempts, abetments and conspiracies in relation to or in connection with the said offences and any other offences committed in the course of same transaction in regard to case FIR No. 37 dated the 25th September, 1984 registered at Police Station Paikmal, Dist. Sambalpur in regard to theft of stone idol of Lord Narasingh Nath from a temple in Sambalpur Dist. of Orissa in the right of 24/25th September, 1984.

[No. 228/1/85-AVD 1']

नई दिल्ली, 26 मार्च, 1985

का. आ. 1474.—केन्द्रीय सरकार, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 (1946 का 25) की धारा 6 के साथ पठिन धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त मिक्तयों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र सरकार की सहमति में भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 292 के अधीन दण्डनीय अपराधों के और उक्त अपराध के मंबंध में या उनमें मंबंधित प्रयत्नों, दुष्प्रेरणों और षड्यंत्रों के तथा उन्हीं तथ्यों से उद्भूत वैसे ही संध्यवहार के अनुक्रम में किए गए किसी अन्य अपराध के अन्वेषण के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन के सदस्यों की शिक्तयों और अधिकारिता का विस्तारण सम्पूर्ण महाराष्ट्र राज्य पर करती है।

[संख्या 228/8/85-ए. वी. डी. (II)] एम. एस. प्रसाद, अवर सचिव

New Delhi, the 26th March, 1985

S.O. 1474.—In exercise of the powers conferred by sub-Section (1) of section 5 read with section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946), the Central Government with the consent of the Government of Maharashtra, hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment to the whole of the State of Maharashtra, for the investigation of offence punishable under section 292 of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860) and attempts, abetments and conspiracies in relation to or in connection with the said offence and any other offence committed in the course of same transaction arising out of same facts.

[No. 228/8/85-AVD. II]

M. S. PRASAD, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 1985

आयकर

का. आ. 1475.— आयकर अधिनयम 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खण्ड (44) के उपखण्ड (III) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एनदृहारा सर्वश्री ओम प्रकाण और बलवीर कुमार को, जो केन्द्रीय सरकार के राजपितत अधिकारी हैं, उकन अधिनियम के अन्तर्गत कर कमूली अधिकारी की णिवनयों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है।

2. यह अधिसूचना सर्वश्री ओम प्रशाण और बलबीर कुमार द्वारा कर वसूली अधिशारी के रूप में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख अर्थात् 11-2-1985 में लागू होगी।

[सं. 6156/फा. सं. 398/44/84-आ. नः. ब.]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 16th February, 1985

INCOME-TAX

S.O. 1475.—In pursuance of sub-clause (iji) of clause (44) of section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby authorises S/Shri Om Piakash and Balbir Kumar being gazetted officers of the Central Government to exercise the powers of a Tax Recovery Officer under the said Act.

2. This Notification shall come into force with effect from 11-2-1985 when S/Shri Om Prakash and Balbir Kumar took over charge as Tax Recovery Officer.

[No. 6156/F. No. 398/44/84-IT(B)]

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 1985

का. आ. 1476—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 ला 43) की धारा 2 के खण्ड (44) के उप-खण्ड (iii) के अनुसरण में और भारत सरकार के राजस्व भिभाग की दिनांक 14-12-1982 की अधिसूचना मं. 5013/फा. मं. 398/32/82-आ. क. (ब.) का अधिलंघन करते हुए, केन्द्रीय सरकार एनवद्वारा श्री सी. एम. अग्रवाल को, जो केन्द्रीय सरकार के राजपित्तन अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के अंतर्गत कर वसूली अधिकारी की प्रक्तियों जा प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है।

2. यह अधिसूचना, श्री सी. एम. अग्रवाल द्वारा कर वसूली अधि .गरी के रूप में कार्यभार ग्रहण किए जाने की नारीख से लागू होगी।

[सं. 6163/फा. सं. 398/3/85-आ . क. (ब)

New Delhi, the 27th February, 1985

S.O. 1476.—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (44) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), and in supersession of Notification of Government of India in the Department of Revenue No. 5013 [F. No. 398]32|82-IT(B)] dated the 14-12-82, the Central Government hereby authorises Shri C. M. Agrawal, being a Gazetted Officer of the Central Government, to exercise the powers of a Tax Recovery Officer under the said Act.

2. This Notification shall come into force with effect from the date Shri C. M. Agarwal takes over charge as Tax Recovery Officer.

[No. 6163/F. No. 398/3/85-IT(B)]

नई दिल्ली, 8 मार्च, 1985

का. आ. 1477.— आयक्त अधिनियम, 1961 (1961 जा 43) की धारा 2 के खण्ड (44) के उपखण्ड (iii) के अनुसरण में और भारन सरकार के राजस्व विभाग की दिनांक 31-12-1982 की अधिसूचना सं. 5043 तथा 5047 [फा. सं. 398/38/82-आ. क. (ब.)] आ अधिलंघन करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा ऋमणः श्री के. एल. भाटिया-II और श्री एम. के. किरपाल को, जो केन्द्रीय सरकार के राजपन्नित अधिकारी हैं, उकत अधिनियम के अंतर्गत कर वसूली अधिकारी की शिक्तयों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है।

2. यह अधिसूचना, श्री के. एल. भाटिया II और श्री एस. के. जिरणाल द्वारा कर बसूली अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किए जाने की तारीख से लागू होगी।

[सं. 6168 (फा. मं. 398/4/85-आ. क. (ब.)] बी. ई. अलैक्जैंडर, अथर मचिव

New Delhi, the 8th March, 1985

S.O. 1477.—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (44) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), and in supersession of Notifications of the Government of India in the Department of Revenue No. 5043 and 5047 [F. No. 398/38/12-IT(B)] dated the 31-12-1982, the Central Government hefeby authorises S/Shri K. L. Bhatia-II and S. K. Kirpal, respectively, being a Gazetted Officers of the Central Government, to exercise the powers of a Tax Recovery Officer under the said Act.

2. This Notification shall come into force with effect from the dates S/Shri K. L. Bhatia-II and S. K. Kirpal take over charge as Tax Recovery Officer.

[No. 6168/F. No. 398/4/85-IT(B)]B. E. ALEXANDER, Under Secy.

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 1985 (आय-कर)

का. आ. 1478—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की घारा 80छ की उप-घारा (2)(ख) द्वारा प्रदत्त मिनतयों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, उक्त धारा के प्रयोजनार्थ, "श्री अरूलिमगु कुमारकुट्टम सूबद्धण्यस्वामी कोइल राजागोपुरम निर्माण, कांचीपुरम" को संपूर्ण दक्षिण भारत में विख्यात् मार्वजनिक पुजा-स्थल के हुए में अधिस्चित करती है।

[संख्या 6162/फा. मं. 176/10/85-आ. का. (नि.-1)] पी. सक्येना, उप सचिव

New Delhi, the 26th February, 1985

(INCOME-TAX)

S.O. 1478.—In exercise of the powers conferred by subsection (2)(b) of Section 80-G of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Sri Arulmigu Kumarakottam Subramaniaswamy Koil Rajagopuram Nirmana, Kancheepuram" to be a place of public worship of renown throughout South India".

[No. 6162/F. N. 176/!0/85-IT(A1)] P. SAXENA; Dy. Secy.

नई दिल्ली, 8 मार्च, 1985 प्रधान कार्यालय संस्थापन

का. आ. 1479.—केन्द्रीय राजस्व वोर्ड अधिनियम 1963 (1963 का संख्यांक 54) की धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदश्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क) के अधिकारी श्री एम. वी. एन. राव को, जो पिछले दिनों राजस्व विभाग में अपर सचिव

(तस्करी रोधी) के रूप में नैनात थे, 6 दिसम्बर 1984 के पूर्वा हुने तक केन्द्रीय उत्पादन शुरुक तथा सीमा शुरुक बोर्ड का सदस्य नियुक्त करती है।

[फा. सं. ए. 11015/5/84-प्रसा. I]

New Delhi, the 8th March, 1985

HEADQUARTERS ESTABLISHMENT

S.O. 1479.—In exercise of the powers conferred by subsection (2) of Section 3 of the Central Boards of Revenue Act, 1963 (No. 54 of 1963), the Central Government hereby appoint Shri M. V. N. Rao, on officer of the Indian Revenue Service (Customs & Central Excise), and formerly posted as Additional Secretary (Anti-Smuggling) in the Department of Revenue, as Member of the Central Board of Excise & Customs with effect from the forenoon of the 6th December, 1984 and until further orders.

[F. No. A-11015/5/84-Ad. I]

मई दिल्ली, 21 मार्च, 1985

प्रधान कार्यालय संस्थापन

का. आ. 1480-- केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 (1963 का संख्यांक 54) की धारा 3 की उप-धारा (2) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्बारा भारतीय राजस्व सेवा (आयकर) के अधि-कारी श्री एस. बिवेदी को, जो पिछले दिनों मुख्य आयुक्त (प्रशा.) तथा आयकर आयुक्त, दिल्ली-1 के रूप में सैनात थे, 11 मार्च 1985 की पूर्वाह्न से केन्द्रीय प्रस्थक्ष कर बोर्ड का सदस्य नियुक्त करती है।

> [फा. सं. ए-19011/1/85-प्रशा.]] जे. एम. लेहन, अवर सचिव

New Delhi, the 21st March, 1985 HEADQUARTERS ESTABLISHMENT

S.O. 1480.—In exercise of the powers conferred by subsection (2) of Section 3 of the Central Boards of Revenue Act, 1963 (No. 54 of 1963), the Central Government hereby appoints Shri S. Dwivedi, an officer of the Indian Revenue, Service (Income-tax) & formerly posted as Chief Commissioner (Admn.) & Commissioner of Income-tax, Delhi-I, as Member of the Central Board of Direct Taxes with effect from the forenoon of the 11th March, 1985.

[F. No. 19011/1/85-Ad. I] J. M. TREHAN, Under Secy.

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 29 मार्च, 1985

श्रादेश

स्टाम्प

का.श्रा 1481.—भारतीय स्टाम्प श्रिधिनियम, 1899 (1899 का 2) की घारा 9 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त सिन्तयों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा मैसर्स हिन्दुस्तान फेरोड़ो लि० को केबल एक लाख चौयन हजार पांच सो सड़सठ रुपये पचास पैसे के उस समेकित स्टाम्प शुक्क की श्रदायगी

गरनं को अनुसान देनो है जो मैसमें हिन्दुस्तान फेरोड़ी लि. इ.र. जारी किए जाने वाले को करोड़ छः लाख नौ हजार गपये के झांकित मूल्य के क सं. 000001 से 206090 तक के ऋणपत्नों के रूप में बन्धपत्नों पर स्टाम्प शुरुक के कारण प्रभाग है।

> [सं. 13/85-स्टाम्प/फा. सं० 33/69/84-बि०क्॰] भगवान दास, भ्रवर सचिव

(Department of Revenue)
New Delhi, the 29th March, 1985

ORDER

STAMPS

S.O.1481.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby permits M/s. Hindustan Ferodo Ltd., to pay consolidated stamp duty of rupees one lakh fifty-four thousand five hunderd sixty-seven and paise fifty only chargeable on account of the stamp duty on bonds in the form of debentures bearing Serial Nos. 000001 to 206090 to be issued by M/s. Hindustan Ferodo Ltd. of the face value of rupees two crores six lakhs nine thousands only.

[No. 13]85-Stamps[F. No. 33]69]84-ST] BHAGWAN DAS, Under Secy.

(श्राधिक कार्यविभाग) (वैंकिंग प्रभाग)

नई (दल्ली, 30 मार्च, 1985

का. आ 1482. - - राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध ग्रीर प्रकीण) उपबंध स्कीम, 1970 के खण्ड 9 द्वारा प्रदत्त मिक्तयों का प्रयोग करते हुए शरत सरकार निदेश देती है कि शरत सरकार, वित्त मंत्रालय, ग्राधिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग) की दिनांक 2 भ्रप्रैल, 1982 के का० ग्रा. संख्या 1522 (संख्या एफ. 9/36/81-बी. भ्रो. 1) के तहन जारी की गयी प्रधिस्चना के अनुसार इंडियन बैंक में निदेशक के रूप में नियुक्त किये गए निम्नलिखित व्यक्ति 3 ग्रप्रैल, 1985 में निदेशक नहीं रहेगें, ग्रथींग् :--

- श्री टी.एम. कलियाणन, चामुंडी हाउस, सी.एच. बी. कालोनी, वेलूर रोष्ट्र, निरुचेंगोडू, जिला सेलम (तिमलनाड्)
- 2. श्री ए. पोसूदुरे,
 भूतपूर्व अध्यक्ष,
 कलरायण लेम्प सोसाइटी,
 मणियारन कृणरम डाक घर,
 करमनदुराई (वाया) चिन्नाकलरायण हिल्स,
 असूर तालूक, जिला मेलम (तिमलनाडु)
 1796 GI/84—3

- श्र्वा सत्यानरैण नाथा नाथा मूर्ति म्यूजियम, मृति मोहल्ला, खजाने वालों का रास्ता, जयपुर (राजस्थान)
- 4. श्री ग्रार. के० गोयल, चार्टर्ड एकाऊटेट, राजेन्द्र के. गोयल एण्ड कम्पनी, ई-2/16, ग्रंसारी रोड़, परियागंज, नई दिल्ली-110002
 - श्री निरन्द्र नाथ नंदा,
 प्रोपराईटर, वी.के. इंडस्ट्रीज,
 25-ए, श्रीद्योगिक क्षेत्र, ग्वालियार (मध्य प्रदेश)
 - श्रीमती लीला प्रामादर मेनन, नौका, याजाद रोड, कालुर, कोचीन-682017 (केरल)
 - 7. श्री पी वी. रंगा राव, हाउस न. 6-4-110, ब्राह्मण वाड़ी, हनामकोंड़ा, जिला वारंगल (ग्रान्ध्र प्रदेण)
 - 8. श्री वी सी मारकार, मामाजिक कार्यकर्ता, वेल्लाकाल हाऊस, इडापल्ली, कोषीन-682024 (केरल)

[सं. एफ० 9/2/82-85-बी०ग्ना०-1] एस० एस० हसूरकर, निदेशक

(Department of Economic Affairs)
(Banking Division)

New Delhi, the 30th March, 1985

S.O. 1482.—In exercise of the powers conferred by clause 9 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaueous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government is pleased to direct that the following persons appointed as Directors of the Indian Bank under notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Banking Division) S.O. No. 1522 (No. F. 9/36/81-B.O. I) dated 2nd April, 1982 shall cease to hold the office of Director with effect from 3rd April, 1985 namely:—

- Shri T. M. Kaliyannan, Chamundi House, C.H.B. Colony, Velur Road, Tiruchengodu-637211, Salem District (Tamil Nadu).
- Shri A. Poonudurai, Ex-President, Kalrayan Lamp Society, Maniyaran Kunram P.O. Karumandurai (Via) Chinnakarlrayan Hills, Attur Taluk, Salem District, (Tamil Nadu).

- Shri Satya Narain Natha, Natha Moorti Museum, Moorti Mohalla, Khazanewalon-Ka-Rasta, Jaipur (Rajasthan).
- Shri R. K. Goel, Chartered Accountant, Rajendra K. Goel & Co, E-2/16 Ansari Road, Darya Ganj, New Delhi-110002.
- Shri Narınder Nath Nanda, Proprietor,
 K. Industries,
 A, Industrial Area Gwallor (Madhya Pradesh),
- Smt. Leela Damodara Menon, 'Nauka' Azad Road, Kaloor, Cochin-682017. (Kerala).
- 7. Shri P. V. Ranga Rao, House No. 6-4-110, Brahman Wadi, Hanamkonda, District Warangal, (Andhra Pradesh).
- Shri V. P. Marakkar, Social Worker, Vellakkal House, Edappally. Cochin-682024, (Kerala).

[No. F. 9/2]85-BO. I] S. S. HASURKAR, Director.

नई दिल्ली, 30 मार्च, 1985

का. आ. 1483.—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रवस शक्तियों का प्रयोग करने हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्य बैंक की सिक रिश पर एतद्द्वारा घोषणा करती है, कि उक्त श्रांधनियम, की धारा 10-ए की उपधारा (1) और (2) के उपबंध गणेश बैंक शाफ कुक्इबाड़ लि॰, कुक्इंड वाड़ पर 19 मार्च, 1985 से 18 जून, 1985 तक की तीन महाने की अवधि के बास्ते या जब तक उस बैंक के लिए नियमित रूप से पूर्णकालिक शब्यक्ष तथा मुख्य नार्थेपालक अधिकारी की नियुक्ति नहीं हो जाती, इन दो में भे जी भो पहले हो लाग नहीं होगें।

[संख्या 15/25/84-ची. ओ. III] एम० के० एम० कुड़ि, श्रवर सचिव

New Delhi, the 30th March, 1985

S.O. 1483.—In exercise of the powers conferred by section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendations of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of sub-sections (1) and (2) of Section 10-B of the said Act, shall not apply to the Ganesh Bank of Kurundwad Ltd., Kurundwad, for a further period of three months from 19th March, 1985 to 18 June, 1985 or till the appointment of a regular wholetime Chairman and Chief Executive Officer for that bank, whichever is earlier.

[No. 15/25/84-B.O.III] M. K. M. KUTTY, Under Secy.

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, 28 मार्च, 1985

मृद्धि-पत

रा. श्रा 1484 — बांडें के बिनास 24/1/85 की शिध-सूचना संख्या 316/74/83 धन कर, जो दिनाम 25/1/85 के श्रमाधारण राजपन्न के भाग-2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित हुआ, की कम संख्या 11-क के सामने स्तम्भ 3 की मद संख्या (ii) में विद्यमान प्रतिष्टियों के स्थान पर निम्नलिखिन प्रतिस्थापित किया जाए :--

> ''तिमिलनाडु के चिगलपुर, दक्षिण प्रकटि, तंत्रावर, नोर्लागिर, कायम्बतूर श्रौर पेरीयार के राजस्व जिले।''

> > [सं. 316/74/83-धनकर] ए. के. फोतेचार,धवर सचिव केल्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES New Delbi, the 28th March, 1985

CORRIGENDUM

S.O. 1484.—For the existing entries in item No. (ii) of column No. 3 against S. No. 11A of the Board's Notification F. No. 316/74/83-W.T. dated 24-1-85, which was published in Part II, Section 3, Sub-section (ii) of Extra ordinary Gazette dated 25th January, 1985, the following may be substituted:—

"and the revenue districts of Chinglepet, South Arcot, Thanjavur, Nilgiris, Coimbatore, and Periyar of Tamil Nadu."

[F. No. 316/74/83-W.T.]
A. K. FOTEDAR, Under Secy.
Central Board of Direct Taxes

वाणिज्य एवं पूर्ति मंत्रालय (मुख्य नियंबक, स्राथन-नियति का कार्यालय)

ऋदिश

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 1985

का. ग्रा 1485.— मैंसर्स कृष्णा एंड के., गोयंका हाउस 44, कम्यूनिटी सेंटर, जमरुदपुर, कैसाश कालोनी एक्सटेंशन, नई (दल्ली-110048 को 1982-83 की श्रवधि के लिए मशीनिरी/उपस्करों के फालतू पुर्जों के आयात के लिए केवल 66,69,832 रु. का एक आयात लाइमेंन सं. पी/ एक/2030153/सीएकन एक्स/85/एच/82, दिनांक 13-11-82 दिया गया था।

्र अब फर्म ने उपर्युक्त लाइसेंस की मुद्र। विनिमय प्रयोजन प्रति की अनुलिपि प्रति जारी करने के लिए इस आधार पर अनुरोध किया है कि मूल मुद्रा-विनिमय प्रयोजन प्रति, नई दिल्ली के सीमाणुलक प्राधिकारी के पास पंजीकृत कराने के पण्चात और औंशिक रूप से उपयोग में लाने के बाद खाँ गई है और बंक द्वारा केवल दस्तावेजीय प्रयाजन के लिए 22,90,000/- रुपए के भेंप सूल्य का पूरा करने के लिए अनुलिपि प्रति की आवश्यकता है। फर्म इससे सहमत है और बचन देती है कि यदि लाइसेंप की गूल मुद्र-विनियम प्रयोजन प्रति बाद में मिल गई तो उसे रिकाई के लिए लौटा देंगे।

3. अपन तर्क के सभर्यन में फर्म ने 1984-85 की आयात-निर्यात कियाबिध पुस्तर के अध्याय 15 के पैरा 353 के अन्तर्गत अपेक्षित एक गपथ-पन्न दाखिल किया है। अवोहस्नाक्षरी इससे संतुष्ट है कि आयात लाइसेंस सं. 2030153, दिनांक 13-11-82 की मूल मुद्रा बिनिसय नियंत्रण प्रति खो गई है और निदेश देता है कि अवेदक को लाइसेंस की मुद्रा बिनिसय प्रयाजन प्रति की अनुलिप प्रति जारी कर दी जाए। इस लाइसेंस की मूल मुद्रा बिनिय प्रयाजन प्रति कर दी जाए। इस लाइसेंस की मूल मुद्रा बिनिय प्रयाजन प्रति उत्तर दुत्र की जाती है।

4. आयात लाइसेंस की मुद्रा विनिसय प्रयोजन प्रति की अनुलिपि प्रति असग से जारी की जा रही है।

[का. स. ६कं/पेस्यसं/एएम/83/जीएलएस]

MINISTRY OF COMMERCE AND SUPPLY (Office of the Chief Controller of Imports and Exports)

New Delhi, the 5th February, 1985

ORDER

- S.O. 1485.—M|s. Krishna & Co., Goenka House, 44-Community Centie Zamrudpur, Kallash Colony Extension, New Delhi-110048, were granted an import licence No. P|F| 2030153|C|XX|85|H|82 dated 13-11-82 for Rs. 66,69,832 only for the import of spares of Machinery/Instruments for the period 1982-83.
- 2. The firm have now requested for the issue of duplicate copy of Exchange Purposes copy of the above licence on the ground that the original Exchange Purposes copy has been lost having been registered with New Delhi Customs Authority and utilised partly & duplicate is requested to cover the balance of Rs. 22,90,000 for documentation propose only by the bank. The firm agree, and undertakes to return the original Exchange Purposes Copy of the licence if traced later, to this office for record.
- 3. In support of their contention the firm have filed an affidavit as required in Para 353 of Chapter XV of Hand-Book of Import Export Procedure 1984-85. The undersigned is satisfied that the original Exchange Purposes Copy of Import Licence No. 2030153 dated 13-11-82 has been lost and directs that duplicate copy of Exchange Purposes copy of the licence may be issued to the applicant. The original Exchange Purposes copy of Licence is hereby treated as cancelled.
- 4. The duplicate copy of Exchange Purposes copy of the Import Licence is being issued separately.

[F. No. 6-K/Spares/AM-83/GLS]

नई दिल्ली, 26 मार्च, 1985

आदेश

का. आ. 1486.—मैंसर्स रेयमंड इन्टरनेशनल आंफ डेलावेयर इन्स., मार्फत इन्टरनेशनल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेंडिंग सिस्टम्स प्रा. लि., आई टी टी एस हाउस. 28, के. दुबाश मार्ग, वम्बई-400023 को 1983-84 अविध के दौरान माल के आयात और पुनः निर्यात के लिए 77,02,800/- रुपए (यू.एस. डालर 568,347 और पौड 122,236) के लिए एक सीमाशुल्क निकासी परिमट सं. पी/जे/3057291/एन/एम एन/87/एच/83/सी जी 1, दिनांक 11-11-1983 दिया गया था।

अब फर्म ने उपर्युक्त सीमाशुल्क निकासी परिमट की अनुलिपि प्रति जारी करने के लिए इस आधार पर अनुरोध किया है कि मूल सीमाशुल्क निकासी परिमट, बम्बई क सीमाशुल्क, (सीमाशुल्क सदन), एयरकार्गों काम्पलेक्स के पास पंजीकृत कराने के पश्चात् और आंशिक रूप से उपयोग में लाने के पश्चात् खो गया है और कुल धनराशि जिसके लिए अब सीमाशुल्क निकामी की अनुलिपि प्रति की आवश्यकता है वह शेष मूल्य 2,85,738/- रुपये को पूरा करने के लिए है। फर्म इससे सहमत है और बचन देती है कि यदि भूत सीमाशुल्क निकासी परिमट बाद में मिल गया तो इस कार्यालय को रिकार्ड के लिए लौटा देंगे।

अपने तर्क के समर्थन में फर्म ने 1984-85 की आयात-निर्यात कियाविधि पुस्तक के अध्याय 15 के पैरा 353 में यथा-अपेक्षित एक शपथ-पत्र दाखिल किया है। अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि मूल सीमाणुल्क निकासी परिमट सं. पी/जे/3057291 दिनांक 11-11-1983 खो गया है और निदेश देता है कि आवेदक को सीमाणुल्क निकासी परिमट की अनुलिपि प्रति जारी की जाए। मूल सीमाशुल्क निकासी परिमट रद कर दिया गया है।

सीमा-शुल्क निकासी परिमट की अनुलिपि प्रति अलग से जारी की जा रही_, हैं।

> [फा. सं. 1074/38/83-84/सी. जी०.-I] पॉल वैंक, उप-मुख्य नियंत्रक, आयात-नियति कृते मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

New Delhi, the 26th Match, 1985

ORDER

S.O. 1486.—M/s. Raymond International of Delaware Inc., C/o. Intermodal Transport & Trading Systems Pvt. Ltd., UTS House, 28, K. Dubash Marg, Bombay-400023, were granted a CCP No. P/J/3057291/N|MN|87|H|83|CG, I dated I1-I1-1983 for 77,02,800 (US \$ 568,347 & £ 122,236 for import and re-export of goods during the period 1983-84.

The firm have now requested for the issue of duplicate copy of Customs Clearance Permit of the above CCP on the ground that the original CCP have been lost after having been registered with the Bombay Custom (Customs House), Aircargo Complex, and utilised partly and the total amount for which the duplicate copy of the CCP now required is to

cover the balance value of Rs. 2,85,738. The firm agrees and undertakes to return the original CCP if traced later, to this office for record.

In support of their contention the firm have filed an affldavit as required in Para 353 of Chapter XV of Hand-Book of Import-Export Procedures 1984-85. The undersigned is satisfied that the original CCP No. P/J/3057291 dated 11-11-1983 has been lost and directs that duplicate copy of CCP may be issued to the applicant. The original CCP has been cancelled.

The duplicate copy of the CCP is being issued separately.

[F. No. 1074/38/83-84/CG. I]

PAUL BECK, Dy. Chief Controller of Imports & Exports, for Chief Controller of Imports & Exports.

(बी. एल. अनुभाग)

नई दिल्ली, 26 मार्च, 1985

आदेश

का. आ. 1487.—श्रीमती नीता मेठी, 5 रेजीडेन्सी रोड़, बंगलीर की एक मर्सीडींज बेंज डीजल कार के आयात के लिए केवल 1,15,200 रुपए का सीमा-शुल्क निकासी परिमट सं. पी/जे/3073285, दिनांक 17-9-84 दिया गया था। आवेदक ने उपर्युक्त सीमा-शुल्क निकासी परिमट की अनुलिपि प्रति जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल सीमा-शुल्क निकासी परिमट अस्थानस्थ हो गया है/खो गया है। आगे यह भी बताया गया है कि मूल सीमा-शुल्क निकासी परिमट किसीं भी सीमा-शुल्क प्राधिकारी के पास पंजीकृत नहीं कराया गया था और इस प्रकार सीमा-शुल्क निकासी परिमट के मूल्य का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया गया है।

2. अपने तर्क के समर्थन में, लाइसेंसधारी ने यथोचित न्यायिक प्राधिकारी के सम्मुख विधिवत् शपथ लेकर एक शपथ-पत्न दाखिल किया है। तदनुसार, मैं संतुष्ट हूं कि मूल सीमा-शुरुक निकासी परिमट सं. पी/जो/3073285, दिनांक 17-9-84 आवेदक से खो गया है। समय-समय पर यथा-संगोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 दिनांक, 7-12-1955 के उप खंड 9(सी सी) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए श्रीमती नीना सेठी को जारी किया गया उक्त मूल सीमा-शुरुक निकासी परिमट सं. पी/जो/3073285, दिनांक 17-9-84 एतद्वारा रह किया जाता है।

3. पार्टी को सीमा-गुलक निकासी परिमट की अनुसिपि प्रति अलग से जारी की जा रही है।

[सं. ए/एस-160/84-85/बी. एल. एस./4433]

(B.L. Section)

New Delhi, the 26th March, 1985

ORDER

S.O. 1487.—Mrs. Nita Scthi, 5 Residency Road, Bangalore was granted a Customs Clearance Permit No. P/J/3073285 dt. 17-9-84 for Rs. 1,15,200 only for import of one Morcedes Benz Diesel car. The applicant has applied for issue of Duplicate copy of the above mentioned Customs Clearance Permit on the ground that the original CCP has been misplaced/lost. It has further been stated that the original CCP was not registered with any Customs authority and such the value of the CCP Inc. 3 not been utilised at all.

- 2. In support of her contention, the licensee has filed an affidavit duly sworn before appropriate judicial authority. I am accordingly satisfied that the original CCP No. P/I/3073285 dt. 17-9-84 has been lost by the applicant. In exercise of the powers conferred under Sub-Clause 9(cc) of the Import (Control) Order, 1985 dt. 7-12-1955 as amended from time to time, the said original CCP No. P/J/3073285 dt. 17-9-84 issued to Mrs. Nita Sethi is hereby cancelled.
- 3 A duplicate copy of the Customs Clearance Permit is being issued to the party separately.

[No. A/S-160/84-85/BLS|4433]

आदेश

का. आ. 1488.—श्री किस्टी एंथनी जोसफ, 4617 न्यू बोईगुड़ा, सिकन्वराबाद (आंध्र प्रदेश), को मर्सीडीज डीजल 200 कार के आयात के लिए 79,900/- क. मान्न का एक सीमा गुल्क निकासी परिमट मं. पी/जे/3073271 दिनांक 15-7-84 दिया गया था। आवेदक ने उपर्युक्त सीमा- गुल्क निकासी परिमट की अनुलिपि प्रति जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल सीमा- गुल्क निकासी खो गया है/अस्थानस्थ हो गया है। आगे यह भी बताया गया है कि मूल सीमा- गुल्क निकासी परिमट किसी भी सीमा गुल्क प्रधिकारी के पास पंजीकृत नहीं कराया गया था और जिसके कारण सीमा गुल्क निकासी परिमट के मूल्य को बिल्कुल भी उपयोग में नहीं लाया गया था।

2. अपने तर्क के समर्थन में लाइसेंसधारी ने उपयुक्त न्यायिक प्राधिकारी के समक्ष शपथ लेकर एक शपथ-पत्र दाखिल किया है। तदनुसार, मैं संतुष्ट हूं कि मूल सीमा-शुरूक निकासी परिमट सं. पी/जे/3073271, दिनांक 15-7-84 आवेदक से खो गया है। समय-समय पर यथा संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेण, 1955, दिनांक 7-12-1955 के उप-खंड 9(सी सी) के अंतर्गत प्रदरत अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री सी. ए. जोसफ के नाम पर जारी किए गए उक्त मूल सीमाशुरूक निकासी परिमट सं. पी./जे/3073271, दिनांक 15-7-84 को एतद्दारा रह किया जाता है।

3. पार्टी को सीमागुल्क निकासी परिमट की एक अनुलिपि प्रति अलग से जारी की जा रही है।

> [संख्या ए/जे-39/84-85/बी. एत. एस./4401] एत. एस. कृष्णामूर्ति, उप मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात कृते मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

ORDER

- S.O. 1488.—Mr. Christie Anthony Joseph, 4617 New Boiguda, Secundrabad, (A. P.) was granted a Customs Clearance Permit No. P/J/3073271 dt. 15-9-84 for Rs. 79,900 only for import of Mercedes Diesel 200 car. The applicant has applied for issue of Duplicate copy of the above mentioned Customs Clearance Permit on the ground that the original CCP has been misplaced/lost. It has further been stated that the original CCP was not registered with any Customs authority and such the value of the CCP has not been utilised at all.
- 2. In support of his contention, the licensee has filed an affidavit duly sworn before appropriate judicial authority. I am accordingly satisfied that the original CCP No. P/I/3073271 dated 15-9-84 has been lost by the applicant. In exercise of the powers conferred under Sub-Clause 9(cc) of the Import (Control) Orders, 1955 dated 7-12-1955 as amended from time to time, the said original CCP No. P/I/3073271 dt. 15-9-84 issued to Mr. C. A. Joseph is hereby cancelled.
- 3. A displicate copy of the Customs Clearance Permit is being issued to the party separately.

[No. A/J]309|84-85|BLS|440]

N. S. KRISHNAMURTHY, Dy. Chief Controller of Imports & Exports

For Chief Controller of Imports & Exports

विदेश मंज्ञालय

(हज सैल)

नई दिल्ली, 22 मार्च, 1985

ा. ा. 1489 हा रामिति नियमावली, 1963 के नियम ६ (आई ए) बारा प्रवत शकित्यों का प्रयोग इसते हुए भारत सरकार हाज समिति, अभाई के लडम्यों श्री मोहम्मद अमीत खंडनानों और श्री युपुफ ह ीज, जो महाराष्ट्र विधान सभा के उनके सदस्य न रहने पर, ने स्थानों को तत्काल रिका बोपिन इसती है।

[सं. एम (हज) 118-1/15/80] आरिफ़ कमरैन, संयुक्त सचिव (अफ्रीका/हज)

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS
(Haj Cell)

New Delhi, the 22nd March, 1985

S.Q. 1489.—In exercise of powers conferred by Rule 6(1A) of the Haj Committee Rules, 1963, the Government of India declare vacant with immediate effect the seats held by Shri Mohd, Amin Khandwani and Shri Yusuf Hafiz, members of the Haj Committee, Bombay consequent upon their ceasing to be members of the Maharashtra Legislative Assembly.

[No. M(Haj) 118-1/15/80] ARIF QAMARAJN, Jt. Secy.

लाद्य एंव नागरिक पृर्ति मंत्रालय

(नागरिक पूर्ति विभाग) भारतीय मानक संस्था नई दिल्ली, 14 मार्च, 1985

का. आ. 1490.--ससय-ममय पर संगोधित भागतीय मानक संस्था (उनागताविक्ष) विनियम, 1955 के विनियम 14 के उपविनियम (4),]के भनुसार अधिसूचित किया जाता है कि लाईसेंस संख्या संग्रम ए-9431027 तथा 1180740 जिनके ब्यौरे नीचे अनुसूची ने दिये गये हैं,वे दिनांक 1984-09-01 भीर 1984-08-01 से लाइसेंसघारियों की प्रार्थना पर रह कर दिये गये हैं।

(सर्म गंगेज टीन वयर्ग 365, हरीभ भज, कानप् र	टोन यें 18 लि , के वर्गाकार दिब्दे	IS . 916-1973 टोन के 18 लि. के वर्गाकार डिट्मों की विमिष्टि (बूसरापुनरीक्षण)
सर्म एक्सपेस टीन कटेनके (प्रा. लि.,) २० के टी- टीक फिलार अनुद्रा	-थशोपरि-	-ग्रथोपरि-
75, आ. ८१. स्व । स्वयुः स्तायका र्यानप्र . 38, बङ्गल्ला स्ट्रीट किला-700007		
)	मर्स एक्सपेस टीन कंटेनसं (प्रा. लि.,))3, जी. टी. रोड मियपुर शवडा प्रीतप्र. 38,बड्सल्ला स्ट्रीट	मर्स एक्सपेस टीन कंटेनसे (प्रा. लि.,) -पशोपरि-)3, र्जा/, टी, 'रोड मिथपूर-शवडा र्यानप्र. 38, बड्सल्ला स्ट्रीट

[संख्या मी एम ही 55.0431027]

ए. एस. चीमा, अपर महानिदेशक

MINISTRY OF FOOD & CIVIL SUPPLIES

(Department of Civil Supplies)

INDIAN STANDARDS INSTITUTION

New Delhi, the 14th March, 1985

S.O. 1493.—In pursuance of sub-regulation (4) of regulation 14 of the Indian Standards Institution (Certification, Marks) Regulations 1955 as amended from time to time the Indian Standards Institution hereby notifies that Licence No. CM/L-0431027 & 1180740 particulars of which are given in the Schedule below have been cancelled with effect from 1984-09-01 & 1984-08-01 at the request of the licensees:

Sl. Licerco No. and Date No.	Name & Address of the License	E Article/Process covered by the Licines C to Hed	Relevant Indian Standar
1 2	3	4	5
1. CM/L-04310 27 	M/s Ganga Tir Works 365 Hartisgan Kanput	18-Litre square ti i containers	18 . 916—1975 Specification of 18-Litre squale tins (Second Revision)
2. CM/L-1180740 1983-04-15	M/s Express Tra Containers (P) Ltd. 493, G.T. Road, Shibpur, Howigh bayes their office at 38, Burtolla Street, Calcutta- 700007.	18-Litre's quito tra containers	IS: 916—1975 Specification for 18-Litre square tins (Second Revision)

[No. CMD/55:043 (027]

A S, CHEEMA, Addl. Director General

्षि और ग्रामीण विदाय महादय (इपि और सहसारित विभाग) नई दिल्ती, 18फालरा, 1985

का. आ. 1491 --पण् भाषात अधिनित्रस, 1898 (1898 . 19) की धारा 2 के खेंड (ख) तथा धारा 3 की उपधारा (1) हाल प्रदत्त मक्तियों का प्रमाग असते हुये, केन्द्रीय नर.पर एनदृहारा अधिसूचित करती है कि "पग्" णब्द के अत्तर्गत कूक्कुट तथा तये जाने याल अडे भी णामिल होगे तथा सयुक्त राज्य अमेरिका में पक्षी एनपपुद्दका के हात के प्रकोप को देखते हुये, संयुक्त राज्य अमेरिका स शुद्ध नस्ल तथा ग्रेड मूल नस्ल अ पश्, सेने जाने वाले अडो आदि सहित क्क्क्ट का भारत म आयात करने पर इस अधिमूचना के जारी होने की तिथि से तीन माह को अवधि के लिये एतंद्रारा प्रतिबंध लगाती है।

> [सं. 50-4/84-एल.डी.टा. (ए. क्यू.)] टा. आर. ब्रेहन, अवर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND KURAL DEVELOPMENT

(Department of Agriculture & Co-operation) New Delhi, the 18th February, 1985

S.O. 1491.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of Section 2 and sub-section (i) of Section 3 of the Livestock Importation Act, 1898 (9 of 1898), the Central Government hereby notifies that the world 'Livesto k' shall cover poultry and hatching eggs also and does hereby pio i-bit for a period of three months from the date of issue of this notification the import into India of poultry including purchine and grandparent stock, hatching eggs, etc. from the United States of America in view of recent outbreaks of avian influenza in that country.

> [No. 50-4/84-LDT (AQ)] T. R TREHAN, Under Secy.

पेट्रेलियम मंत्रालय

नई दिल्ली, 29 मार्च 1935

का णा 1492 .---यत पट्टोमियम श्रीर खनिज पाइपलाइन (भिम मे उपयोग के प्रधिकार का प्रजन) प्रधिनियम, 1962 / 1962 का 50) की धारा 3 की उपभारा (1) के श्रधीन भारत सरकार क कर्जा महालय पेटोलियम विभाग की सिंधित्वना का. श्रा भ 4107 तारीख 15-11-84 तारा केन्द्रीय सरकार ने उस प्रशिसूचना से मलग्न

अनुपुचा भ वितिविष्ट भनियो मे उपयोग के श्रक्षिकार को पा६गनाइनों का बिछ।ने के लिए प्रजिन करने का प्रपना प्राणय घोषित कर विया

और यतः मक्षम प्राधिकारी न उक्त प्रधिनियम की घारा 6 की उपधार। (1) के ग्रदीन सरकार का रिपोर्ट देवी है।

श्रीर श्रामे, यत बेन्द्रोय भरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पण्चात् इस पांच (जना सं सलग्न अनुसूच, मे विनिर्दिष्ट भूमिया मे उपयोग का अधिकौर प्रजित करने का विनिश्वय किया हैं।

भन, भन उन्त राधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा पदन मांक्त का प्रयाग करन हुए केन्द्रीय सरकार एतदहारा मांबित करती ४ कि इस प्रधिसूचना में रालग्न श्रनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का प्रधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एसबुद्धारा ध्रजित किया जाता है।

श्रीर श्रागे उस धारा की उपधारा (4) हारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयाग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश दती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का प्रधिकार कन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तल श्रीर भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में, सभी बाबामी से मक्त रूप में, घोषणा क प्रकाशन क। इस तारीख को निहित होगा।

धनुसूची

हुगर। में बरला से जगशेसहर पाइव लाईन

राज्यगुजरात	जिलापचमह्स	तातुका	हाल	াল
— गाव	 सर्वेन.	 हेक्टर	<u></u> घारे	सन्दीभर -
नूरपुरा नूरपुरा	7	1	61	40
	[H. O140	1 6/272/8		$[\tilde{h}_{2}]$

MINISTRY OF PLIROLEUM

New Delhi, the 29th March, 1985

S.O. 1492.-Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 4107 dated 15-11-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Mmerals Popchnes (Acquisinon of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Se tion (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

nd further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by subsection (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India 1 im ted free from encumbrances.

SCHEDULL:

Pipeline from Hajira-Baroilly-Jagdishpur.

State : Gujarat District : Panchamahal Taluka : Halol

Village	Survey No.	Heacture	Arca	Centiare.
Nurpura.	7	1	61	40
	<i>-</i> 			

[No. O-14016/272/84-GP]

का.आ. 1493 — यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्यप्रदेश राज्य मे हजीरा— बरेली से जगवीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवडन के लिये पाइन लाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिये।

श्रीर यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्गाबद असुसूची में बिणत भूमि में उपयोग का अधिकार अजित करना सावश्यक है ।

श्रतः श्रव पेट्रोलियम श्रीर खनिज पाइप लाइन (भृमि मे उपयोग के श्रधिकार का श्रजेंन) श्रधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने दुर केन्द्रीय मरकार ने उसमें उपयोग का श्रधिकार श्रजित करने का भपना श्राशय एनद्वारा घोषित किया है।

श्रमतें कि उक्त भूमि में हिनबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन विद्याने के लिए भ्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेन तथा प्राष्ट्रितक शैम प्रायोग, एच. वी जे. पाइप लाइन 45, सुभाष नगर सांचेर रोड, उज्जीन (म. प्र.) 456001 को इस प्रधिपूचना की तारीख के 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

श्रीच ऐसा श्राक्षेप करने वाला हर अपनित विभिन्निध्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवार्ड ध्यातिनात हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

एच. बी. जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट ग्राम डामरोन खुर्पै तहसील करेरा जिला----शिवपुरी राज्य (मध्य प्रदेश)

ग्रन्म्ची

 ग्रनु,क,	 खसरा नं .	उपयोग अधिकार भर्जन का क्षेत्र (र्वेक्टमें से)
1		3
1	408/3	0.066
2	411	0.490
3.	4 1 4/ 2	0.090
4	415	0.120
5.	416	0.080
6-	419	0.360
7.	420	0.290
8	421	0.240

-			
1	2	3	
9.	426	0.360	
10	435	0.060	
11	152/1	0 300	
12.	447	0 280	
1.	I 14,	0 300	
1.1	4 10/ 1	0.080	
15.	4 13/ 2	0.040	
16.	501	0,050	
17.	502	0.180	
18.	503	0.090	
19	501	0 130	
20.	5 U J	0.010	
24.	506	0 240	
22	507	0 110	
23	509	0.180	
2.1	776	0 600	
25.	7 79	0.660	
26	770/1	0.240	
27	412	0.190	
28	413	0.010	
29.	417	0.080	
30	125	0 100	
31.	450	0.180	
32.	115	0.030	
1.4	503	0.100	
34	76	0.010	
33.	769	0 200	
16	770/2	0,150	
37_	500/306	0.020	
योग	— —— ाः सुलक्षेत्रफल	6,810	
	-		

[मं. O-14016/183/85-जीपी]

S.O. 1493.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hazira-Bareilly to Jagdishpur in Madhya Pradesh State pipe line should be laid by the Gas Authority of India Linuted.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline, Acquisition of Right of User in the Land). Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, HBJ Gas Pipe Lipe, 45. Subhash Nagar, Sarwer Road, Uljain (M.P.).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

HBJ GAS PIPE LINE PROJECT

Village Damorone Khurd Tehsil Karera Distt : Shwpuri SCHEDULE

S.N	o. Survey No.	Area to be A equired for R.O.U. 111 Hectare
1.	408/3	0.060
2.	411	0.480
3.	414/2	0.090
4,	415	0.120
5.	416	0.080
6.	419	0.360
7,	420	0.290
18,	421	0.240
9.	426	0.360
10.	435	0.060
11.	452/1	0.300
12.	447	0.280
13.	446	0.300
14.	443/1	0.080
15.	443/2	0.040
16.	501	0.050
17.	502	0.180
18.	503	0.090
19.	504	0 180
20.	505	0.440
21.	506	0 240
22.	507	0 140
23.	509	0 180
24.	776	0.600
25.	779	0.660
26.	770/1	0.240
27.	412	0.190
28.	413	0 010
29.	417	0.080
30.	425	0.100
31.	450	0 180
32.	448	0 030
33.	508 768	0.100
34.	769	0 010
35.	770/2	0.200
36.	•	0.150
37.	500/806	0.020
	Total Area	6.810

[No. O-14016/183/85-GP]

का.आ. 1494 यतः भेन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह भाषण्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में हजीरा— खरेली से जगवीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन भारतीय गैम प्राधिकरण द्यापाय द्वारा बिछाई जानी चाहिये।

भीर यतः यह प्रसीत होता है कि ऐसी लाइनों की बिछाने के प्रयोजन के लिसे एतद्पायक धनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का छि-कार भजित करना भावस्थक है।

धतः श्रव पेट्रोलियम श्रीर खनित्र पाइप लाइन (भूमि मे उपयोग के मिधकार का भर्जन) मिधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त मिक्तियों का प्रयोग करने हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमे उपयोग का मिधकार श्रीजत करने का श्रपना भाषाय एतद्वारा घोषित किया है। बणर्ने कि भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति. उग भूमि के तीचे पाइप लाइन बिछाने के लिये आक्षीप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैंग आयोग, एच. बी जे. पाइप लाईन 45, मुभाप नगर संबिर रोड, उज्जैन (म.प्र.) 456001 की इन अधिसुचना की तारीख के 21 विनों के भीतर कर संकेगा।

ग्रीर ऐसा ग्राक्षेप करन वाला हर व्यक्ति विनिर्दिण्टन यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी मुनवाई व्यक्तिगत रूप से हा या किसी विधि व्यवसामी की मार्फत ।

ण्च. बी. जे. गैस पाष्प लाइन प्रोजेक्ट ग्राम छोनिपुर तहसील करेरा जिला⊸शिवपुरी राज्य (मध्य प्रदेश)

	-	
07	ਸਰਾ	

अनु.क	. खसरा न	उपयोग श्रधिकार भर्जन का क्षेत्र (हैक्टर्स में
1	2	3
1.	379	0.200
2.	377/2	0.062
3.	378	0.357
4.	376	0.052
5.	375	0.105
6	373	0.418
7.	372/2	0.130
8	367	0.157
9.	369/2	
10.	370/2	0.214
11.	365/1	0.157
12.	350/1	0.110
13.	350/2	0.080
14	350/5	0.210
15	350/6	0.190
16.	351	0.100
17、	352	0.150
18.	338	0.100
19.	318	0.418
20	321/1	0.468
21.	277/2	0.468
23.	139/1	0.323
23.	140	0.105
24.	141	0.052
25	147/1	0.055
26.	147/2	0.110
27.	147/3	0.105
28.	147/4	0.052
29	145	0.021
30,	144/1	0.055
31	144/2	0.052
32.	144/3	0.021
33.	105/935/6	0.468
34.	105/965/7	
3 5.	105/965/9	0.084
36	6-1	0.100
37.	83	0.050
38.	8 9/1	0.105
39.	89/2	0,105
40.	90	0.073
41.	91	0.063

	2	3	
4 2.	99/1	0.052	•
43.	99/3	0.082	
4.	9 2/ 1/ 2	0.157	
5.	60/4		
46.	93	0.021	
47.	94	0.042	
48.	57/1	0.060	
49.	57 /2	0,120	
50.	57/3		
51.	056	0.031	
5 2.	53/1	0.063	
53.	53/2	0.042	
54.	53/3	0.052	
55.	53/4	0.052	
56.	49/1	0.152	
57.	49/2	0.152	
योग-	—	7.253	

[सं. **O**→14016/181/85-र्जी पी]

S.O. 1494.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hazira-Bareilly to Jagdishpur in Madhya Pradesh State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, HBJ Gas Pipeline, 45, Subhash Nagar, Sanwar Road, Ujiain (M.P.).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

HBJ GAS PIPE LINE PROJECT
Village Chitipur Tehsil Karera Distt. Shivpuri
SCHEDULE

S.No.		Survey No.	Area to be Acquired				
			for R,O.U. in				
			Hectare				
1.	379		0.200				
2.	377/2		0.062				
3.	378		0.357				
4.	376		0.052				
5.	375		0.105				
6.	373		0.418				
7.	372/2		0.130				
8.	367		0.157				
9.	369/2						
10.	370/2		0.214				
11.	365/1		0.157				

1796 GI/84-4

_1		2	3
12.	350/1	0.110	
13.	350/2	0.080	
14.	350/5	0.210	
15.	350/6	0.190	
16.		Q.100	
17,	· -	0.150	
18.		0.100	
19.	318	0.418	
20.	321/1	0.468	
21. 22.	277/2	0.468	
23.	139/1 140	0.323 0.105	
24.	140	0.1 0 5	
25.	147/1	0.052 0.055	
26.	147/2	0.110	
27.	147/2	0.110	
28.	147/4	0.052	
29.	145	0.021	
30.	144/1	0.055	
31.	144/2	0.052	
32.	144/3	0.021	
33.	105/935/6	0.468	
34.	105/965/7	* *	
35.	105/965/9	0.084	
36.	64	0.100	
37.	88	0.050	
38,	89/1	0.105	
39.	89/2	0,105	
40.	90	0.073	
41.	91	0.063	
42. 43.	99/1 99/3	0.052	
43. 44.	99/3 92/1/2	0.082 0.157	
45.	60/4		
46.	93	0.021	
47.	94	0.042	
48.	57/1	0.060	
49,	57/2	0.120	
50.	57/3	• •	
51.	056	0.031	
52.	53/1	0.063	
53,	53/2	0.042	
54.	53/3	0.052	
55.	53/4	0.052	
56.	49/1	0.152	
57.	49/2	0.152	
			

[No. O-14016]181[85-GP]

7.253

का थ्रा. 1495 :—पनः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहिल में बहु आवण्यक है कि मध्य प्रवेश राज्य में हुजीरा—बरेली के जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन मारतीय गैन प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा बिछाई जानी चाहिये।

Total Area

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद् पायक अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग अधिकार अजित करना आवश्यक है।

अतः अस पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाङ्ग (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा (3) की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त मक्तिमों का प्रयोग करने हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना आगय एलव्हारा भोषित किया है। बगर्स कि उन्त भूमि में हितबद कोई व्यक्ति, उस भूमि के तीचे पाइप लाइन विछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, एच. बी. जे. पाईए लाईन 45, सुभाष नगर मांवेर रोड़, उज्जीन (म. प्र.) 456001 को इस अधिसूचना की तारीच 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप फरने वाला हर स्थित जिनिधिष्टत: यह भी कथन करेगों कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई स्यक्तिगत कप से हो या किसी विधि व्यवसायी की सार्फत।

एच. बी. जे. गैस पाईप चाईन प्रोजेक्ट धाम कुचलोन सहसील करेरा जिला जिबपुरी राज्य (मध्य प्रदेक)

अनुसूची

क.सं.	बसरानं,	जपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हेक्टर्स में)
1	2	3
1.	638	0.031
2.	639	0.857
3.	642	0,042
4.	614	0.125
5.	612	0.110
6.	602	0.147
7.	597	0.105
8.	596	0.105
9	593	0.167
10	595 ∫	
11	591	0.073
12	592	0.031
13	588	0.021
14.	562	0.272
15.	564/1	0.052
16	564/2	0,136
I 7.	564/3	0 146
18.	565	
l 9 .	561/1	●.073
20.	21/3,4,5,6	0.470
21.	35	0.282
22.	36	0.231
23.	64/1	0.015
24.	63	•.131
25.	62	0,158
26.	61/1	0.178
27.	60 Asla	0.146
28.	46/3	0.063
29. 30.	109 110	0.324
31.	106/27	0.084
3 2.	108	0,110
33.	116	0.324
34.	117	
35.	118	0.384
36.	122	0.188
37.	121	. 272
38.	133	9.063
39.	130/1	0.073
40.	131	0.261
41	140	0.314

1	2	3
42.	141	0,010
43.	159/2	0.252
4 4.	161/1	0.146
45.	171	0.194
46.	59	0.150
47.	563	0.010
48	589	0.030
49	603	0.175
50-	609	0.400
51.	610	0.020
5 2.	615	0.150
53.	643	0.110
54	644	0.070
55.	704	0.030
56.	705	0.150
57.	640	0.300
58.	627	0.100
 योग-	कुल क्षेत्रफल	8.891
		[म. O-14016/182/85-र्जा पे.]

S.O. 1495.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hazira-Bareilly to Jagdishpur in Madhya Pradesh State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pirelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, HBJ Gas Pipe Line, 45, Subhash Nagar, Sanwer Road, Ujjain (M.P.).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

HBJ GAS PIPE LINE PROJECT

Village Kuchlone Tehsil Karera Distt. Shivpuri

SCHEDULE

5.N	o, Survey No.	Area to be Acquired for R.O.U. in Hectare
1	2	3
1.	638	0.031
2.	639	0.857
3.	642	0.042
4,	614	0.125
5.	612	0.110
6.	602	0.147
7.	597	0.105
8.	596	0.105
9.	593 ገ	0.167
10.	595	• •

[414 11 44 04 3(4)]	41011	
1 2	3	
11. 594	0 073	के प
12. 592	0.031	उप्य
13. 588	0.021	
14. 562	0.272	
15. 564/1	0.052	प्रदम
16. 564/2	0.136	है (
17. 564/3	0,146	मे
18. 565		द्वारा
19. 561/1	0.073	
20, 21/3,4,5,6	0.470	
21. 35	0.282	प्र योग
22. 36	0,231	में उ
23, 64/1	0.015	भार
24. 63	0.131	
25, 62	0.188	मोब
26, 61/1	0.178	
27, 60	0.146	
28. 46/3	0.063	
29. 109	0.324	
30. 110	0.084	ভিল
31. 106/2	0.110	
32. 108	_	
33. 116	0.324	1
34, 117 J	0.384	ভাগন
35, 118		अ रम्
36. 122	0.188	
37. 121	0. 272 0. 0 63	
38. 133	0.073	
39. 130/1	0.261	
40. 131	0.314	
41. 149	0.010	
42. 141 13. 159/2	0.252	
13. 159/2	0.146	
44. 16l/1	0.194	
45. 171	0.150	
46. 59	0.110	
47. 563	0.030	
48, 589 40, 603	0.175	
49, 603 50, 609	0.400	
50. 609 51. 610	0.020	
52. 615	0.150	
	0.110	
	0.070	
	0.070	
	0.150	
	0.300	
57. 640 58. 627	0.100	
)0. 04/	5,100	, S.
Total Area	8 891	India
		SO.

[No. O-14016/182/85-GP]

का ग्रा. 1496 :- पन पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत मरकार के मुत्रालय देट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का आर. सं 3698 भारीख 17-11-84 द्वारा केन्द्रीय संस्कार ने उस अधिं सूचना सै सलग्न अतमुची में जिनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने.का अपनाआयाय घीषित कर दिया

और यत संभ्रम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार की रिपोर्ट वे दी है।

और आगे यत केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसुचना से सलग्न अनसूचः संविनिदिश्ट भसियो से उपयोग का अधिकार अजिल करने का बिनिश्चय किया है।

अब, अंग उक्त अधिनियम की भारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदन मन्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में सलग्न अनुसूची में विनिर्विष्ट उक्त भुमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाईन विद्वान ने प्रयोजन के लिए एतड़-द्वारा अजिन कियाजाना है।

और अगरे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदश शक्तियां का प्रयोग करने हुए केर्न्द्राय सरकार निर्देश वेती है कि उक्त भूमियो में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय मारतीय गैस प्राधिकरण लि से सभी साधाओं से मुक्त रूप मे वोषणा के प्रकाशन की इस तारीका को निहित होगा ।

नत् मुचः हाजिरा बरेल जगद शपुर पाइप लाइन प्राक्रेक्ट

`भ ला 	तहर्गम	प्रश्नी	ग्रामका नाम	गाटा स.	लिया गया रक्तवा	वि व र -
I	2	3	4.	5	6	7
प्रश्ता स	गुरवा	प्रशा	धिरनः खेंड् ।	18	0-0-5	
				19	0 1 1 0	
				3 6	0 - 6- B	
				3 7	0-10-16	
				39	0 13-16	
				41 एम	0 - 1- 1 0	
				63	0-16-0	
				64	0 0 5	
				89	0→ 1 5 - 0	
				90	0-3-0	
				91	0 0 5	
				92	0-3-0	
				Z 8	0-0-10	
				29	0-0-15	
				88	0-0-5	
				110	0-1-0	
				111	0-2-10	

[स. О---14016/155/84-जा(पा)

S.O. 1496.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S.O. 3698 dated 17-11-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intenion to acquire the right of uner in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notificacation:

Now, therefore, in exercise of the power conferred by subsection (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Anthority of India Ltd. free from oncumbrances.

SCHEDULE

Hajira	Barreil	ly J	agdishp	ur	Piţ	oeline	Project.	
Distt.	Telasil	Par	rgana.	Villa	_ ìge.	Plot No.	Area Acquired	Remaraks
1		2	3	4		5	6	7
Б рвао	Unnao	Purwa	ı Dhirji		18		0-0-5	
			K	heda	19		0-11-0	
					36		0-6-0	
					37		0-10-16	
					39		0-13-16	
					41	M	0-1-10	
					63		0-16-0	
					64		00-5	
					89		0-15-0	
					90		0-3-0	
					91		0-0-5	
					92		0-3-0	
					28		0-0-10	
					29		0-0-15	
					88		0-0-5	
					11	0	0-1-0	
					11.	1 .	0-2-10	
_				<u> </u>				

[No. O-14016/155/84-G.P.]

का. आहं. 1497.— यह पेट्रोलिय और खानिज वाइपलाइन (जूमि में अवभीग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अर्धन भारत सरकार के कर्या मंत्रालय, पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का आत. 3781 तारी खा 17-11-84 द्वारा के जी सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिविष्ट भूमिमों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनें की विद्यान के लिए अजित करने का अपना आहम चोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार की रिपोर्ट वे दी है।

और आगे यतः केन्द्राम सरकार ने उस्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संस्थान अनुसूची में विनिधिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिध्यय किया है।

अध, अतः उनतः अधिनियम् की खारा 6 की उपधारा (1) हारा प्रवत्त शिक्त का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा चोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विशिष्टिट उकत भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन विकान के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अणित किया चाता है।

और आगे उस धारा की उपबार। (4) द्वारा प्रवत्त सक्तियों का प्रयोग करने हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश वेती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय शैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त कर में बोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनु सूच

हाजिल बरेली जगह गपुर पाइप लाइन प्रोजैस्ट

জিলা	परमना	नहस स	ाग्राम काना	म गाटा स.	क्षेत्रफल विव	र्ण
1	2	3	4	5	6	7
उन्नाब	पुरवा	पुरवा	भवातं₁पुर	1470	0- 7- 0	
				1471	0-4-0	
				1472	0-6-0	
				1473	0- 4- 0	
				1478	0-1-10	
				1479	0-3-10	
				1480/2	0 1 1 U	
				1480/4	0-12-0	
				1480 6	1-0-0	
				1503	9– 8→ 0	
				1504	0-1-0	
				1506/2	0-1-10	
				1596/3	0-9-0	
				1474	0-1-0	

S.O. 1497.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Peroleum S.O. 3781 dated 17-11-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Ministrals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Covernment:

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of power conferred by subsection (1) of the Section 6 of the said Act. the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of nower conferred by sub-section (4) of that section, the Cenral Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India I imited.

SCHEDULE

Hajira	Barielly .	Jagdishp	ur	Pipeline Project.				
Distt P	argana Ta	hsil Vill	Plot No	Area acquirerd	Remarks			
1	2	3	4	5	6	7		
Unnao I	Purwa Pur	wa Bh	awany	1470	0-7-0			
			pur	1471	0-4-0			
				1472	0-6-0			
				1473	0-4-0			
				1478	0-1-10			
				1479	0-3-10			

6

0-2-14 0-3-4 0-1-15 0-1-15 0-1-4 0-0-6 0-0-12 0-5-12 0-12-6

0-3-0

0-7-13

[सं. O-14016/152/84-- जी पो]

1	2	3	4	5	6	7	1	3	3	4	5
				1480/2	0-11-0						942
			•	1480/4	0-12-10						943
				1480/6	1-0-0						944
				1503	0-8-0 0-1-0						947
				1504 1506/2	0-1-0 0-1-10						948
				1506/3	0-9-0						914
				1474	0-1-0						921
				INIo	O-14016/171	/84 GPI					1396
				[NO.	G-14010/171	/0 1 -01]					1397
<u>ቸ</u> ነ	777 A C	9 — ≖ ∓=-	पेटोलिय	स और अपनि	ज पाइपलाइन	(भामि में					1398

का. प्रा. 498 — मतः पेट्रोलियम और खिनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयांग के अधिकार का अर्जन अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अर्धान भारत मरकार के उर्जी मंत्रालय पेट्रोलियम, बिभाग की अधिसूचना का भ्रा. सं. 3695 तरिंखा 17-11-84 द्वारा केन्द्राय सरकार ने उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में निविष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप खाइनों की बिद्धाने के लिए अर्जिन करने का अन्ता आश्य घोषत कर दिया था।

और बतः सक्षम प्राक्रिकारों ने उनत आधिनियम को बारा 6 की उपबारा (1) के अर्बान सरकार को रिपोर्ट दे वी है।

भीर आगे बतः केर्न्बाव सरकार ने उनत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अबिसूचना सेसलग्न अनुसूची मैं विनिदिष्ट भूमियों में उपयोग का अबिकार ऑजित करने का विनिध्चत किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम का बारों 6 की बारा (1) दारा प्रवक्त सक्ति का प्रकार करते हुए केन्द्रांथ सरकार एतव्द्रारा कोषित है करती कि इस अधिसूचना में मंचन अनुसूची से विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप नाइन बिकान के प्रयोगन के निए एतब्द्रारा अधित किया जाता है।

और आगे उस भारा का अपधारा (4) झारा प्रवत्त गवितयों का प्रयोग करते हुए केन्द्रांच सरकष्य निवंश वेती है कि उनत भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में बिनिहत होने के अजाब भारती अभी साधिकरण लिं, में सभा बाधाओं से मुक्त रूव में भोषणा के प्रकाशन की इस तारी अकी निहित होगा।

अनुसूच. द्वाजिरा बरेली जगवीपापुर पाइप लाइम प्रोजैस्ट

जिला तहर्स ल परगना ग्राम का नाम गाटा सं. लिया गया रक्षणा विवरण								
1	2	3	-4	5	6	7		
 उन्नात्र	 उस्नाब	हरहा	मराई	857	0-15-00			
				870	1- 0-14			
				871	1- 4- 12			
				877	1-1-12			
				878	2-15-0			
				923	1-10-2			
				922	0-2-0			
				919	0-1-4			
				915	0 → 1 → 1 6			
				924	0-1-08			
				925	0-2-19			
				935	0-4-14			
				934	0-0-18			
				936	0-3-6			
				937	0-1-2			

S.O. 1498.—Whereas by notification of the Govt, of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S.O. 3695 dated 17-11-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Mineral, Pipeline (Acquisition of Right of User in I and) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

1399

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by subsection (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited free from encumbrances.

SCHEDULE

Hajira	Bareil	y Jac	dishpur	Pipelir	ne Pro	ject.
Distt.	Tehsil	Pwgana	Village	Plot No.	Area	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
Unnao	Unnao	Harha I		857 870 871 877 878 923 922 919 915 924 925 935 934 936	0-15-00 1-0-14 1-4-12 1-1-12 2-15-0 1-10-2 0-2-0 0-1-4 0-1-16 0-1-08 0-2-19 0-4-14 0-0-18 0-3-6 0-1-2	

1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	ь	7
				942	0-2-14					_	151	0-2-0	
				943	0-3-4								
				944	0-1-15						152	() (()	
				947	0-1-15						153	0-3-0	
				948	0-1-4						161	0-2-0	
				914	0-0-6						162	0-9-0	
				921	0-0-12						165/1	0-6-0	
				1396	0-5-12						163	0-2-0	
				1397	0-12-6						165/4	0-7-0	
				1398	0-3-0						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
				1399	0-7-13						167/6	0-0-10	
			_~-								167/7	0-13-0	
				[No.	O-14016/152/	84-GP]					169	0-19-0	
											170	0-1-0	
		1.00	2-2 -2-2	=6		(see in					160	0-0-5	
					नेज पाइपलाइन 1962 (1962						174	0-1-0	

[म. O-14016/60/84-जी पी]

उपभाग के ग्राधिकार का भजन) भाषानयम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के प्रधीन भारत सरकार के ऊर्जा महालय, पेट्रोलियम विभाग की मधिमूचना का. सा. स. 3744 तारीखा 17-11-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से सलग्न प्रनुसूची मे विनिर्विष्ट भूमियों के उपयोग के प्रधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए मर्जित करने का मपना मासय मोसित कर दिया

भीर यस. सक्षम प्राधिकारी ने उक्त मिश्रिनियम की भाग 6 की उपधारा (1) के प्रधीन सरकार की रिपोर्ट दे दी है।

ग्रीर ग्रागे यत. केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर निचार करने के पश्चात् इस प्रश्नियुचना से सलग्न धनुसूची मे विनिर्दिष्ट भूमियो मे उपयोग का श्रिष्ठकार श्राजित करने का विनिश्वत किया है।

द्मव, ग्रन उन्त ग्रिधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त प्रक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एनवृक्षारा घोषित है कि इस प्रधिसूचना में संलग्न धनुसूची में विनिर्विष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का प्रधिकार पाइप लाइन बिछाते के प्रयोजन के लिए एनद्-द्वारा प्रजित किया जाता है।

भीर भागे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त सक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियो मे उपयोग का प्रधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. मे सभी बाधाओं से मुक्त रूप में योषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहिन होगा।

भनुसूची हाजिरा बरेली जगदीशपूर पाइप लाइन प्रोजैक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम का नी	मि गाटा सं.	रकसा विक	रण
1	2	3	4	5	6	7
-— — उन्नाब	— पुरवा	पुरवा	 टीकाखुर्व	37	1-4-10	
	•	-	•	38	0-8-0	
				39	0-3-0	
				41	0-1-10	
				42/2	0→11 − 0	
				43	1-11-00	
				44	0-4-0	
				45	0-2-0	
				140	0-12-0	
				144	0-5-0	
				149	0-1-0	
				150	0-10-0	

S.O. 1499.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S.O. 3744 dated 17-11-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User) in Land, Act. 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Subsection (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Covernment has after considering he said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Centra Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited free from encumbrances.

SCHEDULE Hajira Barcilly Jagdishpur Pipeline Project.

Distt.	Pargana	Tehshil	Village	Plot No.	Area Acquired	Remarks
1	2.	3	4	5	6	7
Linano	Purwa	Purwa '	Tiberkhur	37	1-4-10	
CHAI	, I W			38	0-8-0	
				39	0-3-0	
				41	0-1-10	
				42/2	0-11-0	
				43	1-11-00	
				44	0-4-0	
				45	0-2-0	
				14?	0-12-0	
				144	0-5-0	
				149	0-1-0	

0-0-2 0-0-5 1-4-0 0-5-10 0-0-5 0-6-0 0-0-5 0-10-0 0-2-0 0-9-0 0-13-0 7

1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	1	5
-				15)	0-10-0					71	
				151	0-2-0						
				152	0-6-0					72	
				153	0-3-0					73	
				161	0-2-0					74	
				162	0-9-0					75	
				165/1	0-6-0					174	
				163	0-2-0					175	
				165/4	0-7-0					176	
				167/6	0-0-10						
				167/7	0-13-0					17 7	
				169	0-19-0					180	
				170	0-1-0					221	
				160	0-0-5					227	
				174	()-1-0					253	
		, ,		 [No.	O14016/60	/84-GP]				258	
				-	,	-				262	
का.	भा.	1500'	-यतः पेटो(लेयम भीर	व्यक्तिज पाइपका	इन (भूमि				272	
										973	

का. भा. 1500'— यतः पेट्रोलियम भीर खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के भ्रिष्ठकार का ग्रजैंन) भ्रिष्ठनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के भ्रधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय पेट्रोलियम विभाग की श्रिष्ठसूचना का. भा. सं. 3745 तारीख 17-11-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस भ्रष्ठसूचना से संलग्स भनुसूची मे विनिर्विष्ट भूमियों के उपयोग के भ्रष्ठिकार को पाइप लाइनों को विछाने के लिए भ्रजित करने का भ्रपना भ्रास्य घोषित कर विया था।

भौर मतः सक्तम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की अपधारा (1) के प्रधीन मरकार को रिपोर्ट देदी है।

भीर धार्गे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस ध्रधिसूचना से संलग्न ध्रनुसूची मे विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का ध्रधिकार ध्रजित करने का विनिश्चय किया है।

ग्रव, भतः उसत प्रधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रवत्त गक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एत्व्द्वारा भोषित करती है कि इस ग्रधिसूचना में संलग्न धनुसूची में विनिर्विष्ट उस्त भूमियों में उपयोग का मधिकार पाइपलाइन विछाने के प्रयोजन के लिए एनव्द्वारा भूजित किया जाता है।

भीर मागे उस द्यारा की उपघारा (4) द्वारा प्रवस्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए केन्द्रीय सरकार निर्वेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का प्रधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. श्रायोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीच को निहित होगा।

ध्रमुस्थी हाजिरा बरेसी जगदीशपुर पाइप साइन श्रीजेस्ड

जिमा }	. सहसील	परग न।	ग्राम	गासं.	लिया गया खाता	वित्रपर
1	2	3	4	5	6	7
उन्नाव	- ভন্নাৰ	ह्वहा	सेमरी-	5 5	0-0-2	
			मधा	56	0-16-0	
				57	0-2-10	
				58	0-3-10	
				64	0-0-2	
				66	0-0-15	
				67	0-11-0	
				70	0-0-5	

[मं. O-14016/62/84---जी, पी.]

0-0-5

0:0-5

0-0-15

0 - 0 - 12

\$.O. 1500.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S.O. 3745 dated 17-11-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1952), the Central

171

172

309

322

Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying the pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Subsection (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of the power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited free from encumbrances.

SCHEDULE
Hajira Barrily Jagdishpur Pipe line Project

Distt.	Tehshil	Pargana	Village	Plot No.	Are∃ Acqu	Remarks ried
1	2	3	4	5	6	7
Tinnao	Unnao	Herha	Semri- 1,5	5	0-0-2	
			mau 56	5	0-16-0	
			57	7	0-2-10	
			58	3	0-3-10	
			64		0-0-2	
			66		0-0-15	
			67	7	0-11-0	
			70)	0-0;5	
			71		0-0-2	
			72		00-5	
			73		1-4-0	
			74		0-5-10	
			75		0-0-5	
			17		0-6-0	
			17		0-0-5	
			17		0-10-0	
			17		0-0-2	
			18		090	
			22		0-13-0	
			22		0-7-0	
			25		1-0-0	
			25	8	0-5-10	
			26	2	0-14-0	
			27		0-0-15	
			27		0-1-0	
			27		0-3-0	
			27		0-4-0	
			27		0-7-0	
			27		0-4-0	
			31		0-11-10	
			31		0-16-0	
			32		0-10-0	
			32		0-2-0	
			32		0-2-0	
			32		07-0	
			32		0-5-0	
	_		32	7	0-5-0	

1	2	3	4	5	6	7
				330	0–1–0	
				3 32	0-12-()	
				355	0-6-0	
				356	0-2-0	
				357	2-12-0	
				518	0-11-0	
				519	0-3-0	
				520	0-2-0	
				521	0-1-0	
				522	0-11-0	
				523	0-3-0	
				-525	1-3-0	
				527	0-9-0	
				528	0-7-0	
				529	0-1-10	
				65	0-0-15	
				171	0-0-5	
				172	0-0-5	
				309	0-0-15	
				322	0-0-12	

[No. O-14016/62/84-GP]

का. मा. 1501 — अतः पेट्रोलियम घोर बानित पाइपलाइन (भृमि में उपयोग के प्रधिकार का क्रार्थन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के प्रधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंद्रालय पेट्रोलियम विभाग की अधिमूचना का. घा. नं. 3743 तारीखा 17-11-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस प्रधिसूचना से संजग्न प्रनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के घिषकार की पाइप लाइनों को बिछाने के लिए ग्रार्जन करने का प्रपना ग्राणय घोषिस कर दिया था।

भीर यत. सक्सम प्राधिकारी ने उक्त प्रधिनियम की धारा 6 की जिपक्षारा (1) के प्रधीन सरकार की रिपोर्ट दे दी है।

ग्रीर ग्रागे यत. केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पत्रचात् इस ग्रिश्तूचना से संलग्न ग्रानुसूची में विनिर्विष्ट भूमियो मे उपयोग का ग्रिश्कार ग्रीजन करने का चिनिश्चय फिया है।

श्रव, श्रतः उक्त श्रविनियमं की धारा 6 की उपवारा (1) द्वारा प्रदन्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एनवृद्धारा बोबित करते हैं कि इस ग्रविसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियो में उपयोग का ग्रविकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एनवृद्धारा श्रवित किया जाता है।

भीर भ्रागे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदस्त मक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का श्रधिकार केन्द्रीय सरकार में निहिन होने के अजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रका- गन की इस नारीख को निहिन होगा।

धन्सूची हाजिरा बरेली जगदीलपुर पाइप लाइन श्रोजेक्ट

 जिला	तहसील	 प रग ना ,	ग्राम कानाम	गाटा सं.	रमया	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
उस्न(ब	 उन्नाव	हड़हा	सद्धागर	50	0-1-00	
				46/4	0-10-11	
				4 5	0-1-16	
				44	1-1-0	
						-,

I —	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6
				76	0-19-0						45	0-1-16
				75	0-0-9						44	11-0
				77	0-10-0						76	0-19-0
				8 9	1-8-0						75	0 –0 –9
				90	0-6-0						77	0-10-0
				88	0-1-8						89	1-8-0
				99	0-0-12						90	0-6-0
				91	1-1-16						88	0-1-8
				92	0-1-16						99	0-0-12
				97	0-1-7						91	1-1-16
				3	1-8-6						92	0-1-16
				94	0-10-16						97	1-1-7
				25	0-1-8						93	1-8-6
				26	0-10-16						94	0-10-16
				79	1-2-4						125	0-1-8
				.76 75	1-2-4						126	0-10-16
				73	1-16-0 0-0-18						179	1-2-4
				36	0-0-18 0-0-10						176	1-2-4
				38	0- 0 -10 1-0-0						175	1–16–0
				48	1-12-0						173	0-0-18
				49	0-16-0						236	0-0-10
				59	2-12-0						238	1-0-0
				61	0-7-0						248	1-12-0
<u> </u>											249	0-16-0
			[सं.	O-1401	.6/56/84-जी. पे	t.]					259	2-12-0
					the Governme						261	0-7-0

[No. O-14016/56/84-GP]

S.O. 1501.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 3743 dated 17-11-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying the pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification:

Now, therefore, in exercise of the power conferred by subsection (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of the power conferred by subsection (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited free from encumbrances.

SCHEDULE

Distt.	Tehscel	Pargana	Village	Plot		Area acquired	Remarks
1_	2	3	4		5	6	7
Unnao	Unna	Herha S		50 46/4		0-1-00 0-10-11	

का.आ. 1502 — यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय पेट्रोलियम जिमाग की अधिमुचना का.आ. सं. 3741 तारीख 17-11-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिमुचना से संलग्न अनुमूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आश्रय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी में उक्त अग्निमियम की बारा θ की उपधारा (1) के अग्नीन सरकार को रिपोर्ट देवी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्क रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिमूचना से संलग्न अनुसूची में धिनिर्विष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की घारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रवस्त कक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतवृद्धारा कोषित करती है कि इस अधिस्वना में संलग्न अनुसूची में विनिद्धिट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतवृद्धारों अजित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) धारा प्रदत्त गर्भितयों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित्त होने के बजाय भारतीय गस प्राधिय ण लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशभ की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची **SCHEDULE** हाजिस Hajira Barrily Jagdesh pur Pipe line Project सरेली जगदीशपुर पाइपलाइन प्रोजेक्ट जिला परगना Distt. Pargana Tehscel Village Plot Arca Remarks तहसील ग्राम **चिवरण** गाटा सं० चाता acquired Nc. का नाम 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 अस्ताव हरहा उम्माध चपरी-Unnao Herha Unnao Chapri-764 0-5-15 764 0-5-15Shahpur 765 0 - 7 - 6मासुपुर 765 0 - 7 - 60-5-10 766 768 **0**~5~10 767 0 - 8 - 0767 0 - 8 - 0768 0-3-5 768 0 - 3 - 5812 0-6-7 812 0 - 6 - 7813 1-12-0 844 0 - 15 - 0813 1 - 12 - 0843 0-14-10 844 0-15-0 222 0-2-30-14-0 843 841 0-0-10 828 0 - 2 - 3842 0-8-0 841 0-0-10 912 0-7-2 842 0 - 8 - 0911 0-5-11 913 0-15-0 912 0 - 7 - 2910 0-0-15 911 0-5-11 908 0-1-0 0 - 15 - 0913 914 0-4-3 0-0-15 910 916 0-2-0908 0 - 1 - 0917 0-8-0 914 0 - 4 - 3846 0-0-10 0-4-0 845 0 - 2 - 0916 0 - 3 - 12917 0 - 8 - 0918 0 - 4 - 0846 0 - 0 - 100-4-0 845 [No. O-14016/57/84-QP] 0-3-12 918 0-4-0

[सं• O-14016/57/84-जीपी]

S.O. 1502.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S.O. 3741 dated 17-11-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying the pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Subsection (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by subsection (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited free from encumbrances.

का.आ. 1503 -- यतः पेट्रोलियम और खानिज पाइपलाइम (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा उकी उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंद्रालय पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का.आ.सं. 3482 तारीखा 3-11-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों की विष्ठाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय धोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राप्तिकारी ने उक्त अधिनियम की घारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट देवी है।

और आगे यमः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के परकात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट सूमियो मे उपयोग का अधिकार अर्जिन करने का विनिश्चय किया है।

अस, अत: उक्त स्रिधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) हारा प्रवक्त सिक्त का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतवृद्वारा भोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त मूमियों मे उपयोग का अधिकार पाइपलाइन विछाने के प्रयोजन के लिए एतवृद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बनाय भारतीय गैस प्राधिकरण में यभी भाषाओं से मुक्त रूप में कोषणा के प्रकाशन की श्रम तारीख को निश्चित होगा।

1839

			Ì	भगुस्				
	प्रो जेक्ट	पाइपलाइन	सपुर	अग	ली	ब	रा	हाजि
विवर्ष	खाता	ाटा सं॰		ग्रार	 त ह सील	गना	<u> ५</u> र	जिला
	6	5			3	2		l
	0-14-0	89	- 1	अर्च	ज म्माव	हा	हड	उन्नाष
	0-13-15	188		गंज				
	0-16-0	182	रा	स्ब				
	0-0-10	181						
	0-015	183						
	-18-10	186 (
	0-15-0	173						
	0-14-0	172						
	-16-15	171 \						
	0-5-0	166						
	0-8-5	50						
	0-2-0	11						
	0-3-0	12						
	0-2-5	10						
	0-2-0	9	,					
	0-0-10	8						
	0-0-10	7	,					
	-17 - 10	13 (
	0-2-10	1.5						
	0-3-0	16						
	0-12-10	36	:					
	0-14-0	34	;					
	1-8-0	26	:					
	0-0-10	167						
	005	в						

[सं॰ O-14016/94/84-जी पी]

S.O. 1503.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S.O. 3482 dated 3-11-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying the pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Subsection (I) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by subsection (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline:

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Cas Authority of India Limited free from encumbrances

SCHEDULE

Hajira Barielly Jagdishpur Pipe line project.

Distt.	Pargana	Tehseel	Village	Plot No.	Area . Acqu	Area Remarks Acquired		
1	2	3	4	5	6	7		
Unnao	Herha	Unnao	Anchal-	189	0-14-0			
			ganj	188	0-13-15			
			Sakora	182	0-16-0			
				181	0-0-10			
				183	0-0-15			
				186	0-18-10			
				173	0-15-0			
				172	0-14-0			
				171	0-16-15			
				166	0-5-0			
				50	0-8-5			
				11	0-2-0			
				12	0~3-0			
				10	0-2-5			
				9	0-2-0			
				8	0-0-10			
				7	0-0-10			
				13	0-17-10			
				15	0-2-10			
				16	0-3-0			
				36	0-12-10			
				34	0-14-0			
				26	1-8-0			
				167	0-0-10			
				6	0-0-5			
				[No	. O-14016/	94/84-GP]		

का आ 1504. — जतः पट्टोलियम और खिनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोक के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की द्वारा 3 की उपदारा (1) के अधीम भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय पेट्टोलियम विभाग की अदिस्चना का.आ.सं. 3665 तारीख 17-11-84 द्वारा के केन्द्रीय सरकार ने उस अधिस्चना से संलग्न अनुसूची में विनिधिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को विखाने के लिए अजित करने का अपना आग्रय घोषित कर विधा था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उन्त अधिनियम की धारा θ की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट देदी है।

और आगे यत: केन्द्रीय सरकार ने उन्त रिपोर्ट पर विभार करने के पश्चाल् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विभिद्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिष्णय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रवक्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एनदृद्वारा घोषित करती है कि इस अधिकार पोइपलायन बिखाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अजित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लिंक में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस कारीक की निहित होगा।

भनुसूची						SCHEDULE							
हाजिर	नरेली	जगदी गपुर	ो गपुर	ू पा इपलाइ न	प्रोजेक्ट		Hajira Barriely Jagdishpur Pipe line Project						
जिला	परगना	-	न प्राम अग्राम	गाटा सं०	कियागया व्यय	विवर्ण	Distt.	Pargana	Tehsil	Village	Plot No.	Area Acquire	Remarks d
1	2	3	4	5	6	7		2	3	4	5	6	7
जनदाव	पुरमा	पुखा	गवीखा	93	0-16-10	I		<u> </u>					·
	•			94	0-12-10)	Unna	o Purwa	Purwa	Gadarwa	a 93	0-16-10	
				96	0-2-10)					94	0-12-10	
				99	0- 3- 0)					96	0-2-10	
				104	1-0-0)					99	030	
				105	0-4-0)					104	1-0-0	
				110	0-3-10)					105	0-4-0	
				112	0-1-10)					110	0-3-10	
				113	0- 8- 0)					112	0-1-10	
				114	0-0-7	7					113	0-8-0	
				117	0- 5- 8	3					114	0-0-7	
				119	0→ 1 2 − 0)					117	0-5-8	
				121	0-3-6	0					119	0-12-0	
				124	0-8-3	5					121	0-3-0	
				125	0-5-1	U					124	0+8-5	
				126	0- 0- :	5					125	0-5-10	
				264	0- 12-	5					126	0-0-5	
				267	0- 0- 0	8					264	0-12-5	
				268	0-10-	5					267	00-8	
				269	0-0-1	2					268	0-10-5	
				270	0- 6-	5					269	0-0-11	
				92	0- 0-	5					270	0-6-5	
				271	0- 7-	0					92	005	
					-14016/54/8						271	0-7-0	

[No. O-14016/54/84-GP]

S.O. 1504.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S.O. 3665 dated 17-11-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schendule appended to that notification for purpose of laying the pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Subsection (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by subsection (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited free from encumbrances.

का॰ बा॰ 1505. -~ पत्रि पेट्रोलियम बौर खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का खर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिमूचना का. भी. सं, 3760 तारीख 6-11-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिमूचना से संलग्न अनुसूची में बिनिर्विट भूमि के उपयोग के अधिकार को पाइप छोषिन कर विया था।

भौर यतः सक्षमं प्रधिकारी ने उक्त प्रधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के मधीन सरकार को निपौर्ट देशी है।

भौर भागे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विकार करने के पक्वात इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची में विनिर्विष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अणिन करने का विनिध्चय किया है।

श्रव, सतः उक्त प्रधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदरत शक्तियों का उपयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतब्द्वारा कोषित करतें है कि इस अधिमूचना में संस्थन अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में जपयोग का अधिकार पाइए लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतव्द्वारा अभिन किया जाता है।

भीर भागे इस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदस्त गिक्तियों का प्रयोग करने हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का व्यधिकार केन्द्रीय सरकार में निहिन्त होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि॰ में सभी बाधाओं से मुक्त घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित्त होगा।

हाजिरा

श्रनुसूची हुजीरा से बरेली से जगदीणपुर तक पाइपलाइन बिछाने के लिए

राष्य-गुज रात	जिला-एवं-तालुका- भरुव						
गाज	 ब्लाक नं	ह्रक्टेयर	भार	मेंटीयर			
करमाली	49	0	0.4	00			
	50	0	37	60			
	5 1	0	28	00			
	53	0	81	60			

[स॰ O-14016/120/84-जी पी]

S.O. 1505.—Whereas by notification of the Government of India in the Department of Petroleum S.O. 3760 dated 6-11-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that noification for purpose of laying pipeline;

And, whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government:

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by subsection (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification henreby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Hajira - Bareilly - Jagdishpur State : Gujarat District & Taluka : Bharuch

Village	Block No.	Hec- tare	Are	Cen- tiare
Karmali	49	0	04	00
	50	0	37	60
	51	0	28	00
	53	0	81	60

[No. O-14016/120/84-GP]

का. प्रा. 1506:—पतः पेट्रोलियम धौर खिनिय पाइपलाइम (भूमि में उपयोग के प्रधिकार का प्रजैन) प्रधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के प्रधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंतालय पेट्रोलियम विभाग की धिभूचना का. भा मं. 3465 तारीख 3-11-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस प्रधिसूचना से संलग्न प्रमुची में विनिदिष्ट भूमियों के उपयोग के प्रधिकार को पाइप लाइनों को खिछाने के लिए प्रजिन करने का प्रधान धायय घोषिन कर दिया था।

भीर, यतः, सक्षम प्राधिकारी ने उत्तर प्रधिनियम की धारा 6 की अपधारा (1) के प्रधीन सरकार की रिपोर्ट देवी है।

भौर मार्गे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस मधिसूचना से संनग्न मनुसूची में विनिर्विष्ट भूमियों मे उपयोग का मधिकार भाजत करने का विनिश्चत किया है।

श्रम, भतः, उन्त भिधिनियम की भारा 6 की उपधारा (1) द्वारा श्रवत्त गक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित है कि इस श्रिधसूचमा में संलग्न भनुसूची में विनिध्निट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइएशाइन विद्याने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अजित किया जाता है।

भीर भागे जस धारा की जपधारा (4) द्वारा प्रदश्न गक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उच्च भूमियों में जपयोग का प्रधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के भारतीय गैस प्राधिकरण लिं० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में धोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

श्रनुसूची बरेसी अगबीभापुर पाइपलाइन प्रोजेक्ट

						-
जिला	परगना	तहसील	प्राम	गाटा सं	रकदा	 विवरण
1	2	3	4	5	6	7
उन्नाव	पुरवा	पुरवा	विभुन			
			खेड़ा	5	0→6→	- 0
				6	09	– 0
				7	0-2-	•0
				9	0-8-	-0
				10	0-11-	- 0
				11	0-1-	-0
				17	0 2 -	- 0
				18	0-12	-0
				20	0-16	-0
				21	0-8-	-0
				44	0 0	5

[स॰ O-14016/11/84-जीपी]

S.O. 1506.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Feuoleum S.O. 3465 dated 3-11-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And, whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by subsection (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited frefrom encumbrances.

1842	TH	E GAZI	ETTE (OF INDIA	A: APRIL 13	1985/CHA	AITRA 23, 1907	<u> </u>	PART II—S	EC. 3(ii)
		SCHED	ULE			1	2	3	4	5
H	ajira-Bareilly-Jago	lishpur Pi	pe line	Project			65	0	00	25
Diett	Doronno Tabail	Village	Diet N	o Aren	D-mode		72/3	0	15	30
Disti.	Pargana Tehsil	у пла ве	PIUI IN	o. Area Acquired	Remarks		72/2	0	03	5 0
	<u> </u>						71/2/1	9	24	00
1	2 3	4	5	6	7		71/1	0	31	50
Unnac	Purwa Purwa	Bishun	5	0–6–0			70/2/2	0	26	75
U	2 11 11 11 11 11 11	Kheda	6	0-9-0			69/2	0	46	50
			7	0-2-0			70/1	0	00	60
			9	0-8-0			69/1	0	54	0.0
			10	0-11-0			50/2	U	01	26
			11 17	0-1-0 0-2-0			50/1	0	25	6.5
			18	0-12-0			49	0	22	0 0
			20	0-16-0			51/1	0	02	88
			21	0-8-0			48/2	9	01	υQ
			22	0-0-5			53/3	0	20	78
			- INI	a O 14016	/11/04 CIBI		53/4	0	00	08
			[14	o. O-14016	/11/64-GPJ		53/2/ 2	0	13	60
45 1	. भ र. 1507.—-यर	ा: पेटालिया	गधीर ख	मिज पाइपसा	पन भसि में		53/2/1	0	08	60
	के प्रधिकार का(!						53/1	0	00	30
	त 3 की उपधारा	,		•	,		54	0	05	80
	की मधिसूचना क				•		27/1/6	0	04	00
	सरकार ने उस प्रक्रि						27/1/5	0	03	00
	ोग के भक्षिकार को						27/1/4	0	03	00
	ना भाष्य घोषिस कर			21.1 1.1(1)	71 90 7101		27/1/3	U	03	00
•							27/1/2	0	04	00
	र यतः सक्षम प्राधिक			मकीधारा 6	की उपधारी		27/1/4	0	04	00
(1) 略	भ्रधीन सरकार को	रिपोर्ट वे वे	हिं।				27/2	0	02	60
भी	र, मार्ग, यतः केन्द्री	य सरकार न	ने उपस रि	पोर्ट पर विच	ार करने के		13/2	U	07	87
पश्चात	इस प्रविसूचना से स	तंलग्न चनुसूर	बी में विश	निर्दिष्ट भूमियं	ों में उपयोग		13/1	υ	12	13
	व्रकार म्रजित करने व						12/2	O	18	08
	ा, प्रतः, उपत प्रधिनि		-) 2777 1778		12/1	0	03	06
	ा, भरान, उपरा भावान हा प्रयोग करते हुए						12/3	O	15	26
	शात्रकाय करताहुए धिसूचना में संलग्न ।						9/1	0	02	70
	प्रकार पा इ पलाइन विद						12/4	0	12	00
का आध जाता है		21P 4 P P15	निया च्या । १९४१	द दवक्षाराः	भाषात ।कथा		11	0	01	00
	-						9/2	0	04	30
	र मागे उस धारा की						10/1	U	26	13
4	ए केन्द्रीय सरकारनि			•••			10/2	0	00	33
ग्रधिकार	केन्द्रीय सरकार मे	निहित होने	की बजाय	तेल भीर	भारतीय गैस		<u>-</u>	-		

[सं॰ O-14016/455/84-जी पी]

27

80

00

प्राधिकरण नि० में, सभी बाधाओं से मुक्त कप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहिन होगा। प्रनुसूर्चा

श्रिष्ठिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की अजाय तेल भीर भारतीय गैस

हुजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइपलाइन विछाने के लिए राज्य-गजराम जिला-पंचमहल तालुका-हालोल

गोव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	मारे.	सेंटीयर
1	2	3	4	5
<u>ईटवाडी</u>	208/1	0	27	00
	208/2	0	0.0	25
	62/3	n	11	25
	62/4	0	22	75
	62/2	0	16	0.0
	61, 1	a	14	35
	64	0	31	0.0

S.O. 1507.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S.O. 4552 dated 10-12-84 under sub-section (1) of Section 3. of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Comment delegated its intention to acquire the right of Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

Ü

0

6/2

6/1

And, whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this

Now, therefore, in exercise of the power conferred by subsection (1) of the Section 6 of the said Act, the Central

Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Hazira-Bareilly-Jagdishpur

State: Gujarat	District : Panchmanal	Taluka : Halol		
Village	Survey No.	Hec-	Are	Cen-

Village	Survey No.	Hec- tare	Are	Cen- tiare
1	2	3	4	5
Itwadi	208/1	0	27	00
	2 08/2	0	00	25
	62/3	0	11	25
	62/4	0	22	75
	62/2	0	16	00
	61/1	0	14	35
	64	0	31	00
	65 50/2	0	00	25
	72 /3	0	1.5	30
	72/2 71/2/1	0	03 24	50 00
	71/2/1 71/1	0	31	50
	70/2/2	0	26	75
	69/2	0	46	50
	70/1	0	00	60
	69/1	ő	54	00
	50/2	Ō	01	26
	50/1	0	25	65
	49	0	22	00
	51/1	0	02	88
	48/2	0	01	00
	53/3	0	20	78
	53/4	0	00	08
	53/2/2	0	13	60
	53/2/1	0	08	60
	53/1	0	00	30
	54	0	05	80
	27/1/6	0	04	00
	27/1/5	0	03	00
	27/1/4	0	03	00
	27/1/3	0	03	00
	27/1/2	0	04	00
	27/1/1 27/2	0	04	60
	27/2	0 0	02 07	60 87
	13/2	. 0	12	13
	13/1 12/2	0	18	08
	12/2	0	03	06
	12/3	0	15	26
	9/1	0	02	70
	12/4	o	12	00
	11	ŏ	01	00
	9/2	ŏ	04	30
	10/1	ō	26	13
	10/2	Ó	00	33
	6/2	0	27	80
	6/1	0	05	00

[No. O-14016/45 5/84-GP]

का. जा. 1508:— पतः पेट्रोबियम और खिनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का जजन) अधिनियम, 1902 (1962 का 50) की आरा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत मरकार के ऊर्जा महालय पैट्रोलियम बिभाग की अधिमुचना का.जा.सं. 3931 तारीख 12-11-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिमुचना से संसम्म अनुसूची में विनिधिद्ध भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को विछाने के लिए अजित करने का अपना आश्य धोषित कर दिया था।

और, यतः, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की घारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिय्चय किया हैं।

अब, अतः, उनतः अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रयक्त प्रक्ति का प्रयोग करते द्वुए केन्द्रीय सरकार एनवृद्धारा घोषित करती है कि इस अधिसूजना में संलग्न अनुसूची में विनिद्धित उक्त भूमियों मे उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एनवृद्धारा अजित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रवस्त शक्तियों का प्रयोग करते श्रुए केन्द्रीय सरकार विदेश देती हैं कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण जि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसुची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर पाइपलाइन

राज्य-गुजरात	जिला-पंचम हल	त ह-हालोल
	, , , , , , , , , ,	

गांव	सर्थे नं.	हेक्टेयर	आरे	से	टीयर
वासेती	92		0	37	00
	93		0	34	00

[स. O-14016/270/84-जी पी]

S.O. 1508.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S.O. 3931 dated 12-11-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Covernment declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And, whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by subsection (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And, further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeliue from Hajira Bareilly Jagdishpur State : Gujarat District : Panchmahal Taluka ; Halol

Village	Survey No.	Hec- tare	-	Cen- tiare
Vaseti	92 93	0	37 34	00

[No. O-14016/270/84-GP]

का.आ. 1509 — यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपाइप (मूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की द्यारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का.आ.सं. 4551 सारीख 10-12-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचनों से संलग्न अनुमूची में विनिर्विष्ट धूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों का विद्याने के लिए अर्जित करने का अपना आध्य घोषित कर विया या।

और, यतः, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त श्रधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट देवी है।

और, आगे,, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अभूमूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयौग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः, उपत अधिनियम की घारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदल्त गक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतवृद्वारा घोषित करती है कि एग अधिगुषना में मंतरन अनुसूची में विनिधिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन विकान के प्रयोजन के लिए एतचुंद्वारा अजित किया जाता हैं।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदश्न शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निद्रग देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निष्ठित होने की बजाय नन और भारतीय गैस प्राधिकरण नि॰ में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निश्चित होगा।

अनुसूची हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइपलाइन बिछाने के लिए।

राज्य-गुजरात	जिला-पंचमहाल	लालुका-हाल	ील			
गांव		हेक्टेयर	आर	सेंटीयर		
अभेटवा	128	0	39	00		
	129	1	00	00		
	139	0	30	00		
	135	0	03	00		
	138	0	36	00		
	142	0	02	00		
	110	0	50	00		
	111	0	14	00		
	109	0	22	00		
	108	0	00	50		
	107	0	59	00		
	106/बी	0	19	00		

[सं. O-14016/454/84-जी पी]

S.O. 1509.— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S.O. 4551 dated 10-12-84 under sub-section (1) of Section 3

of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And, whereas, the Competent Authority has under Subsection (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by subsection (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited free from encumbrances.

SCHEDULE
Pipeline from Hazira Barcilly Jagdishpur

State: Gujarat District: Pauchmahal Taluka: Halol

Village	Block No.	Hec- tare	Ате	Cen- tiare
Abhetwa	128	0	39	00
	129	1	00	00
	139	0	30	00
	135	0	03	00
	138	0	36	00
	142	0	02	00
	110	0	50	00
	111	0	14	00
	109	0	22	00
	108	0	00	50
	107	0	59	00
	106/B	0	19	00

[No. O-14016/454/84-GP]

का. आर्ं 1510: — यतः पेट्रोलियम और सानिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की बारा 3 की उपप्रारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंजालय की अधिस्थाना का.आ.सं. 4558 तारीख 10-12-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संजन्न अनुसूची में विनिधिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आय्य घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपद्यारा (1) के अधीन सरकार को रिगोर्ट वेदी हैं।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिधिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपघारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय भग्कार एतद्द्वारा कोषित करती है की इस अधिसूचना में संख्या अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन विकान के प्रयोगन के लिए एलद्द्वारा अणित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रवक्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि॰ में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइपलाइन बिछाने के लिए।

राज्य-गुजरात	जिला-पंचमहल	तालुका-कालोल	i	
गोव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	आर	र्सेटयर
मलाव -	221/1/ ए /30	0	19	00
	221/1/ ए /41	0	02	00
	2 2 1/ 1/ए/ 5 1	0	32	00
	2 2 1/1/Q/61	0	12	0.0
	221/1/ए/60	0	21	0.0
	221/1/ए/71	0	34	00
	221/1/ए/7 0¹	0	10	0 (
	2 21/1/4/81	0	15	00
	2 21/1/ए/80	0	16	00
	221/1/ए/83	0	08	00
	2 2 1/ 1/ए/ 9 1	0	05	00
	2 2 1/ 1/ए/ 7 9	' 0	01	00
	221/1/ए/90	0	19	0.0
	221/1/प्/99	0	17	00
	221/1/ए/98	0	03	0.0
	2 2 1/ 1/ए/ 1 0 6	0	01	00
	2 2 1/ 1/ए/ 1 0 5	0	21	0.0
	221/1/U/112	0	22	60
	221/1/U/111	0	00	0.0
	221/1/Q/120	0	05	00
	221/1/प्/119	0	16	00
	221/1/ए/127	0	07	00
	221/1/ए/126	0	26	0.0
	221/1/ए/133	0	07	0.0
	2 2 1/ 1/ए/ 1 3 8	0	29	00
	221/1/ए/142/ पी	0	33	00
	221/1/ए/142/ पी	0	24	00

[सं. O-14016/461/84-जी पी]

S.O. 1510.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 4558 dated 10-12-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Rght of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And, whereas, the Competent Authority has under Subsection (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government:

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by subdection (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification bereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Hajira Barellly Jagdishpur State : Gujarat District : Panchmahal Taluka : Kalok

Village	Survey No.	Hec- tare	Are	Con- tlar
Malay	221/1/A/30	0	19	00
	221/1/A/41	0	02	00
	221/1/A/51	0	32	00
	221/1/A/61	0	12	00
	221/1/A/60	0	21	00
	221/1/A/71	0	34	00
	221/1/A/70	0	10	0
	221/1/A/81	0	15	0
	221/1/A/80	0	16	0
	221/1/A/83	0	08	0
	221/1/A/91	0	05	0
	221/1/A/7 +	0	01	0
	221/1/A/90	0	19	0
	221/1/A/99	0	17	0
	221/1/A/98	0	03	0
	221/1/A/106	0	01	0
	221/1/A/105	0	21	0
	221/1/A/112	0	22	0
	221/1/A/111	0	00	6
	221/1/A/120	0	05	0
	221/1/A/119	0	16	0
	221/1/A/127	0	07	0
	221/1/A/126	0	26	0
	221/1/A/133	0	07	0
	221/1/A/138	0	29	0
	221/1/A/142/P	0	33	0
	221/1/A/142/P	0	24	0

[No. O-14016/461/84-GP

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 1985

का. आ. 1511:—यतः, पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंद्रालय की अधिस्चना का. आ. सं. 2391 तारीख 7-7-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिस्चना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को विछानें के लिए अजिन करने का अपना आश्रम घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम अधिकारो ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और, आगे, यत:, केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करमे के पश्चात् इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची राज्य-गजरात

में विनिर्दिष्ट	भृमियों	में	उपयोग का	अधिकार	র্জী বর	करने
का निम्चय	किया	है।				

अब, अत, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रवत्त शक्ति का उपयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतव्द्वारा घोषित है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतव्दारा अजित किया जाता है।

और आगे इस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्रप्रधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनु सूची

हजीरां से बरेली से जगदीशपुर तक पाईंप लाईन बिछाने के लिए।

जिला-बडोदरा तालका-करजण

	~	3.5			
गोव नं०	सर्वे न०	हेक्टेयर	भार ———	सन्टीयर	
1	2	3	4	5	
कोठाव कोठाव	95	0	10	56	
	96	0	09	12	
	97	0	20	64	
	98	0	18	88	
	99	0	07	04	
	100	0	17	76	
	91	0	22	5 6	
	103	0	04	64	
	90/1	0	00	16	
	89 ·	0	24	6	
	88/2	0	09	4 4	
	87	0	33	76	
	86	0	01	4	
	116	0	00	1	
	119	0	21	1	
	67	0	15	8	
	66/1/P 66/1/P)	0	97	6	
	$\left. \begin{array}{c} 66/2/\mathbf{P} \\ 66/2/\mathbf{P} \end{array} \right\}$	0	39	6	
	123/9	Ó	03	0	
	123/10	0	13	1	
	123/11	0	10	4	
	123/12	0	13	1	
	123/13/ A	0	16	0	

1	2	3	4	5
· _ _	1 2 3/ 1 3/B	0	08	00
	125	0	0.8	96
	126	0	11	04
	127	0	09	60
	128	0	04	80
	129	0	14	56
	130	0	14	72
	131	0	11	36
	132	0	03	04
	138	0	19	20
	137/1/2	0	04	00
	$ \begin{array}{c} 35 \\ 36/1/2 \end{array} $	0	36	24
	26	0	04	00
	27/1	0	10	72
	27/2	0	11	04
	27/3	0	11	20
	27/4	0	12	0.0
	27/5	0	11	36
	28/1	0	20	80
	28/2	0	45	76
	28 /3	0	00	08
	16	0	60	80
	10	0	04	80
	11	0	21	60
	12	0	16	48
	13	0	00	32
	8	0	00	80
	9/1	0	19	68
	9/2/P	0	14	72
	375	0	05	12
	[ਜਂ ∩ -	14016/5	8 /8 4-जी	पी.

[सं. Q-14016/58/8 4-जी. पी.] New Delhi, 2nd April, 1985

S.O. 1511.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S.O. 2391 dated 7-7-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And, whereas, the Competent Authority has under Subsection (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And, further, whereas, the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification:

Now, therefore, in exercise of the power conferred by subsection (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appened to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authoriy of India Limited free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline From Hajira to Bareilly to Jagdishpur State: Gujarat District: Vadodara Taluka: Karjan

Village	Survey No.	Hectare	Aro	Cen tiar
1	2	3	4	
Kothav	95	0	10	50
	96	0	09	12
	97	0	20	64
	98	0	18	88
	99	0	07	04
	100	0	17	76
	91	0	22	56
	103	0	04	64
	90/1	0	00	16
	89	0	24	64
	88/2	0	09	44
	87	0	33	76
	86	0	01	44
	116	0	00	10
	119	0	21	1.
	67	0	15	8
	66/1/P	0	07	
	66/1/P 66/2/P 66/2/P	0	39	6 6
	123/9	0	03	0-
	123/10	0	13	1
	123/11	o	10	4
	123/12	ō	13	1
	123/13/A	0	16	0
	123/13/B	0	08	ŏ
	125	Û	08	9
	126	0	11	ó
	127	0	09	6
	128	ō	04	80
	129	0	14	5
	130	0	14	7
	131	0	11	3
	132	0	03	0
	138	0	19	2
	137/1/2	0	04	0
	35 36/1/2	0	36	2
	26	0	04	0
	27/1	0	10	7
	27/2	0	11	0
	27/3	0	11	2
	27/4	0	12	0
	27/5	0	11	3
	28/1	0	20	8
	28/2	0	45	7
	28/3	0	00	0
	16	U	60	86
	10	0	04	80
	11	U	21	60

1	2	3	4	5
	12	0	16	48
	13	0	00	32
	8	0	00	80
	9/1	0	19	68
	9/2/P	0	14	72
	375	0	05	12

[No. O-14016/58/84-GP]

का॰ आ॰ 1512: — यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय, पेट्रोलियम विभाग को अधिसूचना का. आ. सं. 875 तारीख 19-2-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्देख्ठ भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अजित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार इस्ते के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्विष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया हैं।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपद्यारा
(1) द्वारा प्रदश्च शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय परकार
एतव्हारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न
अनुसूची में विनिर्विष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार
पाइप लाइन विद्याने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अजित
किया जाता है।

और आगे उस घारा की उपधारा (4) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्वेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख में निहित होगा।

अनुसूची

विजयपुर (म. प्र.) से सवाई माधोपुर (राज.) तक पाइप लाइन विछाने के लिए

राज्य: राजस्थान जिला: कोटा तहसील: छबड़ा

गोव	खसरा नं 0	हेक्टर	भार	सेन्टी मार
नियामतपुर	8	0	03	56
•	9	0	35	35
	22	0	39	20
	67	0	19	60
	66	0	02	38

									<u> </u>
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
_ 		· - ·			·	52	0	37	72
	63	0	03	67		49	0	16	93
	62	0	29	95		48	0	10	39
		•				76	0	20	77
	64	0	09	99		77	0	15	24
	59	0	40	39		61	0	02	42
	58	0	34	16		78	0	06	90
	30	U				75	0	03	12
	52	0	37	72		21	0	01	19
	49	0	16	93	 -		<u> </u>	-	
	48	0	10	39			[No. O-140	016/91/85	-GP]
	40	U							
	76	0	20	77	TTA STA 4	s t o			/c

24

42

90

12

19

15

02

03

01

[सं. O-14016/91/85-जी. पी.]

0

S.O. 1512.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S.O. 875 dated 19-2-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

77

61

78

75

21

And whereas the Competent Authority has under Subsection (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification:

Now, therefore, in exercise of the power conferred by subsection (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests from this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Bijaipur (M.P.) to Sawai Madhopur (Raj.)

State: Rajasthan District: Kota Tehsil Chabra

Village	Survey No.	Hectare	Are	Cen- tiare	
Niyamatpur	8	0	03	56	
	9	0	35	35	
	22	0	39	20	
	67	0	19	60	
	66	0	02	38	
	63	0	03	67	
	62	0	29	95	
	64	0	09	99	
	59	0	40	39	
	58	0	34	16	

कां ० आ ० 1513 — यतः पेट्रीलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) श्रिधिनियम 1962 (1962 का 50) की घारा 3 की उपधारा (1) के अधीन धारत सरकार के ऊर्जा मंद्रालय, पेट्रोलियम वि:ाग की श्रिधसूचना का. आ. सं. 877 तारीख 19-2-85 द्वारा केन्द्रीय सर-कार ने उस अधिसूचना से संलग्न धनुसूची में विनिधिष्ट भूमियों के उपयोग के श्रिधकार को पाइप लाइनों को विछाने के प्रयोजन के लिए अजित करने का अपना श्राणय घोषित कर दिया था।

श्रौर यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त श्रिधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के श्रधीन सरकार को रिपोर्ट ने बीहै।

ग्रीर श्रागेयत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस ग्रधिसूचना से संलग्न ग्रनुसूची में विनिष्टि भूमियों में उपयोग का ग्रधिकार ग्रजित करने का विनिश्चय किया हैं।

श्रव, ग्रतः अक्त श्रिधिनियम की धारा 6 की उपधारा
(1) द्वारा श्रद्धत गांवत का श्रयांग करते हुए केन्द्रीय सरकार
एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस श्रिधसूचना में संलग्न
श्रनुसूची में विनिर्मिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का श्रिधकार
पाइप लाइन विछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा श्रजित
किया जाता है।

श्रीर श्रागे उस धारा की उसधारा (4) द्वारा प्रधत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश वेती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का श्रिधकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजान भारतीय गैस प्राधिकरण कि. में सभी बाधाश्रों से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख से निहित होगा।

अनुसूची

विजयपुर (म. प्र.) से सवाई माधोपुर (राज.) तक **पाइप** लाइन बिछाने के लिए

राज्य: राजस्थान जिला: कोटा तहसील: छबड़र

गांव खोप र	खसरा न.		श्रार सेन्टीश्रार	
	39	0	02	38
	40	0	05	35
	41	0	17	23

1	2	3	4	5
	43/475	0	01	0 6
	43/476	0	80	01
	45	0	50	38
	46	0	04	75
	112	0	36	18
	434	0	04	75
	419	0	17	23
	418	0	0.0	78
	420	1	16	53
	423	0	45	44
	416	0	19	01
	424	0	21	09
	449	0	23	11
	450	0	52	27
	451	0	25	84
	452	0	00	08
	448	0	16	34
	111	0	00	35
	47	0	07	13
	48	0	00	71
	453	0	06	45
	425	0	05	10

[सं. O-14016/94/85-जी. पी.]

S.O. 1513.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy. Department of Petroleum S.O. 877 dated 19-2-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Subsection (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by subsection (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests from this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Bijaipur (M.P.) to Sawai Madhopur (Raj.) State: Rajasthan District Kota Tehsil Chabra

Village	Survey No.	Hectare	Are	Cen- tiare
Khopar	39	0	02	38
	40	0	05	35
	41	0	17	23
	43/475	0	01	06
	43/476	0	80	01
	45	0	50	38
	4 6	0	04	75
	112	0	36	18
	434	0	04	75
	419	0	17	23
	418	0	00	78
	420	1	16	53
	423	0	45	44
	416	0	19	01
	424	0	21	09
	449	0	23	11
	450	0	52	27
	451	0	25	8-
	452	0	00	08
	448	0	16	34
	111	0	00	35
	47	0	07'	13
	48	0	06	71
	453	0	00	4:
	425	0	05	10

INo. O-14016/94/85-GPI

का. अा. 1514:—यतः पेट्रोलियम भौर खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का भर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की घारा 3 की उपधारा (1) के अधीन ारत सरकार के ऊर्जा मंद्रालय पेट्रोलियम वि गण की अधिसूचना का आ, सं. 878 तारीख 19-2-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिधिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को विछाने के प्रयोजन के लिए अजित करने का अपना आश्य घोषित कर दिया था।

भौर यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त श्रिधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के श्रिधीन सरकार को रिपोर्ट दे वी है।

श्रौर श्रागे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस श्रधिसूचना से संलग्न श्रनुसूची में विनिधिष्ट भूमियों में उपयोग का श्रधिकार श्राजित करने का विनिश्चय किया है।

श्रव, श्रत: उक्त श्रधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस श्रधिसूचना में संलग्न श्रनुसूची में विनिधिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का श्रधिकार पाइप लाइन विछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा श्रिजित किया जाता है।

श्रीर श्रागे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश वैती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का श्रिधकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय शारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाश्रों से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख से निहित होगा।

अनुसूची

्ৰ विजयपुर (म. प्र.) से सवाई माधोपुर (राज.) तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य: राजस्थान जिला: फोटा तहसील: छवड़ा

^ए गांध	खमरान.	हे क्ट र	भ्रार —	सेंटीभार
हनुवंत खेड़ा	134	0	5 5	64
•	135	0	45	14
	136	0	45	14
	141	0	03	71
	142	0	42	95
	143	0	31	60
	132	0	49	01
	133	0	24	65
	134/450	0	00	20
	138	0	07	72

सिं. O-14016/95/85-जी. पी.]

S.O. 1514.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S.O. 878 dated 19-2-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Subsection (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government.

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by subsection (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Sentral Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests from this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Bijaipur (M.P.) to Sawai Madhopur (Raj.) State: Rajasthan District: Kota Tehsil: Chabra

Village	Survey No.	Hectare	Are	Con- tiare
Hanwant Kheda	134	0	55	64
	135	0	45	14
	136	0	45	14
	141	0	03	71
	142	0	42	95
	143	0	31	60
	132	0	49	01
	133	0	24	65
	134/450	0	00	20
	138	0	07	72

[No. O-14016/95/85-GP]

का. आ. 1515:—यत: पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन), अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय, पेट्रोलियम विभाग को अधिसूचना का. आ. सं. 879 तारीख 19-2-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिविष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अजित करने का अपना आश्रय घोषित किर विया था।

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यत. केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों मे उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अत: उक्त अधिनियम की घारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदक्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिमूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन विछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अजित किया जाता हैं।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्वेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाये भारतीय गैस आधिकरण लि में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख से निहित होगा।

	अन् सूर्च	Ť			
विजय पुर (स. प्र.) से सवाई माघोपुर (राज.) तक पाईप लाईन बिछाने के लिए। राज्य: राजस्थान, जिला: कोटा, तहसील: छबड़ा					
राज्य: राजस्था	न, जिला : कोटा,	तहसील : '	छब ड़ा		
गांव	खसरा ने.	हेक्टर	भार	सेंटीआर	
पीपल्या	222	0	11	11	
	223	o	64	45	
	224	0	17	82	
	225	0	07	13	
	226	0	05	64	
	230	0	03	27	
	240	0	23	64	
	241	0	33	30	
	238	0	60	70	
	237	0	00	08	
	235	0	23	30	
	234	0	39	32	
	320	0	14	60	
	322	0	06	88	
	321	0	45	61	
	ਜਿਂ O	-14016/9	6/85-3	———— ति. पी.ी	

[स. O-14016/96/85-जा. पा.]

S.O. 1515.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S.O. 879 dated 19-2-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the schedule appended to that notifica-tion for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Subsection (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in he said lands shall instead of vesting in Central Government vests from this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Bijapur (M.P.) to Sawai Madhopur (Raj.)

State: Rajasthan District: Kota Tehsil: Chabra

Village	Survey No.	Hectare		Centi- are
Piplva	222	0	11	11
	223	0	64	45
	224	0	17	

1	2	3	4	5
	225	0	07	13
	226	0	05	64
	230	0	03	27
	240	0	23	64
	241	U	33	30
	238	0	60	70
	237	0	00	08
	2 35	0	23	30
	234	0	39	32
	320	0	14	60
	322	0	06	88
	321	0	45	61
	IN ₀ O	14016/6	VE 10 E C	

[No. O—14016/96/85-G.P.]

का. आ. 1516:--यत: पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 3680 तारीख 30-10-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अजित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है। -

और आगे, यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अत: उक्त अधिनियम की घारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रवस णिक्त का प्रयोग करते हुए केन्द्रेय सरकार ण्**तवृद्धारा घोषित करती है** की इस अधिसूचना में सलग्न अनसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भ्मियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एनदृहारा अजिस किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषण के प्रकाणन की इस तारीस्त्र की निहित होगा ।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने केलिए।

राज्य-गुजरात जिला-एवं-तालुका-भरूच

गांव	सर्वे न०	हेक्टर	आर	— मेंन्टीयर
1	2	3	4	5
करजण	37	0	24	80
	कार्ट ट्रेंक	0	05	20
	38	0	08	64

1	2	3	4	5
,	40	0	42	40
	41	0	02	72
	62	0	02	72
	61	0	16	00
	63	0	16	80
	64	0	14	40
	65	0	13	76
	58	0	43	68
	57	0	20	00
	कार्ट द्रेक	0	05	95
	114	0	52	80
	117	0	32	00
	122	0	28	80
	123	0	18	40
	[सं. O-14	016/117/	84-जी.	पी.]

S.O. 1516.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 3680 dated 30-10-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land), Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Subsection (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government heerby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laving the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Hajira—Bareilly—Jagdishpur

State : Gujarat District & Taluka : Bharuch

Village	Survey No.	Hectare Are Centi- are		
1	2	3	3	
Karjan	37		24	80
	Cart Track	0	05	20
	38	0	08	64
	40	0	42	40
	41	0	02	72
	62	0	02	72
	61	0	16	00
	63	0	16	80
	64	0	14	40
	65	0	13	76

1	2	3	4	5
	58	0	43	68
	57	0	20	00
	Cart Track	0	05	95
	114	0	52	80
	117	0	32	00
	122	0	28	80
	123	Ō	18	40

का. आ. 151%.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि राजस्थान राज्य में विजयपुर (म. प्र.) से सवाई माधोपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यत: यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अत: अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अश्विनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदक्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना सागय एतद्वारा घोषित किया है।

बेशर्ते कि उक्त भूमि में हितबज्ञ कोई व्यक्ति, उस भूमि के तीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, सी एंड एम प्रभाग. एच. बी. जे. गैस पाइप लाइन परियोजना, 49, इन्द्रा कालोनी, सवाई माघोपुर की इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर न्यामित निर्दिष्टतया यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी मुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

विजयपुर (म. प्र.) से सवाई माधोपुर (राज.) तक पाईप लाइन बिछाने के लिए

राज्य: राजस्थान जिला: कोटा तहसील: पीपल्वा

गांव	खसरा न.	हेक्टर	आर	सेंटीआर ——
1	2	3	4	4
श्रीपुरा	130	0	18	15
	137	0	08	56
	241/133	0	03	00
	131	0	04	95
	134	0	13	50
	135	0	26	40

90

20

25

70

06

40 90

1	3	3	5	4
	152	· 0	17	34
	151	". 0	25	80
	154	0	13	80
	155	0	59	10
	156	0	17	10
	161	0	39	45
	162	0	0.5	25
	171	0	45	90
	174	0	34	20
	172	0	50	25
	159	0	14	70
	150	0	00	06
	129	0	02	40
	133	0	03	90
	[स. O-1	1016/184/	 8 5- जी .	पी.]

S.O. 1517.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Bijaipur (M.P.) to Sawai Madhopur in Rajasthan State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, H.B.J. Gas Pipeline Project, 49, Indra Colony, Sawai Madhopur.

And every person making such an objections shall also state specially whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Core Bligger (M. B.) to Sawai Madhlapur

Pipeline from Bijapur (M. P.) to Sawai Madhlopur (Raj.) State: Rajasthan District: Kota Tehsil Piplada

Village	Survey No.	Hect- are	Are	Centi- are
1	2	3	4	5
Shree Pura	130	0	18	15
	135	0	08	55
	241/133	0	03	00
	131	0	C4	95
	134	0	13	50
	135	0	26	40
	152	0	17	34
	151	0	25	80
	154	0	13	80
	155	0	59	10
	156	0	17	10
	161	0	39	45
	162	0	05	25

[No. O-14016/184/85-G.P.]

0

0

0

0

0

O

45

34

50

14

00

03

का. आ. 1518.— यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि राजस्थान राज्य में विजयपुर (म. प्र.) से सवाई माधोपुर तक पेट्रो-लियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन भारतीय गैस प्राधि-करण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

171

174

172

159

150

129

133

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपाबद्ध अनुसूची में बर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवण्यक है।

अन अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रतत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एत्र्द्रारा घोषित किया है।

वणतें कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्रतिध-कारी, तेल एवं प्राक्तिक गैम आयोग, सी एण्ड एम प्रभाग एच. बी. जे. गैस पाइप लाइन परियोजना, 49 इन्द्रा कालोनी, सवाई माधोपुर की इस अधिसूचना की तारीख में 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतय यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी मुनवाई व्यक्तिगत रूप में हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूचो विजयपुर (म. प्र.) से सवाई माधोपुर (राज.) तक पाईप लाईन बिछाने के लिए राज्य : राजस्थान जिल : कोटा तहसील : पीपल्दा

- गांव	खसरा न.	हेक्टर	आर	सेटीआर
1	2	3	4	5
	8	0	08	- — — 40
	10	0	40	24
	9	0	33	60
	107	0	13	95
	133	0	64	31
	131	0	37	50

1	2	3	4	5	specially whether	son making such an ob he wishes to be heard	jections si I in perso	hall als n or b	o state y legal
	121	0	00	16	practitioner.	SCHEDULF			
	132	0	33	11	TO 1			11	maix
	130	0	02	89	Pipeline from State : Rajas	Bijarpur (M.P.) to Si sthan District : Ko		inopui hsil: P	
	128	1	04	39					
	126	0	06	24	Village	Survey No.	Hect- are	Are C	aro
	127	0	29	46	Prempura .	8			40
			04	86	Tiempera .	10	ő		24
	179	0				9	0	33	60
	223	0	06	24		107	0		95
	224	0	°33	06		133 131	0		31 50
	593/179	0	00	24		121	0		16
	225	0	35	12		132	Ö		11
	227	0	23	18		130	0		89
			77			128	1	04	39
	228	1		17		126 127	0		24 46
	214	0	30	90		179	0		86
	210	0	03	45		223	ő	06	24
	422	0	05	18		224	0	33	06
	229	0	09	60		593/179	0	00	24
	411	1	53	45		225 227	0 0		12 18
	416	0	50	70		228	ĭ	77	17
						214	0	30	90
	415	0	24	00		210	0		45
	417	0	40	50		422	0		18
	420	0	60	15		229 411	0	09 53	60 45
	421	0	27	37		416	ò		70
	433	0	53	40		415	0		00
						417	0		50
	572	0	15,	60		420	0		15
	423	0	17	70		421	0		37
	424	0	12	12		433 572	0		40 60
	425	0	00	10		423	0		70
	226	0	04	10		424	0	12	12
	212		00	28		425	0		10
		0				226 212	0		10 2 8
	545	0	29	40		545	0		40
	544	0	22	80		544	ő		80

[सं. O-14016/185/85-जी. पी.]

S.O. 1518.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Bijaipur (M.P.) to Sawai Madhopur in Rajasthan State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of Use: in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, H.B.J. Gas Pipeline Project. 49. Indra Colony, Sawai Madhopur.

[No. O-14016/185/85-G.P.]

का. आ. 1519. — यत. केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि राजस्थान राज्य में विजयपुर (म.प्र.) में सवाई माधापुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची मे वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खिनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त गिक्तयों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना आश्रय एतदहारा घोषित किया है।

बशर्से कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधि-कारी, तेल एवं प्राकृतिक गैम आयोग, सी एण्ड एम प्रभाग. एच. बी. जे. गैस पाइप लाइन परियोजना. 49, इन्द्रा कालोनी, सवाई माधोपुर की इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

विजयपुर (म. प्र.) से सवाई माधोपुर (राज) तक पाईप लाईन विछाने के लिए

राज्य : राजस्थान, जिला : कोटा, तहसील : पीपल्दा

गांव	 खसरा नं.	— हेक्टर	 आर	
अयानी	529	0	18	18
	530	0	03	90
	534	0	32	66
	533	0	40	20
	528	0	00	20
	531	0_	39	30

[सं. O-14016/186/85-जीपी]

S.O. 1519.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Bijaipur (M.P.) to Sawai Madhopur in Rajasthan State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, H.B.J. Gas Pipeline Project, 49, Indra Colony, Sawai Madhopur.

And every person making such an objections shall also state specially whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Bijaipur (M. P.) to Sawai Madhopur (Raj.) State: Rajasthan District: Kota Tehsil: Piplada

Village	Survey No.	Hect- are	Are	Centi- are
Ayani	. 529	0	18	18
•	530	0	03	90
	534	0	32	66
	533	0	40	20
	528	U	00	20
	531	0	39	30

[No O-14016/186/85---GP]

का. आ. 1520. — यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि राजस्थान राज्य में विजयपुर (म.प्र.) से सवाई माधोपुर तक पेट्रो-लियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाबच्च अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अिबनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजिन करने का अपना आशय एसद्द्वारा घोषित किया है।

वशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, सी एण्ड एम प्रभाग, एच. बी. जे. गैस पाइप लाइन परियोजना, 49, इन्द्रा कालोनी, सवाई माधोपुर की इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्विष्टतया यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची विजयपुर (म.प्र.) से सवाई माघोपुर (राज.) तक पाईप लाईन बिछाने के लिए

राज्य: राजस्थान जिला: कोटा तहसील: पीप्रल्दा

गांव	खसरा नं.	हेक्टर	आर	सेन्टीआर
ण्योपुरा	102	0	41	40
	104	0	12	62
	108/203	0	31	86
	108	0	71	76
	108/221	0	00	16
	137	0	60	56
	136	0	53	92
	158	0	29	07
	159	0	77	85
	161	0	62	46
	160	0	15	60
	169	0	03	45
	170	0	73	63
	173	0	04	20
	172	0	83	75
	180	0	02	16
	166	0	06	75

[सं. O-14016/187/85-जीपी]

S.O. 1520.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interes, that for the transport of petroleum from Bijaipur (M.P.) to Sawai Madhopur in Rajasthan State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed bereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Constitution and Maintenance Division, H.B.I. Gas Pipeline, Project, 49, Indra Colony, Sawai Madhopur,

And every person making such an objections shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Bijaipur (M.P.) to Sawai Madhopur (Raj) State: Rajasthan District: Kota Tehsil: Piplada

State: Rajasthan	District : Kota	Tehsil: Piplada			
Village	Survey No.	Hect-	Are (enti- are	
Shyo Pura .	. 102	0	41	40	
- 2	104	0	12	62	
	108/203	0	31	86	
	108	0	71	76	
	108/221	0	00	16	
	137	Ó	60	56	
	136	0	53	92	
	158	0	29	07	
	159	0	77	85	
	161	0	62	46	
	160	0	15	60	
	169	0	03	45	
	170	0	73	63	
	173	0	04	20	
	172	0	83	75	
	180	0	02	16	
	166	0	36	75	

[No. O-14016/187/85-GP]

का. आ। 1521.—यत केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि राजस्थान राज्य में विजयपुर (म प्र.) से सवार्ड माधोपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन भारतीय गैंस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए;

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अन्सूची में वर्णित भिम में उपयोग का अधिकार अजित करना आवश्यक हैं:

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एनदद्वारा घोषित किया है:

बणतें कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधि-कारी, नेल एवं प्राकृतिक गैंस आयोग, सी एण्ड एम प्रभाग, एच. बी. जे. गैंस पाइप लाइन परियोजना, 49, इन्द्रा कालोनी, सवाई माघोपुर की इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ;

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतया यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहना है कि उसकी मुनवाई व्यक्तिगत रूप में हो या किमी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची विजयपुर (म प्र) से सवाई माधोपुर (राज) तक पाईप लाईन विकाने के लिए

राज्य: राजस्थान जिला: कोटा तहसील: पीपल्दा

गांव	खसरान.	हेक्टर	आर	सेन्टीआर
 अयाना	121	0	13	68
	128/1563	0	18	90
	128	0	08	40
	130	0	35	35
	129	0	01	60
	131	0	41	35
	132	o	16	20
	126	0	10	80
	147	0	07	40
	148	0	10	50
	125	0	02	40
	149	0	08	61
	146	0	04	50
	145	0	52	39
	151	0	00	20
	152	0	31	90

[मं. O-14016/188/85-जीपी]

S.O. 1521.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Bijaipur (M.P.) to Sawai Madhopur in Rajasthan State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pineline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, II.B J. Gas Pipeline Project, 49, Indra Colony, Sawai Madhopur.

And every person making such an objections shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Bijaipur (M.P.) to Sawai Madhopur (Raj.) State: Rajasthan District: Kota Tehsil: Piplada

State : realestimic	1517/1100 1 10//60		101111111111		
Village	Survey No.	Hect-	Are Centi-		
				_	
Ayana	121	0	13	68	
	128/1563	0	18	90	
	128	U	08	40	
	130	0	35	35	
	129	0	01	60	
	131	0	41	35	
	132	0	16	20	
	126	0	10	80	
	147	0	07	40	
	148	0	10	50	
	125	0	02	40	
	149	0	08	61	
	146	0	04	50	
	145	0	52	39	
	151	0	00	20	
	152	o	31	90	

[No. O -14016/188/85—GP]

का. आ. 1522.—यनः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि राज-स्थान राज्य में बिजयपुर (म. प्र.) में सवाई माधोपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. बारा बिछाई जानी चाहिए;

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को विछाने के प्रयोजन के लिए एतदृपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अफित करना आवश्यक है ;

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाष्टप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है;

बसर्ने कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधि-कारी, तेल एवं प्राकृतिक गैस अधीग, सी एण्ड एम प्रभाग, एच. बी. जे. गैस पाइप लाइन परियोजना, 49, इन्द्रा कालोनी, सवाई माधोपुर की इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा;

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टर्सथा सह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहना है कि उसकी मृनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

बिजयपुर (म. प्र.) से सवाई माधोपुर (राज.) तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य: राजस्थान जिला: कोटा महसील: पीपल्दा

 ्गाव	- खसरा नं.	 हेक्टर	— आ <i>र</i>	— सेन्टी- आर
 रघुनाथपुरा	36	0	78	30
	. 39	0	06	00
	38	0	09	30
	37	0	02	22
	 [सं ,	O-1401	6/189/8	5-जीपी]

S.O. 1522.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Bijaipur (M.P.) to Sawai Madhopur in Rajasthan State pipeline should be laid by the Gas Authority of India_Limited;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to a quite the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act. 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, H.B.I. Gas Pipeline Project, 49, Indra Colony, Sawai Madhopur;

And every person making such an objections shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Bijaipur (M.P.) to Sawai Madhopur (Raj.) State: Rajasthan District: Kota Tehsil: Piplada

t-	Are	Centi- are
0	78	30
U		
0	06	6 00
0	09	30
0	` 02	2.2
		0 <u>02</u> 016/189/8

का. आ. 1523:—अतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि राजस्थान राज्य में बिजयपुर (म.प्र.) से सवाई माधोपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइए लाइन भारतीय गैंस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए;

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ;

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962

का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त मिन्तयों का प्रयाग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकाः अजिन करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बमर्से कि उक्त भिम में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि कें नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप 4क्षम प्राधि-कारी, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, सी एण्ड एम प्रभाग, एच. र्व(, जे गैस पाइप लाइन परियोजना, 49, इन्द्रा कालांनी, सवाई माधोपुर की इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतया यह भी कैथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप में हो या किसी विधि व्यवसायी की

बिजयपुर (म. प्र.) से सवाई माधोपुर (राज) तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : राजस्थान जिला : कोटा तहसील : पीपल्दा					
गांव	खमरा नं.	हे क ्टर	आर	सेन्टी- आर	
कॉकरा	120	0	02	40	
	128	0	46	20	
	[सं .	O-1401	6/190/85	≔जीपी]	

S.O. 1523.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Bijaipu (M.P.) to Sawai Madhopu in Rajasthan State pipelme should be laid by the Gas Authority of India Limited;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (1) of the Section 2 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, H.B.J. Gas Pipeline Project. 49, Indra Colony, Sawai Madhopur.

And every person making such an objection, shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Bijaipura (M.P.) to Sawai Madhopur (Raj.) Tehsil: Piolada State . Rajaethan District: Kota

State . Rajastnan	District . Rota	Tonen : Tipaca			
Village	Survey No.	Hect- are	Are	Centi- are	
Kankara	, 120	0	02	40	
	128	0	46	20	
	[No.	O-14016	5/190/8	35- G P]	

का. आ. 1524. ---यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवण्यक है कि राजस्थान राज्य में बिजयपूर (म.प्र.) से सवाई माधोपूर तक पेट्रो-लियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन भारतीय गैस प्राधि-करण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यत. यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्रपाबद्ध अन्सूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) को धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त णक्तियां का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्-द्वारा घोषित किया है।

बणर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधि-कारी, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग सी एण्ड एम प्रभाग, एच. बी. जे. गैस पाइप लाइन परियोजना, 49, इन्द्रा कालोनी, सवाई माधोपुर की इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतया यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सनवाई क्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची बिजयपूर (म. प्र.) से सवाई माधोपूर (राज.) तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : राजस्थान जिला : कोटा सहसील : पीपल्दा खसरानं. हेक्टर आर सेन्टी-गांव आर 0 30 107 उम्मेक्षपुरा 108 0 30 109/134 0.7

00 90 80 109 00 17 70 110 164 20 13 20 169 20 0.4170 20 171

[मं. O-14016/191/85~जीपी]

S.O. 1524.—Wherether it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Bijaipur (M.P.) to Sawai Madhopur in Rajasthan State pipeline should be laid by the Gus Authority of India Limited;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of uses in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority. Oil & Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, H.B.I. Gas Pipeline Project, 49, Indra Colony, Sawai Madhopur.

And every person making such an objection shall also state specially whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Bijaipur (M.P.) to Sawai Madhepur (Raj.) State : Rajasthan District : Kota Tohsil : Piplada

Village	Survey No.	Hect- are	Are	Centi- are
Ummed Pura	. 107	0	30	00
	108	0	30	90
	109/134	0	07	80
	109	0	48	00
	110	0	17	70
	164	0	04	20
	169	0	13	20
	170	0	04	20
	171	0	07	20

[No. O-14016/191/85 -GP]

का. आ. 1525: — यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि राजस्थान राज्य में बिजयपुर (म.प्र.) से सवाई माधोपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा विछाई जानी चाहिए।

और यक्षः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची मे वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित करना आवस्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाष्टप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदक्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमे उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना आशय एतद्-द्वारा घोषित किया है।

बशतें कि उक्त भूमि में हितबढ़ कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधि-कारी, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयीग, सी. एष्ड एम. प्रभाग, एच. बी. जे. गैस पाइप लाइन परियोजना, 49, इन्द्रा कालोनी, सवाई माधोपुर की इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतया यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहना है कि उसकी -मुनवाई व्यक्तिगत रूप ये हो या किसी विवि व्यवशायी की मार्फत ।

अनुसूची

बिजयपुर (म. प्र.) से सवाई माधोपुर (राज.) तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : राजस्थान	जिला : कोटा	तह-	प्तील :	मांगरौल
गांव	खासरा नं.	हेक्टर	आर	
				आर
कुष्या	10	0	01	34
	8	0	14	41
	9	0	01	08
	7	0	01	77
	5	0	06	0 0
	4	0	00	30

[सं . O- 140 16/ 192/85-जीपी]

S.O. 1525.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Bijaipur (M.P.) to Sawai Madhopur in Rajasthan State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of the user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, H.B.I. Gas Pipeline Project, 49, Indra Colony, Sawai Madhopur.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Bijarpur (M.P.) to Sawai Madhopur (Raj.) State : Rajasthan District : Kota Thehsil : Mangrol

Starto I realmitin	DADMIEU : 170,		1110111711 1 17141		
Village	Survey No.	Hect- are	Are	Conti-	
Kushya		0	01	34	
	8	0	14	41	
	9	0	01	08	
	7	0	01	77	
	5	0	06	00	
	4	0	00	30	

[No. O-14016/192/85—GP]

का. आ. 1526: — यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि राजस्थान राज्य में बिजयपुर (म.प्र.) मे नवाई माधोपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाउप लाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यत: यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजींन के लिए एतदुपाबद्ध अनसूची मे वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित करना आवस्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि मे उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रवत्त मित्तयों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजिन करने का अपना आगय एनव्-द्वारा घोषिन किया है।

बणर्ते कि उक्त भूमि में हिनबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप प्राधिकारी, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, सी एण्ड एम प्रभाग, एच. बी. जे. गैस पाइप लाइन परियोजना, 49, इन्द्रा कालोनी, सबाई माधोपुर की इस अधिसूचना की नारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा!

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतया यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी मुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अमुसूची

बिजयपुर (म.प्र.) से सवाई माधोपुर (राज.) तक पाइप लाइन विछाने के लिए

राज्य: राजस्थान	ाजला∶क	दि त	हसील .	मागरील	
- गांव	खसरानं.	हेक्टर	आर	सेन्टी- आर	
 स्थाम <u>गु</u> रा	342	0	0.5	25	
	340	0	10	80	
	333	0	15	75	
	332	0	48	15	
	330	0	06	21	
	327	0	32	22	
	322	0	43	68	
	150/2	0	16	08	
	229	0	07	92	
	150/1	0	35	70	
	154	0	42	00	
	158	0	33	0.6	
	156	0	00	72	
	157	0	28	32	
	181	0	11	40	
	18 ?	0	13	80	
	185	0	0.0	64	
	184	0	16	61	
	183	0	03	45	
	186	0	13	50	
	187	0	17	70	
	188	0	14	10	

शोख	खाथरा नं.	हे ग टर	भार	स्रेस्ट्।-
				आर
- *****	205	0	08	10
	191	0	02	25
	204	0	29	5 5
	192	0	53	5 5
	203	0	11	40
	172	0	07	10
	100	0	18	20
	10 4	0	02	60
	321	0	12	60
	339	0	02	70
	98	0	02	10
	99	0	00	30

[स. O-14016/193/83-जीपी]

S.O. 1526.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Bijaipur (M.P.) to Sawai Madhopur in Rajasthan State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission. Construction and Maintenance Division, H.B.J. Gas Pipeline Project, 49, Indra Colony, Sawai Madhopur.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Bijaipur (M.P.) to Sawai Madhopur (Raj.) State: Rajasthan District: Kota Tehsil: Mangrol

Village	Survey No.	Hect- are	Are	Conti- are
Shyam Pura .	. 342	0	05	25
_	340	0	10	80
	333	0	15	75
	332	0	48	15
	330	0	06	2
	327	0	3 2	23
	322	0	43	6
	150/2	0	16	0
	229	0	07	92
	150/1	0	35	7(
	154	0	42	00
	158	0	33	06
	156	0	00	72
	157	0	28	32
	181	0	11	40
	182	0	13	80
	185	0	00	64
	184	0	16	61
	183	g	03	45

_ 1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	186	0	13	5 0		51		14	70
	187	n	17	7 0		0.4	v	* 3	,,
	188	o	14	10		23	0	14	16
	205	0	08	10		22	1	05	28
	191	0	02	25					
	204	0	29	55		14	0	00	5 6
	192	0	53	55		11	0	34	50
	203	0	11	40		10	0	53	96
	172	0	07	10		10			
	100	0	18	20		7	0	12	00
	104	0	02	60		8	0	45	60
	321	0	12	60		-			
	339	0	02	70		5	0	33	00
	98	0	02	10		4	0	07	02
	99	0	00	30		1	0	05	58
	[No. O-	-14016/193/8	35GI	?]		12	0	00	04

[सं. O-14016/194/85- जीपी]

का. आ. 1527: — यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि राजस्थान राज्य में बिजयपुर (म.प्र.) से सवाई माधोपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि मैं उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रवत्त मिन्तयों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना आमय एतद्-द्वारा घोषित किया है।

बशर्तेकि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधि-कारी, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, सी एण्ड एम प्रभाग, एच. बी. जे. गैस पाइप लाइन परियोजना, 49, इन्द्रा कालोनी, सवाई माधोपुर की इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतया यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनसची

बिजयपुर (म. प्र.) से सनाई माधोपुर (राज.) तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य राजस्थान	:जिला: कं	ोटा तः	हसील :	मांगरील
गांव	खसरा नं.	हेक्टर	आर	सेन्टी- आर
पाङ्सिया	19	0	06	60
	20	0	94	48
1796 GI/84	-8	- 		

S.O. 1527.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Bijaipur (M.P.) to Sawai Madhopur in Rajasthan State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, H.B.J. Gas Pipeline Project, 49, Indra Colony, Sawai Madhopur.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Bijaipur (M.P.) to Sawai Madhopur (Raj.) State: Rajasthan District: Kota Tehsil: Mangrol

			_ • · ·			
Villago			Survey No.	Hect- are	Are	Centi- are
Padliya			. 19	0	06	30
			20	0	94	48
			51	0	14	70
			23	0	14	16
			22	1	05	28
			14	0	00	56
			1 l	0	34	50
			10	0	53	96
			7	0	12	00
			8	0	45	60
			5	0	33	00
			4	0	07	02
			1	0	05	58
			12	0	00	04

[No. O-14016/194/85-GP]

का. आ 1528: यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि राजस्थान राज्य में बिजयपुर (म. प्र.) से सवाई माधोपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खानिज पाईप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना आशय एतद्- द्वारा घोषित किया है।

षणतें कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिक्षारी, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, सी एंड एम प्रभाग, एच. बी. जे. गैस पाइप लाइन परियोजना, 49, इन्द्रा कालोनी, सवाई माधोपुर की इस अधिसूचना की तारीख से 21 विनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतया यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत

अमुसुधी

बिजयपुर (म.प्र.) से सवाई माधोपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : राजस्थान	जिला : कोटा	. त ह र	ील∶ ग	मांगरील —
गांव	खसरा मं.	हेक्टर	आर	सेन्टी- आर
1	2	3	4	5
चन्द्रा हेड़ी	139	0	05	94
	138	0	18	84
	137	1	22	28
	103	0	10	84
	104	0	33	60
	72	0	10	50
	74	0	42	35
	73	0	01	45
	47	0	00	12
	48	0	48	90
	39	0	87	00
	40	0	59	40
	17	0	57	84
	18	0	00	96
	16	0	41	34
	21	0	09	60
	14	0	02	30
	10	0	09	14

1	2	3	4	5
	11	0	01	76
	7	0	0.5	42
	6	0	04	40
	12	0	18	28
	15	0	0.0	36
	105	0	00	80
	8	0	03	00
				- —

सिं. O-14016/195/85-जीपी]

S.O. 1528.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Bijaipur (M.P.) to Sawai Madhopur in Rajasthan State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, H.B.J. Gas Pipeline Project, 49, Indra Colony, Sawai Madhopur.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be hear l in person or by legal practitioner.

Pipeline from Bijaipur (M.P.) to Sawai Madhopur (Rai.)

SCHEDULE

[No. O-14016/195/85-GP]

का. था. 1529.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोक हित में यह आवश्यक है कि राजस्थान राज्य में बिजथपुर (म.प्र.) से सवाई माधोपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन भारतीय गैं सप्राधिकरण लि. बारा बिछाई जानी चाहए;

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्बद्ध अनुसूची में विणत भूमि में उपयोग का अधिकार अजित करना आवश्यक है;

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 को उपधारा (1) ब्रारा प्रदत्त मिनन्यों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने गा अपना आशय एतद्द्रारा घोषित किया है:

बंशतें कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधि शारी, तेल एवं प्राइतिक गैन आयोग, भी एंड एम प्रभाग, एच. बी. जे. गैंस पाइप लाइन परियोजना, 49, इंप्राद्रा कालोनी, सवाई माधापुर की इन अधिमूचना की नारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टनया यह भी कथन करेगा िक क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनूसुची विजयपुर (म.प्र.) से सवाई माधोपुर (राज.) तक पाइपलाइन बिछाने के लिए

राज्य : राज	स्थान जिलाः	कोटा तहस	ील :	मागरौल
गांव	खसरा नं.	हेक्टर	आर	सेंटीअर
1	2	3	4	5
श्रीनाल च क	बी 83	0	84	19
	83/94	0	01	00
	65	0	05	00
	68	0	09	00
	81/93	0	17	31
	82	0	04	00
	69	0	13	20
	67	0	00	40
	70/92	0	22	20
	70	0	36	30
	47	0	72	00
	48	0	13	50
	27/8 7	0	49	06
	25	0	01	04
	24	0	41	10
	21	0	26	40

3	4	5
0	26	28
0	30	60
0	19	80
0	30	30
0	04	00
o	02	00
0	07	50
0	00	42
	0 0 0 0 0	0 26 0 30 0 19 0 30 0 04 0 02 0 07

[सं. O-14016/196/85-जी पी]

S.O. 1529.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Bijaipur (M.P.) to Sawai Madhopur in Rajasthan State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein:

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, H.B.J. Gas Pipeline Project, 49, Indra Colony, Sawai Madbopur.

And every person making such an objections shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Bijaipur (M.P.) to Sawai Madhopur (Raj.) State: Rajasthan District: Kota Tehsil Mangrol

State . Rajasinan	District . Kota	roman minnig		
Village	Survey No.	Hect- are	Are	Centi- are
Srl Nal Chak B .	. 83	0	84	19
	83/94	0	01	00
	65	0	05	00
	68	0	09	00
	81/93	0	17	31
	82	0	04	
	69	0	13	20
	67	0	00	40
	70/92	0	22	
	70	0	36	30
	47	0	72	00
	48	0	13	
	27/87	0	49	06
	25	0	01	04
	24	0	41	10
	21	0	26	
	20	0	26	
	6	0	30	60
	7	0	19	
	8	0	30	
	9	0	04	-
	10	0	02	
	12	0	07	
	19	0	00	-

[No. O-14016/196/85-GP]

का. आ. 1530.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्य है है कि राजस्थान राज्य में बिजयपुर (म.प्र.) से सवाई माधोपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपाबद्ध अनुसूची में विणित भूमि में उप-योग का अधिकार अजित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) ब्रारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्ब्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना आशय एतद्द्रारा घोषित किया है:

बगतें कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग सी एंड एम प्रभाग, एच. बी. जे. गैस पाइपलाइन परियोजना, 49, इन्द्रा कालोनी, सवाई माधोपुर की इस अधिमूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतया यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या कितो विवि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूच। विजयपुर (म.प्र.) से सवाईमाधोपुर (राज.) রফ पापइलाईन बिछाने के लिए

राज्य : रा	_जिला_ः कोटा	तहसील मांगरौर			
गांव	खसर	ा न <u>ं</u> .	हेक्टर	आर	सेंटो आ र
श्री नील चन	0е уз		0	06	90
	89		0	12	30
	8 7		0	06	76
	88		0	08	32
	83		0	47	08
	84		0	47	64

[सं. O-14016/197/8 5-जी पी]

S.O. 1530.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Bijaipur (M.P.) to Sawai Madhopur in Rajasthan State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein:

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, H.B.J. Gas Pipeline Project, 49. Indra Colony, Sawai Madhopur.

And every person making such an objections shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Bijapur (M.P.) to Sawai Madhopur (Raj.) State: Rajasthan District: Kota Tehsil: Mangrol

Village	Survey No.	Hect- are	Are	Centi- are
Sri Nal Chaka .	. 90	0	06	90
	89	0	12	30
	87	0	06	76
	88	0	08	32
	83	0	47	08
	84	0	47	64

[No. O-14016/197/85-GP]

का. आ. 1531 - यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोशहित में यह आवश्यक है कि राजस्थान राज्य में बिजअपुर (म.प्र.) से सवाई माधोपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन भारतीय गैंस प्राधिकरण लि. बार बिछाई जानी चाहिए;

और यतः यह प्रतीत होता है कि एसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लियं एतदुपाबद अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित दणना आवण्यक है;

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) बारा प्रवत्त मक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना आणय एतद्द्रारा धोषित किया है:

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल एवं प्राःनिक गैस आयोग, सी एंड एम प्रभाग, एच. बी. जे. गैस पाइप लाइन परियाजना, 49, इंद्रा कालोनी, सवाई माधोपुर की इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीनर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतया यह भी कथन करेग कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप में हो या किसी विधि व्यक्तायी की मार्फत।

अनु सूची

विजयपुर (म.प्र.) सं सवाई माधोपुर (राज.) तक पाइप लाईन विकान के लिए

राज्य : राजस्थान जिला : कोटा तहसील : मागरौल

गांव	खसरा नं .	हेक्टर	आर	संटीआर
महुआ	201	0	39	30
•	194	0	75	06
	192	0	19	20
	191	0	33	5 0
	197/2	0	03	30
	193	0	00	04
	193		00	

[स. O-14016/198/85-जी पी)]

S.O. 1531.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Bijaipur (M.P.) to Sawai Madhopur in Rajasthan State pipeline should be laid by the Cias Authority of India Limited;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein:

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, H.B.J. Gas Pipeline Project 49, India Colony, Sawai Madhopur.

And every person making such an objections shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Bijapur (M.P.) to Sawai Madhopur (Raj)

State: Rajasthan	District: Kot	a Tchs	Tehsil: Mangro		
Village	Survey No.	Hect- are	Are	Conti- are	
Mahuwa	. 201	0	39	30	
	194	0	75	06	
	192	0	19	20	
	191	0	33	50	
	197/2	0	03	30	
	193	0	00	04	

[No. O-14016/198/85-GP]

का. आ. 1532. — यत केन्द्रीय गरशार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि राजस्थान राज्य में बिजयपुर (मं प्र.) में नवाई माधोपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन भाग्तीय गैंस प्राधिकरण लि. हारा बिछाई जानी चाहिए;

और यन: यह प्रतीत होता है शि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपावद अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित करना आवश्यक है; अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपनाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त णक्तियों का प्रयोग करने हुए केन्द्रीय सरकार ने उ.में उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना आणय एतद्वारा घोषित थिया है:

बगर्ते कि उक्न भूमि में हितवढ कोई व्यक्ति, उस भूमि के तीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए अक्षीप सक्षम प्राधिकारी, तेल एवं प्राःतिक गैस आयोग, भी एंड एम प्रभाग, एच. बी. जी. गैस पाइपलाइन परियोजना, 49, इंद्रा जालोनी, सवाई माधोपुर की इस अधिसूचना की तारीख ने 21 दिनों के भीतर कर सकेगा;

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति निर्निदेष्टतया यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहा। है कि उनको मुनवाई व्यक्तिगत रूप ने हा या िता निर्मि व्यवतायी की मार्फत।

अनुसूची
विजयपुर (म.प्र.) से सवाई माधोपुर (राज.)
तक पाईपलाईन विछाने के लिए

राज्य:	राजस्थान	जिला. कोटा	तहर	तित:	मागरील
गाव	खस	 स. न.	हक्टर	आर	संटीआर
 बोहत	42		0	33	08
•	49		0	65	62
	57		0	44	19
	50		0	04	76
	44		0	46	77
	45		0	00	06
	43		0	33	87
	41		0	05	56

[सं. O-14016/199/-85 जी.पी.]

S.O. 1532.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Bijaipur (M.P.) to Sawai Madhopur in Rajasthan State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein:

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, H.B.J. Gas Pipeline Project, 49, Indra Colony, Sawai Madhopur.

And every person making such an objections shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

		Bijapur	CHEDULI (M.P.) t District :	o Sawai I			r (Raj. [angrol
Village		Su	rvey No.	H _e		Aro	Centi- are
Bohat .	- <i>-</i>		42		0	33	08
			49		0	65	62
			57		0	44	19
			50		0	04	76
			44		0	46	77
			45		0	00	06
			43		0	33	87
			41		0	05	56

[No. O-14016/199/85-GP]

का. आ. 1533.—यत केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित मे यह आश्यक है कि राजस्थान राज्य में बिजयपुर (म.प्र.) से सवाई माधोपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के लिये एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित करना आवण्यक है।

अतः अब पेट्रांलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962, (1962, का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अन्ना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है:

बशर्ते कि उक्त भूमि में हिनबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, सी एंड एम प्रभाग, एच. बी. जे. गैस पाइप लाइन परियोजना, 49, इंद्रा कालोनी, सवाई माधोपुर की इस अधिसूचना को तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतया यह भी कथन करेगा कि क्या तह यह चाहता है कि उसकी मुनवाई व्यक्तिगत रूप से हा या किभी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अन्सूची

विजयपुर (म.प्र.) से सवाई माधोपुर (राज.) सक पाईप लाईन बिछाने के लिए

राज्य , राजस्थान जिल		कोटा तहस	ালি :	मागरौल
गाव	खसरानं.	=== =================================	आर	सेंटीआर
 हिगोंनिया	221	0	32	10
	215	0	32	40
	217	1	00	79

2	3	4	5
218	0	25	50
190	0	00	28
188	0	30	48
46	0	00	10
45	0	06	80
44	0	09	60
43	0	10	20
	218 190 188 46 45	218 0 190 0 188 0 46 0 45 0 44 0	218 0 25 190 0 00 188 0 30 46 0 00 45 0 06 44 0 09

[सं. O-14016/200/85-जी. पी.]

S.O. 1533.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Bijaipur (M.P.) to Sawai Madhopur in Rajasthan State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therin.

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, H.B.J. Gas Pipeline Project, 49, Indra Colony, Sawai Madhopur.

And every person making such an objections shall also state specifically whether be vishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Bijapur (M.P) to Sawai Madhopur (Raj.) State: Rajasthan District: Kota Tehsil Mangrol

Village	Survey No.	Hect- are	Are	Conti- are
Hingonia	. 221	0	32	10
-	215	0	32	40
	217	1	00	79
	218	0	25	50
	190	0	00	28
	188	0	30	48
	4 6	0	00	10
	45	0	06	80
	44	0	09	60
	43	0	10	20

[No. O--14016/200/85-GP]

का. आ. 1534.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि राजस्थान राज्य में बिजयपुर (म.प्र.) से सवाई माधोपुर तक पेट्रोलियम के परियहन के लिए पाइप लाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी शाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित करना आवश्यक है। अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आश्रय एतद्द्वारा घोषिस किया है।

बंशर्ते कि उक्त भूमि में हिसबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, सी एंड एम प्रभाग, एच. बी. जे. गैस पाइप लाइन परियोजना, 49, इंद्रा कालोनी, सवाई माधोपुर की यस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिधिष्टतया यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

विजयपुर (म.प्र.) से सवाईमाधोपुर (राज.) तक पाईप
लाईन बिकाने के लिए

राझ्य	राजस्थान	जिला	कोटा	तहसील	मांगर	.ौल
गांव	खस	रानं.	हेबटर		आर	संटीआर
चैनपुरि	रया 144	1		0	09	00
	228	3		0	09	60
	145	6/2		0	39	60
	145	i/1		0	24	00
	145	3		0	23	40
	146	;		0	38	40
	147	•		0	26	40
	176	3		0	27	15
	178	3		0	26	52
	174	ļ		0	21	16
	173	3		0	10	07
	172	2		0	0.3	30
	167	•		0	29	70
	168	3		0	10	80
	166	;		0	29	10
	165	i		0	26	40
	163	3		0	34	50
	194			0	57	00
	195	i		0	02	10
	207	1		0	06	22
	196	i		0	11	10
	205	;		0	45	08
	204	<u> </u>		0	45	60
	198	;		0	41	90
	199) 		0	01	00

गांव	खसरा न.	ह े क्ट र	आर सेटीआर	
	75	— 0	${02}$	00
	76	0	0.2	09
	74	0	07	26
	73	0	0.5	20

[付. O-14016/201/85~ff. 介.]

S.O. 1534.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Bijaipur (M.P.) to Sawar Madhopur in Rajasthan State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited;

And whereas it appears that for the purpose of laving such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the nipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, II B J. Gas Pipeline Project, 49, Indra Colony, Sawai Madhopur

And every person making such an objection, shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE
Pipeline from Bijapur (M.P.) to Sawai Madhopur (Raj.)
State : Rajasthan District : Kota Tabell Margarita

State: Rajasthan	District: Kot	a Tehsil M	Mangrol
Village	Survey No.	Hect- Are	Cneti-
		are	are
Chainpuria	. 144	0 0	00
	228	0 0	
	145/2	0 39	
	145/1	0 2	
	145/3	0 23	
	146	0 38	-
	147	0 20	
	176	0 2	
	178	0 20	_
	174	0 21	
	173	0 10	
	172	0 03	
	167	0 29	
	168	0 10	-
	166	0 29	
	165	0 26	
	163	0 34	
	194	0 57	7 00
	195	0 02	
	207	0 06	
	19 <i>6</i>	0 11	
	205	0 45	
	204	0 45	60
	198	0 41	
	199	0 01	00
	75	0 02	00
	76	0 02	
	74	0 07	26
	73	0 05	
	[No. O-	-14016/201/85	— GP]

का, आ. 1535 .—यतः केन्द्रोय सरकार को यह प्रतीत हाता है कि लोकाहन में यह प्रावण्यक है कि मध्यप्रदेश राज्य में हजीरा—वरेलों से जगदीशापुर तक पेट्रोंकाम के परिवहन के लिये पाइप लाइन भारतीय गैंस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिये।

श्रीर यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबड श्रनुसूची में विणित भूमि मे उपयोग श्रधिकार श्रीजित करना श्रावश्यक है।

श्रतः श्रव पेट्रांलियम श्रीर खनिज पाइप लाइन (भूमि मे उपयांग के अधिकार का श्रजंन) श्रिधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की अपधारा (1) द्वारा प्रधत्त सिक्तयों का प्रयाग करते हुए केन्द्रीय मरकार ने उसमें उपयोग का श्रिधकार श्रजित करने का अपना श्राशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बगतें कि उकत भूमि में हितबढ़ कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधि-कारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस श्रायोग, एच. बी. जे. पाइप लाइन, 45, मुभाष नगर, सांवेर रोड, उज्जैन (म.प्र.) 456001 को इस अधिसुचना की तारीख 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

श्रीर ऐमा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिधिष्टत: यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी मुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

एच. बी. जे. गैस पाईप लाईन प्रोजेक्ट

ग्राम खिरिरा साहब तहसील भांडेर जिला ग्वालियरराज्य (मध्य प्रदेश)

(48						
श्रनु सूची						
ध्रनु. खसरा नं. 1 ऋ.	उपयोग श्रधिकार अर्जन का क्षेत्र (हैक्टर्स में)					
1. 634/2	0.275					
2. 635	0.260					
यागः कुल क्षेत्रफल	0.535					
	[सं. O-14016/202/85-जी पी]					

S.O. 1535.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that the transport of petroleum from Hazira-Bareilly to Jagdishpur in Madhya Pradesh State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited,

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government bereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gus Commission, HBJ Gas Pipe Line, 45, Subhash Nagar, Sanwer Road, Ujjain, (M.P.).

And every person making such an objections shall also state specifically whether he wishes to be board in person or by legal practitioner.

HBJ GAS PIPELINF PROJECT

Village Khiriya Sahab Tehsil : Bhander Distt. Gwalio
SCHEDULE

Sl. No	Survey No.		Area to be acquired for R.O.U. in Hector
1.	634/2		0.275
2.	635		0.260
	Tot	al Area	0.535
_		[N	o O—14016/202/85—GPI

का. थ्रा. 1536 .— यतः केन्द्रीय सरकारको यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह ग्रावश्यक है कि मध्यप्रदेश राज्य में हजीरा-बरेली से जगवीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन भारतीय गैंम प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

श्रीर यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग श्रधिकार श्रीजित करना श्रावश्यक है।

ग्रतः श्रव पेट्रोलियम श्रौरखितज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के श्रिष्ठकार का श्रजेंन) श्रीष्ठित्यम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का श्रिष्ठकार श्रीजित करने का श्रपना श्राशय एतद्द्रारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के तीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, एच. बी. जे. पाइप लाइन, 45, मुभाष नगर, मांबेर रोड, उज्जैन (म.प्र.) 456001 को इस अधिसूचना की तारीख 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

श्रीर ऐसा श्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिधिष्टत: यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहका है कि उस की सुन-वाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

D Wee	सीठ	चे०	र्गे म	पार्श्वप	लाई≃	प्रोजेक्ट
V VIV	will	On V	ч 🗆	7197	1100	A 1017G

ग्राम	 पिपरौवा	खुर्द	तहसील	भांडेर	 जिला	 ग्वालियर
		Ū				(मध्य प्रदेश)

	ग्रनुसूची			
—	खसरा नं. 1	अपयोग श्रधिकार श्रर्जन का क्षेत्र (हैक्टर्स)		
1.	6	0.493		
2.	4	0,585		
3.	1 2	0,035		
4.	19	1.044		
5.	21	0.178		
6.	22	0,408		
7.	5	0.002		
य	ािग : कुल क्षेत्रफल	2.745		

[सं. O-14016/203/85-जी पी]

S.O. 1536.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hazira Bareilly to Jagdishpur in Madhya Pradesh State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act. 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, HBJ Gas Pipe Line, 45, Subhash Nagar, Sanwer Road, Ujjain, (M.P.).

And every person making such an objections shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

HBJ GAS PIPELINE PROJECT

Village: Piprauva Khurd Tohsil: Bhander Distt. Gwalior

SCHEDULE

		SCHE	DULE
SI. No.	Survey	No.	Area to be acquired for R.O.U. in Hector
1.	6		0.493
2.	4		0.585
3.	12		0.035
4.	19		1.044
5.	21		0.178
6.	22		0.403
7. –	5 		- 0.002
		Total Area	2.745
_			[No. O—14016/203/85—GP]

का. था.1537 --यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह श्रावश्यक है कि मध्यप्रदेश राज्य मे हजीरा-भरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिये।

श्रीर यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध श्रनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग श्रधिकार श्रजित करना श्रावण्यक है।

श्रतः श्रव पेट्रोलियम श्रौर खंनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के श्रीधकार का श्रर्जन) श्रीधनियम, (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का श्रीधकार श्रीजित करने का श्रीपना श्रीणय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बणतें कि उक्त भूमि में हितते ग्रं कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस श्रायोग, एच. बी. जे. पाइप लाइन, 45, सुभाष नगर सांवेर रोड, उज्जैन (म.प्र.) 456001 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

भौर ऐसा भ्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

एच०वीं०जे०गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट

गाम निचरोली तहसील भांडेर जिला-ग्वालियर राज्य (म.प्र.)

ग्रनुसूची

नु. खमरानं. 1	उपयोग श्रधिकार अर्जन का क्षेत्र (हैक्टर्स में)
1. 2	0.157
2. 3 मीन	1.009
კ. 9 मीन	0.497
4. 10	0,569
5. 12	0.280
6. 18	0.342
7- 19	0.705
यागः कुल क्षेत्रफल	3.559
	[मं. 0-14016/304/85-जी पी]

SO. 1537—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hazira-Bareilly to Jagdishpur in Madhya Pradesh State pipeling should be laid by the Gas Authority of India I imited,

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, HBJ Gas Pipe Line, 45, Subhash Nagar, Sanwer Road, Ujjain, (M.P.).

And every person making such an objections shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

HBJ GAS PIPELINE PROJECT

Village : Nicharoli Tehsil : Bhander Distt. : Gwailio,

SCHEDULE

Si. No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U. in
140.		Hector
1.	2	0.157
2.	3 Meen	1 009
3.	9 Min	0.497
4.	10	0.569
5.	12	0.280
б.	18	0.342
7.	19	0.705
_	Total Area	3.559

[No. O--14016/204/85--GP]

का. आ. 1538.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह भ्रावश्यक है कि मध्यप्रदेश राज्य में हजीरा-बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन भारतीय गैंस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिये।

भौर यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध भ्रनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग ग्रधिकार अर्जित करना श्रावस्यक है।

श्रतः श्रव पेट्रोलियम श्रीर खिनिश पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के श्रीधकार का श्रार्जन) श्रीधिनियम, 1962 (1962 का 50) को धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें अपयोग का श्रीधकार श्रीजत करने का श्रीपना श्रीशय एतब्द्वारा घोषित किया है।

बगर्ते कि उक्त भूमि में हितबढ़ कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछ ने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, एच. बी. जे. पाइप लाइन, 45, सुभाष नगर सांबेर रोड, अज्जैन (म.प्र) 456001 को इस अधिसूचना की तारीख 21 दिनों के भीतर कर सकैगा।

श्रीर ऐसा श्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिधिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी मुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

एच. बी. जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट ग्राम डोंगर तहसील राघोंगढ़ जिला—गुना राज्य (मध्यप्रदेश

	भ्रनु सूचे।
भनु. ग्रसरा नं. 1	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र
	हैक्टर्स में)
1. 1	0.941
2. 134	0,031
3. 135	0.188
4. 136/1	0.147
5. 136/2	0.021
6. 140/1/1	0.167
7. 139	0.575
8. 141	0.021
9. 145	0.491
10. 147/2	0.010
11. 2	0.105
12. 147/1	0.010
13. 147/3	0.084
14. 148	0.439
15. 215/1	2.132
16. 245	0.031
17. 223/1	1.296
$18 \cdot 223/2$	1.118
19. 245	0,031
20. 225/1	2.278
$21. \ 243/2$	0.147
22. 241/1	0.136
23. 240	0,157
24. 238/2	0.261
25. 239	0.105
26. 237	0.272
27. 234/3	0.157
28. 225/2	6.081
29. 225/3	0.157
योगः कुल क्षत्रफल	9.592

[सं. O-14016/205/85-जीपी]

S.O. 1538.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Haziri-Bareilly to Jagdishpur in Madhya Pradesh State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipe Lines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein:

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipe line under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, HBJ Gas Pipe Line, 45, Subhash Nagar, Sanwer Road, Ujjain, (M.P.).

And every person making such an objections shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

HBJ GAS PIPE LINE PROJECT

Village : Dongar Tehsil : Raghogarh Distt. : Guna SCHEDULE

		SCHEDOL	
Sl. No.	Survey N	10.	Area to be Acquired for R.O.U. in Hector
1.	1		0.941
2.	134		0.031
3.	135		0.188
4.	136/1		0.147
5.	136/2		0.021
6.	140/1/1		0.167
7.	139		0.575
8.	141		0.021
9.	145		0.491
10.	147/2		0.100
11.	2		0.015
12.	147/1		0.010
13.	147/3		0.084
14.	148		0.439
15.	215/1		2.132
16.	245		0.031
17.	223/1		1.297
18.	223/2		1.118
19.	246		0.031
20.	225/1		2.278 0.147
21.	243/2		0.147
22.	241/1		0.157
23.	240		0.137
24.	238/2		0.105
25.	239		0.103
26.	237		0.272
27.	234/3		0.137
28. 29.	225/2 225/3		0.157
		Total Area	9.592

[No. 14016/205/85—GP]

का. आ. 1539.— -यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में हजीरा-बरेली थे जगदीणपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा विछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग अधिकार अजिन एरना आवश्यक है।

अतः अब पैट्रोलियम और खितिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उनमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना आशय एउद् द्वारा घोषित किया है।

वंशर्ते कि उक्त भूमि में हिनबद्ध कोई व्यक्ति, उत्त भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राक्ति गैस आयोग, एच. बी. जे. पाईप लाईन 45, सुभाप नगर सांवेर रोड़, उज्जैन (भ. प्र.) 456001 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप धरने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी मुनवाई व्यक्तिगत रूप से ही या िसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

एच. बी. जे. गैस पाईप लाईन प्रोजेक्ट

ग्राम उदयपूरी तहसील राघोगढ़ जिला-गुना राज्य (मध्य प्रदेश)							
अनुक्र. खन्नरा नं	. 1 उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेट (हैक्टर्स में)						
1. 30	0.219						
2. 41/4	0.094						
3. 40	0.230						
4. 41/5	0.167						
5. 42	0.052						
6. 43	0.261						
7. 44	0.136						
8. 46	0.010						
9. 51	0.564						
10. 56	0.021						
11. 80	0.031						
12. 90/1	0 199						
13. 97	0.010						
14 91	0.261						
15. 92	0.397						
16. 95	0.042						
17. 96	0.209						
18. 99	0.115						
19. 100	0.063						
20. 242	0.324						
21. 243	0.010						
22. 244	0.188						
23. 348	0.084						
24. 249	0.324						
25. 250	0.115						
26. 251	0.084						

1	2	3	
	252	0.397	
27. 28.	39	0.397	
29.	58	0.105	
30.	88/1	0.042	
यो	ग / कुल क्षेत्रफल	4.764	

[सं. O-14016/206/85---जी पी]

S.O. 1539.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hazira-Bareilly to Jagdishpur in Madhya Pradesh State pipe line should be laid by the Gas Authority of India Limited.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipe line, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein:

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipe line under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, HBI Gas Pipe Line, 45, Subhash Nagar, Sanwer Road, Ujjain, (M.P.).

And every person making such an objection, shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

HBJ GAS PIPE LINE PROJECT

Village: Udaypuri Tehsil: Rdghogarh Distt.: Guna

SCHEDULE

Sl.	Survey No.	Area to be Acquired			
No.		for R.O.U. in			
_		Hector			
1.	30	0.219			
2.	41/4	0.094			
3.	40	0.230			
4.	41/5	0.167			
5.	42	0.052			
6.	43	0.261			
7.	44	0.136			
8.	46	0.010			
9.	51	0.564			
10.	56	0.021			
11.	80	0.031			
12.	90/1	0.199			
13.	97	0.010			
14.	91	0.261			
15.	92	0.397			
16.	98	0.042			
17.	96	0.209			
18.	99	0.115			
19.	100	0.063			
20.	242	0.324			
21.	243	0.010			
22.	244	0 188			
23.	248	0.084			
24.	249	0.324			
25.	250	0.115			
26.	251	0 084			
27.	252	0.397			

1	2		-
28,	39	0.010	`
29.	58	0.105	
30.	88/1	0.042	
	Total Area	4.764	_
			٠.

[No. O-14016/206/85-GP]

का. आ. 1540.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है फि लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में हजीरा—बरेली थे जगदीणपुर तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन भारतीय गैंस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद् पाबद्ध अनुसूची में विणित भूमि में उपयोग अधिकार अजित करना आवश्यक है।

अतः अब पैद्रोलियम और खिनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार ना अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त मिन्तयों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजिन करने का अपना आगय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उत्त भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधि-कारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, एच. बी. जे. पाईप लाईन 45, सुभाष नगर सांवेर रोड़, उज्जैन (म. प्र.) 456001 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिविष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

एच. बी. जे. गैस पाईप लाईन प्रोजेक्ट ग्राम : विजयपूर तहसील : राघोगढ़ जिला : गुना राज्य (मध्य प्रदेश)

		अनुसूची
 अनुऋ .	खसरा नं.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षे त (हैक्टर्स में)
1.	406	0.240
2.	407	0.320
3.	410/1	0.105
4.	410/2	0.314
5.	411	0.105
6	417	0.083
7.	420/1 मी.	0,042
8.	420/1 मी.	0.167
9	420/1 मी. 	0.240

_1	2	3
10.	420/1 मी.	0,126
11.	420/2	0.031
12.	421	0.083
13.	422	0.021
14.	425	0.356
1 5.	426	0.220
16.	431	0.178
17.	432	0.397
18.	412	0.187
19.	416	0.198
20.	423	0.042
21.	430	0.011
22.	471	0.010
23.	4 18	0.378
24.	443	0.042
25.	464/1	0.167
26.	465	0.480
27.	467	0.021
28.	472/1 मी.	0.397
29.	473	0.356
30.	474	0.178
31.	476	0.083
32.	477	0.188
33.	478	0.439
34.	855 ₋ मी.	1,150
	कुल क्षेत्रफल —————	7.355
		

[सं. O-14016/207/85-जी पी]

S.O. 1540.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hazira-Bareilly to Jagdishpur in Madhya Pradesh State pipe line should be laid by the Gas Authority of India Limited.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipe line, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipe Lines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein:

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipe line under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, HBJ Gas Pipe Line, 45, Subhash Nagar, Sanwer Road, Ujjain, (M.P.).

And every person making such an objections shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

HBJ GAS PIPE LINE PROJECT

Village : Vijaypur Tehsil : Raghogarh Distt. : Guna
SCHEDULE

SI.	Survey No.	Area to be Acquired
No.		for R.O.U. in
		Hector
1.	406	0.240
2.	407	0.320
3.	410/1	0.105
4.	410/2	0.314
5.	411	0.105
6.	417	0.083
7.	420/1 M.	0.042
8.	420/1 M.	0.167
9.	420/1 M.	0.240
10.	420/1 M.	0.126
11.	420/2	0.031
12.	421	0.083
13.	422	0.021
14.	425	0.356
15.	426	0.220
16.	431	0.178
17.	432	0.397
18.	412	0.187
19.	416	0.198
20.	423	0.042
21.	430	0.011
22.	471	0.010
23.	418	0.378
24.	443	0.042
2 5.	464/1	0.167
26.	465	0.480
2 7.	467	0.021
28.	472/1 M.	0.397
29.	473	0.356
30.	474	0.178
31.	476	0.083
32.	477	0.188
33.	478	0.439
34. 	855 M.	1.150
	Total Area	7.255

[No. O-14016/207/85-GP]

का. श्रा. 1541 — यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह भ्रावश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में हजीरा—बरेली से जगदीशपुर तक पैट्रोलियम के परवहन के लिए पाइप लाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. हारा बिछाई जानी चाहिए।

श्रौर यतः यह प्रतीत होतः है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद् पाबद्ध श्रनुसूची में विणित भूमि में उपयोग श्रधिकार श्रजित करना श्रावश्यक है।

श्रतः श्रव पेंद्रोलियम श्रीर खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के शिधकार का अर्जन) श्रीधनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वाराप्रदत णिक्तयों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमे उपयोग का श्रधिकार श्रजित करने का अथना श्रःशय एतद्द्वारा घाषित किया है ।

बणतें कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप मक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, एच. बी. जे. प। लाईन 45, सुभाष नगर साबेर रोड़, उज्जैन (म. प्र.) 456001 को इस प्रधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

श्रीर ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिश्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

ग्राम कबूलपूरा तहसील राषांगकु जिला-गुना राज्य (मध्य प्रदेश)

एच, बी, जै: गैस पाईप लाईन प्रोजेक्ट

म अस

	श्रनु स् ची
श्रनुक. खसरा नं.	उपयोग प्रधिकार श्रर्जन का क्षेत्र (हैक्टर्समे)
1. 109	0.072
2. 24	0.042
3. 25	0.084
4. 26	0.126
5. 27	0.067
6. 28	0,094
7. 29	0.031
8. 36	0,136
9. 35	0.490
10. 34	0.031
11. 41	0.105
12. 48	0,240
13. 47	0.366
14. 51	0.742
15. 52	0.031
16.88	0,370
17. 86	0,345
18. 107/8	0.094
19. 107 में से	0.540
20.107/1	0.031
21. 37	0.010
22. 38	0.031
23. 45	0,010

0.021

0.021

0.010

योगः कुलक्षेत्रफल 4.140

24. 46

25. 53

26. 37

[सं. O--14016/208/85--जी पी]

S.O. 1541.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Pertoleum from Hazira-Barilly to Jagdishpur in Madhya Pradesh State pipe line should be laid by the Gas Authority of India Limited.

And whereas, it appears that for the purpose of laying such pipe line, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (1) of the Section 3 of the Petroleum and Mirerals Pipe Lines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of User therein:

Provided, that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipe line under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, HBJ Gas Pipe Line, 45, Subhush Nagar, Sanwer Road, Ujjain (MP.).

And, every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

HBJ GAS PIPE LINE PROJECT

Villa —	ige : Kabulpura	Tehsil: Raghogarh	Distt.: Guna
	·	SCHEDULE	
S. No.	Survey No.		Area to be Acquired for R.O.U. in Hector
1.	109		0.072
2.	24		0.042
3,	25		0.084
4.	26		0.126
5.	27		0.067
6.	28		0.094
7.	29		0.031
8.	36		0.136
9.	35		0.490
10.	34		0.031
11.	41		0.105
12.	48		0.240
13.	47		0.366
14.	51		0.742
15.	52		0.031
16.	88		0.370
17.	86		0.345
18.	107/8		0.094
19.	107 M.S.		0.540
20.	107/1		0.031
21.	37		0.010
22.	38		0.031
23.	45		0.010
24.	46		0.021
25.	53		0.021
26.	87	<u> </u>	0.010
7	OTAL AREA		4.140
		[No.	O-14016/208/85-GP]

का. था. 1542.—यतः केन्द्रीय सरकारको यह प्रतीत होता है कि लोंकहित में यह श्रावश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में हजीरा-बरेली से जगदीणपुर तक पैट्रोलियम के परिवहत के लिए पाइप लाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए। श्रीर यतः यह पतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध श्रनुस्ची मे विणत भूमि में उपयोग का श्रधिकार श्राजित करना श्रावण्यन है।

श्रतः श्रव पेट्रालियम श्रीर खिन्ज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के श्रिधकार का श्रर्जन) श्रिधनियम, 1962 (1962 का 50) को धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रथत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का श्रिधकार श्रिजित करने का श्रपना श्राणय एतद्-द्वारा घोषिन किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबढ़ कोई व्यक्ति, उस भूमि कें नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए अक्षेप सक्षम प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैंस श्रायोग, एच. बी. जे. पाइपलाइन 45, मुभाप नगर सावेर गेड़, उज्जैन (म. प्र)-456001 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनीं के भीतर कर सकेगा।

ग्रीर ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिद्धिटतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधिष्यवसायी की मार्फत,

एच०बी०जे० पाइप लाइन प्रोजेक्ट

ग्राम: भूमरा खेड़ी तहसील: राष्ट्रोगढ़: जिला: गुना राज्य (मध्य प्रदेश)

अनुसूची					
श्रनुक. यमगन.	उपयोग ग्रधिकार श्रर्जन का क्षेत्र (हैक्टर्म में)				
1. 29	0.261				
2. 27	0.010				
3. 30/3	0.307				
4. 13	0.010				
5. 170/1	0.052				
6. 171/1	1.766				
7. 172	0,157				
8. 170/2	0,490				
9. 170/3	0.533				
10 174/2	0.031				
11. 173/2	0.021				
यंगकुल क्षेत्रफल	3.638				

[सं. O--14016/209/85-जी पी]

SO. 1542.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hazira-Bareilly to Jagdishpur in Madhya Pradesh State pipe line should be laid by the Gas Authority of India Limited.

And whereas, it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals

Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of User therein;

Provided, that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, HBJ Gas Pipe Line, 45, Subhash Nagar, Sanwer Road Uljam (MP.).

And, every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be hear in person or by legal practitioner.

HBJ GAS PIPE LINE PROJECT

Village: Bhumarakhedi Tohsil : Raghogarh Distt : Guna **SCHEDULE** Survey No. Area to be Acquired for R.O.U. in Hector No. 1. 29 0.2612. 27 0.010 30/3 0.307 3. 4. 13 0 010 5. 170/1 0.0526. 171/1 1.766 7. 172 0.157 170/2 8. 0.4909. 170/3 0.533 10. 174/2 0.03111. 173/2 0.021 TOTAL AREA 3.638

[No. O-14016/209/85-GP]

न्या. आ. 1643.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्य-प्रदेश राज्य में हजीरा-बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. बारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों की बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद अनुसूची में विणित भूमि में उपयोग का अधिकार ऑजत करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खिनज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रवक्त शिक्तयों का प्रयोग करने हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना आणय एतद्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, नेल तथा प्राकृतिक गैम आयोग एच. बी. जे. पाईप लाईन 45, मुभाष नगर मांबेर रोड, उज्जैन (म. प्र.) 456001 को इस अधिमुचना की नारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने काला हर व्यक्ति विनिदिष्टत यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी

			_						_
सुनव।ई	व्यक्तिगत	रूप	मे	हो	या	किसी	विधि	व्यवसायी ः	की
मार्फत	t								

एच. बी. जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

भाम : भैसाना तहसीलः राघोगढ जिला-गुना राज्यः (मध्य प्रदेश)

अनुसूची			
अनुक. खसरा न	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षे (हैं क्टर्स में)	'ਜ' _	
1. 564	0.042		
2. 296/1	1.118		
3. 552/1	0.147		
4. 55/2	0.271		
5. 554	0,219		
6. 553	0.440		
7. 561	0.021		
8. 560	0.126		
9. 545 मी.	0.178		
10 545 मी.	0.021		
11. 565	0.052		
योग कुल क्षेत्रफ़ल	2,635		

[सं. O--14016/210/85-जी पी]

S.O. 1543.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hazira-Bareilly to Jagdishpur in Madhya Pradesh State pipe line should be laid by the Gas Authority of India Limited.

And whereas, it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of User therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission HBJ Gas Pipe Line, 45, Subhash Nagar, Sanwer Road, Ujjain (M.P.).

And, every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be hear in person or by legal practitioner.

HBJ GAS PIPE LINE PROJECT

Village : Bhesana	Tehsil : Raghogarh Distt : Guna	
\$CHEDULE		
S. Survey No. No.	Area to be acquired for R.O.U. in Hector	
1. 564	0.042	
2. 296/1	1.118	
3. 552/1	0.147	
4. 55/2	0.271	

	
1 2	3
5. 554	0.219
6. 553	0.440
7. 561	0.021
8. 560	0.126
9. 545 M.	0.178
10. 545 M.	0.021
11. 565	0.052
TOTAL AREA	2.635
	[No. O-14016/210/85-GP]

मा. आ. 1544.—-यतः केन्द्रीय सरकार की यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्य-प्रवेश राज्य में हजीरा-घरेली से जगदीश्रपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. हारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को विष्ठाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खानिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रवत्त मन्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना आगय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बणतें कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग एच. बी. जे. पाइप लाइन 45 सुभाष नगर सांवेर रोड़ उज्जैन (म. प्र.) 456001 को इस अधिमूचना की तारीखासें 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिदिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहत। है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप में हो या किसी विधि व्यवसायी की सार्फत ।

ए.च. बी. जे. गैंस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

। ाम : दौराना तहसील : राघोगढ़ जिलाः गुना राज्य : (मध्य प्रदेश)

अनुसूची			
अनु ऋ .	खसरा न.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेट (हैक्टर्म में)	
$\frac{}{1}$ $\frac{}{2}$		3	
1. 18		0.355	
2. 19		0.052	
3. 20		0.292	
4. 21		0.052	
5. 26		0.270	
6. 27		0.147	

1 2	3	·
7. 28	0.366	
8. 30	0.250	
9. 67/1	0.062	
10.72	0.220	
11. 74	0.021	
12. 75	0.147	
13.76	0.292	
14. 78	0.126	
15.84	0.031	
16. 93	0.721	
17. 99/2	0,184	
18. 99/3	0,126	
19. 10	0.302	
20. 102	0.157	
21. 111	0.043	
22. 112	0.126	
23. 123	0.031	
24. 124	0.031	
25. 125	0,031	
26. 155	0.084	
27. 156	0,043	
28. 164	0.418	
29. 15/2	0.021	
30. 17	0,031	
31. 80	0.083	
32. 103	0.010	
33. 99/1	0.010	
34. 71	0.010	
35. 165	0.073	
36. 166	0.043	
37. 167	0,021	
38. 171/1	01303	
39. 173	0.536	
40. 192	0.272	
41. 193	0.324	
योग कुल	भेत्रफ़ल 7.167	

ॉमं. O-14016/211/85-जी पी.]

S.O. 1544.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hazira-Bareilly to Jagdishpur in Madhya Pradesh State pipe line should be laid by the Gas Authority of India Limited.

And whereas, it appears that for the purpose of laving such pipeline, it is necessary to acquire the righ of user in the land described in the schedule annexed hereto:

Now, therefore, in express of the powers conferred by subsection (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquive the right of User therein;

1796 GJ/84--10

Provided, that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the public under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, HBJ Gas Pipe Line, 45, Subhash Nagar, Sanwer Road, Ujjain (M.P.).

And, every person making such an obejection shall also state specifically whether he wishes to be hear in person or by legal practitioner.

HBJ GAS PIPE LINE PROJECT
Village: Dorana Tehsil: Raghogarh Distt: Guna

SCHEDULE

	SCHEDULE
S. Survey No. No.	Area to be acquired for R.O.U. in Hector
1. 18	0 355
2. 19	0 052
3. 20	0.292
4. 21	0 052
5. 26	0.270
6. 27	0.147
7. 28	0.366
8. 30	0.250
9. 67/1	0.062
10. 72	0.220
11. 74	0.021
12. 75	0.147
13. 76	0.292
14. 78	0.126
15, 84	0.031
16. 93	0.721
17. 99/2	0.194
18. 99/3	0.126
19. 10	0.302
20. 102	0.157
21. 111	0.043
22. 112 23. 123	0.126 0.031
24. 124	0.031
25. 125	0.031
26. 155	0.084
27. 156	0.043
28. 164	0.418
29. 15/2	0.021
30. 17	0.031
31. 80	0 083
32. 103	0 010
33. 99/1	0 010
34. 71	0 010
35. 165	0 073
36. 166	0.043
37. 167	0 021
38. 171/1	0.303
39. 173	0.536
40. 192	0.272
41. 193	0.324
TOTAL AREA	7.167

[No. O-14016/211/85-GP]

का . आ . 1545.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में हजीरा—बरेली से जगवीशपर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन भारतीय गैस प्राधिकरण द्वारा बिछाई जानी चाहिये।

और यत: यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्गाबद्ध अनुसूची में विणित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि मे उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रवक्त मिल्लयों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आगय एतद्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबढ़ कोई ध्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, एच. थी. जे. पाइप लाइन 45, सुभाष नगर सांवेर रोड, उज्जैन (म. प्र.) 456001 को इस अधिसूचना की तारीख के 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत. यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप मे हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

एच. बी. जे. गैम पाइप लाइन प्रोजेक्ट ग्राम: ढाड तहसील: करेरा जिला—शिवपुरी राज्य (म.प्र.) अनुसूची

अनु ऋ .	खसरा नं.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हेक्टर्समें)
1.	164	0.860
2.	162	0.640
3.		
	163	0,420
4. •	157	0,420
5.	160	0.020
6.	159	0.020
7.	151	0.010
8.	152	0.120
9.	153	
10.	144	0.060
11.	57/2	0.484
12.	59	
13.	55	0.240
14	53	0.180
15.	6 5	0.960
16	64	0.150
17.	127	0,040
18.	124	0.720
Į 9.	75/3मी .	0.220
20.	101	0.120
21.	94/2	0.500

1	2	3
22.	92	0.540
23.	97/1	0.940
24.	97/2मी .	
25.	9 7/ 2मी .	0.500
26.	97/1145	0.060
27.	39	0.200
28.	40	0,030
29.	56	0.015
30⋅	74	0.080
31.	75/1	0.200
32.	75/2	0.250
33	7 5/ 3मी .	0.003
34.	75/4	0.200
35.	75/5	0.015
36	75/6	0.100
37.	75/7	0.050
38.	78/ 6	0.010
39.	158	0.136
40.	58	0.032
41	95	0.080
42	104	0.080
योग	-कुल क्षेत्रफल	9.562

[मं. O-14016/212/85-जी. पी.]

S.O. 1545.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hazua-Bareilly to Jagdishpur in Madhya Pradesh State pipe line should be laid by the Gas Authority of India Limited.

And whereas, it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of Use: in the Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of User therein;

Provided, that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Cormission HBI Gas Pipe Line. 45, Subhash Nagar, Sanwer Road, Uliam (M.P.).

And, every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be hear in person on by legal practitioner.

HBJ GAS PIPE LINE PROJECT Village · Dhand Tehsil : Karera Distt : Shivpuri SCHEDULE

S. No.	Survey No.	-			acquired Hector
	164 162			0.860 0 640	
3,	163				

	-
1 2	3
4. 157	0.420
5. 160 6. 159	0.020
7. 151	0.010
8, 152	0.120
9. 153	0.060
10. 144	_
11. 57/2	0.484
12. 59	
13. 55	0.240
14. 53	0.180
15. 65	0.960
16. 64	0.150
17. 127	0.040
18. 124	0.720
19. 75/3 M.	0.220
20. 101	0.120
21. 94/2	0 500
22. 92	0.540
23. 97/1	0.940
24. 97/2 M.	-
25. 97/2 M.	0.500
26. 97/1145	0.060
27. 39	0.200
28. 40	0.030
29. 56	0,015
30. 74	0.080
31. 75/1	0.200
32. 75/2	0.250
33. 75/3 M.	0.003
34. 75/4 25. 75/5	0.200 0.015
35. 75/5 36. 75/6	0.100
36. 75/6 37. 75/7	0.050
37. 73/7 38. 78/6	0.010
39. 158	0.136
	0.032
40. 58	0.032
41. 95 42. 104	0.080
TOTAL AREA	9.562
	[No. O-14016/212/85-GP]

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रयत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एनवृद्धारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनमूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एसदहारा अजित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय मरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाणन की इस तारीख से निहित होगा ।

अनुसूची विजयपर (म . प्र .) से सवाई माधोपुर (राज .) तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : राजस्थान जिला : कोटा तहसील : अटरू

VI-11 VI-11 VIII		46414	,.,	
गांव	खसरा नं.	हेक्टर	आर	संटीआर
बेडिकिया	189	0	01	95
	107	0	02	92
	136	0	02	44
	134	0	02	44
	181	0	13	89
	182	0	09	50
	335	0	00	05
	135	0	26	80
	190	0	02	92
	123	1	17	42
	124	0	48	93
	180	0	13	15
	192	0	13	64
	52	0	01	71
	53	0	23	14
	137	0	10	96
	138	0	19	73
	184	0	5 5	30
	186	0	09	62
	187	0	41	53
	177	0	08	04
	150	0	05	85
	164	0	04	26
	188	0	42	39
	191	0	15	10
	176	0	07	80
	165	0	02	44
	332	0	00	10
	133	0	01	95

का.आ. 1546.--यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के उर्जा मंद्रालय, पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का. आ. सं. 4667 तारीख 14-12-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अजित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय संरकार ने उस्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिविष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिष्क्य किया है।

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	139	0	01	98		191	0	15	10
	166	0	04	26		176	0	07	80
		•				165	0	02	44
	303	0	01	66		332	0	00	10
	301	0	0.0	37		133	0	01	95
		_				139	0	01	98
	334	0	40	26		166	0	04	26
	[सं. O−14	016/483/	e /—_जी	 ਰੀ:		303	0	01	66
	[4. 0-14	010 400	54——VII	. 11.1		301	0	00	37
S.O. 1546	Whereas by notific	cation of th	ne Gove	ernment		334	0	40	26

S.O. 1546.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S.O. 4667 dated 14-12-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by subsection (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests from this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from: Bijaipur (M.P.) to Sawai Madhopur (Raj.)

Tehsil : Atru State: Rajasthan District: Kota Cen-Village Survey No. Hec-Are tiare tare Bedkiya Λ O O n

[No. O-14016/483/84-G.P.]

का. आ 1547. — यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप काइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के उर्जा मंत्रालय, पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का. आ. सं. 431 तारीख 14-1-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइन को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आष्य घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे धी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रवत्त सक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्धिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अजित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रवस्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्वेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस सारीख से निहित होगा।

अनुसूची विजयपुर (म.प्र.) से सवाई माधोपुर (राज.) तक पाइप लाईन बिछाने के लिए

राज्य : रा	जस्थान जिलाः	कोटा	तहसील :	: अटरू
गांव	खसरा नं.	हेक्टर	आर	सेटीआर
1	2	3	4	5
कवाई	7	0	15	05
	6	0	47	57

[11 (V) 10 (V) 11 (10) 14 (23, 1907								
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	8	0	50	33		981	0	0.4	16
	13	0	60	45		1327	0	00	94
	9	0	30	51		988	0	03	29
	10	0	00	07		982	0	20	77
	379	0	11	62		969	0	00	48
	956	0	02	35		980	0	19	57
	955	0	16	23		43	0	00	05
	957	0	04	70		54	0	02	43
	987	0	03	29		5 5	0	27	98
	1316	0	13	03		30	0	56	37
	1364	0	30	81		22	0	36	35
	1448	0	02	82		52	5	04	23
	1471	0	76	91		386	0	18	85
	1326	0	07	29		385	0	00	43
	1470	0	07	29		31/1554	0	03	96
	7 2	0	35	0.4		376	0	17	17
	1316/1553	0	06	35		377	0	53	01
	62	0	01	88		381	0	00	15
	12	0	64	17		42	0	32	87
	979	0	06	67		59	0	48	27
	1336	0	40	34		388	0	33	15
	972	0	02	32		389	0	09	17
	971	0	03	03		391	0	39	84
	1330	0	00	0 5		392	0	03	53
	970	0	00	28		393	0	12	94
	989	0	25	40		1454	0	31	54
	23	0	0 5	03		1455	0	12	09
	32	0	02	34		1466	0	12	94
	40	0	56	38		1365	0	00	05
	1325	0	31	05		973	0	00	89
	53	0	29	40		241	0	09	64
	1317	0	03	91		21	0	01	30
	1351/1563	0	00	74		[सं. Ö −−14(016/546	/84-जी	. पी.1
	378	0	04	61				-	
	1329	0	60	60	S.O. 1547	-Whereas by notific e Ministry of Energy,	ation of	the Gov	ernment
	1352	0	52	63	S.O, 431 date	ed 14-1-85 under sub	-section (of Se 	ection 3
	44	0	07	29	of the Petrole of User in La	um and Minerals Pipel nd) Act, 1962 (50 of 1	line ₅ (Acq. 962), the	uisition Central	of Right Govern-
	56	0	39	7 5	ment declared	l its intention to acq ified in the schedule a	uire the	right of	user in
	387	0	24	93		urpose of laying pipeli		o mar	Countest.
	29	0	01	63	And whoma	as, the Competent A	uthovite. 1	الحدد مور	ω Γ _{1−} 1−
	31	0	52	71	section (1) of	Section 6 of the said	Act, sub	mitted r	eport to
	11	0	06	86	the Governme	ent;			
	978	0	00	18		r, whereas the Centra			
	58	0	01	12	considering th	ie said report, decided ands specified in the s	to acqui	re the r	ight of
	1453	0	47	28	notification;		uulle 6	-bhouara	mis
	75	0	08	94	Now, therei	fore, in exercise of the	power c	onferred	by sub-
					continu (1) of	the Castion C of the	م مداد اسلم	ba Cana	í a

Now, therefore, in exercise of the power conferred by subsection (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests from this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances

SCHEDULE Pipeline from: Bijaipur (M.P.) to Sawai Madhopur (Raj.) State: Rajasthan District: Kota Tehsil: Atru						
/illage	Survey No.	Hec- tare	Are	Cer tiar		
1	2	3	4	—. 5		
Kavai	. 7	- 0	15			
	6	0	46	5		
	8	0	50	3		
	13	0	60	4		
	9	0	30			
	10 379	0	00 11	(
	956	0	02	3		
	955	0	16			
	957	ő	04	-		
	987	0	03	2		
	1316	0	13	(
	1364	0	30	{		
	1448	0	02	1		
	1471	0	76	5		
	1326	0	07	:		
	1470	0	07	7		
	72 1316,1553	0 0	35 06			
	62	0	01			
	7 2	0	64			
	979	0	06	(
	1336	0	40			
	972	0	02	,		
	971	0	03	(
	1330	0	80	(
	970	0	00			
	989	0	25			
	23	0	05			
	32 40	() ()	02 56			
	1325	0	31			
	53	0	29	,		
	1317	0	03	9		
	1351/1563	0	00			
	378	0	04	(
	1329	0	60	(
	1352	0	52	•		
	44	0	07	:		
	56 387	0	39 24	9		
	29	0	01	3		
	31	ŏ	52	,		
	11	ŏ	06			
	978	0	00			
	58	0	01			
	1453	0	47			
	75	0	05	!		
	985	0	25			
	990	0	13			
	781	0	04			
	1327	0	00			
	988	0	03			

1	2	3	4	5
Kavai	. 969	$\frac{1}{0}$	00	48
	980	0	19	87
	43	0	00	05
	54	0	03	43
	55	0	27	98
	30	0	56	37
	22	0	36	35
	52	0	04	23
	386	0	18	85
	38 5	0	00	43
	31/1554	0	03	96
	276	0	17	17
	377	0	53	01
	381	0	00	15
	42	0	32	87
	59	0	48	27
	388	0	33	J 5
	389	0	09	17
	391	0	39	84
	392	0	03	53
	393	0	12	94
	1454	0	31	54
	1450	0	12	09
	1466	0	12	94
	1365	0	00	05
	973	0	00	89
	241	0	09	64
	21	0	01	30

[No. O-14016/546/84-G.P.]

का. अा. 1548—पत. पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के उर्जा मंत्रालय, पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का. आ. सं. 422 तारीख 14-1-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उम अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्विष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को विछाने के प्रयोजन के लिए अजिस करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यत. सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पण्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिष्णय किया है।

अक्ष, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतवृद्धारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में मंलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन विछाने के प्रयोजन के लिए एतव्-द्वारा अजिन किया जाता ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त णिवतयों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देनी है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख से निहित होगा ।

अन्सूची

विजयपुर (म.प्र.) से सवाई माधोपुर (राजे.) तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य:	राजस्थान	जिला: कोटा	तहसीलः	अटरू
गांव	खसरा नं	, हेक्टर	आर	सेन्टीआर
हानी हेड़ा	69	0	00	08
	470	0	04	5.5
	477	0	21	40
	115	0	0 1	6.5
	97	0	14	65
	107	0	16	4.4
	111	0	16	70
	96	0	15	76
	99	0	11	17
	112	0	0.1	27
	72	1	30	70
	119	0	19	19
	100	0	16	66
	124	0	02	0.0
	116	0	4 8	33
	108	0	361	70
	118	0	39	91
	98	o	0.8	73
	480	0	5 1	74
	110	0	17	76
	1	0	0.9	16
	476	0	25	26
	481	0	10	82

[सं. O-14016/548/84-जी पें]

S.O. 1548.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of t nergy, Department of Petroleum S.O. 422 dated 14-1-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (59 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pixeline;

And whereas, the Competent Authority has under Subsection (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And whereas, the Competent Authority has under Subconsidering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification:

Now, therefore, in exercise of the power conferred by subsection (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests from this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHFDULE

Pipeline from Bijaipur (M.P.) to Sawai Madhopur (Raj.)

State: Rajasthan	District : Kota	Tehsil ; Atru			
Village	Survey No.	Hec- tare	Are	Cent	
Hanlheda	. 69	0	00	08	
	470	0	04	55	
	477	0	21	40	
	115	0	01	65	
	97	0	14	65	
	107	0	16	44	
	111	0	16	70	
	96	0	15	76	
	99	0	1.1	17	
	112	0	01	27	
	72	1	30	70	
	119	0	19	19	
	100	0	16	60	
	124	0	02	00	
	116	0	48	3	
	108	0	36	70	
	118	0	39	9	
	98	0	08	7.	
	480	0	51	7.	
	110	0	17	70	
	1	0	09	10	
	476	0	25	2	
	481	ō	10	82	

[No O-14016/548/84-G.P]

का. आ. 15.19 — यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के उर्जा मेंन्नालय, पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का. आ. सं. 424 तारीख़ 14-1-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से मंलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अजित करने का अपना आगय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट वे दी हैं।

और आगे यतः केन्द्रीय मरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिध्चय किया है। अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतव्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में मंलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अजित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि॰ में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख से निहित होगा ।

अनुसूची

विजयपुर (म. प्र.) से सवाई माधोपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्यः राजस्य	यान जिला. [ः]	कोटा	तहसीलः	अटरू
गांव	खसरा नं.	हेक्टर	आर	 से ग्टी आर
यर ला .	415	0	51	27
	420	0	65	30
	396	0	00	13
	419	0	14	58
	398	0	27	86
	421	0	02	12
	423	0	00	0 5
·			~	

S.O. 1549.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S.O. 424 dated 14-1-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline₅ (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

सं. O-14016/549/84-जी पी]

And whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the sold Act, submitted report to the Government;

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by subsection (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests from this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Village	Survey No.	Hec- tare	Are	Cen- tiare
Barla	. 415	0	51	27
	420	0	65	30
	396	0	00	13
	419	0	14	58
	398	0	27	86
	421	0	02	12
	423	0	00	05

[No. O-14016/549/84-GP]

का.आ. 1550—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन मारत सरकार के उर्जा मंत्रालय, पेट्रो-लियम विभाग की अधिसूचना का. आ. सं. 425 तारीख 14-1-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आगय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उनत अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाउन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अजित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रवक्त शिव्यों का प्रयोग करने हुए केन्द्रीय सरकार निर्देण देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैम प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त क्ष्य में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख से निहित होगा ।

अनुसूची

विजयपुर (म. प्र.) से सवाई माधोपुर (राज.) तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : राजस्थान जिला : कोटा तहसील : छवड़ा

गांव	खसरा नं.	हें क्टर	आर	सेन्टीआर
कमलपुरा	57	0	02	97
-	58	0	25	99
	59	0	12	86
	60	0	24	37
	63	0	33	04
	76	0	64	15
	61	0	00	7

[सं. O-14016/550/84-जी पी]

S.O. 1550.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S.O. 425 dated 14-1-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas, the Competent Authority has under Subsection (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by subsection (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests from this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Bijaipur (M.P.) to Sawai Madhopur (Raj.)

State: Rajasthan	District : Kota	Tehs	dI:C	habra
Village	Survey No.	Hec- tare	Are	Cen- tiare
Kamalpura .	. 57	0	02	97
	58	0	25	99
	59	0	12	86
	60	0	24	37
	63	0	31	04
	76	0	64	15
	61	0	00	78

[No. O-14016/550/84-GP]

का आ. 1551:- यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्थत) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) कै 1796 GI/84—11

अधीन भारत सरकार के उर्जा मंत्रालय, पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का. आ. सं. 426 तारीख 14-1-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुभूची मे विनिर्विष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाईन विछाने के प्रयोजन के लिए एतद्- बारा अजित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रवत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख से निहित होगा ।

अनुसूची

विजयपुर (म.प्र.) से सवाई माधोपुर (राज.) तक पाइप लाइन विछाने के लिए

राज्य : राजस्थान जिला : कोटा तहसील : छब्डा

गांव	खसरा नं.	हेक्टर	आर सेन्	टीआर
घट्टा	367	2	38	49
	[ti. () 14016	 551 84-vi	ी पी]

S.O. 1551.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petrolcum S.O. 426 dated 14-1-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petrolcum and Minerals Pipeline₃ (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by subsection (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests from this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Bijaipur (M.P.) to Swai Madhopur State: Rajasthan; District: Kota; Tehsil: Chabra

Village	Survey No	Hec- tare	Are	Cen- tiare	
1	2	3	4	5	
GHATTA	367	2	38	49	

[No. O-14016/551/84-GP]

का.श्रा. 1552—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की घारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के उर्जा मंद्रालय, पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का.आ. सं. 432 तारीख 14-1-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्विष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आण्य घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा, 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यत केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिधिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करवे का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रवत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भुमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अजिल किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रवस्त मिन्तयों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्वेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाघाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख से निहित होगा।

अनुसूची

विजयपुर (म . प्र .) में सवाई माधोपुर (राज .) नक पाडप लाइन विछाने के लिए

राज्य : राज	ास्थान जिलाः	कोटा	तहसील	: ভঞ্জা
गांव	खसरा नं.	हेक्टर	आर	सेन्टीआर -
भौंरा	1	0	00	30
	2	0	30	29
	3	0	08	02
	4	0	48	41
	11	0	23	17
	14	0	38	31
	15	0	04	75
	35	0	34	76
	43	0	30	29
	44	0	30	96
	47/295	0	02	29
	46	0	27	92
	45	0	04	46
	38	0	25	56
	50	0	01	47
	51	0	02	97
	52	0	39	79
	54	0	26	73
	55	0	34	16
	53	0	- 21	98
	1/295	0	01	49

[सं. O-14016/552/84-जी पी]

S.O. 1552.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S.O. 432 dated 14-1-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lends shall instead of vesting in Central Government vests from this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances

SCHEDULE

Pipline from Bijiapur (M.P.) to Sawai Madhopr (Raj.) Tehsil: Chabra State: Rajasthan District: Kota;

Village	Survey No.	Hec- tare	Are	Centi- ar
BHONRA	1	0	00	30
	2	0	30	29
	3	0	08	02
	4	0	48	41
	11	0	23	17
	14	0	38	31
	15	0	04	75
	35	0	34	76
	43,	0	30	29
	44	0	30	9 6
	47/295	0	02	29
	46	0	27	92
	45	0	04	46
	38	0	25	56
	50	0	01	47
	51	0	02	97
	52	0	39	79
	54	0 `	26	73
	55	0	34	16
	53	0	21	98
	1/295	0	10	49

[No. O-14016/552/84-GP]

का. आ. 1551--- प्रत पेट्टोलियम और खनिज पाइप लाइन (भिम में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के उर्जा मंत्रालय, पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना को. आ. सं. 433 तारीख 14-1-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर विया था।

और यत. सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उपत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची मे विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त गिक्त का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदुद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एसपुद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रवत्त शनितयों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय संरकार निर्वेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार

में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में भोषणा के प्रकाशन की इस तारीख से निहित होगा ।

अनुसूची

विजयपुर (म. प्र.) से सवाई माधोपुर (राज.) तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

न जिला	:कोटा र	तहसील :	छबड़ा
खसरा नं.	हेक्टर	आर	सेन्टीआर
82	0	86	62
81	0	08	83
79	0	84	54
85	0	18	3 41
	खसरा नं. 82 81 79	खसरा नं . हेक्टर 82 0 81 0 79 0	खसरा नं. हेक्टर आर 82 0 86 81 0 08 79 0 84

[सं. O-14016/553/84-जी पी]

S.O. 1553.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S.O. 433 dated 14-1-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the schedule appended to that notification for the purpose of levin-pipeline in the specific that notification for the purpose of levin-pipeline. tion for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government:

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification:

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (I) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Contral Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests from this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Bijaipur (M.P.) to Sawai Madhopur (Raj.) State: Rajasthan District: Kota Tehsil: Chabra

Village	Survey No	Hec- tare	Are	Centi- are
YAMINPUR	82	0 ·	86	62
NAYAGAON	81	0	08	83
	79	0	84	54
_	85	0	18	41

[No. O-14016/553/84-G P]

का०आ० 1554--यतः पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जेन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय, पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना

का. आ. सं. 434 तारीख 14-1-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिधिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए प्रयोजन के अजित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार की रिपोर्ट देवी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरशार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न, अनुसूची में विनि-दिस्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया हैं।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतव्द्वारा घोषित करती है कि इत अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिविष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन विछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अजित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदस्त मिक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है जि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहिन होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं ने मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख में निहित होगा।

अनुसूची विजयपुर (म.प्र.) में सर्वाई माधोपुर (राज.) तक पाईप लाईन बिछाने के लिए

राज्य : राजस्थान जिला		: कोटा	तहसील : छबड़ा		
गांव	खारा नं.	हेक्टर	आर	सं न्टीआर	
षट्टी	102	1	25	33	
•	98	0	29	94	
	94	0	06	98	
	99	0	01	25	
	96	0	23	02	
	97	0	24	65	
	92	0	38	50	
	162	0	55	23	
	147	0	0.0	04	
	119	0	0.0	71	
	91/204	0	10	31	
	91/205	0	10	58	
	91/220	0	11	18	
	160	0	04	54	
	164	0	50	34	
	165	0	52	42	
	167	0	26	73	

1	2	3	4	5
	202	0	13	07
	95	0	01	78
	146	0	00	27
	148	0	00	06
	149	0	01	19
	161	0	01	18
	159	0	00	16

[सं. O-14016/555/84-जी. पो.]

S.O. 1554,—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S.O. 434 dated 14-3-85 under sub-section [1] of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conterred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline:

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests from this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Bijaipur (M.P.) to Sawai Madhopur (Raj.)

State: Rajasthan District: Kota Tehsil: Chabra

	151011100	1011511 .	CALLE	14
Village	Survey No	Hec- tare	Are	Con- tiare
GHATTI	102	1	25	33
	98	0	29	94
	94	0	06	98
	99	0	01	25
	96	0	23	02
	97	0	24	65
	92	0	38	50
	162	0	55	23
	147	0	00	04
	119	0	00	7 1
	91/ 2 04	0	10	31
	91/205	0	10	58
	91/220	0	11	18
	160	0	04	54
	164	0	50	34
	165	0	52	42
	167	0	26	73
	202	0	13	07
	95	0	01	78
	146	0	00	27

					+			====	
= 1	2	3	4	5	1	2	3	4	
	148	0	00	06		13	0	43	96
	149	0	01 01	19 18		161	0	34	30
	161 159	0	00	16		162	0	8 6	8 7
	 	4				164	0	23	51
	[]	No. O-14016	/555/84	-GP]		188	0	20	79
का०आ०	1555यतः पेट्रोलियम्	और खनि ज	पाईपल	गईन		190/333	0	07	43
	पोग के अधि पर या अर्ज					2 78	0	33	73
	50) की धारा 3 की उपधा					190	0	27	03
	र्जा मंत्रालय, पेट्रोलियम					191	0	24	65
	437 तारीख 14-1-85 व					241	0	43	31
अधिसूचना स	मंलग्न अनुसूची में विनि	दंष्ट भूमियो	के उप	ायोग		240	1	57	69
	को पाइप लाइनों को					290	0	44	72
	ति करने का अपेना आशय					288	0	77	22
						277	0	08	04
	ा सक्षम प्राधि गरी ने उ					279	0	00	55
	ारा (1) के अधीन सरकार					246/331	0	00	04
अं₹ आ	गे यतः केन्द्रीय सरकार	ने उक्त	रिपोर्ट	पर		160/371	0	02	33
				A. 74		,			

[सं. O-14016/556/8 4-जी. पी.]

अं ि आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार इस्ने के पश्चात् इस अधिसूचना केसंलग्न अनुसूची में विनिद्धिट भूमियों में उपयोग इस अधिकार अजित इसने का विनिश्चय दिया हैं।

अब, अनः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति हा अयोग ारते हुए केन्द्रीय सरदार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों मे उपयोग का अधिक पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अजित विया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) इतरा प्रदत्त प्राक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इद नारीख से निहित होगा।

अनुसूर्चा

विजयपुर (म.प्र.) संसवाईमाधोपुर (राज.) त∴पाईप लाईन विकाने के लिए

राज्य: राज	स्थान जिल	ाःकोटा क्ष	(सील :	छबड़।
गांब	खसरा न०	ह े#ट र	आर	सेन्ट्रीआर
र।छड़ा	6	0	01	`04
	159	0	04	46
	192	0	03	8 6
	287	0	00	8 9
	9	0	01	78
	7	0	02	98
	14	0	56	42
	8	0	64	0.0
				

S.O. 1555.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S.O. 437 dated 14-1-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the India specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests from this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Bajaipur (M.P.) to Sawai Madhopur (Raj.) State: Rajisihan District: Kota. Tehsil: Chabra

Village	Survey No.	Hec- tare	Are	Cen- tiare
REENCHDA	6	0	01	04
	159	0	04	46
	192	0	03	86
	2 87	0	00	89
	9	0	01	78
	7	0	02	98
	14	0	56	24

1	2	3	4	5
	8	0	64	00
	13	0	43	96
	161	0	34	30
	162	0	86	87
	164	0	23	51
	188	0	20	79
	190/333	0	07	43
	278	0	33	73
	190	0	27	0.
	191	0	24	65
	241	0	43	31
	240	1	57	69
	290 ·	0	44	72
	288	0	77	22
	277	0	08	04
	279	0	00	55
	246/331	0	00	04
	160/371	0	02	33

[No. O-14016/556/84-GP]

का.आ 1556.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन (भूमिमें उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मन्त्रालय, पेट्रोलियम विभाग को अधिसूचना का. आ. सं 427 तारीख 14-1-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को विछाने के प्रवोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है। और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिष्चय किया है।

अब, अतः उम्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रवस्त गक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के लिए एतद्द्वारा अजित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रवेश्त शिक्सियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख से निहित होगा।

अनुसूची

विजयपुर(म.प्र.) से सवाईमाधोपुर (राज.) तक पाइप लाईन विछाने के लिए

राज्य :	राजस्थान	जिला : कोटा	तस्	तहसील : छवड़ा			
गांब		खसरा नं.	हुक्टर	आर रे	ोन्टी आ र		
काला खेर्ड	Ť	108	0	10	99		
		102	0	24	76		
		107	0	09	69		
		107/133	0	28	62		
		110	O,	20	37		
		109	0	14	47		
		111	0	02	5 9·		
	112	0	23	46			
		101	0	00	78		
		[स. O-140	16/557	84- जी .	पी.]		

S.O. 1556.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S.O. 428 dated 14-1-85 under sub-section (!) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (I) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests from this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Bijaipur (M.P.) to Sawai Madhopur (Raj.) State: Rajasthan District: Kota. Tehsil: Chabra

Village	Survey No.	Hec- tare	Are	Cen- tiare
KALAKHEDI	108	0	10	99
	102	0	24	76
	107	0	09	69
	107/133	0	28	62
	110	0	20	37
	109	0	14	47
	111	0	02	59
	112	Ü	23	46
	101	0	00	78

का.आ. 1557.—यतः पेट्रोलियम और किनज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962
(1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन
भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रोलय, पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना
का. आ. सं. 428 तारीख 14-1-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार
ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिद्दिष्ट भूमियों के
उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के प्रयोजन
के लिए अजित करने का अपना आशय घोषित कर दिया

और यत. सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अणित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त मक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्बारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्बारा अजित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदस्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख से निहित होगा।

अनुसूची
विजयपुर (म.प्र.) से सवाईमाधोपुर (राज.) तक पाइपलाइन
विकान के लिए

राज्य : राजस्थान	जिल्ला: कोटा		तहसील : अटरू		
गांव	सासरा नं.	हेक्टर	आर	सेन्टीआर	
सींदनी जागीर	34	0	02	08	
	41	1	33	35	
	35	0	51	39	
	224	2	13	84	
	53	0	17	82	
	29	0	16	93	
	56	0	03	56	
	28	0	34	75	
	51	0	11	88	
	52	0	21	09	
	54	0	08	70	
	30	0	19	60	
	49	0	0 1	25	
	50	0	33	32	

1	2	3	4	5
	42	0	03	56
	48	0	75	23
	223	0	02	08
	सिं. O-1	4016/558	/84-जी.	वी . ो

S.O. 1557.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S.O. 428 dated T4-1-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests from this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Itd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipoline from Bijaipur (M.P.) to Sawai Madhopur (Raj.) State: Rajasthan District: Kota. Teshsil: Atru

Village	Survey No.	Hec- tare	Are	Con- tiare
SINDANI JAGIR	34	0	02	08
	41	1	33	35
	35	0	51	39
	2.74	3	13	84
	53	(1	17	82
	29	0	16	93
	₹6	0	03	56
	28	0	34	75
	51	0	11	88
	52	0	21	09
	54	0	08	70
	30	0	19	60
	49	0	01	25
	50	0	33	32
	42	0	03	56
	48	0	75	
	223	0	02	

[No. O-14016/558/84-GP]

का.आ. 1558: — यतः पेट्रोलियम और खनिजपाइपलाइन (भिम में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मस्त्रालय, पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का. आ. सं. 429 सारीख 14-1-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना मे संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अजित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट वे दी है।

और आगे यत. केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिभूचना में संलग्न अनुसूची में विनि-विष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रवत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिशुचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अजित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शिवती का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों मे उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. सभी बाधाओं से मृक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख से निहित होगा।

अनुसूची

विजयपुर (म प्र.) से मवाई गाधोपुर (राज.) तक पाईप लाईन যিষ্ঠান কৈ लिए

्रराज्य : राजस्थान		कोटा	तहसील	: अटरू
गांव	खसरा नं.	हेक्टर	आर सं	न्टीआर
लोला हेड़ी	232	1	52	88
	 [सं. O-1	4016/55	9/84-জী	. पी.]

S.O. 1558.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S.O. 429 dated 14-1-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

'Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in

Central Government vests from this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances,

SCHEDUŁE

Pipelino from Bijaipur (M.P.) to Sawai Madhopur (Raj.) State: Rajasthan District: Kota Tehsil: Atru

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Lolahedi	232	1	52	88
		No. O-14	1016/55	9/84-GP]

का.आ. 1559. —यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962
(1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन
भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय, पेट्रोलियम विभाग की अधिमूचना का. आ. मं. 876 तारीख 19-2-85 द्वारा केन्द्री
सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट
भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को विछान
के प्रयोजन के निए अजित करने का अपना आणय घोषित
कर दिया था।

और यनः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे वी हैं।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पण्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिष्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) ब्रारा प्रवस्त सक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एत्र्द्रारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में मंलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एत्रवृद्वारा ऑजित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रवत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्वेश देती हैं कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्रधिकरण लि॰ में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणों के प्रकाशन की इस तारीख से निहित होगा।

अनुसूची

विजयपुर (म .प्र.) से सवाई माधोपुर (राज .) तक पाईप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : राजस्थान	जिला : कोटा _ तहमील : छवड़ा			
गांव	खसरा नं.	हेक्टर	आर	सेन्टीआर
रीक्षड़ी	79	0	22	57
	77	0	18	37
	76	0	29	25
	74	0	21	38
	101	0	06	55
	100	0	08	38

102	0	08	61
103	0	47	04
109	0	04	97
110	0	56	06
111	0	00	34
70	0	00	12
75	0	13	36
 			

[सं. O-14016/93/85-जी. पी.] एम. एस. श्रीनिवासन, उप सिचव

S.O. 1559.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S.O. 876 dated 19-2-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under subsection (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests from this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Bijaipur (M.P.) to Sawai Madhopur (Raj.) State: Rajasthan District: Kota Tehsil: Charba

Village	Survey No.	Hectare	Are Co	ntiare
Rijhari			,	
Kijit 40)	79	0	22	57
	77	0	18	37
	76	0	29	25
	74	0	31	38
	101	0	06	55
	100	0	08	38
	102	0	08	61
	103	0	47	04
	109	0	04	97
	110	0	56	06
	111	0	00	34
	70	0	00	12
	75	0	13	36

[No. O--14016/93/85-G.P.] M.S. SRINIVASAN, Dy. Secy. संचार महालय

(डाक तार बोर्ड)

नई दिल्ली, 29 मार्च, 1985

का. आ. 1560.—स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1980 द्वारा लागू किये गये भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खण्ड 111 के पैरा (क) के अनुसार डाक-तार महानिदेशक ने पुन्नयूरकुलम/पालयाडनडा/पृवरणी टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 16-4-85 से प्रमाणित दर प्रणाली लाग् करने का निक्चय किया है।

[संख्या 5-9/85-पी. एच. बी.] अजराम सिह, सहायक महानिदेशक (पी. एच. बी.)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS (P&T Board)

New Delhi, the 29th March, 1985

S.O. 1560.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 195!, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Posts and Telegraphs, hereby specified 16-4-1985 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Poovarani/Punnayurkulam/Palayadnada Telephone Exchanges Kerala Circle.

[No. 5-9/85-PHB] B. R. SINGH, Asstt. Director General (PHB)

(भारतीय डाक-तार विभाग)

कार्यालय पोस्ट मास्टर जनरल, उ.प्र. परिमण्डल, ल्रूनिऊ लखनऊ, 22 नवम्बर, 1984

का. अ. 1561.—-जबिक भारत सरकार के संघार मंत्रालय (भारतीय डाक-तार विभाग) की अधिसूचना सं. एस. की.-3901 दिनांक 18 मई, 1979, जो कि भारत के राजपत्र भाग II, धारा 3 उपधारा (II), दिनांक 1 अक्तूबर 1979 के पृष्ठ 3426 पर प्रकाशित हो चुकी है, द्वारा केन्द्रीय सरकार ने अन्यों के बीच निम्न हस्ताक्षर-कर्ता को विभागीय जांच (साक्ष्य उपस्थित प्रवर्तन एवम् दस्तावेज प्रस्तुतीकरण) अधिनियम 1972 (1972 का 18) के अन्तर्गत सरकार की शिक्तयों का प्रयोग करने हेनु विनिविष्ट किया है।

अंद जबिक निम्न हस्ताक्षरकर्ता के विचार से यह आवश्यक है कि श्री राम धीरज पांडे, डाग्र सहायक डाकघर नवाबगंज जिला गोंडा के किंद्ध विभागीय जांच के उद्देश्य हेतु श्री जमुना श्रसाद पाण्डेय आंद श्रीमती धनराजी, जो कि बेलसर (गोंडा) डाकघर बचन बेंद्र खाना सं. 866858 एवम् 870040 के क्रमण. जमावती है, को गवाहों के रूप में अथवा कोई दस्तावेज मांगे जाने हेतु तलब किया जाए।

अतः व्यथित अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (i) द्वारा प्रदस्त मक्ति का उपयोग करते हुए अधो स्ताक्षरकर्ता एतद्द्वारा श्री चेतराम सक्सेना, सहायक डाम अधीक्षक (जांच) II कार्यालय पोस्ट मास्टर जनरल, उ. प्र. परिमण्डल, लखनऊ, जांच अधिकारी को बेल्सर डाकचर गोंडा डाक मंडल गोंडा के डाकघर बचत बैश खाता सं. 866858 के जमाकर्ता ओ जमुना प्रशाद पाण्डे एवंम् खाता सं. 870040की जमाकर्ता श्रीमती धनराजी के सम्बन्ध में कथित अधिनयम की धारा 5 में विकिदिष्ट गक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करना ह ।

[पत्ना क -- - : तर्कता/एम-6-108/79/7] . ह./-पोस्ट मास्टर जनरल

INDIAN POSTS AND TELEGRAPHS DEPARTMENT Office of the Postmaster General, U.P. Circle, Lucknow Lucknow, the 22nd November, 1984

S.O. 1561.—Whereas by the notification of the Govt. of India in the Ministry of Communications (Posts and Telegraphs Board) No. SD-3901 dated the 18th May 1979 published in the Gazette of India Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 1st October, 1979 at Page 5426, the Central Govt. has specified, among others, the undersigned, to exercise the powers of the Govt. under sub-section (1) of Section 4 of the Departmental Enquiries (Enforcement of Attendance of witnesses and Production of Documents), Act, 1972 (18 of 1972).

And whereas the undersigned is of the opinion that for the purpose of departmental enquiry against Shri Ram Dhiraj Pandey, Postal Assistant, P.O. Nawabgani, Distr. Gonda, it is necessary to summon as witnesses or call for any documents from Shri Jamuna Prasad Pandey and Smt. Dhanraji depositors of Belsar (Gonda) Post Office Savings Bank A/Cs No. 866858 and 870040 respectively.

Now, therefore, in exercise of power conferred by Sub-section (i) of Section 4 of the said Act the undersigned hereby authorises Shri Chet Ram Saxena, A.S.P. Enquiry II O/O P.M.G. U.P. Circle, Lucknow, the Enquiry Authority, to exercise the powers specified in section 5 of the said Act in relation to Shri Jamuna Prasad Pandey the depositor of Post Office Savings Bank A/C No. 866858 and Smt. Dhanraji the depositor of SB A/C No. 870040 of Belsar P.O. of Gonda Postal Division, Gonda.

|No. VIG/M-6-108/79/7] (Sd/-)

Postmaster General

श्राप मंत्र(लय

नई दिल्ली, 27 मार्च, 1985

का. आ., 1562.— मैसर्म वम्बई इलेक्ट्रिक मप्लाई एंड ट्रांमपपोर्ट अण्डरटेकिंग, बेस्ट हाउस, पी. बी. नं. 192, बम्बई-39 (महाराष्ट्र/1568) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहित बोमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहें है और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल है, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चान् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुक्रेय है,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त गिवतयों का प्रयोग करते हुए और इससे उपावड अनुसूची में विनिर्धिष्ट गतौं के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन में छूट देती है।

अनुसूची

- 1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रावेशिक भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा नया निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्विष्ट करें।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।
- 3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत सेवाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संवाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों संवाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजन द्वारा किया जाएगा।
- 4. नियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामृहित बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संगोधन किया जाए, तब तक उम संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुमंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, मंस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदक्षित करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भिष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है, तो नियोजिक, मामूहित बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदल करेगा।
- 6. यदि उन्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित कृप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिसमे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उनन स्कीम के अधीन अनुन्न स्कीम के अधीन अनुन्न स्कीम के अधीन

- 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन मंदेय रक्षम उस रक्षम से कम है तो कर्मचारी को उस दशा में मंदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विविध वारिस नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रक्षमों के अन्तर के बराबर रक्षम का संवाय करेगा।
- 8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संगोधन, प्रावेणिक भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संगोधन के कर्मचारियों के हित पर प्रतिकृल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने मे पूर्व कर्मचारियों को अपना वृष्टिकोण स्पष्ट करने की युक्तियुक्त अवसर देगा।
- 9. यदि किसी कारणवंश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते है, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाने है, तो यह रह की जा सकतीं है।
- 10. यदि किसी कारणवंग, नियोजक उस नियत तारीख के भींतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा संकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यक्तिकम की दणा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्दे-शितियो या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।
- 12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रक्षम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रक्षम प्राप्त होने के एक साह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस.-35014/58/85-एस. एस.-4]

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 27th March, 1985

S.O. 1562.—Whereas Messrs Bombay Electric Supply and Transport Undertaking, Best House, P.B. No. 192, Bombay-39 (MH/1568), (herinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insu-

rance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter refrered to as the said Scheme):

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section 2(A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Schedule for a period of three years.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall subnet such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Gentral Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section !7 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Grour, Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insutance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior aporoval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to nay the premium etc within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in cayment of premium and responsibility for nayment of assurance benefits to the nomines or the legal being of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption shall be that of the employer.

12. Upon the death of the memoris covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects".

[No. S. 35014/58/85-SS-IV]

का. आ. 1563.—मैसर्स जोहन फोवलर (इडिया) लिमिटेड, सरजापुर रोड, बंगलौर (कर्नाटक/3174) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किमी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामु-हिंक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पण्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुक्रेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रयत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्विष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन में छूट देती है।

अन्सूर्चाः

- 1 उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, कर्नाटक को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।
- 3. सामुहिक बीमा स्कीम के प्रशासन मे, जिसके अंतर्गत लेखाओ का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का बहुन नयोजन द्वारा किया जाएगा।
- 4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब तक उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा मे उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, संसंथान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन मे नियोजित किया जाता है, जो नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।
- 6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामुहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुजेय हैं।
- 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है तो कर्मचारी को उस दशा में सदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक बारिस नाम निर्देशित को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का मंदाय करेगा।
- 8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, कर्नाटक के पूर्व अनुमीदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने को युक्तियुक्त अवसर देगा।
- 9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामुहिक बीमा स्कीम के, जिमे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते है, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते है, तो यह रह की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का सदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रह की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिमों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उदत स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के जधीन जाने धाने किसी सदस्य की मृत्यू होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय नन्परता में और प्रत्येक दक्षा में भीरतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/59/85-एमएस-4]

5.0. 1563.—Whereas Messrs John Fowler (Ind.a) Limited, Sa japur Road, Bangalore (KN/3174). (Lereinafter referred to 8 the said establishment) have applied for exemption under suc-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act. 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Scuedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and maintain such accounts and provide such facilities for injection as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alchgwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employe been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nomince of the employee as compensation.

- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the empolyees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium and responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nomine/Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects".

[No. S. 35014/59/85-SS-IV]

का. आ. 1564.— मैससं हिन्द्स्तान कापर लिमिटेड 10, कैमिक स्ट्रीट, कलकता-700017 (डब्ल्यू बी / 15008) (जिसे इसमें इसके पण्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पण्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना हो, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूष हैं, जो कर्मचारी निजेग सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चान उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुश्चेय हैं;

अत: केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17, की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्ती के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को नीन वर्ष के अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन में छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रावेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पश्चिम बंगाल को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा नथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, सुमय समय पर निर्दिष्ट करें।

- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समा समय पर निर्दिष्ट करें।
- 3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रेमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण निरेक्षण प्रभारों संदाय आदि भीं है, होने वाले सभी व्ययों का बहुन नियीजन द्वारा विया जाएगा।
- 4. नियोजा, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कंम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें मंगोधन किया जाए, तब तक उस संशोधन की प्रति तथा कर्मश्रारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, संस्थान के मुचना पटट पर प्रदर्शित करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य तिधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है, जो नियोजिक, सामूहिन बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।
- 6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों की उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुक्षेय हैं।
- 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कमंचारी की मृत्यू पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उम रकम से कम है तो कमंचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/ नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।
- 8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पश्चिम बंगाल के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहा प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने को युक्तियुक्त अयसर देगा।
- 9 यदि किसी कारणवण, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामृहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नही रह जाते है, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियो को प्राप्त होने वाले फायदे

किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है।

- 10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रह की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सदाय में किए गए किसो व्यतिकम की ध्वा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिनः वारिसों को जो यदि यह छूट न दो गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गन होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।
- 12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसी की बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दणा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस- 35014 /60 / 85/ एस. एस.-4]

S.O. 1564.—Whereas Messry Hindustan Copper Limited, 10, Camac Street, Calcutta-700017 (WB/15008), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act):

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjighment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme):

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, trasfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exencised under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insutance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nomince of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the empolyees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adonted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10 Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exerction is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium and responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects".

[No. S. 35014/60/85-SS. IV]

का. आ. 1565.— मैसर्म भारत स्टील ट्यत्म लिमिटेड, गन्तीर जिला सोनीपत (पी. एन. 2508) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छट विए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पथक अभिदाय या प्रीमियम का मंदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की मामृहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों मे अधिक अनुकृल है, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुक्रेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रवत्त मित्रियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट मर्ती के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की के लिए उक्त स्कीम के सभी उपवधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

- 1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भिनिष्य निधि आयुक्त, हरियाणा को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसा लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निविष्ट करें।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर मदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय समय पर निर्विष्ट करें।
- 3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुस किया जाना, बीमा प्रीमियम ा मंदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का बहुत नियोजन द्वारा किया जाएगा।
- 4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदिन सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब तक उस मंशोधन की प्रति यथा कर्मचारियों की बहुमंख्या की भाषा मे उसकी मृख्य बातों का अनुवाद, संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रविश्व करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा ार्मचार , जो वार्मचार भिविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है, तो निशंजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप मे उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा अंद उसकी बाबन आवण्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदन्त करेगा।
- 6. यदि उक्त स्कींम के अधीन कर्मचारियों की उपलब्ध फायदे बढाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिसमें कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन
- 7. सामूहिक बीमा स्कीम मे किसी बात के होते हुए भी, यदि किनी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदाय रकम उस रकम से कम है तो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब यह उस्त स्कीम के अधीन होता

तो नियोजक कर्मनारी के विधिक द्वारिस नाम निर्देणिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

- 8. सामृहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी मंगोधन, प्रादेशिक भिषठम निधि आयुक्त, हरियाणा के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और उहां किसी संगोधन के कर्मचारियों के हित पर प्रतिकृत प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भिषठम निधि आयुक्त अपना अगुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने को युक्तियुक्त अवसर देंगा।
- 9. यदि किसी करणवण, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थान पहने अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती हैं।
- 10. यदि किसी कारणवंग, नियोजक उस नियक तारीखं के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियन करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहना है और पालिसी को व्यागन हो जाने दिया जाना है तो छूट रह की जा सकता है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय मे दिए गए किर्म व्यितिकम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विविध वारिमों को जो यदि यह छूट नदी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।
- 12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियां/ विधिः वारिमो को बीमा कृत रक्षम का संदाय तत्परना में और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा विभाग से बोमाकृत रक्षम प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/61/85-एस एस-4]

S.O. 1565.—Whereas Messrs Bharat Steel Tubes Limited, Ganuar District, Sonepat (PN/2508), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act. 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the henefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now 'herefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed leretog the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Haryana and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the sit Act within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the lenefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Nowithstanding anything contained in the Gioup Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Haryana and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium and responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceated members who would have been covered under the siad Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/Legal heirs of the deceased number entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/61/85-SS-IV]

का. आ. 1566. मैससं दि कनारा डिस्ट्रिक्ट सैन्ट्रल को-आंपरेटिय मैंक लिमिटेड सिरमी (उत्तर कन्नाड़ा) (कर्नाटक/2989) (जिसे इसमें इसके पण्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पण्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का ममाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहित बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उटा रहे हैं और ऐमें कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल है, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चान् उक्त स्कीम कहा कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुजीय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबढ अनुसूची में विनिदिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को नीन वर्ष की अविध के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन में छूट देती है।

अन्सूची

- 1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भिष्ठिय निधि आयुक्त, कर्नाटक की ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।
- 3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्त-गैत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तृत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, नेखाओं का अंतरण, निरी-क्षण प्रभारों संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का बहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।
- 4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब तक उस संशोधन की एक प्रति तथा कर्मधारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुबाद, संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदिशत करेगा ।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है, तो नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवण्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदन्त करेगा।

- 6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की ब्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों में अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुजेय हैं।
- 7. सामृहिक बीमा स्कीम के किसी बात के होते हुए, भी, किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दणा में संदय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोज्जिक कर्मचारी के विधिक बारिस/नाम निर्देणित को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।
- 8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, कर्नाटक के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकृत प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।
- 9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधोन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रोति से कम हो जाते हैं, तो यह रह की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारणवंश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा नियम नियत गरें, प्री-मियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यव्मत हो जाने दिया जाता है तो छूट रह की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की वणा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्दे-णितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।
- 12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हक-दार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता में और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम में बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं. एस-35014/66/85-एस एस-4]

S.O. 1560.—Whereas Messrs. The Kanara District Central Cooperative Bank Limited, Sirsi (Uttara Kannaua) (KN/2989), (hercinatter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer,
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the

- employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Instrance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium and responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nommee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S. 35014/66/85-SS-IV]

का. आ. 1567.—मैसर्म अम्को बैटरीज लिमिटेड, मैसूर रोड, बंगलौर-26 (कर्नाटक/60) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारियों भविष्य निधि और प्रकीण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) को धारा की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन 17 किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामू-हिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों मे अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गथा है) के अधीन उन्हें अनुजेय हैं;

अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की घारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त गिक्तयों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट गर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अविधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्गन से छूट देती हैं।

अनुसूची

- उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, कर्नाटक को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर मंदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्स अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करें।
- 3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निर्दाक्षण प्रशारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी ब्ययों का बहुन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

- 4. नियोगक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों का एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब तक उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में मुख्य मुख्य बातों का अनुवाद, संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रविशत करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनयम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है उसके स्थापन मे नियोजित किया जाता है, तो नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम सुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रोमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।
- 6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों की उपलब्ध फ़ायदे बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीभ के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फ़ायदों में समुचित रूप से बृद्धि को जाने को व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फ़ायदे उन फ़ायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुकें हैं।
- 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी को मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस / नामिन वेशिती को प्रतिकर के रूप में बोनों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।
- 8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशो-धन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, कर्नाटक के पूर्व अनु-मोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन के कर्मचारियों के हिन पर प्रतिकृत प्रकास पड़ने की संकासना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना वृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।
- 9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारो, मारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिं बीमा स्कीम के जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फ़ायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रह की जा सकती है।
- 10. याँद किसी कारणवंश, नियोजन उस नियत तारीख के भीतर जो सारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संवाय करने में असफ़ल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रह की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यक्तिक्रम की वणा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्दे-क्रितियों या विधिक कारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई

हीता उक्त स्काम के अंतर्गत होते बामा फ़ायदा के संदाय का उत्तरदाधिस्व ।नयोजक पर हागा।

12. उक्त स्थापन के सबध में नियोजक, इस स्काम के अधीन आने वाले किसा सदस्य का मृत्यु होने पर उसके हक-दार नाम निर्देशातयों/विधिक वारिसो का बामाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक वशा में भारताय जावन बामा निगम से बामाकृत रकम प्राप्त होने के एक माह के भांतर निगम से बामाकृत रकम प्राप्त होने के एक माह के भांतर निगम से बामाकृत रकम प्राप्त होने के एक माह के भांतर

[सन्ध्या एस-35014/67/85-एस एस-4]

S.O. 1567.—Whereas Messrs Amoo Batteries Limited, Mysore Road, Bangalore-26 (KN/60), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (here nafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Lile Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hercinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (2A) of section 17 of the said Act and subjet to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and maintain such accounts and provides such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, duect under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of acounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately emol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect to him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the henefits available to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the Jeath of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium and responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/Legal heirs of the deceased number entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/67/85-SS-IV]

भा. आ. 1568:— मैंसमं कर्नाटक स्टेट स्माल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, राजाजी नगर, बंगलीर-44 (कर्नाटक-2256) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी मिंवण्य निधि और प्रकीण उपबंध अधिनियम 1952 (1953 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क्र) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रामियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फ़ायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फ़ायदे उन फ़ायदों से अधिवा अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुक्रेय है ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनयम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त गिक्तयों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिदिष्ट गर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन की तीन वर्ष की अविधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन में छूट देती है।

अनुसूची

 उक्त स्थापन के संबंध में नियोक्त प्रादेशिक पविषय निधि आयुक्त, कर्तटिक की ऐसी विवरणियां मेजेगा और ऐसे

- लेखा रखोगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्देष्ट करें।
- 2. नियोजक, ऐसे निरोक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर मंदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।
- 3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रणासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, वीमा प्रोमियम का मंदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रमारों का मंदाय आदि भी है होने वाले सभी व्ययों का बहन नियोजक द्वारा किया आएगा।
- 4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनके संशोधन किया जाए, तब तक उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों को बहुसंख्या की भाषा में उसको मुख्य बातों का अनुवाद, संस्थान के मूचना पट्ट पर प्रदिशत करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन को भविष्य निधि का पहुँच ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है, तो नियोजिक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरस्त दर्ज भरेगा और उसको बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।
- 6. यदि उक्त स्कोम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फ़ायवे बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक मामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फ़ायवों में समुचित रूप से युद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फ़ायदे उन फ़ायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुक्रेय हैं।
- 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होंते हुए भी, यदि किसी कर्मवारी की मृथ्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है तो कर्मवारी को उस दशा में मंदेय हो, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजन कर्यवारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।
- 8. सामूहिक बोमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संगो-धन, प्रावेशिक भविष्य निश्चि आयुक्त, कर्नाटक के पूर्व अनु-मोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संगोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकृत प्रभाव पढ़ने की संभा-बना हो, वहां प्रावेशिक भविष्य निश्चि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकीण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।
- प्रांद किसी कारणवश्न, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस मामूहिक जीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन,

नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अबीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फ़ायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्व को जा सकती है।

- 10 याँद किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जोवन बीमा निगम नियत करे, प्रोमियम का सदाय करने में असफल रहता है और पालिसा को व्यपगन हो जाने दिया जाता है ता, छूट रदद को जा सकतो है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सदाय में किए गए किसों व्यक्तिकम का दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या निविध बारिसों को जो याद यह छूट न दो गई होता सो उक्त स्काम के अतगत हाते, बोमा फायदों के सदाय का उत्तरदाथित्व नियोजक पर होगा।
- 12. उनत स्थापन क सबंध में नियोजक देस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देणितियो / विधिक वारिसो को बोमा-कृत रकम का सदाय तत्परता से और प्रत्येक वणा में भारतीय जीवन बोमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्तहों ने के एक माह के भीतर सुनिध्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/68/85-एस एस-4]

S.O. 1568.—Whereas Messrs Karnataka State Small Industries Development Corporation Limited, Rajaji Nagar, Bangalore-44 (KN/2256) (hereinatter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-action (2A) of section 17 of the Employees' Provident I unds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinatter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit I inked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme):

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annual hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and maintain such accounts and Provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges, as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts navment of inspect on charges etc., shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended alongwith a translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Limployees' Provident Fund of the Provident Fund of an estatishment exempted under the said Act, is employed in his a ablishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary pre furn in respect of him to the Life Insurance Corporation of 1 has.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropri tely, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount phyable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominac of the employee as compensation
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Karnatuka and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9 Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be hable to be carcelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date as fixed by the Life Insulance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11 In case of default, if any made by the employer in payment of premium and responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased member who would have been covered under the said Scheme, but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme, the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominees/Legal hens of the deceased member entitled for it and in any case with n one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S. 35014/68/85-SS-IV]

का.आ. 1569.—मैसर्स एस. वी. रंगास्वामी एड कम्पनी लिमिटेड, 75 कालासिपारुयम न्यू एक्सटेंगन, पी० बी० नं. 6539, बंगलीर-2 (कर्नाटक/1994) (जिसे इसमें इसके पण्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपवध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पण्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जीने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमि-यम का संदाय किए बिना हो भारतीय जीवन बीमा निगम की गामूहिक बीमा स्कीम क अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहें हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहयद्ध बोमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चान् उक्त स्कोम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुक्षेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार 'उक्त अधिनियम की घारा 17 को उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त सांक्तयों का प्रयोग करते हुए और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट मतीं के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तोन वर्ष की अविधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती हैं।

अनुसूची

- 1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजिक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, कर्नाटक को ऐसी विवर्णिया भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय समय पर निर्विष्ट करें।
- 2. नियोगक, ऐसे निराक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाम करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त आंधनियम की धारा 17 की उप-धारा (अक) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।
- 3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय अ। वि भी है, होने वाल सभी क्यायों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।
- 4. नियो जंक केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संगोधन किया जाए, तब तक उस मंशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुमंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निश्चि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोगित किया जाता है तो नियोगिक सामृहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम नुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।
- 6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों की उप-लब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं, तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा, जिममें कि कर्मचारियों के लिए मामूहिक बोमा स्कीम के अधीन उप-लब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुक्रेय हैं।
- 7. सामूहिक बोमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की भृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी की उस

- दशा में संदेय होता अब यह उक्त स्कोम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारो के विधिक वारिस / नाम निर्देशिती को प्रतिकार के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा।
- 8. सामुहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक अविषय निधि आयुक्त, कर्नाटक के पूर्व अनुमोदन के बिना नही किया आएगा और जहा किसी मंशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का मंभावना हो वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकीण स्प्रष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।
- 9. यदि कितो कारणवश स्थापन के कर्मचारो भार-तोय जोवन बोमा निगम को उस सामूहिक बोमा स्काम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधोन नहीं रह जाते हैं या इस स्कोम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी राति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रदद की जा सकता है।
- 10. यांद किसी कारणवण नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जोवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का मंदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यवगत हो जाने दिया जाता है, तो छूट रदद को जा सकती है।
- 11. नियोजन द्वारा प्रोमियम के संदाय में किए गए किसो व्यतिक्रम की दशा में उन भृत सदस्यों के नाम निर्वेशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दो गई होतो तो उक्त स्कोम के अन्तर्गत होते, बीमा फ़ायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।
- 12. उनते स्थापन के सबय में नियोजन, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सवस्य की मृश्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियां/विधिक विश्वित को बीमाकृत रकम का संवाय तत्परता से और प्रत्येक वणा में भारतीय जावन बामा निगम से बामाकृत रकम प्राप्त होने के एक माह के भातर सुनिर्धिनत करेगा।

[संख्या एस-35014/69/85~एस एस-4]

S.O. 1569.—Whereas Messrs S. V. Rangaswamy and Company Limited, 75, Kalasiplayam New Extension, P.B. No. 6539, Bangalore-2, (KN/1994), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under subsection (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funda and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (heremafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees that the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the

Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said acheme for a period of three years.

SCHEDULE

- 1. The employer to relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, 1 om time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month,
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employed been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in pavment of premium and responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the local heirs of deceased members who would have been covered under the said Schemel but for grant of this exemption, shall be that of the employer,
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominees/Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all

का , आ , 1570 .--मैसर्स कमानी मेटल्स एंड आले।यस लिमिटेड, व्हाइटफील्ड गड, महादेवपुरा पोस्ट, बंगलीर-48 (कर्नाटक/4539) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पण्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

> और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी. किसी पृथक अभिदाय या प्रीमि-यम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदें उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों में अधिक अनुकुल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पण्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुक्रेय

> अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त मिक्सियों करते हुए और इससे उपबाद अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्ती के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कींम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देमी है।

अन्मृची

- 1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, कर्नाटक को ऐसी विवर्णियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षक के लिए ऐसी सुबि-धाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करे।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रस्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर मंदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय समय पर निहिच्ट करे।
- 3 सामृहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तृत किया जाता, बीमा प्रीमियम का संवाय, लेखाओं का अंतरण निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययो का बहुन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।
- 4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित साम-हिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब तक उस संशोधन की प्रति तथा कमंचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अन्याद, संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

- 5. यदि कोई ऐसा कर्मनारी, जा कर्मनारी प्रश्विप्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसो स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है, तो नियोजिक, सामूहित को मा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।
- 6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उप-लब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचिक रूप से युद्धि की जाने का व्यवस्था करेगा, जिसमें कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकृत हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुक्षेय हैं।
- 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होने हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम में कम है जो कर्मचारी को उस दिशा में संदेय होती, जब यह उक्त स्कीम के अधीन होता, तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस / नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रुप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।
- 8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संगोधन, प्रावेशिक भविष्य निधि आयुक्त, कर्नाटक के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किनी मंगोधन से कर्मचारियों के हिन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की मंभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टि-कोण स्पष्ट करने को युक्तियुक्त अवसर देगा।
- 9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय, जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी गीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।
- 10. यदि किसी कारणवंश, नियोजक उस नियत तारीख, के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यवगत हो जाने दिया जाना है, तो छूट रद्द की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दणा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देणितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।
- 12 उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके

हकदार नाम निर्देशितियों/विधिय आरिसो को बीमाक्कत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाक्कत रकम प्राप्त होने के एक माह के भीतर मुनिश्चित करेगा ।

[स . एस- 350 14 / 70 / 85-एस-एस- 4]

S.O. 1570.—Whereas Messrs Kamani Metals and Alloys Limited, Whitefield Road, Mahadevapura Post, Bangalore-48 (kN/4539) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month,
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc., shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately curol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him 'o the Yife Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme he less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, karnataka and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium and responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominees/Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/70/85-SS-IV]

का. आ. 1571: — मैसर्स किनेटिक्स टैक्नालाजी इंडिया लिमिटेड, 73-74, नेहरू प्लेस, नई विल्ली-19 (दिल्ली/ 3268) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मेचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952) (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहित बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायवों से अधिक अनुक्ल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अमुजेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अविध के लिए उक्त स्थीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन में छूट देनी है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, दिल्ली को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करें। 1796 GI/84—14

- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंण्ड (क) के अधीन ममय समय पर निर्दिष्ट करें।
- 3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, धिषरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी ध्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।
- 4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब तक उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी बातों का अनुवाद, संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रविशित करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है, तो नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सबस्य के रूप में उसका नाम नुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संबन्त करेगा।
- 6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की अधवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुजेय हैं।
- 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इत स्कीम के अधीन संवेय रक्षम उस रक्षम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संवेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्वेशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रक्षमों के अन्तर के बराबर रक्षम का संदाय करेगा।
- 8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशो-धन, प्रादेशिक मविष्य निधि आयुक्त, दिल्ली के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, बहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।
- 9. यदि किसी कारणवण, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना खुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रह की आ सकती है।

- 10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रह् की जा सकती है।
- 11. नियोजक बारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यक्तिश्रम की वशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्वेशितियों या विधिक बारिसों को जो यदि वह छूट न वी गई होती तो उन्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।
- 12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अक्षीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हुकदार नाम निर्वेशितियां/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संवाय तत्परता से और प्रत्येक वशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संस्था एस-35014/71/85-एसएस-4]

S.O. 1571.—Whereas Messrs Kinetics Technology India Limited, 73-74, Nehru Place, New Delhi-19, (DL/3268), (hereinafer referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Mis-ellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And, whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable 10 such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner. Delhi and maintain such accounts and provide such facilities for inspection a_{δ} the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (AA) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia. transfer of accounts payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is airendy a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as

- a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the penefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium and responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the lagal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/71/85-SS-IV]

का. आ. 1572: — मैसर्स मैशनल इंग्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, 31 मिड्डालेटान स्ट्रीट फलक्सा, इसके डिबीजन और बांच आफिसों सहित, (पिंचम बंगाल/13087) (जिसे इसमें इसके पण्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कमेंचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952) (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पण्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छट दिए जाने के लिए आयेटन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का ममाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कमेंचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामृहित बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कमेंचारियों के लिए ये पायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कमेंचारी निष्टेंप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पृथ्वात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुजेय हैं;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त मिक्तयो का प्रयोग करते हुए और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट मतों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधो के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

- 1. उक्त स्थापन के सबध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पश्चिम ढंगाल को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करें।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संवाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करें।
- 3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन मे, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, विवासी का प्रतिमयम का सदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का सदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का बहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।
- 4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहित बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब तक उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, सस्थान के सुचना पट्ट पर प्रविधित करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उनत अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन मे नियोजित किया जाता है, तो नियोजक सामूहित, बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सदत्त करेगा।
- 6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामृहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों का उपलब्ध फायदा में समृचित रूप सं वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामृहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हो, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुजेय हैं।
- 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी वाल के होते हुए भी, यदि किसी कर्मवारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मवारी को उस दणा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मवारी के विधिक वारिस/नाम निर्वेशिती की प्रतिकर के रूप मे दोनों रकमो के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

- 8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों मे कोई भी संगोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पश्चिम बंगाल के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी सगोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहा प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने मे पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।
- 9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मवारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नही रह जाते है, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते है, तो यह रह की जा सकती है।
- 10 यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो, भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रह की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देगितियों या विविध वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के सदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।
- 12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्वेशितियो/विधिक बारिसों को बीमाकृत रकम का सदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सख्या एस-35014/72/85-एसएस-4]

SO 1572.—Whereas Messrs National Insurance Company Limited, 3, Middleton Street, Calcutta, including its Divisional and Branch Offices (WB/13087), (hereinafter referred to as the said estalishment) have applied for exemption under subsection (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And, whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (heerinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient teatures thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benchts available to the employees under the Group insurance scheme appropriately, it the benchts available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benchts available under the Group Insurance Scheme are more ravourable to the employees than the benchts admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc, within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium and responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nomince/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

का. आ. 1573: — मैसर्स ग्रामोफोन कम्पनी आफ इंडिया लिमिटेड, 33, जेस्मोर, रोड, इमडम, कलकत्ता-28 (पिष्ट्यम वंगाल/296) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की बारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट विए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहित बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सह-बद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुक्षेय हैं;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त मिक्तयों का प्रयोग करसे हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट मर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अविध के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

- 1. उनत स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेणिक भविष्य निधि आयुक्त, पिचम बंगाल को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निविष्ट करें।
- 2. नियाजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों के प्रस्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करें।
- 3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।
- 4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोवित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब तक उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्य की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदिश्वस करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य हैं, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है, तो नियोजक, सामूहिक

[No. S-35014/72/85-SS-IV]

बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरस्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

- 6. यदि उन्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ायें जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुक्रेय हैं।
- 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है तो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।
- 8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में काई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पश्चिम बंगाल के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकृल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।
- 9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीभा निगम की उस सम्मृहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते है तो यह रह की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जोवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संवाय करने में असफ़ल रहता है, और पालिसी को व्यप-गत हो जाने विया जाता है तो छूट रह की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिकम की दगा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्दे-शितियों या विधक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गंदी होता तो उक्त स्कीम के अतर्गत होते बीमा फ़ायदों के
 - 12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निर्मम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिष्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/73/85-एस. एस.-4]

2.0.1273.—Whereas Messis Chamophon: Company of India Landed, 23, Jessore Road, Dum Dum, Carcanta-28 (WB/ 200), (netentative referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), (hereinatter referred to as the said Act);

And, whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said estatons much are, without making any separate condition of payment of premium, in employment of ocidins under the Group Instituce Scheme of the Line Insurance Corporation of India in the nature of Line Insurance which are more tryomable to such employees from the benefits admissible under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (herematter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the schedule annexed pereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already

adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the payment of permium and responsibility for payment of assurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be caucelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium and responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/73/85-SS-IV]

का. आ. 1574:—मैसर्स इडियन टेलीफोन इंड-स्ट्रीज लिमिटेड, दूरवाणीनगर, बंगलीर- 16(कर्नाटक/32) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रोमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा रकीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फ़ायदे उटा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फ़ायदे उन फ़ायदों मे अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पण्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुक्रेय हैं;

अत., केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त गिक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिधिष्ट गतौं के अधीन रहने हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अविधि के लिए उक्त स्नोम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुमूचो

- 1. उनत स्थापन के सबध में नियोजक प्रदिशिक भविष्य निधि आयुक्त, कर्नाटक को ऐसो विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरोक्षण के लिए ऐसी मुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।
- 2. नियाजक, ऐसं निरोक्षण प्रभारों का प्रस्येक भास की समाप्ति के 15 दिन के भातर मदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अबीन समय समय पर निर्दिष्ट करे।
- सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अतर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना,

बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का यहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

- 4. नियोजका, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनके संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, मंस्यान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भिष्टिय निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन कूट प्राप्त किसी स्थापन को भविष्य निधि का पहले हो सबस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है, तो नियोजिक, सामूहिक बीमा स्कोम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संवत करेगा।
- 6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फ़ायदे बढ़ाये जाते हैं हो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फ़ायदों में समूचित रूप से बृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि क्षर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फ़ायदे उन फ़ायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुक्षेय हैं।
- 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रक्तम उस रक्तम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में बीनों रक्तमों के अन्तर के बराबर रक्तम का संदाय करेगा।
- 8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, कर्नाटक के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया आएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने को संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने को युक्तियुक्त अवसर देगा।
- 9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते है, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फ़ायवे किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रह की जा सकती है।
- 10. यदि निसी कारणवण, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे प्रीमियम का संदाय करने मे असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रह की जा सकती है।

- 11. नियोजका द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यक्तिकम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिमों को जो यदि वह छूट न वी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फ़ायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।
- 12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संवाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस.-35014/74/85-एस. एस.-4]

S.O. 1574.—Whereas Messts Indian Telephone Industries, Limited, Dooravan nagar, Bangalore-16 (KN/32) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme

- appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Sheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10 Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium and responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of decrased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee Meral helrs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects".

INO S-35014/74/85-SS-IV]

का. आ. 1575:—मैंसमें कोटम आफ इंडिया लिमिटेंड, ट्रांसपोर्ट डिपोट रोड, तारातला, कलकत्ता-88 (पिष्टिम बंगाल/1188) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भिष्य निधि और प्रकीण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है उक्त कि स्थापन के कर्में चारी, किसी पथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकृष हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुश्चेय हैं:

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त गक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट गतों के अधीन रहते हुए, उक्त स्यापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उपत स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्षन में छूट देती है ।

अनुसूची

- 1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पश्चिम बंगाल को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करें।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करें।
- 3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।
- 4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब तक उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदक्षित करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सवस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है, तो नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बावत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम की संदत्त करेगा।
- 6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से बृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुक्ल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अवजेन क्रांग अनक्षेप हैं।
- 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मरपु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है तो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती है, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक बारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।
- सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पश्चिम बंगाल

- के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकीण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।
- 9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों की प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रह की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रह की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा श्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक बारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायवों के मंदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।
- 12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/75/85-एस. एस.-4]

S.O. 1575.—Whereas Messrs Coates of India Limited, Transport Depot Road, Taratala, Calcutta-88 (WB/1188), (thereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund ot an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nomines of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner. West Bengal and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium and responsibility for payment of assurance hencits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Cornoration of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/75/85-SS-IV]

का. आ. 1575.—मैनमें युनियमेंल इलैक्ट्रिक लिमिटेड, डी. एच. रोड, डाकघर जोका, जिला 24-परगना (पिष्यम बंगाल/11576) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मघारी भविष्य निधि और प्रकीण उपबंध अधिनियम. 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17की 1796 GIt84—15

उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय मरकार का समाधान हो गया है कि उस्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदें उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल है, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपावड़ अनुसूची में विनिद्धिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थानन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्थीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन में छुट देती है।

अनुभूची

- 1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पिण्वम बंगाल को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रस्थेक मास की समाक्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।
- 3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुन किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का बहुन नियोजन द्वारा किया जाएगा।
- 4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक की मा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब तक उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है, तो नियोजिक, सामृहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम नुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सदन्त करेगा।
- 6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से

षृति की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकृष हों, जो उवत स्कीम के अधीन अनुसेय ।

- 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है तो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमो के अन्तर के वरावर रकम का संदाय करेगा।
- 8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पश्चिम बगाल के पूर्व अनुमोदन के विना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने को युक्तियुक्त अवसर देगा।
- 9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते है, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति में कम हो जाते हैं, तो यह रह की ज सकती है।
- 10. यदि किसी कारणवण, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रहकी जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा श्रीमियम के संवाय में किए गए किसी व्यतिकम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वीरिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।
- 12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हुकदार नाम निर्देशितियों/विधिक बारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता में और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक माह के भीतर स्निष्चित करेगा।

[सख्या एस. - 35014/76/85-एस. एस. - 4]

S.O. 1576.—Whereas Messis, Universal Electrics Limited, D. H. Road, P.O. Joka, District, 24 Parganas, (West Bengal), (WB/11576), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annual hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act. is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount nayable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal hair/nomines of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner. West, Bennal and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9 Where, for any reason the employees of the said establishment do not remain covered under the Grown Insurance Scheme of the Life Insurance Cornoration of India as already adopted by the said establishment, or the henefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled
- 10 Where for any reason, the employer fails to now the premium etc, within the due date as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to larse, the exemption is liable to be cancelled.

- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium and responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/76/85-SS-1V]

का, आ. 1577.—मंसर्स जी. डी. फाम्सयूटिफल्स लिमिटेड, 25-एन, ब्लाक "बी", नई अलीपुर, कलकत्ता-88 (पश्चिम बंगाल/1919) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मधारी भविष्य निधि और प्रकीण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आबेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हां गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीगियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामू-हिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन दीमा के रूप में फायदे उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों मे अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा क्कीम, 1976 (जिसे इसके पण्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है;

अत: केन्द्रीय सरकार, उन्नप्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रवस्त मन्त्रियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुभूची में बिनिर्दिष्ट भर्तों के अधीन रहते हुए, उन्नत स्थापन को तीन वर्ष की अविध के लिए उन्नत स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन में छूट देती हैं।

अनुसूची

- 1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भिविष्य निधि आयुक्त, पश्चिम बंगाल को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्धिष्ट करें।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर मंदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।
- 3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रोमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रधारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

- 4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदिक सामूहित बीमा स्कीम के नियमों को एक प्रति और अब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब तक उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों को बहुसख्या की नाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदक्षित करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो क्रमंचारी प्रविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन को निविष्य निधि का पहते ही सबस्य हैं, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजिक सामूहिक बीमा स्कीम के सबस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसको बाबत आवश्यक धीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को नवस्त करेगा।
- 6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदं बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि को जाने की व्यवस्था करेगा जिसमें कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदों में अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुजेय है।
- 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी वात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारों को मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है तो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उकत स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारों के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दानों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।
- 8. सामूहिक बोमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक मन्विष्य निश्चि आयुक्त, पश्चिम बंगाल के पूर्व अनुमोदन के विना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहा प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दिन्हकोण स्पष्ट करने की युक्तियुक्त अवसर देगा।
- 9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहों रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाने हैं, तो यह रह की जा सकती है।
- 10 यदि किसी कारणवण, नियोजक उस नियत तारीख के भोतर, जो सारतीय जीवन बीमा नियम नियत करे, प्रीमियम का मंदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रह की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रामियम के संदाय में किए गए किसी व्यक्तिकम को दशा में उन मृत सदस्यों के ताम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती सो

उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फ़ायदों के संदाय का उत्तरदाधित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सबध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने बाले किसा सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हक-दार नाम निदीशातियो/विलिध वारिसी की बामाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में मारतीय जीवन बीमा निगम से बामाकृत रकम प्राप्त होने के एक माह के भीतर सूनिश्चित करेगा।

[संख्या एस.-35014/77/85-एस .एम.-4]

S.O. 1577.—Whereas Messis, C. D. Pharmaceuticals Limited, 25 N, Block 'B', New Alipore, Calcutta-88, (WB/1919), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that

- would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident I und Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc, within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium and responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/77/85-SS-IV]

का.आ. 1578.—मैंसमें क्लारिओन अडवरटाइिंग मिंबसेस लिमिटेड 55-बी, मिर्जा गालिब स्ट्रीट, कलकत्ता-76 (पिंचम बंगाल/5413) (जिसे इसमें इसके परवात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कमैचारों प्रविष्य निधि और प्रकीण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके परवात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना हा, भारतीय जावन बीमा निगम की मामू-हिक बीमा स्कोम के अधीन जावन बीमा के रूप में फ़ायदे उटा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फ़ायदे उन फ़ायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचरी निक्षेप सहबद्ध वीभा स्कीम, 1976 जिसे इसके पश्चान् (उक्त स्काम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुक्रेय है;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्न शिक्तयों का प्रयोग करते हुए और इससे उपायदा अनुसूची में विनिदिष्ट शर्तों के अधीन रहने हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अविधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपवंधों के प्रवर्तन से छूट देती हूं।

अनमुची

 उक्त स्थापन के संबंध में नियोजन प्रादेशिक भिक्ष्य निधि आयुक्त, पश्चिम बंगाल को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रचेंगा तथा निरोक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्राय सरकार, समाय-समय पर निविध्य करें।

- 2 नियो तक, ऐसे निराक्षण प्रकारों का प्रत्येक मास यो समापित के 15 दिन के भागर सदाय करेगा जो केन्द्राय सरकार के खंड उनन अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधान समय-सभय पर निद्धित करें।
- 3. सामूहिक बामा स्कीम के प्रणासन में, जिसके जैनर्गत लेखाओं का रखा जाना दिवरणियों का प्रस्तुत किया जाना बामा प्राप्तियम क नदाय, लेखाओं का अंतरण निरोक्षण प्रमारा संदाय आदि भी है, होने काल ममी व्ययो का बहुन निर्योजन द्वारा किया जाएगा।
- 4. नियोगक, केन्द्राय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिल बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और या क्यों उत्तेष संगोधन किया चाए, तब तक उस संगोधन का प्रति तथा कर्मचारियों का बहुसंख्या का जाया में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।
- 5. याद कोई ऐसा कर्मचारा, जो कर्मचारा पविषय निधि का या उनत आधिनियन के अवान छूट प्राप्त किसा स्थापन की प्रविष्य निधि का पहले हा सदस्य है उसके स्थापन में नियोगित किया जाता है, तो नियोगिक पासूहित बोमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसका बाबन आवश्यक प्रामियम भारताय जीवन बीमा निजम को सदस्त करेगा।
- 6. यदि उक्त स्कीम के अधार वर्मचारियों को उपलब्ध फ़ायदे बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामू हिक बामा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फ़ायदों से समुचित रूप से बृद्धि को जाने को व्यवस्था करेगा जिसमें कि कर्मचारियों के लिए प मू हिक प्रामा स्काम के अधीन उपलब्ध फ़ायदे उन फ़ायदों से अधिक जन्तून हों जा उ∓न स्कीम के अधीन अनुजेय है।
- 7. नामूहिक बामा किमा में किनी वान के होते हुए भी,
 यदि किनी कर्मचारों की मृत्यु पर इस क्लोम के अबीन संदेय
 रक्तम उन रक्षम में कम है तो कर्मचारों की उस दणा में
 संदेय होती, जब यह उसने काम के अबीन होता तो नियोजक
 कर्मचारों के विविध वारित नाम निर्देणियों को प्रतिकार क
 क्ष्म में दोनों रक्तमों के अन्तर के बराबर एक्स का संदाय
 करेगा।
- ०. स मूहिल बाना स्काम के उपबंधां में काई भी संगोधित, प्रादेणिक सांबच्य निर्ध आयुक्त, पश्चिम बंगाल के पूर्व अनुमादन के बिना नहीं किया अन्ति और अहा किया गंगीधित में कर्मचारियों के हिन पर प्रातिहल प्रकाब पड़ने की पीत देन हों, बहु प्रादेशिक निष्य निर्धि आयुक्त अपना अनुमोदन देन से पूर्व कर्मचारियों की अपना दृष्टिकीण स्पष्ट करने का युक्ति-यक्त अवसर देगा ।

- 9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक वीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने बाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते है, तो यह रह की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारणवण, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का सदाय करने मे असफल रहता है, और पालिमी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो प्रृट रह् की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सदाय में किए गए किसी व्यतिकम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट ने दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।
- 12. उस्त स्थापन के सबध में नियाजक, इस स्कीम के अधीन आने वाल किसी सदस्य की मृत्यू होने पर उसके हकदार नाम निर्देशिनियो/ब्रिधिक वारिमा को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परना से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक माह के भीतर मुनिश्चित करेगा।

[सं॰ एस-35014/78/85-एसएस-4]

S.O. 1578.—Whereas Messia, Clation Advertising Services Limited, 55B, Mirza Ghalib Street, Calcutta-76 (WB/5413), (hereinafter referred to as the establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more tavourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit I inked Insurance Scheme, 1976 (hereinatter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

- 1 The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.
- 2 The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group I surance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of

accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of nim to the Life Insurance Corporation of India.
- 6 The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be tiable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the dur date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium and responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the sald Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee_leval heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/78/85-SS-IV]

का आ. 1579.— मैसर्स ईणर गृडअर्थ लिमिटेड, 212. दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-2,(डी. ल./6729), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का सभाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पथक अभिदाय या प्रीमियम का सदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐमे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल है, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है

अत केन्द्रीय सरकार, उक्तुअधिनियम की धारा 17 की उपधीरा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे विनिर्दिष्ट शर्ती के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अविध के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देनी है।

अन्सूर्च।

- 1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, दिल्ली को ऐसी विवरणिया भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी मुविधाए प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करें।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करें।
- 3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम क ासंदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का बहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।
- 4. नियोजिक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब तक उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुमंख्या की भाषा मे उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, संस्थान के मूचना पट्ट पर प्रदिश्ति करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजिन किया जाता है, तो नियोजिक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।
- 6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदें बढ़ाए जाने हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रुप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उवत स्कीम के अधीन अनुक्रेय हैं।

- 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किमी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दणा में संदेय हाती, जब बह उक्त स्कीम के अधीन होता ता नियोजक कर्मचारी के बिविध बारिस नाम निर्देणिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के वराबर रकम का संदाय करेगा।
- 8. साम्हिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संगोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, के पूर्व अनमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संगोधन से कर्म-चारियों के हिन पर प्रतिकृत प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्ति-युक्त अवसर देगा।
- 9. यदि किसी कारणवण, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा गिगम को उस सामूहिक बीमा रकीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदें किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रह की जा गकति। है।
- 10. यदि किसी काण्णवण, नियोजक उस नियत नारीख़ के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहना है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रह की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दणा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्दे-शितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।
- 12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसो को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दणा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिष्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/81/85-एस एस-4]

S.O. 1579.—Whereas Messrs. Eicher Goodearth I imited, 212, Deendyal Upadhya Marg, New Delhi-2, (Dl. 67229), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

__: .____

SCHFDULE

- l. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3.4) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3 All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately entol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nomines of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner. Delhi and where any amendment is blely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Infe Insurance Cornoration of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled
- 10 Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be can telled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium and responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/leval heirs of the deceased member entitled for it and in any case

within one month from the receipt of claim complete in all respects

[No S-35014/81/85-SS IV]

का आ 1580—मैंसर्म मैंग्नम इंटरनेशनल ट्रेनिंग कम्पनी (प्रा) लिमिटेड, 48/1, कामिश्यल मैंटर, मालचा मार्ग, नई दिल्ली-110021 (डील/7111), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उकत स्थापन कहा गया है) ने कर्मचार्रा भविष्य निधि और प्रकीण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 ना 19) जिस इसमें इसके पण्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क्र) के अधीन छूट दिए जाने के निध आवेदन किया है,

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्षत स्थापन के कर्मचारी, शिमी पृथक अभिदाय या प्रीमियम वा सवाय किए बिना ही, भारतीय जीवन वीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप म फायद उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये पायदे उन फायदो से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पण्चात् उत्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुजेय है,

अत केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) हारा प्रदत्त गक्तियों का प्रयोग करते हुए ओर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्नों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थानन को तीन वा की अविध के लिए उक्त स्कीम के सभी उपवधी के प्रवर्तन में छूट देती है।

अनुसूची

- 1 उस्त स्थापन के सर्बंध में नियोजक प्रादेशिक भिवाण निधि आयुक्त, दिल्ली को ऐसी विवर्णिया भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाण प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिण्ट करें।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (उक्त) के खड़ (क) के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करे।
- 3 सामृहिक बीमा स्कीम वे प्रशासन मे, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तृत किया जाना, बीमा, प्रीमियम का सदाय, लेखाओं का अतरण, निरीक्षण प्रभारों सदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजन द्वारा किया जाएगा।
- 4 नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामृहिव बीमा स्कीम के नियमो की एक प्रति और जब नभी उनमें संशोधन किया जाए, तब तक उस मशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, संस्थान के स्चना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।
- 5 यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन

- की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियाजित किया जाता है, ता नियाजिया, सामृहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवण्यक प्रीमियम नारतीय जीवन बीमा निगम को सदन करेगा।
- 6 यदि उक्त स्वीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढाए जाते है तो नियोजक सामृष्टिक बीमा स्कीम के अधीन वर्जनारियों को उपलब्ध फायदों में रामृचित रूप सं विद्ध की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों विष् सामृहिक बीमा स्वीम के अधीन उपलब्ध फायदे उनके फायदों से अधिव अनुकृत हो, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुक्ष है।
- 7 सामूहिक बीमा स्कीम मे किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी वर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सदेय रकम उस रकम मे कम है तो कर्मचारी को उस दशा मे सदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक क्रिंगी के विविध बारिस नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप मे दोनो रकमो के अन्तर के बराबर रकम का सदाय करेगा।
- 8 राम्हित बीमा स्कीम के उपबधों में वोई भी संशोधन प्रादेशिक भिविष्य निधि आयुक्त, दिल्ली के पूर्व अनुमोदन के विना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्म-चारियों के हिन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सभावना हो, वहां प्रादेशिक भिविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारिया को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने को युक्ति-युक्त अवशर देगा।
- पदि किसी कारणवश, स्थापन के कमेचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहल अपना चुका है, अधीन नही रह जाते है, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदें किसी रीति से कम हो जाते हैं, ता यह छूट रह की जा सकतीं है।
- 10 यदि किसी कारगवण, नियोजक उस नियत तारीख़ के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का सदाय करने में असकल रहता है, और पालिमी को व्ययगत हा जाने दिया जाता है तो छूट रह की जा सकती है।
- 11 नियोजक द्वारा प्रीमियम के सदाय में किए गए किसी व्यक्तिकम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्दे-शिनियों या विधिक वारिसों का जो यदि यह छूट न दी गई होती ता उक्त स्कीम के अतर्गत होते, बीमा फायदों के सदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।
- 12 उक्त स्थापन के सबध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किमी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हक-दार नाम निर्देशितियो/विधिक वारियो को बीमाकृत रकम का सदाय तत्परता में और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीम

निगम में बीमाकृत रक्षम प्राप्त होने के एक माह के भातर मुनिंश्चित करेगा।

[सन्या एस- 35014/82/85-एस एस-4]

S.O. 1580.—Whereas Messes, Magnum International Trading Company Private 1 imited, 48/1 Commercial Centre, Malcha Marg, New Delhi-110021 (DL/7111), thereinafter referred to as the said establishment; have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Imployees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6 The employer shall arrange to enhance the henefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the level heir/nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner 1796 GI/34—16

- shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium and responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/82/85-SS-IV]

का. आ. 1581:——मैसर्स दिदवानीया बादर्स प्राइवेट लिमिटेड 33, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली-110020 (डी. एल./325) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारीं भिवष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उनत स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामू-हिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सह्बद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पण्चात् उन्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अन्ज्ञेय है :

अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) हारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपावद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहने हुए, उक्त स्थापन की तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

- 1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भिक्य निधि आयुक्त, दिल्ली को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करें।
- तियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करें।

- 3. सामृहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना विवर्णायों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमयम का संदाय, लेखाओं का अंतरण निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है होने वाले राभी व्ययो का बहन नियोजन द्वारा किया जाएगा ।
- 4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामृहित बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब तक उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य वातों का अनुदाद, संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदिशात करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भिवष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भिवष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है, तो नियोजिक, सामूहिक बीमा स्कीभ के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवण्यक प्रामियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सदन करेगा।
- 6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हूं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप में बृद्धि की जान की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के निए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकृत हों, जो उक्त स्कोम के अधीन अनुजेब हैं।
- 7 सामूहिक बीमा स्कीम में कियी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है तो कर्मचारी को उस दणा में संदेय होती, जब वह उक्त स्वीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विविध वारिस / नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोतों रकमों के अन्तर के वरावर रकम जा संदाय करेगा।
- 8. सामृहिक बीमा स्कीम के उपबधों ने कोई भी संजोधन प्रादेशिक भिवष्य निधि आयुक्त, दिल्ली के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी सशाधन के कर्मचारियों के हिन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्ति-युक्त अवसर देगा।
- 9. यदि किसी कारणवण, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नही रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदें किसी गीन से कम हो जाते है, तो यह छट रद्द की जा सकती है।

- 10. यदि किसी कारणवण, नियोजक उस नियत नारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगभ नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्ययगन हो जाने दिया जाता है तो छूट रह की जा सथानी है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सदाय में किए गए किसी व्यक्तिकम की दणा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्दे-णितियों या विविध वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।
- 12 उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी गदस्य की मृत्यु होने पर उसके हक-दार नाम निर्देशितियों/विधिक वारियों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता में अं।र प्रत्येक दणा में भारतीय जीवन बीमा निगम में बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक माह के भीतर मुनिष्चित करेगा ।

[स. एस-35014/83/85-एस एस-4]

S.O. 1581.—Whereas Messis. Didwania Brothers Private Limited, 33, Okhla Industrial Estate, New Delhi-1100020, (DL/325), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act):

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment, are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme):

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-vection (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said S heme for a period of three years.

SCHEDULF

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insuran e premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees

- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund of the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Schenie, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Croup Insuran e Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is hable to be can elled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium and responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal hears of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/83/85-SS IV]

नई दिल्ली, 28 मार्च, 1985

णद्भिपत्न

का. आ. 1582.—भारत के राजपत्न भाग 2, खण्ड 3, उप खंड (ji) में तारींख 19 फरवरी, 1983 को प्रकाशित भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 1246, तारींख 4 फरवरी, 1983 में, पंक्ति 3 में, "(हैदराबाद)" के लिए "जिला विजयनगरम, आन्ध्र प्रदेश" पढें।

[एस-35019/340/82-पी. एफ.-II]

New Delhi, the 28th March, 1985

CORRIGENDUM

S.O. 1582.—In the notification of the Government of India in the Manistry of Labour, No. S.O. 1246, dated the 4th February, 1983, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ir), dated the 19th Lebruary, 1983, in line 4 for "(Hyderabad)" read "Vizianagai im District, Andhra Pradesh".

का . अ . 1583 — केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स वैस्टर्न इडिस्ट्रियल मेरिन एंड आयल फिल्ड मॉविसेज प्रा. लि., वस्वर्ड स्यूववल चैस्वन्स 19-21 अस्वाला डोसी मार्ग, वस्वर्ड-100023 नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसख्या इस बान पर सहमन हो गई है कि कर्मचारों भाविष्य निधि आर प्रकीण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपवंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए :

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की श्रारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करने हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन की लागू करती है।

[स. एस-35018/2/85-एस. एस-2]

S.O. 1583.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Western Industrial Marine and Oil Field Services Private Limited, Bombay Mutual Chambers, 19-21, Ambala (Doshi Marg, Bombay-400023, have agreed that the provisions of the Imployees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35018/2/85-SS-II]

का. अ. 1584—केन्द्रीय गरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसमं सदाक सी पूड्स 2, गणेण चन्द्रा एवेन्यू, चौथी मंजिल कलकत्ता-13 और प्लॉट 3, गैस स्ट्रीट, कलकत्ता-9 शामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहु-सख्या इस बान पर गहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उगधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[म. एस-35017/36/85-एम. एस-2]

S.O. 1584.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Sadaf Sea Foods, 2, Ganesh Chandra Avenue, 4th Floor, Calcusta-700013 including Plant at 3, G is Street, Calcusta-700009, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35017/36/85-SS-11]

का. आ. 1585.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स श्री राधा माध्य आयल मिल, 111, राजा दिनेन्द्र स्ट्रीट, कलकत्ता-700004 नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर महमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रवत्त गिक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35017/37/85-एस, एस॰ 2]

S.O. 1585.—Wheeras it appears to be Cental Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Sree Radhamadhab Oil Mill, 111, Raja Dinendra Street, Calcutta-700004, have agreed that the provisions of Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. \$-35017/37/85-\$S-H]

का. आ. 1586:—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीन होता है कि मैं मर्म यूनि सिस्टम प्रा. लि. 220-ए, नाशकरपारा रोड, घुसुरी हावडा-7 (वैस्ट बंगाल) और कार्यालय 33/1, नेताजी सुभाष रोड, सयूट नं. 529, कलकत्ता-1 और रिज. आफिस 64, बिडन स्ट्रीट, कलकत्ता-6 में स्थित नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भिषय निधि और प्रकीण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अत . केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

सिं. एस-35017/38/85/एस. एस-2}

S.O. 1586.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messignia Uni Systems Private Limited. 220 A. Naskarpara Road, Ghusuri, Howrah-7 (WB) and office at 33/1, Netaji Shubhas Road, Suite No. 529, Calcutta-1 including Registered office at 64. Beadon Street, Calcutta-6, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35017/38/85-SS-II]

का. आ. 1587—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैंसर्स विजय इंटरनेशनल, 14 एंड 15, ओल्ड कोर्ट हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता-1 नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपवंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को नागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त णिक्तयों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35017/39/85 एस. एस-2]

S.O. 1587.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messis Vijay International, 14 and 15. Old Court Street, Calcutta-1, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35017/39/85-SS-11]

का. आ. 1588 — केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स ट्रेके इंटरनेशनल लि., 50, चौरंजी रोड, 11 वी मंजिल, कलकत्ता-700071 नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुमंख्या इस बात पर सहमत हो एई है कि कर्मचारी भविष्य निधि आर प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उपन स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[स. एस-35017/40/85/एस.एस०-2]

S.O. 1588.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messis Turnkey International Limited, 50, Chowinghee Road, 11th Hoor, Calcutta-70071, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers contented by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35017/40/85-SS-II]

का. आ.1589.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि है कि मैसर्स मुरलीधर रतनलाल 14 एंड 15, ओल्ड कोर्ट हाऊस स्टीट, कलकत्ता-1 नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भिवष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अत. केन्द्रीय सरकार, उन्न अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त णक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35017/41/85-एम. एस-2]

S.O. 1589.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messis Muridhar Ratan I.al, 14 and 15, Old Court House Street, Calcuita-1 (Post Box 790) have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35017/41/85-SS-IJ]

का. आ. 1590.—केन्द्रीय मरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्म कुमार ट्रेडिंग कम्पनी, प्रा. लि. 18, लाउडन स्ट्रीट कलकत्ता-17 और रिज. आफिस 42/1 स्ट्राग रोड, कलकत्ता-7 और प्रांच आफिस 8, कप्रशीम मोय रोड, कामर्स हाउस, बेलाई इस्टेट, बम्बई-38 में स्थित नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुमंख्या इस बात पर सह्मत हो गई है कि कर्मचारी मिबिष्य निधि और प्रकीण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को नागू किए जाने चाहिए।

अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिख्यिम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त मिक्तयों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लाग् करती है।

[स. एस-35017/33/85/एस. एस-2]

S.O. 1590.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Kumar Trading Company Private Limited, 18, Loudon Street, Calcutta-17 including Registered Office at 42/1, Strand Road, Calcutta-7 and branch office at 3, Currimbhoy Road, Commerce, House, Ballard Estate, Bombay-400038, have agreed that the provisions of the Pmployees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35017/33/85-SS-II]

का. आ 1591 — केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसमें चूडी श्रीनियास एंड कं., फरीद ग्राम मैन्यफैक्चर्रस, पटेल रोड, रायचर, कर्नाटका नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अत. केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की यारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

· [स . एस-35019/131/85-एस . एस-2]

S.O. 1591—Whereas in appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Chudi Srinivas and Company, Friedgram Manufacturers, Patel Road, Raichur, Karnataka, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act. 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(131)/85-SS-III

का आ. 1592.— केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्ग मेक इंजीनियरिंग कारपोरेणन, 117, रेसकार्ग रोड, कांप्रस्बट्टर-641018, तिमलनाड नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लाग किए जाने चाहिए।

अत. केन्द्रीय सरकार, उक्त आधीनयम की धारा 1 की उपधारा (1) हारा प्रदत्त गक्तिया का प्रयोग करने हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35019/132/85-एस०एस० 2]

S.O. 1592.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Mak Figineering Corporation, 117, Race Course Road, Coimbacore-641018, Tamil Nadu, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers confurred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(132)/85-SS-II]

का. आ 1893 — केन्द्रीय मरकार को यह प्रतीत होता है कि मैंसर्म श्री चानाबामावेण्वर राईस मिल्म, मिधानूर, रायचूर डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुमंख्या इस बात पर महमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) ज्ञारा प्रदन्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है। [मं. एस-35019/133/85/एस, एस-2]

S.O. 1593.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messis Sri Channabasaveshwar Rice Mills, Sindhanur, Raichui District, Karnataka, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(133)/85 SS-II]

का.आ. 1594 — केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स तारातरीनी आटो इंजीनियरिंग वर्क्स एट/ गोस्ट आफिस, बेरहामपुर, डिस्ट्रिक्ट गजम, उडीसा नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध स्थापन उक्त को लागु किए जाने चाहिए।

अत. केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करता है।

[स . एस-35019/134/85- एसएस-2]

S.O. 1594.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Taratarini Auto Engineering Works, At/P.O. Berhampur District Ganjam, Orisas, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(134)/85-SS-JI]

का.आ. 1595 — केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैं. दी इन्वेस्टमेट एंड कर्माशयल कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, नं. 56, कोरल मर्चेंट्स स्ट्रीट, मद्रास-600001 तिमलनाडु नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि अर प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) हारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त रथापन को लाग करती है।

[स. एप-35019/136/85/एप.एस.-2]

S.O. 1595.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messis The Investment and Commercial Corporation Private United, No. 56, Coral Merchant Sheet, Madras-600001, Tamil Nadukave agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions, Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(136)/85-SS-II]

का. आ 1596: — केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैं. भगीरथा इलैक्ट्रीकल्स एंड स्ट्रक्चरल्स प्राइवेट लिमिटेड, कालामासेरी, अलवाए-683101, कन्यानूर तालुक, एरनाकुलम डिस्ट्रिक्ट, केरला नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बान पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा(4) द्वारा प्रदत्त णक्तियों का प्रयोग करने हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करनी है।

[स. एस-35019/137/85-एस एस-2]

S.O. 1596.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messis Bhageeratha Electricals and Structurals Private Limited, Kalamassery, Alwaye-683104, Kanayannur Taluk, Emakulam District, Kerala, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscelfaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conterred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(137)/85-58-11]

का.आ. 1597 — केन्द्रीय सरकार का यह प्रतीत होता है कि मैं ऐक्सल ट्रासिमणन प्रोडेक्ट कम्पनी, सेड न. 50 , ए/1, फेज-3 जी. आई. डी. मी. बतवा, अहमदाबाद (गुजरात) नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मनारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा-4 द्वारा प्रदत्त मक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लाग् करती है।

[सं. एस-35019/138/85/एस. एस.2]

S.O. 1597.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messis Excel Transmission Product Company, Shed No. 501, A/1, Phase-III, G.I.D.C., Vatva, Ahmedabad 45, Gujuat, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions, Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

INo. S-35019(138)/85-SS-II]

का. आ. 8951:—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैं. देवा मीता ट्रेडर्स, 98/1, साउथ अवानीमुला स्ट्रीट, मदुराई-625001, तिमलनाड् नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लाग किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा (﴿) द्वारा प्रदत्त णक्तियों का प्रयोग करने हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35019/139/85/एस. एस.-2]

S.O. 1598.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messes Deva Sita Traders, 98/1, South Avanimoola Street, Madurai-625001, Tamil Nadu, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment,

[No. S-35019(139)/85-SS-II]

का, आ 1599:—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्म अन्ज इंटर प्राइजिज ए/2, 114/2, जी. आई. डी. सी. इस्टेट फेज-2 बतवा-1 रोड, अहमदा-धाद, नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुर्सख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उसत अधिनियम की धारा-1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35019/140/85/एस. एस.-2]

S.O. 1599.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Anuj Enterprises, A/2, 114/2, G.I.D.C. Estate, Phase-II, Vatva I Road, Ahmedabad, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(140)/85-SS-[1]

हा. आ. 1600 --केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है ि मैंपर्म मोनामुथ रोड्येज, 10-ई/3, विवेन्द्रम रोड, तिक्नेलवेली-627002, तमिलनाडु नामक स्थापन के राम्बद्ध नियोज अर्थर कर्मनारियों की बहुसंख्या इस दान पर सहमत हो गई है कि क्षमंचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू ज़िए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय गरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 ती उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियो दा प्रयोग दस्ते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू दस्ती है।

सिं. एप-35019/141/85/एस०एस०-2]

S.O. 1600.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Sonamuthu Roadways, 10-E/3, Trivandrum Road, Titunelveli-627002, Tamil Nadu, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(141)/85-SS-II]

का. आ. 1601: — केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि एमको एल एन (इंडिया) लि. आनन्द सुजीया रोड, बल्लभ विद्यानगर-20 गुजरात, नामक स्थापन के सम्बद्ध नियं कि और क्रमीचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू िए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त प्रवित्तयो दा प्रयोग द रते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को नागू करती है।

[सं. एस-35019/142/85/एस. एस.-2]

S.O. 1601.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Einco Elecon (India) Limited, Anand, Sojitra Road, Vallabh Vidyanagar-20, Gujarat, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(142)/85-SS-II]

का. आ. 1602:—-केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि चूजे कम्बाइंस, 127, दमवा कीन, मालेक्वरम, वंगलीर-560003, वार्नाटका नामक स्थापन के सम्बद्ध नियाजक और दर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य विधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन की लागू किए जाने चाहिए।

अनः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धाराना की उपधारा-4 द्वारा प्रदत्त मक्तियों भा प्रयोग भरते हुए उक्त अधिभियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू धरती है।

[सं. एस-35019/143/85/एम. एस.-2]

S.O. 1602.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Yuje Combines, 127, 10th Cross, Malleswaran, Bangalore-560003, Karnataka, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(143)/85-SS-II]

का. आ 1603: — केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैं. वेगई ऐसो कैमिकल्स, के-3 यूक्ट, इंडस्ट्रियल, एस्टेट, थेनी, तमिलनाडु, नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुमंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि वर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतं केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) ब्रारा प्रदत्त मिन्तयों ा प्रयोग नास्ते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करनी है।

सि. एम-35019/144/85-एम एस-2]

S.O. 1603.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messis Vaigai Agio Chemicals, K3, Unit, Industrial Estate, Theni, Tamil Nadu, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019/144/85-SS-II]

का. आ 1604. — केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैं. बी सिंधानूर तालुक लैंड डेवलपमेंट को-आपरेटिव सोमाइटी लि., सिंधानूर, रायचूर डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटना नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहु-संख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंधों अधिनियम, 1952 (1952 दा 19) के उपबंध उकत स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त मिक्नियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35019/145/85-एस एस-2]

S.O. 1604.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs The Sindhanur Taluk Land Development Co-operative Society Limited, Sindhanur, Raichur District, Karnataka, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019/145/85-SS-II]

या. आ 1605: -- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि बोर फाई। आर्ट प्रैस-ए-८, मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली-64 नामक स्थापत के सम्बद्ध नियोजक और कर्म- जारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि धर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 हा 19) के उपबंधों उक्त स्थापत को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरशार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपवारा(4) द्वारा प्रदक्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

सि. एस-35019/146/85-एस एस-2]

S.O. 1605.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Vir Fine Art Press, A-8, Maya Puri Industrial Area, New Delhi-64, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019/146/85-SS-II]

का. आ 1606:— केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीस होता है कि मैं. प्योव, 24, मुराय मोहल्ला, राज टाकीज अम्पाउंड, इन्दौर, म. प्र.; नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागु किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रवत्त मक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35019/147/85-एस एस-2]

S.O. 1606.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Pio Tech 24, Murai Mohalla, Raj Talkies Compund, Indore, Madhya Pradesh, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment,

[No. 35019/147/85-SS-II]

भा. आ 1607: — केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी कुटुम्ब पेंगन स्कीम, 1971 के पैरा 28-इं के अनुसरण में, यह निदेश देती हैं कि 31 मार्च, 1985 को कुटुम्ब पेंशन पाने बाले पेंशन भोगियों और उसके बाद के कुटुम्ब पेंशन भोगियों को अनुपूरक वृद्धियां नीचे विनिर्विष्ट दरों पर अप्रैल, 1985 के पहले दिन संदी जाएंगी।

- (1) ऐसे पेंशन भोगी जो 100 रुपये 60 रुपये प्रति माह प्रति मास तक पेंशन ले रहेथे। की वृद्धि।
- (2) ऐसे पेंशन भोगी जो 100 रुपये 75 रुपये प्रति माह से अधिक और 200 रुपये प्रति भी वृद्धि। माह तक पेंशन ले रहे थे।
- (3) ऐसे पेंशन भोगी जो 200 रुपये 90 रुपये प्रति माह प्रतिमाह से अधिक पेंगन ले रहे थे। की वृद्धि।
- 2. अनुपूरक वृद्धि की वरें ऐसी कुटुम्ब पेंशन से संबंधित होगा जो कर्म चारी कुटुम्ब पेंशन स्कीम, 1971 के पैरा 28 (1) के निबन्धनों के अनुसार संदेय होगी बंशर्ते कि पेंशन की कुल राशि (जिसमें अनुपूरक वृद्धियां भी शामिल है) अन्तिम प्राप्त वेतन की राशि से किसी भी हालन में अधिक नहीं होगी।
- 3. उपरोक्त अनुपूरक वृद्धि पहले की अधिसूचना संख्या का. आ. 1351, ता. 16 फरवरी, 1983 झा. आ. 1611, तारोख 5-3-1983 और का. आ. 2609, ता. 21-7-1984 द्वारा मंजूरकी गई अनुपूरक वृद्धियों के अतिरिक्त होगी।
- 4. जहां तक 31-3-1982 को पेंशन पाने वाले कुटुम्ब पेंशन भोगियों का संबंध है, उपरोक्त अनुपूरक वृद्धि भारत सरकार के तरकालीन श्रम और पुनर्वात मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 1351, ता. 16-2-1983 इंग्से 1-4-1982 से बढ़ाई गई पेंशा के साथ संबंधित होगी।

[संख्या आरम11025/7/84न एस. एस-4]

S.O. 1607.—In pursuance of the paragraph 28A of the Employees' Family Pension Scheme, 1971, the Central Government hereby directs that the F. mily Pensioners as on 31st March. 1985 and thereafter shall be granted supplementary additions at the rates specified below with effect from the 1st day of April, 1985:—

- (i) Pensioners who were drawing An increase of pension upto Rs. 100/- per month. Rs. 60/- per month.
- (ii) Pensioners who were drawing Anincrease of pension above Rs. 100/- per Rs. 75/- per month. month upto Rs. 200/- per month.
- (iii) Pensioners who were graving An increase of pension above Rz. 200/- per Rs. 90/- per month, month.
- 2. The rate or supplementary additions will be related to the F-mily Pension as would be payable in terms of para 28(1 1796 GI/84-17

of the Employees' Family Pension Scheme, 1971 subject to the condition that the total amount of pension (including supplementary additions) shall in no case, exceed the last pay drawn.

- 3. The above supplementary additions will be in addition to the supplementary additions sanctioned earlier vide S.O. 1351, dated 16-2-1983, S.O. 1611, dated 5-3-1983 and S.O. 2609 dated 21-7-1984.
- 4. In relation to the Family Pensioners as on 31-3-1982, the above supplementary increase will be related to the pension as increased w.e.f. 1-4-1982 vide notification of the Government in the Ministry of Labour and Rehabilitation, S.O. No. 1351, dated the 16th February, 1983.

[F.No. R-11025/7/84-SS-IV]

नई दिल्लो, 2 अप्रैल, 1985

का. अत. 1608.— मैसर्न कातकाता मैडिकल रिसर्च इंक्टोब्यूट, 7/2, डायमंड हारबोर रोड, कातकाता-27 (पिष्टिम बंगाल / 150009) (जिसे इसमें इसके पश्चात उकत स्थापन कहा भया है) ने कार्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अग्निनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा एय है)। धारा 17 की की उपधारा (2क) के अबीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कांचारी किसो पृथक अभिदाय या प्राप्तियम का संदाय किए धिना हो, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्त्रीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बोमा स्त्रीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात जनक्र स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुजेय हैं ;

शतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम् की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त मक्तियी का पयोग करते हुए ओर इसमे उगाबद्ध अनुसूचो में विनिधिष्ट मती के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन बने तान वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्नोम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देतो ।

अन्सूची

- 1. उक्न स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि अध्युक्त, पश्चिम बंगाल को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरोक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरक र समय-समय पर निर्दिष्ट करें।
- 2. नियोजन ऐसे निरोक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भोतार संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) क खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।
- 3. राष्ट्रहिक बोमा स्कोम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं के रखा जाना विवरणियों के प्रस्तुत किया जाना, जान प्रोमियम का संदाय, लेखाओं का अतरण, निरक्षिण

प्रभारों संदाय आदि भी हैं, होने बाले सभी व्ययों का वहन नियोगक द्वारा किया आएगा।

- 4. नियोजक, केन्द्रीय संस्कार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और एव कभी उनमें संशोधन किया जाए तब तक उस संशोधन की प्रति तथा कर्मियारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद-संस्थान के सूचना-पटट पर प्रविशत करेंगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भिष्य निधि का या उक्त अधिनिथम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भिष्य निधि का पहले ही सबस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है, तो नियोजिक, सामूहिक बीमा स्कीम के सबस्य के रूप में उनका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उस की बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदक्त करेगा।
- 6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाने है तो नियोजक सामूहिक बामा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से यृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुकेय ।
- 7. सामूहिक बीमा स्कीभ में किसी वात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन नंदेह रकम उस रकम से कम है तो कर्मचारी को उस दणा में संदेग होतो, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विविध वारिस नाम निर्देणिती को प्रेसिकर के रूप में बीनों रकमों के अन्तर के वरावर रकम क मंदेश करेगा।
- 8. सामूहिंदी नीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संगोधन, प्रादेशिक भीक्या निधि आयुक्त, पिष्णम बगाल, के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसो संगोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकृत प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां प्रादेशिक भविष्य विधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना कृष्टिकीण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।
- 9. यदि किसी कारणवण, स्थापन के कर्मचारं, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक वीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका हैं, अधीन नहीं रह जाते है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों की प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रह की जा सकती।
- 10. यदि किसी कारणयभा, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन नीमा नियम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को भ्ययम हो जाने दिया जाता है, तो छुट रह की जा संभती।

- 11. नियोजक द्वारा प्रोमिथम के संवाय में किए गए किसी व्यक्तिकम की वणा में उन मृत सवस्यों के नाम निर्देशि-शित्तयों या विधिक वारिसों की जो यदि यह छूट नदी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा कायदों के मंदाय का उन्तरदायित्व नियोजक पर होगा।
- 12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किनी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देणितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रक्षम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निर्म से बीमाकृत रक्षम प्राप्त होने के एक माह के भोतर सुनिष्विन करेगा।

[संख्या एस-35014/ 80/ 85-एस एस-4] New Delbi, the 2nd April, 1985

S.O. 1608.—Whereas Messrs Calcutta Medical Research Institute, 7/2, Diamond Harbour Road, Calcutta-27 (WB/15009), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees that the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The en-ployer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of reutrns, payment of insurance premia. transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended alongwith a translation of the salient features recof, in the language of the majority of the employees.
- 5 Whereas are employe, who is already a member of the I'mnlovees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Jasurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6 The employer shall arrange to sphance the benefits available to the employees under the coup Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the emp-

loyees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain the r point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium and responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal helrs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects".

[No. S. 35014/80/85-SS-IV]

का. आ. 1609.—मैंसर्स वेबेल टेलिकम्यूनिकेणन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, 4 और 5 कैनाल वैस्ट रोड, कलकत्ता—700015 (उब्ल्यूबी/ 15705) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिये जाने के लिये आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे है वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुक्रेय है;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 1782, तारीख 8 मई, 1982 के अन्- सरण में और इससे उपाबद अनुसूधी में विनिधिष्ट शतों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को 8 मई, 1985 से तीन वर्ष की अवधि के लिये जिसमें 7 मई, 1988 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

- उक्त स्थापन के संबंध में नियोजन प्रादेशक भविष्य निधि आयुक्त, पश्चिम बंगाल को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिये ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय - समय पर निर्दिष्ट करे।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्त के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।
- 3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, के लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।
- 4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना—पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।
- 6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मजारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मधारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मधारियों के लिये सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुक्षेय है।
- 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी,
 यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन
 संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा
 में संदेय होती है, जब बह उक्त स्कीम के अधीन होता तो,
 नियोजक कर्मचारी के विविध वारिस/ नाम-निर्देशिती को
 प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का
 संदाय करेगा।
- सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशो-धन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पश्चिम बंगाल के पूर्व

अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकृत प्रभाव पड़ने की सभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने की युक्तियुक्त अवसर देगा।

- 9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिससे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नही रह जाते है, या उस स्कीम के, अधीन कर्मचारियो को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते है, तो यह रद्द की जा सकती है।
- 10 यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का सवाय करने मे असफल रहता है, और पालिमी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सवाय में किये गये किसी व्यक्तिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्वेशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरवायित्व नियोजक पर होगा।
- 12. उक्त स्थापन के सबध मे नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्वेशितियो/ विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का सदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा मे भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/44/80- भ. नि. II (एसएस-4)]

SO. 1609—Whereas Messrs Webel Telecommunication Industries Limited, 4 and 5, Canal West Road, Calcutta-700015 (WB/15705) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-sect on (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of the India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notificat on of the Government of India in the late Ministry of Labour SO No 1722 dated the 8th May, 1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annext hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provision of the said Scheme for a further period of three years with effect from 8th May, 1985 upto and inclusive of the 7th May, 1983.

SCHEDULE

1 The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal and maintain such accounts and

- provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.
- 2 The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.
- 3 All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc shall be borne by the employer
- 4 The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Instrunce Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India
- 6 The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available unler the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme
- 7 Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insunance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9 Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scherre of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled
- 10 Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled
- 11 In case of default, if any made by the employer in payment of premium and responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal herrs of deceased members who would have been covered under the said Scherre but for grant of this exemption, shall be that of the employer
- 12 Upon the death of the members evocred under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects"
- का. आ 1610 मैसर्स संधी बीव्रेजेस प्राइवेट लिमिटेड, मुम्बई, आगरा रोड, इंदौर-452001 (एम. पी./1550), मध्य प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चास उक्त स्थापन कहा

गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिये जाने के लिये आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक आभिदाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे है वे ऐसे कर्म-चारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल है जो उन्हें कर्म-चारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय है;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करने हुए और भारत सरकार के श्रम मंद्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 2948 तारीख 21 अगस्त, 1983 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को 21 अगस्त, 1985 से तीन वर्ष की अवधि के लिये जिसमें 20 अगस्त, 1988 भी सिम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अन् सूच /

- 1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, मध्य प्रदेश को ऐसी विवरणियों भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिये ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-सम्प्रपर निदिष्ट करें।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संवाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।
- 3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन, नियोजक द्वारा किया जायेगा।
- 4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोधित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए; तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना- पट्ट पर प्रविधित करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भिष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भिवष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम गुरन्त दर्ज करेगा

और उसकी बाबत आवण्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

- 6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिये सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुश्रेय हैं।
- 7. जीवन बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दणा में संदेय होती है, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/ नाम निदंशिती को प्रतिकर के एप में दोनों रकम रकमों के अन्तर के बरावर रकम का संदाय करेगा।
- 8. सामूहिक वीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संणो-धन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, मध्य प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के विना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशो-धन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पढ़ने की -संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।
- 9. यदि किसी कारणवण, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय, जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारूणवंश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के. संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्दे- शितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।
- 12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्वेषितियों/ विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से वीमाकृत रकम प्राप्त होने के सान दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा

[मंख्या एस-35014/57/82-भ. नि.(jj)एसएस-4]

S.O. 1610.—Whereas Messrs Sanghi Beverages Private Limited, Bonzbay-Agra Road, Indore-452001 (Madhya Pradesh), (MP/1550), (herematter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour S.O. No. 2948 dated the 21-8-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 21st August, 1985 upto and inclusive of the 20th August, 1988.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable

oppertunity to the employees to explain their point of

- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as afready adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium and responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heir of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects".

[No.S. 35014/57/82-PF.II(SS.IV)]

का०आ०1611.—मैससं एच०एम०एम० लिमिटेड, दोबलई-स्वरम पूर्वी गोदवारी जिला, आन्ध्र प्रदेश (ए०पी०/4322) (जिसे इसमे इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) को धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिये जाने के लिये आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्स स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप मे जो फायदा उठा रहे है वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कोम कहा गया है) के अधीन अनुजीय है;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त णिक्तयों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का अग 2725 तारीख 4 अगस्त, 1982 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट णतों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को 4 अगस्त, 1985 से तीन वर्ष की अवधि के लिये जिसमें 3 अगस्त, 1988 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपवन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रावेशिक भविष्य निधि आयुक्त, आन्ध्र प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिये ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रस्थेक मास की समिष्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन गमथ-समय पर निर्दिष्ट करे।
- 3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तृत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निगीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियाजक द्वारा किया जायेगा।
- 4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन का प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सुचना-पट्ट पर प्रदिशित करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजिक, सामुहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी वाबन आवष्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।
- 6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढाये जाने हैं तो नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों मे समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिये सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदें उन फायदों से अधिक अन्कूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुझेय है।
- 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रक्षम उस रक्षम से कम है जो कर्मचारी को उस दक्षा में संदेय होती हैं, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक बारिस/नाम निर्देणित को प्रतिकर के रूप में दोनों रक्षमों के अत्तर के बंरावर रक्षम का संदाय करेगा।
- 8. सामृहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संगोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, आंध्र प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के विना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संगोधन से कर्मचारियों के हिन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने में पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का यक्तियुक्त अवसर देगा।
- 9. यदि किसी कारणवण, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामृहिक बीमा स्तीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते है. या उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने बाल फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रह की जासकर्ता है।

- 10. यदि किनी कारणवण, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिमी को व्यपनत हो जाने दिया जाता है तो छूट रह की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय मे किये गये किसी व्यतिक्रम की दणा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के गंदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।
- 12. उक्त स्थापन के संबंध में, नियोजन, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देणितियों/विश्विक वारिसों को बीमाकृत रकम का मंदाय तत्यरता से और प्रत्येक दणा में भारतीय जीवन वीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं॰ एस-35014/61/82-भ०नि॰-I]-एसएस 4]

S.O. 1611.—Whereas Messis H.M.M. Limited, Dowlaishwaram, East Godawari District, Andhra Pradesh, (AP/4322), (here nafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act. 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour S.O. No. 2725 dated the 4th August, 1982 and subject to the conditions specied in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 4th August, 1985 upto and inclusive of the 3rd August, 1988.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner. Andhra Pradesh and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.
- 3 All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and

when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Andhia Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Cornoration of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10 Where, for any reason, the employer fails to nay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium and responsibility for payment of assistance benefits to the nominees or the legal heir of deceased members who would have been covered under the said Schembut for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12 Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominea/Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects".

[No. S 35014/61/82-PF-II/SS-IV]

का०आ० 161?—मैसर्स संधी ब्रदर्स (इंदौर) लिमिटेड, 6, मनोरमागंज, इंदौर-452001 (मध्यप्रदेश) (एमपी/249) (जिमे इसमें इसके पश्चान् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मवारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चान् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अवीन छट दिये जाने के लिये आयेदन किया है:

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थान के कर्मचारी किसी पथक अभिदाय या प्रीमियम कर संदाय किये विना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामुहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीम। के ख्य में जो फायवा उठा रहे है वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदो से अधिक अनुकूल है जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पण्यात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय है;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) बारा प्रवत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का अगः 3232 तारीख 11-9-1982 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट गतों के अधीन रहीं हुए, उना स्थापन को 10-9-1985 में तीन वर्ष की अवधि के लिये जिसमें 9 सितम्बर, 1988 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन में छूट देती है।

अनुसूची

- 1. उन्त स्थापन के सबंध में नियोजन प्रावेशिक भविष्य निधि आयुक्त, मध्य प्रदेश, को ऐसी विवरिणया भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिये ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय~स्थायर निर्दिष्ट करे।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्त के 15 दिन-के भीतर संवाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उकत अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।
- 3. साम्हिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी हैं, होने वाले मभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।
- 4. तियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये; तय उस मंशोधन की प्रति यथा कर्षचारियों की बहुमंख्या की भाषा में उसकी मुख्य वातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पड़ पर प्रदिशत करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य हैं, उसके स्थापन में निगोजित किया जाता है तो नियोजक, सामृहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उपका नाम तरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवण्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।
- 6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपनब्ध फायदे बड़ाये जाते हैं तो नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समृचित स्प से बुद्धि की जाने की ब्ययस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिये सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे

उन फायदों से अधिक अनुकूल हो, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

- 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए ते, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती है, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, तियोजक कर्मचारी के विविध बारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।
- 8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, मध्य प्रदेश के पूर्व अतुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने की युक्तियुक्त अवनर देगा।
- 9. यदि किसी कारणवंश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन जीना निगम की उस सामूहिल बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहुंचे अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर. जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है, तो छूट रह की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किमी व्यक्तिकम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उना स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के मंदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।
- 12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजका, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सवस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक वशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से वीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिधिनत करेगा।

[संख्या एस-35014/18/82-भ०निः-II(एस एस-4)]

S.O. 1612.—Whereas Messrs Sanghi Brothers (Indore) Limited, 6, Manoramaganj, Indore (Madhya Pradesh) (MP/249), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment 1796 GI 84—18.

of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour S.O. No. 3232 dated the 11th September, 1982 and subject to the coaditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 10th September, 1985 upto and inclusive of the 9th September, 1988.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such reutrns to the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insutance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insu-

rance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium and responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heir of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/Legal beirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects".

[No. S. 35014/18/82-PF.II(SS.IV)]

का. आ. 1613.—मैसर्स राजपुताना मोटर्स 6 मनोरमागंज इंदौर-2152001 मध्य प्रदेश (एमपी/590) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनयम कहा गया है) की धारौँ 17 की उपधारा (2क) के अधीन छुट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उकत स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियस का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पण्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुजेय है;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त मिन्यों का प्रयोग करतें हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3031 तारीख 28 अगस्त, 1982 के जनु-सरण में और इससे उपायद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट मतौं के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को 28 अगस्त, 1985 स तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 27 अगस्त, 1988 भी सम्मिलत है, उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन में छूट देती है।

अनुसूची

- उक्त स्थापन के संबंध में नियोज हा प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, मध्य प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार पर समय-समय पर निर्दिष्ट करें।
- 2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3 के खंड (क) के अधीन सनय-समय पर निर्दिष्ट करे।
- 3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिन्त अन्तर्गतः लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना,

- बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों कः मंदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों दा बहुत नियोजक द्वारा किया जाएगा।
- 4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमो की एक प्रति और कभी उनमें संगोधन किया जाए, तब उस संगोधन की प्रति सथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदिशात करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीवियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।
- 6. यदि सामूहिक बीवा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढाए जाते हैं तो नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुक्षेय हैं।
- 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बास के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती है, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।
- 8. मामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, एध्य प्रदेश के पूर्व अनुभोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हिल पर प्रतिकृत प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने की युक्तियुक्त अवसर देगा।
- 9. यदि किसी कार्यवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रह की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यवगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रह की जा सकती है।

- 11. नियाजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मत सदस्यों के नाम निर्देशितियो या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगः।
- 12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्य होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संवाय तत्परत। से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम ने बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या 35014/9/82-भ.नि.] (एस.एस.-4)]

S.O. 1613.—Whereas Messrs Rajputana Motors, 6, Manoramaganj, Indore, Madhya Pradesh (MP/590), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of the India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour S.O. No. 3031 dated the 28th August, 1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further neriod of three years with effect from 28th August, 1985 upto and inclusive of the 27th August, 1988.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Madbya Pradesh and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.
- 3 All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is erroloyed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insunance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer falls to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium and responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heir of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Schere the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects".

INo. S. 35014/9/82-PF-Π(SS.IV)]

CORRIGENDUM

New Delhi, the 4th April, 1985

S.O. 1614.—In the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour and Rehabilitation, Department of Labour, No. S.O. 3518 dated 16th October, 1984 published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 3rd November, 1984, in line 6 for "Circular Road" read "Circular Road, Calcutta-19".

[No. S-35017(67)/84-PF.II]

का. आ. 1615 — केन्द्रीय मरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 8 के खण्ड (क) के अनुसरण में श्री एच.एम.एस. भटनागर सचिव, भारत सरकार श्रम मंद्रालय, नई दिल्ली की श्री बी. जी. देशमुख के स्थान पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम की स्थायी समिति के अध्यक्ष के रूप में नामनिविष्ट किया है

अतः अब केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की घारा 8 के अनुसरण में, भारत सरकार के भूतपूर्व, श्रम और पूनर्वास मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का आ 1820-

विनांक 22 मार्च, 1983 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :----

उक्त अधिसूचना में, "केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 8 के खण्ड (क) के अधीन नामनिर्दिष्ट" शीर्षक के नीचे मद 1 के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर निग्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएंगी, अर्थात् :---

"श्री एच. एम. एस. भटनागर, सचिव, भारत सरकार, श्रम महालय, नई दिली ं"

> [संख्या यू-16012/7/84-एच.आई.] ए. के. भट्टराई, अवर संचिव

S.O. 1615.—Whereas the Central Government has, in pursuance of clause (a) of Section 8 of the Employees State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) nominated Shri H.M.S. Bhatnagar, Secretary to the Government of India, Ministry of Labour as the Chairman of Standing Committee of the Employees' State Insurance Corporation in place of Shri B. G. Deshmukh:

Now, therefore, in pursuance of section 8 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, in the late Ministry of Labour and Rehabilitation S.O. No. 1820, dated the 22nd March, 1983 namely:—

In the said notification, under the heading "(Nominated by the Central Government under clause (a) of Section 8)" for the entry against Serial number 1, the following entry shall be substituted, namely:—

"Shri H.M.S. Bhatnagar,
Secretary to the Government of India,
Ministry of Labour,
New Delhi."

[No. U-16012/7/84-HI]
A. K. BHATTARAI, Under Secy.

नई विल्ली, 28 मार्च, 1985

का. आ. 1616.→ औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 वा 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, भारत कोर्किंग कोल लि. की बरोरा कोलियरी के प्रबंधसंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नं. 2, धनबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 21-3-1985 को पाप्त हुआ था।

New Delhi, the 28th March, 1985

S.O. 1616.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2. Dhanbad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Barora Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Limited, and their workmen, which received by the

Central Government on the 21st March, 1985.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

Reference No. 7 of 1983,

In the matter of Industrial Disputes under Section 10(1)(d) of the I.D. Act., 1947.

PARTIES:

Employers in relation to the management of Barora Colliery of Messrs. Bharat Coking Coal Limited and their workmen.

APPEARANCES:

On behalf of the employers.—Shri B. Joshi, Advocate.

On behalf of the workmen.—Shri B. K. Ghose, Member, Executive Committee, Janta Mazdoor Sangh.

STATE: Bihar. INDUSTRY: Coal.

Dhanbad, the 18th March, 1985

AWARD

The Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the I.D. Act., 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication under Order No. L-20012(242)/82-D.III(A), dated, 28th January, 1983

SCHEDULE

"Whether demand of Secretary, Janta Mazdoor Sangh, Iharia (Dhanbad) for regularisation of Shri Haradhan Banerjee as Electrical Supervisor grade 'A' by the management of Barora Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Limited is justified? If so, to what relief is the workman entitled?".

The case of the workmen is that the concerned workman Shri Haradhan Banerjee has been working as Electrical Supervisor at Barora Colliery and is getting difference of wages between technical and supervisory grade-C and technical and supervisory grade-A with effect from 18-1-81. The concerned workman has continuously worked against a permanent vacancy for more than one year and as such he is entitled to be regularised in Technical and Superv sory Grade-A and his designation may accordingly be changed with effect from 18-1-81.

The case of the management is that the present dispute has been raised due to certain confusion by the workmen. The post of Electrical Supervisor do not now exist under the Wage Board Recommendation after the changing pattern developed in the Coal Mines. The persons holding Electrical Supervisor's certificates were called Electrical Supervisors. Prior to the implementation of the Wage Board Recommendation the top most post of Electrical department was held by an Electrical Supervisor and as such the posts used to be designated as the post of Electrical Supervisor. The Electrical Supervisors used to be appointed as Engineer of Coal Mines prior to the coming into force of the Coal Mines Regulation 1957. After the introduction of various types of machines in Coal Mines the Coal Mines Regulation stipulated appointment of persons holding degree or diploma in Electrical as Engineers of the Coal Mines. After the nationalisation the management introduced several machines in Coal Mines and appointed Senior Engineers, Colliery Engineers and Junior Engineers as, Asstt. Engineers. Similarly Junior Electrical Supervisors are appointed as Asstt. Foreman (Electrical) in Grade-C Semi senior Flectrical Supervisors are promoted to the post of Foreman (Electrical) in Grade-B and Senior Flectrical Supervisors are promoted as Engineer of the Coal Mines after passing Flectrical or mechanical engineering degree although there is no statutory bar and no person is appointed as Foreman Incharge (Electrical) after passing Electrical Supervisory certificate without having experience on the post and giving satisfactory performance

and thereafter promotion is accordingly made according to the cadre scheme. The concerned workman is a Junior Electrical Supervisor and does not possess sufficient experience to be appointed as Forenian Electrical. He has been appointed as Assistant Forenian (Electrical), and he has been placed in Grade-C. He had on some occasions worked as Forenian and was paid the extra allowance for acting on higher posts. He has not yet been promoted to Grade-A is without any justification. The demand of the workmen is unjustified and the concerned workman is not entitled to any relief.

The only point for determination in this case is whether the concerned workman is entitled to be regularised as Electrical Supervisor Grade-A.

The workman has examined himself as WW-1. The management has examined two witnesses, one is a Senior Personnel Officer of Barora Area and the other is Executive Engineer in the Barora Colliery. The workman has exhibited two documents Ext. W-1 and W-2 and the management as exhibited one document viz. Promotion policy for E&M non-executive cadic in BCCL and the same is marked Fxt. M-1.

The concerned workman claims regularisation as Electrical Supervisor in Technical and Supervisory Grade-A on the basis of the Office order Ext. W-1 dated 18-1-81. It will appear from this office order that the concerned workman who was working as an Asstt. Foreman of Technical Grade-C. was authorised to work as Electrical Supervisor Technical Grade A and he was to be paid the difference of wages of Technical and Supervisory Grade-A with effect from 18-1-81. This Office order 1xt, W-1 is only an authorisation given to the concerned workman to work as Electrical Supervisor Technical Grade-A and is not an appointment or promotion in Electrical Supervisor Technical Grade-A. The workman WW-1 has stated in his cross-examination that in Wage Board Recommendation there are posts of Asstt. Foreman, Foreman and Foreman Incharge. He does not know if the rules of BCCL provide that a workman from Assit. Foreman is to be promoted as Foreman and thereafter Foreman is to be promoted as Foreman Incharge. It will also appear from his evidence that Shri R. C. Roy Foreman Incharge is in Grade-A. He has stated that in May, 1979 he was promoted in Grade-C from the post of Flectrician Cat. V. In his further arrest examination has been detailed. further cross-examination he has stated that before March of April, 1983 he was getting the difference of wages between Grade A&C. But thereafter he was not getting the officience of wages. He has also stated that an Electrician is promoted to Grade-C as Asstt. Foreman after obtaining Electrical Supervisory Certificate. He has stated that Asstt. Foreman, Foreman and Foreman Incharge perform the duties under the Electrical Rules and that Foreman Incharge is the head of the Electrical department and controls all the employees of the department. Fxt. M-1 is the Promotion policy or E&M non executive cadres in BCCL. It provides that in accordance with the promotion policy the General Manager of the Area concerned is the cadre controlling authority for the post up to cat. VI and technical Supercontrolling visory Grade-C and that the Chief Inginee E&M is the cadre controlling authority for the post of Technical and Supervisory Grade B&A. It also provides that the promotion will be made on the basis of the approved staffing pattern for the colliery to be finalised in the manner laid down m Clause VI of the cadre scheme. MW-2 is the I recutive Engineer of Barora Colliery. He has stated that the promotion of Electrical personnel is done according to the promotional scheme of the cadre. He has stated that a person holding electrical supervisory certificate is first appointed as Asstt. Foreman Electrical and, thereafter he is promoted as Foreman. It wil also appear from his evidence that Shri R. C. Roy is Electrical Foreman Incharge in respect of all other surface installation and that Shri workshop of all other surface installation and that Shri K. C. Paul was the Foreman Incharge in respect of all the underground and the concerned workman is working under Shri K. C. Paul. He has further stated that the duties prescribed under the Electricity Rules and Act are performed by the Asstt. Foreman, Foreman and Foreman Incharge who hold the electrical supervisor certificate but their responsibility varies according to the posts held by them and the persons holding higher posts have higher responsibilities in respect of breakdown. MW-1 Shri M. K. Singh is the Senior Personnel Officer working in Barora Area. According to his 1796 GI/84--19

evidence it will appear that there are posts of Asstt. Foreman, Foreman and Foreman Incharge in each colliery and that the Foreman and the Asstt. Foreman work under the l oreman Incharge of the colliery. He has stated that Foreman Incharge is in Grade-A, Foreman in Grade-B and Asstt. Foreman in Grade-C. He has stated that since February, 1978 the promotion of electrical and mechanical persons are er red by the promotion scheme Ext. M-1. He has also stated that, there is no post of Electrical Supervisor in any colliety after the implementation of the Wage Board Re-commendation. Thus on perusal of Ext. M-1 and the evi-dence of MW-1 and MW-2 it will appear that there is a promotion scheme of the management according to which the promotion is made and that the Asstt. Foreman is promoted to the post of Foreman and Foreman is promoted to the post of Foreman Incharge on fulfilling the conditions promotion laid down under the promotion scheme. From the evidence of WW-1 also it appears that the Asstt. Foreman is in Grade-C, a foreman is in Grade-B and that a Foreman Incharge is in Grade-A. Thus according to the promotion scheme an Asstt. Foreman cannot directly promoted to the post of Foreman Incharge in Grade-A and that an Assit. Foreman can be first momoted to the post of Foreman under Grade-B and only thereafter promotion can be made in Grade-A. Admittedly the concerned workman is in Grade-C and according to the promotion scheme and the evidence in the case the concerned workman who is in Grade-C may be promoted as Foreman in Grade-B and he cannot jump promotion as Foreman Incharge in Giade-A. The order of authorisation Ext. W-1 appears to be only an authorisation given to the concerned workman to work in Technical Grade-A when required and it cannot be said that he was promoted to Grade-A as is being claimed by the concerned workman. At page 79 in Chapter-8 of the Wage Board Recommendation Volume I the wage structure of engineering department is stated. It will appear from this that those who are designated as Flectrical Supervisor. Flectrical Chief Foreman, Flectrical Senior Foreman and Flectrical Foreman Incharge before the implementation of the Wage Board Recommendation were designated as Foreman Inchaige Technical in Grade-A. It will further aprear that Asstt Foreman Flectrical, Asstt Electrician were designated as Asstt Foreman Electrical in Grade-C and that held Flectrical Foreman. Electrical Foreman and Flectrical Chargeman were designated as Electrical Foreman. Grade-B The Wage Roard Recommendation also shows that Assit Foreman Electrical, Foreman Electrical and Forenvin Inchange Flectrical were the 3 posts under the electsenior to Grade-C rical department and that Grade-B was and Grade-A was senior to Grade-R.

As the concerned workman was in Asstt Foreman in Grade-C he could not be promoted to Grade-A and as such the demand of the workman does not appear to be justified. Moreover the promotion from Grade-C to Grade-B has to be made in accordance with the promotion scheme and unless the concerned workman fulfills all the conditions of promotion to Grade-B he cannot be promoted by the Tribunal. MW-2 has clearly stated that the concerned workman who is presently working as Asstt. Foreman will be duly considered for promotion according to the promotion scheme when vacancy will arise. WW-1 has stated that he has been promoted in Grade-C from Electrician Cat. V only in May, 1979 and as such it is very ontimistic on the part of the concerned workman to get Grade-A in such a short region and such demand was against the promotion scheme.

Taking all the facts evidence and circumstances of the case into consideration, I hold that the demand of the Secretary, Ianta Mazdoor Sangh, Jharia (Dhanbad) for regularisation of the concerned workman Shri Haradhan Banetice as Flectrical Supervisor Grade-A by the BCCI is not justified and as such the concerned workman is entitled to no tellef.

This is my Award.

⁷ N. SINHA, Presiding Officer INo. J-22012(242)[82-D. JJ (A)]

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 1985

कः. आ. 1617—औतोगिका विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनसरण में, केन्द्रीय गरकार, भारत कोकिंग कोल लि. की तेतुलमारी कोलियरी के प्रबंधनंत्र से सम्बद्ध नियोजको और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण नं. 2, धनवाद के पंचाट को प्रकाणन करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 25-3-1985 को प्राप्त हुआ था।

New Dolhi, the 1st April, 1985

S.O. 1617.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Dhanbad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Tetulmari Colliery of Messis Bharat Coling Coal Limited, and their workmen, which was received by the Central Government on the 25th March, 1985.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

Reference No. 94 of 1984

In the matter of Industrial Disputes under Section 10(1) (d) of the I.D. Act, 1947.

PARTIES:

Employers in relation to the management of Tetulmani Collicry of Messis. Bharat Coking Coal Limited and their worknen.

APPFARANCES:

On behalf of the employers.—Shri G. Prasad, Advocate.

On behalf of the workmen.—Shri D. Mukherjee, Secretary, Bihar Colliery Kamgar Union.

STATE: Bihar. INDUSTRY: Coal.

Dhanbad, the 20th March, 1985

AWARD

The Government of India in the Ministry of Labour & Rebabilitation in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the I.D. Act., 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication under Order No. I-20012(317)/84-D.III(A), dated 20-12-1984.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Tetulmari Colliery of Messrs. Bharat Coking Coal Limited. P. O. Sijua, Distt, Dhanbad in stopping Shri Kishen Prasad Turi from work as Bonus Clerk Provident Fund Clerk with effect from 10-6-1983 is justified? If not, to what relief the concerned workman is entitled?"

The case of the workmen is that the concerned workman Shri Kishun Prasad Turi was appointed on 25-12-82 under the Land Acquisition Scheme as Miner/loader but actually he was deployed to work as Provident Fund/Bonus Clerk from the very day of his joining as per understanding between the nunagement and the concerned workman. The concerned workman is an educated young boy and the management had given him an understanding to deploy him in clerical job keeping in view his educational qualifications. In perusance of the said understanding given by the management the concerned workman and his father had agreed to give his land to the management of M/s. B.C.C. Itd. The concerned workman had been working as Bonus P F. Clerk continuously to the satisfaction of the management since the date of his appointment. As soon as the conceined workman registered his land in the name of M/s. B.C.C. the management started planning to remove him from service and the management stopped him from working as Bonus-cum-P.F. Clerk vide letter dated 25/26-5-83. The action The action of the management in stopping the concerned working from working as Bonus-cum-P.F. Clerk was a breach of understanding and cheating of the local villagers. No teason was assigned by the management while stopping the concerned workman as Bonus-cum-P.F. Clyerk. The concerned workman represented before the management several times for allowing him to work as Bonus-cum-P.F. Clerk but with no effect. The union raised industrial dispute before the ALC(C) for conciliation but the same ended in failure and thereafter this case has been referred by the Government of India. According to the workmen the action of the management in stopping the concerned workman from working as Bonus-cum-P.F. Clerk was illegal, arbitrary and unjustified and against the principles of natural justice. The management had not given any notice under Section 9A of the LD. Act. It is submitted that the management be directed to allow the concerned workman to work as Bonus-cum-P.F. Clerk with all consequential benefits after regularising him in the jub.

The case of the management is that the concerned workman Shri Kishon Prasad Tui was appointed under the Land Acquisition scheme initiated by M/s. B.C.C. Itd as temporary Miner/loader at Tetulmary colliery in group VA on an initial pay of Rs 18.50 p. per day as per terms and on an initial pay of Rs 18.50 p. per day as per terms and conditions of service land down in the appointment letter dated 3/4-11-82 on piece rate basis. The concerned workman joined on 25-11-82. Under the I and Acquisition Scheme the appointments are to be made on piece rate basis and not on time rate basis. The father of the concerned workman registered two Sale deeds in respect of 2.44 acres of land in Mouza Nagtikalam Mouza. Originally the father of the concerned workman had agreed to sell acres of land and as such the management of M/s R.C.C. Itd. arreed to employ two of his nominces namely the concerned workman and Shri kasinath Turi and they were actually allowed to work. On a scrutiny it was found that the father of the concerned workman had only 2.44 acres of land and therefore the management refused to allow the two nominees to work and their work was stopped. Subsequently it was agreed that only the concerned workman will under the Land Acquisition scheme for 2.44 acres of land sold, the concerned workman was allowed to join his service as Minerlloader in Tetulmary colliers with immediate effect vide letter dated 15-12-83.

The concerned workman was a student at the time of his first appointment and therefore keeping in view his future carrier he was allowed to work on his request as Clerk in the Bonus and P.F. Section temporarily till completion of his examination against temporary vacancy caused by leave/sick of permanent employees although as per I and Acquisition scheme any person selling land or his nominee is appointed as piece rated Miner loader in Group VA. The concerned workman was never appointed as time rated worker or to work as Bonus P.F. Clerk. He had hardly worked for a period of 6 months as Bonus-cum-P.F. Clerk. As the concerned workman had not been employed on time roted basis, he was stopped from work as Bonus-cum-P.F. Clei) with effect from 10 6-83. Since 15-12-83 the concerned work man has been allowed to work as Minerlloader in Group VA It is denied by the management that the concerned workman was given an understanding that he would be deployed permanently in clerical job. There was never an agreement between the vendor of the land and the management that the concerned workman would be offered time rated elerical job. The management was fully justified in appointing the concerned workman and allowing him to work as Miner loader as per terms of his appointment. No notice under Section 94 of the ID. Act was necessary as the concerned workman had been appointed on niece inted basis as Miner Joader and that he was allowed to work only temporarily as Bonus-cum-P.F. Clerk for the number of his studies. On the above facts it has been submitted on behalf of the management that the concerned workman is not entitled to any relief.

The point for consideration in this case is whether the action of the management was justified in stopping the concerned workman from work as Bonus-cum-P F. Clerk with effect from 10-6-83.

The management examined three witnesses in support of his case and the workmen examined the concerned workmen in support of the case. The management has further exhibited documents which have been marked Ext. M-1 to M-13. The workman also have exhibited documents which have been marked Ext. W-1 to W-3.

Some facts are admitted by the parties. It is admitted case of the parties that the concerned workman was appointed under the Land Acquisition scheme as Loader Miner, in Tetulmari Colliery in Cat. V.A on initial pay of Rs. 18.50 P. per day on piece rated basis vide letter of appointment ext. M-3 dated 3-11-82. It is also admitted by the management that the concerned workman was working as P.F. cum-Bonus Clerk since the date of his appointment till his work was stopped on 10-6-83. It will also appear that the Kuldip Turi father of the concerned workman and others had executed two saics deeds dated 15-10-82 by which 2.44 acres of land were sold to B.C.C. Ltd. It was on the basis of the said sale of 2.44 acres of land to M/s, B.C.C. 1.td. that the concerned workman was given employment under the Land Acquisition scheme. WW-1 is the concerned work-man Shri Kishun Prasad Turi. He has stated that he was appointed as Minei loader under the land acquisition scheme vide appointment letter Ext. M-3. Ext. M-3 dated 3-11-82 shows that the concerned workman was appointed as shows that the Miner loader at Tetulmary colliery in Cat, VA on piece rate basis on initial basic pay of Rs. 18.50 P. per day. This according to the appointment letter and evidence of the component of the specific pay. concorned workman itself it will appear that the concerned workman was appointed as Miner loader under the Land Acquisition Scheme. The land acquisition scheme is 1-xt. M-12 in the case. It will appear from this circular that employment was to be offered to those whose lands were acquired by M/s. B.C.C. Ltd. It was provided that one person for sale of every two acres of paddy land and three acres of other lands would get employment and that the appointment shall be on piece rate basis and the persons selected for appointment will be appointed as Miner tramme, and underground labourers. Thus according to the circular Ext. M-12 a person under the land acquisition scheme was given employment on sale of two acres of paddy land and three acres of non-paddy land as Min21 Trammers on piece rated basis. Of course the conditions given under the circular are only guidelines but as stated by the management's witnesses the appointment in the land acquisition scheme were made in accordance wih the conditions as laid down in the circular Fxt. M-12. It is therefore apparent that the concerned workman was appointed as Miner loader on piece rated basis under the Land Acquisition scheme.

It is also admitted that the concerned workman although appointed as Miner loader under the land acquisitions scheme was working as P.F.-cum-Bor's Clerk since the date of his joining. The case of the management is that the concerned workman was deployed to work temporarily as P.F.-cum-Bonus Clerk on the request of the concerned workman as he was prosecuting his studies. The case of the concerned workman is that he was permanently working as P.F.-cum-Bonus Clerk and it is decied by him that he was temporarily engaged to work as P.F.-cum-Bonus Clerk. The case of the concerned workman is that he was permanently engaged to work as P.F.-cum-Bonus Clerk against the nature of his appointment vide Ext. M-3. Admittedly, the concerned workman has no paper with him to show that he was permanently working as P.F.-cum-Bonus Clerk. Of course the management has also not produced any paper of the produced that the content of the course the management has also not produced any paper. to show that the concerned workman was temporarily deployed to work as P.F.-cum-Bonus Clerk on his own representation for prosecuting his studies. As the concerned workman is claiming against the terms of his appointment it is for the concerned workman to establish that he was permanently employed to work as P.F.-cum-Bonus Clerk. MW-2 Shri Ranjlt Kumar Sinha, Senior Administrative Officer in Sijua Area has stated that the concerned workman had requested that he is a student and as such he may be given temporarily job of P.F.-cum-Bonus Clerk and accordingly the concerned workman was temporarily given the job of P.F.-cum-Bonus Clerk. He has further stated that the concerned workman told that his examination was flushed and he was saled to work as Minerlloeder and finished and he was asked to work as Miner loader and presently the concerned workman is working as Miner loader. He has also given reason as to why no notice under Section 9A of the I.D. Act was given to the concerned workman when his work of P.F.-cum-Bonus Clerk was stopped and was asked to work as Miner loader. He has stated that as the concerned workman was temporarily given the job of P.F.-cum-Bonus Clerk no notice was given to the concerned workman when he was asked to work to his original post of employment. In his cross-exananation he had denied that the concerned workman was employed in a permanent vacancy of P.F.-cum-Bonus Clerk, MW-3 is the Dy. Personnel Manager. He has stated that the appointment of the concerned workman was made in accordance with the circular Ext. M-12 and that under the said scheme no one can be employed in clerical grade. He has further stated that the concerned workman had requested that he was a student and was to appear in examination and as such some other job may be given to him and thereafter he was allowed to work temporarily as P.F.-cum-Bonus Clerk. Thus the decision of the fact that the concerned workman was allowed to work as P.F.-cum-Bonus Clerk depends on the oral evidence. The oral evidence of the concerned workman cannot be accepted in view of the letter of his appointment Ext. M-3 and the evidence adduced on behalf of the management which appears to be more convincing.

One may have some sympathy for the concerned workman in seeing him appointed as P.F.-cum-Bonus Clerk in view of the fact that he had already worked for about 7 months as P.F.-cum-Bonus Clerk since the date of his joining but the whole question is whether the said sympathy can be allowed to over power the admitted terms and conditions of appointment of the concerned workman. Ext. M-9 dated 25]26-5-83 is the letter for stopping the work of the concerned workman. It will appear from this letter that the concerned workman along with Kashinath Turi were employed as Minerloader against purchase of lands pending approval of the headquarters and it was observed by the Director (GRP) that it was not possible to grant two employments for 2.44 acres of land and as such they should be stopped immediately from their employment until further orders. Thus from this letter it will appear that the concerned workman along with Kashinath Turi were stopped from work as two persons could not be employed under the Land Acquisition for the sale of 244 acres of land. It will, therefore appear that reason has been assigned as to why work of the concerned workman along with another was stopped and it cannot be said that there was no reason of the stoppage of the work of the concerned workman. It will further appear from Ext. M-5 dated 15-12-83 which is a letter from the Senior Administrative Officer to the Dy. C.M.E., Telulmari colliery referring to the stoppage of work of the concerned workman vide letter dated 25|26-5-83 and it further states that the party has now drawn the consideration of the money of the land and given consent in writing to accept one employment against the land and as such Shri Kishun Prasad Turi be allowed to join his services as Miner loader. The workmen have rejoin his services as Miner loader. The workmen have referred to the note of Shi M. K. Singh, Senior Personnel Officer which is Ext. W-1 in the case. The note Ext. W-1 is dated 20-12-83. After the concerned workman was allowed to work as Miner loader from 15-12-83, the note states that the concerned workman was working as P.F. and Bones Clerk from 25-12-82 to 11-6-83 and he was stopped for some land dispute and has been allowed to work from 15-12-83. The note further states that the work of the concerned workman was very satisfactory and he should be given change to work as Clerk It appears he should be given chance to work as Clerk. It appears therefore that the concerned workman was satisfactorily working as P.F.-cum-Bonus Clerk but this Tribunal cannot force the management to regularise him in the said post as he was acually appointed as Miner loader on piece rate basis under the Land Acquisition scheme. It is up to the management to consider if the concerned workman can be usefully employed in any job other than miner loader. I have already discussed the evidence to show that there is no reliable evidence to indicate that the concerned workman, was employed to work as P.F.-cum-Bonus Clerk permanently against the terms of his employment and as such it is not possible for this Tribunal to direct the management to regularise the concerned workman as P.F.-cum-Bonus Clerk.

Taking the enthe facts evidence and circumstances of the case into consideration I hold that the action of the management of Tetulmari Colliery of Mls. B.C.C. Ltd., for stopping Shri Kithun Prasad Turi from work as Bonus Clerk! P.F. Clerk with effect from 10-6-83 is justified and as such

the concerned workman is entitled to no relief.
This is my Award.

I. N. SINHA, Presiding Officer [No. L-20012(317) | 84-D.III(A)]
A. V. S. SHARMA, Desk Officer

नई दिल्ली, 30 मार्च, 1985

का , प्रा 1618. -- बीड़ी तर्मकार कत्याण निधि नियम, 1978 के नियम 3 के उप-नियम 2 के साथ पठित बीड़ी कर्म-कार कल्याण निधि अधिनियम, 1976 (1976 का 62) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करने हुए केन्द्रीय मरकार उडीसा राज्य के लिए एक सलाहकार समिति गठित करती है जिसमें निम्नलिखित मदस्य होंगे, अथित; --

- श्रम ग्रौर राजगार मंत्री, --श्रध्यक्ष उड़ीसा सरकार, भुवतेण्वर
- कल्याण श्रायुक्त
 प्लाट नं. 33, अर्णाक नगर --उपाध्यक्ष
 भूबनेश्वर पदेन
- श्रमासुक्त, उड़ीमा
- श्री वीरेन्द्र कुमार पाण्डे --- गप्तस्य पदेन

विधान सभा मपस्य, झारम्गुदा

मदस्य पेदेन

नियोजकों के प्रतिनिधि

---मदस्य

5. श्री एम के शाह , बीड़ी सप्लाई कम्पनी खतराजपुर, संभलपुर

6. श्री जगबंधु माहु, पाल्ली बीडी निर्माता मुक्ताम श्रीर डाकघर ब्रह्म बडीबां जिला कटक

बंडीयां जिला कटक े र्रे 7. श्री अरुण डे, प्रेजीडेन्ट,

> बालामौर बीड़ी श्रमिक संघ बालामौर

 श्री विषित बिहारी पटनायाक, प्रेजीडेन्ट, तिनाथ बीड़ी श्रमिक संघ, मुकाम श्रीर डाकचर चोलापुर बाबा श्राथागढ़, जिला कटक कर्मचारियों के - प्रतिनिधि

9. श्रीमती सरस्वती प्रधान, महिला प्रतिनिधि श्रध्यक्षा राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड उड़ीसा भूवनेश्वर

10. कत्याण प्रशासक, भूवनेश्वर

म(चिव

2. उक्त नियमों के नियम 16 के श्रधीन केन्द्रीय सरकार् भूवनेश्वर को उक्त सलाहकार समित का मुख्यालय नियत करती है।.

> [यू. 19012/3/84-क्ल्याण-2] रविदन मिश्रा, ग्रवर सचिव

Now Delhi, the 30th March, 1985.

- S O. 1618.—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Beedi Workers Welfare Fund Act, 1976 (62 1976) read with sub-rule 2 of rule 3 of the Beedi Workers Welfare Fund Rules, 1978, the Central Government hereby constitutes an Advisory Committee for the State of Orissa consisting of the following members, namely:—
 - 1. Minister for Labour and Employment —Chairman Government of Orissa, Bhubaneswar.
 - Welfare Commissioner, Plot No. 33,
 Ashok Nagar, Bhubaneswar,

-Vice-Chairman (Ex-Officio)

3. Labour Commissioner, Orissa.

Member-Ex-Offici

 Shri Birendra Kumar Pandey, M.L.A., Jharsuguda. ---Member Ex-Officio

 Shri M.K. Shah, Becdi Supply Company, Khatrajpur, Sambalpur,
 Shri Jagabandhu Sahu,

 Shri Jagabandhu Sahu, Palli Becdi Nirmata, At/P.O. Brahma Baroda, District: Cultack. Employers' representatives

 Shri Arun Dey, President, Balasore Beedi Sramik Sangha Bajasore.

 Shri Bipin Behari Patnaik, President, Trinath Beedi Sramik Sangha, At /P.O. Gholapur, Via Athagarh, District: Cuttack. Employees' representatives

representatives

 Smt. Saraswati Pradhan, Chairman, State Social Welfare Advisory Board, Orissa, Bhubaneswar.

10. Welfare Administrator Bhubaneswar. -Secretary

Women

2. Under rule 16 of the said rules, the Central Government hereby fixes Bhubaneswar to be the headquarter of the said Advisory Committee.

[No. U-19012/3/84-W-II] R.D. MISHRA, Under Secy.

नई (दल्ली, 1 अप्रेल, 1985

का. आ. 1619.—खान श्रधिनियम, 1952 (1952 का 35) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रधन शक्तियों का प्रयोग करते हुए और जारत सरकार के भूतपूर्व श्रम और पुनर्वीम मंत्रान्य (श्रम विभाग) की श्रधि-सूचना संख्या का. श्रा. 458, धिनांक 28 जनवरी, 1984 का श्रतिक्रमण करते हुए कन्द्रीय सरकार श्री बी०सी० वर्मा को उन सभी क्षेत्रों के लिए जिम पर उक्त श्रधिन्यम लागू होता है 1 श्रप्रैल, 1985 से मुख्य खान निरीक्षक नियुक्त करती है।

[संख्या ए-32012/3/84-एम I] एल०के० नारायणन, श्रवर मध्वि

New Delhi, the 1st April, 1985

S.O. 1619.—In exercise of the powers conferred by subsection (1) of Section 5 of the Mines Act, 1952 (35 of 1952) and in supersession of the notification of the Government of India in the then Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour) SO. No. 458, dated 28th January 1984, the Central Government hereby appoints Shit V. C. Varma to be the Chief Inspector of Mines with effect from the 1st April 1985 for all the territories to which the said such extends.

[No. A-32012/3/84-MI] L. K. NARAYANAN. Under Secy.

नई (दल्ली: 1 अप्रैल, 1985

का. आ. 1620.— आँद्यागिक वित्राद्य श्रीधानियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण, में, केन्द्रीय गरकार, लाइफ इनक्यंत्रेन्स कारपंत्रिणन आफ इंडिया, दिवीजनल आफिस, नागपुर के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजको और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंधों में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण नं. 1, बम्बई के पंचाद को प्रशासित करती है, जो केन्द्रीय सरकार का 21-3-85 को प्राप्त दुमा था।

New Delhi, the 1st April, 1985

S.O. 1620.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal No. 1, Bombay as shown in the Annexum in the industrial dispute between the employers in relation to the management of L.I.C. of India, Divisional Office, Nagpur and their workmen which was received by the Central Government on the 21st March, 1985.

DEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1 AT BOMBAY

PRESENT:

Dr. Justice R. D. Tulpule Esqr., Presiding Officer.

Reference No. CGIT-16 of 1984

PARTIES:

Employers in relation to Life Insurance Corporation, Nagpur.

AND

Their Workmen

APPFARANCES:

For the employer.-Mr. P. R. Rai Advocate.

For the Workmen.-Mr. B. N. Kohale the workman.

INDUSTRY: Insurance STAE: Maharashtra.

Nagpur, the 13th day of February, 1985

AWARD

This is a reference made to this Tribunal under Section 10(2) of the Industrial Disputes Act, referring the dispute agreed between the parties and award in the following para:—

"Whether the action by the management of Life Insurance Corporation of India in relation to their Divisional Office, Nagpur in terminating the service of Shri Bhaiat N. Kohale, Badli Chowkidar/Watchman watchman with effect from 27-5-1983 and not considering him for re-employment is justified? If not to what relief the workman is entitled?"

Parties to the reference are present in person. The employee is represented by the President of the Bharatiya Jeevan Bima Nigam Chaturtha Shreni Karmachari Sangh. Naghur. The employee himself is also present. The parties to the reference have arrived at a settlement. The terms of

it, they have reduced to writing and produced before me. The terms have been explained to the vorkman in my presence, who understood them and were also understood by the union representative, representing him. I am satisfied that the settlement is bonafide and Genuine and is also morder. In the circumstances, I accept the settlement and direct award in terms of settlement which are as under:—

- (i) That Bharat N. Kohale, workman concerned will be empanelled in the panel of watchmen for Nagpur Divisional Office of Life Insurance Corporation of India constituted on 10-9-1984, a copy of which is annexed to the compromise petition of 13-2-1985.
- (ii) That Bharat N. Kohale, workman concerned agrees to appear before the interview committee which has selected the empanelled candidates mentioned above within 3 weeks from 13-2-1985 and further agrees to be placed in the said panel of ten candidates at a place recommended by the said Interview Committee. That Nagpur Divisional Office will communicate the date, time and place of interview to the concerned workmen Bharat Nanaji Kohale.
- 2. Award accordingly,

Sd/-

R. D. TULPULE, Presiding Officer [No. L-17012(25)]83-D, [V(Λ)]

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 1985

का.आ. 1621. - - अप्रैद्योगिक विवाद श्रिश्वित्यम, 1947 (1917 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, सेन्द्रीय सरकार, मैंसर्स चुनीलाल प्राणजीवनदास एस्ड कम्पनी बम्बई, के प्रबंधतत्र में सम्बद्ध नियोजको और उनके कर्मकारों के बीच, समुबंध में निद्दिष्ट औद्योगिक विवाद में नेन्द्रीय सरकार औद्योगिक आधकरण न० 1, बम्बई के पंचाट की प्रकाणित करनी हैं, जा केन्द्रीय सरकार का 21-3-85 की प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 2nd April, 1985

S.O. 1621.—In pursuance of section 17 of the Industial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal No. 1, Boombay as shown in the Annexus in the industrial dispute between the employers in relation to the management of M/s. Chunilal Pranjivandas & Co. Bombay, and their workmen which was received by the Central Government on the 1st March, 1985.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. I AT BOMBAY

PRESENT:

Dr. Jutice R. D. Tulpule Esqu.,

PARTIES:

Presiding Officer.

Reference No. CGJT-17 of 1984

M/s. Chunilal Prajivandas & Company.

 ΛND

Their Workmen

APPEARANCES:

For the employer.-Mr. P. Ramaswamy, Advocate.

For the workmen,-Mr. S. R. Wagh, Advocate.

INDUSTRY: Prots & Docks STATE . Muharashtra.

Bombay, the 18th day of February, 1985

AWARD

This is a reference made to this Tribunal under Section '0-(2) of the Industrial Disputes Act, referring the following dispute agreed between the parties vide order No. L-31012/1/84-D. IV(A), dated 14th August, 1984.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Ms. Chunital Pranjivandas & Company, Bombay in terminating the services of Shir Akshit R. Shah, Customs Clerk, w.c.f. 30-6-1985 is justified? If not, to what relief the concerned workman is entitled?"

Heard the parties. During the course of hearing the parties arrived at a settlement which they produced. Workman Mr. Shah is present in person. I have questioned him. He stated that he fully understood the contents of the settlement and be also stated what the settlement arrived at is. As the settlement is found to be bonafide and acceptable to all concerned, I accept the settlement and direct an award in terms of the settlement.

Sd/-

R. D. TULPULF, Presiding Officer [No. L-31012(1)/84-D. IV(A)] N. K. VERMA, Desk Officer

BEFORF THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT BOMBAY SHRI R. D. TULPULE

Ref. No. CGIT. 17 of 1984 BETWEEN

M/s. Chunilal Prajivandas & Co.

AND

Their Workmen.

May It Please You! Honour :-

The parties abovenamed have reached a settlement of the dispute of reinstatement of Shri Akshit, R. Shah and pray that all award in terms thereof may be made.—

The workman Shri Akshit R. Shah agrees to receive Rs. 15,000 (Rupces Fifteen thousand only) in full and final settlement of all his claims including the claim of reinstatement and as such there are no other claim against the employers M/s. Chumlal Prajvandas & Co.

The Respondent Employers M/s. Chunilal Prajivandas & Co. do hereby agree to pay the said Alshit R. Shah the sum of Rs. 15,000 in full and final settlement of all his claims against them including the claim of reinstatement.

There will be no order as to costs.

Dated this 18th day of February, 1985

For the workman.

Advocate for the workman.

Advocate for the Employers

Advocate for the Employers

नई दिल्ली. 2 अप्रैल, 1985

ा. 1622 -- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, वेस्टर्न रेलवे मैने जमैंट, चर्चगेट, बम्बई के प्रबंधल क्षा मिस्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-1 बम्बई के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 21 मार्च 1985 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 2nd April, 1985

S,O. 1622.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court No. 1, Bombay, as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Western Railway, Churchgate, Bombay, and their workmen, which was received by the Central Government on the 21st March, 1985.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL FRIBUNAL NO. I AT BOMBAY

COMPLAINT NO. CGIT-4 OF 1984

(Arising out of Reference No. CG11-7 of 1983)

PARTIES:

Manifal Gopal Surfi

. . Complainant,

Versus

The General Manager,

Western Radway, Churchgate, Bombay . . . Opponent. APPEARANCES:

For the Complainant—Mr. Vaidya, Advocate. For the Opponent—Mr. P. R. Pai, Advocate.

INDUSTRY . Railways . STATE : Maharashtra.

Bombay, the 20th day of February, 1985

AWARD

This is a complaint filed by the complainant under Section 33-A of the I.D. Act, 1947.

- 2. The concerned complanant to this complaint has given m writing that he was only a substitute Khalashi and that his name was entered into roll as a substitute or Badli Khalashi, and that he was not in the regular employment/service of the Railways as such. He, therefore admitted that there could be no question of termination of his services and what was done was only to remove his name from the roll of substitute Khalashis. He says that he would be satisfied if his name is brought back on the roll of substitute Khalashis and given work as substitute Khalashi as before, whenever there is an occasion and also considered for the post of temporary Khalashi in future when a vacancy actises. In view of this statement, and in view of the Railways being willing to consider the applicant's request sympathetically on human tarian grounds, the workmen concerned does not press his complaint as also the reference.
- 2. In the circumstances, I direct the Railways to bring the workmen concerned on the roll of substitute Khalashi as early as possible and consider his case also for appointment as temporary Khalashi in view of his long experience and work in Railways. The concerned workman has now stated in writing that he is willing to work on transfer at any place within the unit in which Surat and Udhna falls.
- 3. In view of this, the reference is disposed of and the complaint dismissed as not pressed.

R. D. TULPULE, Presiding Officer [No. L-41025(2)/85-D IJ(B)] HARI SINGH, Desk Officer

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 1986

का. आ. 1623— औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार झारखन्ड एरिया आफ कोलफील्ड लिमिटेंड के प्रबंध-तंन्न से सम्बन्द्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीध अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में विवाधक श्री के. सनमूचवल (अवकाशप्राप्त) उपयुक्त श्रमायुवत (केन्द्रीय) के पंचाट को प्रकाणित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 26 मार्च 1985 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 2nd April. 1985

S.O. 1623.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Arbitration Award of Shri K. Shanmughevel, Dy. Chief Labour Commissioner (Central) (Retd.) (Arbitrator) as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Jhagrakhand Area of Western Coalfields Limited and their workmen, which was received by the Central Government on the 26th March, 1985.

A vaid under Section 10 A of the Industrial Disputes Act 1947 in an Industrial Dispute between the Management of Jbagrakhand Colliery, Western Coulhelds and some of their workman employed in South Jbagrakhand Colliery, represented by M.P. Colliery Workers' Federation (INTUC), District Furgura (M.P.)

PRESENT

Shri K Shanmughavel, Dy Cl C (() (Retd.), Consultani (Industrial Relations) Newvah Lignite C 1pn Lie Neyveli (Tamiliadu)

PARTIES

Representing Employer

Management of Jhagrakhand Area, Western Coalfields Limited, P.O. Jhagrakhand Colliers, Distt Singma (M.P.)

Representing workmon.

M.P. Colhory Workers' Federation (INTUC), Jhagrakhand Area, Jhagrakhand Colhery, Distt Surguja (M.P.)

APPEARANCE

On behalf of M in igoment

Shii II P Singh, Personnel Manager, Western Coalfields Ltd., Jhagrakhand Area

On behalf of workmen

Shit GP Shitma, General Societary, MP Colliery worters Federation, Jhagra khand Area

Specific matter in dispute referred to Arbitration

"Whether the jobs performed by S/Shri Mohan, Lakheshwir and Budhu, although designated is Tippler Klialasis, justifies their claim for upgradation to the post of Mechanical Fitter-cum-Tippler Khalasis? If not, what relief they are entitled to?

By an agreement under Section 10A of the Industrial Disputes Act 1947, the aforesaid parties referred the dispute cited above to my arbitration. A number of hearings were held and were adjourned on account of reasons mutually agreed upon and on account of unavoidable reasons. The parties, however, by mutual consent had agreed to extend the date for issuance of the Award upto 31st March 1985. The final hearing/arguments were held on 19th January, 1985 and on 20th January, 1985 at Neyveli.

- 2 The statements and counter statements from the parties were received, evidence were addited by them and final arguments were heard
- 3 On behalf of the workmen it was argued that the concerned workmen were permanent employees of South theigrathand Colliery Originally they had been designated as Screening Plant Khalas's Later on they were given a combined designation as Screening Plant cum Tippler Khalasis and placed in Cat. III
- 4 Since then then work load, responsibility, etc. had been increased on account of installation of 16 Bunkers and n troduction of conveyor system for expediting Wagon loading by rotation of tubs. In this regard the following motors had been installed —

- (1) One motor of 50 HP for Belt Conveyor (Slack),
- (1) One motor of 50 HP for Belt Conveyor (Steam)
- (iii) One motor of 10 HP for Chain Conveyor.
- the workmen had to perform additional work by operating them and by doing allied works in addition to their normal work assigned in the capacity of Screening Plant-cum Tip plei khalasis. No Firter is exclusively earmarked to attend to breakdown work during the shifts All minor repairs pertaining to the Belt Conveyor, Screening Plan and Conveyor Chain etc. are being attended to by them According to the principles laid down by the Central Wage Board for Cold Mining Industry and the National Coal Wage Agreements, the following factors have to be taken into consideration while eneconsideration in a particular workman or group of workmen
 - (a) Degree of Still.
 - (b) Strain of work
 - (c) Experience involved
 - (d) Iraining required
 - (e) Responsibility undertaken
 - (f) Mental or physical strain
 - (g) Disagree ibleness of tisk
 - (h) Hizaid of work
 - (1) Fitigue involved
- 6 There is no doubt that the workmen had been called upon to carry out a certain amount of add formal work on account of installation of Bunker and Introduction of Conveyor system. Consequently the workmen had to shoulder a greater decree of skill strain of work responsibility, mental and physical strain, fatigue etc. So they have to be correspondingly compensated and rewarded suitably. The union further stated that similar category of workmen in Ramagui Colliery of Thierinkhand area are placed in Category V Himilly the union pleaded that the concerned workmen shall be placed in Category VI and payment made accordingly
- 7 On the other hand the Management averred that the concerned workmen were operating only the Scieening Plant regularly and attending the belt, at times, and as and when needed. They are not at all operating the Tippler Creeper, Horst, etc. By the installation of motors which facilitates expeditions wagon loading the physical strain generally, faced by the Tippler Khalasis has been mitigated to a great extent Switching on the motors, which is the normal job of Tippler Khalasis does not involve more responsibility non-emanates fatigue and strain as argued by the Union. Once the switch is inade on no other manual operation is required till the process of coal handling is over. Besides they are being centrally operated. At the time of breakdown of the motors regular filters are invariably called upon to attend to break down. As such, no additional burden of work is devolved on the Scieening Plant Tippler Khalasis. So the Management argued that the concerned workmen have been tightly categorised and placed in Category III. However, during the course of the hearing on behalf of the Management it was argued that even if it was admitted that the original three workers who were mentioned in the reference to Arbitration were exist some exita job then they would be entitled for payment of wages to only one category higher than their existing category as per the recommendations of the Wage Bond Regarding restrospective effect of the award it was said that the Management would abide by the spirit of the mitial agreement between the pattes saying if the award goes in favour of the workmen then they would get the airears from the date of installation of the Bunker/Conveyor. The Management would stand by the commitment given.
- 8 From the evidences available and from the tenor of the arguments placed before me I have no hesitation to state that the conceined workmen have to carry out extra burden of work since the installation of the Bunker/Conveyor But at the same time the burden of work had not been aug-

FATTLE C

mented to the extent of categorising them under Category-VI is highly skilled as the strength of the Operators had been adequately augmented to man the additional machines. So the concerned workmen can not be upgraded to the post of Mechanical Fitter-cum-Fippler Khalasis.

- 9 The National Wage Board Agreements have opined that as and when changes in conditions of work occurred, the rates of wages have to be reviewed and revised within the frame work of the NCWA.
- 10. In view of the above, I award that the concerned workmen would be placed on Category-IV with effect from the date of installation of the Bunker/Conveyor.
- 11. With regard to the argument of the union that the award should bind other workmen who are now engaged, I have to state that I have to function within the terms of the reference. According to the terms the names of Sarvashri Mohan, I akheshwari and Budu only are the contestants. Hence I may not go beyond the terms of reference.
 - 12. The union demanded award of cost. In 'he circum-

stances of the case and the manner in which the hearing was held, I do not find any justification to award cost.

Award dated 21st March, 1985.

K. SHANMUGHAVEI, Dy. CLC (C) (Retd.)
Consultant (Industrial Relations)
Neyveli Lignite Corporation Ltd.,
Neyveli (Tamilnadu)
AND
ARBITRATOR
[No. L-22013(7)/79-D,[V(B)/D V]

R. K. GUPTA, Desk Officer

New Delhi, the 12th April, 1985 CORRIGENDUM

S.O. 1624.—In para 15 of the Award of the Industrial Tribunal, Bangalore published under Notification No S.O. 1336 dated the 30th March, 1985 in Part II, Section 3, Sub-Section (II) of the Gazette of India dated the 31st March, 1985, for the words "rejecting the reference", read "accordingly".

[No. L-29011]59[79-D.III(B)] M.L. MEHTA, Under Secy.